

देवेन्द्र कौशिक

आधुनिक मध्य एशिया

(१९वीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर अब तक का इतिहास)



प्रगति प्रकाशन • मास्को

अनुवादक अली अशरफ

Д. КАУШИК

Средняя Азия в новые времена

На языке хинди

हिंदी अनुवाद • प्रगति प्रकाशन • १९७७

सोवियत संघ में मुद्रित ।

K $\frac{11601-382}{014(01)-77}$ 575-76

आठवाँ अध्याय । बुखारा और एवारज्म लोक सोवियत जनतंत्र	
से सोवियत समाजवादी जनतंत्र में सन्नमन	२४२
नया अध्याय । सोवियत जातीय जनतंत्रों का निर्माण	२५६
दसवाँ अध्याय । आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन	२७२
उपसंहार	३२१

लेखका के लिखे हुए हैं, जिन्हें आमूदरिया के उत्तर, हिंदूकुश के परे समाजवादी निमाण की उपलब्धियाँ की बाबत सच कहने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालाँकि ये ऐसी सफलताएँ हैं, जिनका उल्लेख भारतीय गणराज्य के प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सबपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद ने सोवियत संघ की अपनी यात्राओं के बाद उत्साहपूर्वक किया।

इसलिए यह आशा की जा सकती है कि इस पुस्तक का विशेष निलचस्पी से पढ़ा जायगा। लेखक एक भारतीय विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने सोवियत संघ में वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान अपने तथ्य जमा किये। वह घपहल ताश्कन्द में रहे जो उज्बेकिस्तान की राजधानी और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनस्थल है। वहीं उन्होंने अपना थीसिस लिखा और सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, जिसकी बदौलत उन्हें विज्ञान (इतिहास) के कंडीडेट (पी एच०डी०) की उपाधि मिली।

बर्द जातिया में यह कहावत है कि किसी चीज के बारे में सो बार सुनने से अच्छा उसको एक बार देख लेना है। देवेन्द्र कौशिक ने सोवियत मध्य एशिया में नए सोवियत समाज को छुड़ अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने देखा है कि वह पेचीदा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और उन्नत विज्ञान तथा संस्कृति के फल से लाभान्वित हो रहा है।

एक ऐसे इतिहासकार की हैसियत से जिनने मध्य एशियाई जनता का अतीत का गहरा अध्ययन किया है, यह भारतीय विद्वान इस स्थिति में थे कि उन विज्ञान परिवर्तना का सही मूल्यांकन कर, जो सोवियत संघ के उस भाग में हुए है। वास्तव में वह यही बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़स्तान के लोगों ने (वह कज़ाख़स्तान की बात कम करते हैं) १९वाँ सदी के पूर्वार्द्ध से हमारे जमाने तक क्या रास्ता तय किया है। उन्होंने अनन्य प्रशंसित स्तावज़ा माखिमोव मार-भूचिया पत्र-पत्रिकाओं तथा पुरा संशोधन की सामग्री का उपयोग किया है। उनकी पुस्तक वास्तव में तथ्यों से भरी पानी की मगर तथ्य इनके बाव में दसा नहीं, जस कुछ लोग धा के बाव से न्य जानें। उन्होंने अपने तथ्यों का खूब जाला

है और उचित कालप्रमाणानुसार पेश किया है जिस से उनका गहन मद्भातिव चिन्तन का परिचय मिलता है।

लेखक ने १९वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मध्य एशिया के पान शासित प्रशा-बुधारा, ग्रीवा और कोवान-की स्थिति का वर्णन किया है और टीका ही उनका अत्यंत प्राथमिक सैनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन पर जार दिया है। वह मध्य एशिया में अंग्रेजों की साजिश और व्यापारिक तथा राजनीतिक धुम-पैठ की कागिशा, और उस इलाके में जारशाही के सैनिक विस्तार पर प्रवास डालत हैं। उन्होंने यह विन्तुल सही कहा है कि जारशाही के अधिनारिया द्वारा वहां स्थापित प्रशासन औपनिवेशिक था, पर वह यह भी बताते हैं कि वहां प्रगतिशील रूसी वैज्ञानिकों का, जिन में इतिहासविज्ञ भूर्वैज्ञानिक वनस्पतिज्ञ और प्राणिविज्ञ सभी थे, कार्य-नाप बहुत महत्त्वपूर्ण था। औपनिवेशिक तुविस्तान अथवा उनके विश्लेषण में लेखक इस सही नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस इला में पूजावाद से पहले के संस्था की प्रमुपता थी।

पुस्तक का एक मूल्यवान पहलू यह है कि यह वादायक है। लेखक तथा को इकट्ठा करके इतिहास के पूजावादी जानसाजों की कुत्सापूर्ण मनगढन्त का परदाफास करते हैं, जिन्होंने सोवियत यथायता को ताड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयत्न किया है। इनमें जेआर्मी हीलर रिचर्ड पाइप्स, हयुग सीटन-वाटसन, अलेक्सांद्र पान और स० जेवाक्की हैं। देवेद्र कौशिक ने हीलर के इस दाव का खंडन किया है कि बुधारा अक्टूबर आति से पहले उन्नति कर रहा था। उस अंग्रेज लेखक ने मध्य युग के उस अधकारमय अवशेष, बुधारा के सामंती उपराज को बड़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया है, ताकि सोवियत युग में बुधारा नखलिस्तान में जा शानदार परिवर्तन हुए हैं, उनके अमर को कम करे।

कौशिक ने अंग्रेज और अमरीकी "सोवियतज्ञों" के इस झूठ दावे की धज्जिया उड़ाई है कि मध्य एशिया में समाजवादी आति बाहर से लाई गई और लागा पर जबरदस्ती लादी गई थी। वह साबित करते हैं कि शोषित जनता में-उज्बेक, ताजिका, किर्गिजा और तुक्माना में- समाजवादी आति की जमीन तयार थी और वे अमृतूनर आति की विजय

के लिए सावित सत्ता के लिए, जिसे वे स्वयं अपनी सत्ता मानते थे, वीरतापूर्वक लड़े। भारतीय विद्वान न ह्यूीतर के इस कथन का मजाक उड़ाया है कि मध्य एशिया का अधनत आज औपनिवेशिक है।

मुझे सब स अच्छी बात यह लगी कि लेखक ने मध्य एशिया और भारत के इतिहास में समान तत्त्वा की हमेशा तुलना करने का प्रयास किया है। उन्होंने आधुनिक युग में उनके संबंध का वर्णन अधिकतर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय अभिलेखागार की भूली विसरी दस्तावेजों के आधार पर किया है। इस प्रसंग में मैं उस दिलचस्प सूचना की चर्चा करना चाहूंगा, जो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लेनेवाला द्वारा सावित हम की यात्रा और प्ला० इ० लेनिन से उनकी भेट के बारे में दी है।

मुझे आशा है कि भारतीय स्वाधीनता के सेनानियों—महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू—के दश में इस पुस्तक के दूसरे भाग पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिस में मध्य एशिया की जातियाँ के इतिहास के आधुनिकतम दौर—तुर्किस्तान में, बुखारा और खीवा खानशाही में श्रमजीवी जनमण की सत्ता की विजयी और सुदृढ़ बनाने के लिए उनका संघर्ष, राष्ट्रीय प्रभुसत्ताप्राप्त राष्ट्रीय जनतंत्र की स्थापना, शापक वर्ग का उन्मूलन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का अंत और उद्योग कृषि तथा संस्कृति का समानतादी स्थापन—पर प्रकाश डाला गया है। इन सब की इस पुस्तक में संविस्तार चर्चा की गई है। इन अध्ययन से लेखक के स्वदेशवासी खाला अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जारशाही हम के पिछड़े औपनिवेशिक इलाकों का समाजवादी स्थापन करने तथा ऐतिहासिक दृष्टि से उतनी कम मुद्दत में उन्हें वर्तमान प्रभुसत्ता प्राप्त और उन्नत आधुनिक कृषि जनतंत्र बनाने के लिए क्या उपाय करने और कौन से साधन अपनाने पड़े।

लेखक ने मतवाद को केवल कहीं कहीं कुछ संक्षिप्त किया गया जिसका विषय वस्तु पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ कहीं हम टिप्पणी करने, या लेखक के किसी कथन पर बल देने की जरूरत हुई है, हम ने फुटनोट में 'ग०' का चिह्न लगाकर ऐसा किया है। चित्र भी हम ने चुने हैं।

न० आ० लालसिंह
विद्वान (इतिहास) के दायरे

हम भारतवासियों को मध्य एशिया की घटनाओं में हमेशा गहरी दिलचस्पी रही है। अनेक बार इन घटनाओं ने हमारे इतिहास की गति को प्रभावित किया है। ऐसे समय जबकि सोवियत संघ तथा भारत के जनगण की मंजी दिना न्तिन जार पवड रही है यह स्वाभाविक है कि मध्य एशिया के जनगण व जो वास्तव में हमारे पडोसी है, ऐतिहासिक विकास में हमारी दिलचस्पी और गहरी हो। प्रस्तुत पुस्तक में १९वीं सदी के शुरू से लेकर लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक के मध्य एशिया व आधुनिक इतिहास पर विचार किया गया है।

प्राक्कथन

दूर अतीत में मध्य एशिया का बड़ा महत्व था, भिन्न भिन्न सभ्यताओं और सभ्यताओं की धाराएँ वहाँ आकर मिलती थीं। मगर १५वीं सदी के अंत में महान नाविकों की युगप्रवर्ती यात्राओं के बाद वह गुमनामी में पड़ गया। लेकिन १९वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों से ज़ारशाही रूस तथा ब्रिटन की औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता के प्रभाव के कारण इस इलाक़े का कुछ-कुछ पुराना महत्व फिर बहाल हो गया। इस प्रकार मध्य एशिया का आधुनिक इतिहास जब शुरू हुआ, उस समय दो प्रतिद्वंद्वी पश्चिमी साम्राज्यों का साथ इस इलाक़े पर था। मध्य एशिया की जातियाँ सामंती खानों के कुशासन तले अत्यंत आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की स्थिति में पड़ी हुई थीं। उनकी हैसियत दो यूरोपीय शक्तियों की औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता में शतरंज के मोहरा की थी।

इस पुस्तक की तैयारी में मैंने जो काय अपने सामने रखा है, वह था मध्य एशिया में ज़ारशाही

रूस की बदेशिक नीति के उद्देश्या की छानबीन करना, जहाँ तक उसका संबंध साम्राज्य की अदरुनी, खासकर आर्थिक स्थिति से था। मेरा दूसरा लक्ष्य मध्य एशिया में आगलरूसी प्रतिद्वंद्विता की समस्या का आलोचनात्मक तथा व्यापक अध्ययन करना था। मध्य एशिया में जारशाही सरकार के आक्रामक चरित्र के बावजूद उसने प्रचलित आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत पर कब्जा करने का कभी इरादा नहीं किया। भारत पर रूसी आक्रमण का हौआ अंग्रेज साम्राज्यवादी हलकों ने झूठमठ खड़ा किया था क्योंकि वे मध्य एशिया में अपनी विस्तारवादी कारवाइयाँ पर परदा डालना चाहते थे। मैंने रूसी तथा भारतीय मूल सामग्रियों की सहायता से मध्य एशिया में ब्रिटेन के आक्रामक मनस्वी का परदाफाश किया है। मध्य एशिया में अंग्रेजों की साजिश का ही प्रभाव था कि उस इलाके पर रूसी कब्जे की रफ्तार तेज हो गई, जो बुनियादी तौर पर विकासमान पूँजीवाद की विस्तारवादी आवश्यकताओं का नतीजा था।

मध्य एशिया पर रूसी कब्जा वस्तुनिष्ठ रूप से उस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास के लिए प्रगतिशील महत्त्व रखता है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस इलाके में प्रारम्भिक पूँजीवाद का उदभव हुआ जिसके कारण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेज हो गये।*

१९१७ की अस्तूरर समाजवादी क्रांति ने मध्य एशिया की जातियों का जीवन में नया युग शुरू किया। क्रांति में पहले मध्य एशिया जारशाही रूस का उपनिवेश था। उसके विनाश का स्तर पूँजीवाद से पहले का था। उसका अथर्व पिछड़ा हुआ था और जीवन-स्तर दरिद्रता का हूँ तब नीचे गिरा हुआ था। क्रांति के बाद मध्य एशिया का जानिया न अलग मानियत जानिया के साथ मिलकर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत कम

*मानियत इतिहासकारों की राय में इस कब्जे का मुख्य प्रगतिशील पहलू यह था कि उसने मध्य एशिया के उत्पीड़ित श्रमजीवी जनगण का रूसी साम्राज्य की क्रांतिकारी क्रांतियों में जोड़ दिया और यह चीज अनिश्चित में जार, पूँजीपतियों और जमाने के शासन का तन्ना उखटन का निण, भार रूस में समाजवादी क्रांति की विजय के लिए बन्ने महत्वपूर्ण माना हुआ है। — स०

समय में एक समाजवादी समाज का निर्माण किया। समाजवादी बहुजातीय राज्य की स्थिति में, जो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित था, इस भूतपूर्व उपनिवेश में जिस जारशाही साम्राज्य की परिधि में वतपूर्वक घेर रखा गया था, सत्तार के समक्ष स्वेच्छापूर्वक विराट्ना सन्ध का ज्वलंत उदाहरण पेश किया।

कुछ और सोवियत जातियाँ की तरह मध्य एशिया के जनगण भी सत्तार में पहले से जा पूँजीवादपूर्व सबंधों से समाजवाद में अपने सत्रमण में पूँजीवाद से बचकर निकल गये। उनका अनुभव उन राष्ट्राँ के लिए दिलचस्प होगा, जिन्होंने औपनिवेशिक गुलामी का जूझा उतार फेंका है और स्वतंत्र आपिन तथा राजनीतिक विकास का रास्ता अपनाया है। प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप में बताया गया है कि मध्य एशिया के लोगों ने कैसे सावियत सत्ता की स्थापना की अपने आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर किया, समाजवाद का निर्माण किया और तब से अब तक क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की।

आधुनिक मध्य एशिया के इतिहास के अध्ययन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अब तक उपेक्षित रहा है। इस इलाके से संबंधित काफी सामग्री भाग्यीय अभिलेखागारा में मौजूद है और इस सामग्री तथा मध्य एशिया तथा भारत की समस्याओं के प्रसंग में इसकी छानबीन बाछनीय है। मैं इस मूल सामग्री का कुछ उपयोग किया है। इस किताब में मध्य एशिया और भारत के संबंधों पर भी एक अध्याय जोड़ा गया है। इस शीपक के अंतर्गत सिकमाग या चीनी तुकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है क्योंकि मध्य एशिया में आग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता से इसका गहरा संबंध है।

मैं बहुत से सोवियत विद्वानों तथा लेखकों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके अनुसंधानों और कृतियों का मैं व्यापक उपयोग किया है।

इसी तरह मैं आभारी हूँ सोवियत प्राफ़ेसरगण में ग० व० बहावोव, न० अ० खालफिन, अ० अ० गोदियेव, ख० त० तुमूनोव, ताशकंद के सबंधी ग० अ० हिलायानीव, त० अ० तुतुनजान तथा व० वूबनिकोव का, जिन्होंने अपने विचारों से इस पुस्तक में प्रस्तुत समस्याओं पर ज्यादा अच्छी तरह दृष्टिपात करने और समझने में मेरी सहायता की।

विशेष रूप से मैं प्रोफेसर न० अ० खालफिन का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया और इस के बारे में कुछ शब्द लिखे हैं।

मैं अपने मित्रा सवथी सुरेश चंद्र अग्रवाल, साधुराम और शक्तिप्रसाद के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पांडुलिपि पढ़ी और कई बार आभार सुझाव दिये।

अपनी पत्नी राधा तुंगेशेवा का मैं बहुत आभारी हूँ जिनकी सहायता और प्रोत्साहन इस काम का पूरा करने में मेरे लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुए।

इस पुस्तक को कई प्रकार की सहायता से लाभ पहुँचा है। मैं डॉ० बुद्धप्रकाश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे पहले मध्य एशिया व इतिहास में मेरी दिलचस्पी पैदा की।

विभिन्न पुस्तकालयों के कमियाँ के सौजन्य तथा सहयोग के लिए भी मुझे धन्यवाद देना चाहिये जहाँ से मैं इस कृति के लिए सामग्री प्राप्त की। इन में खासकर उल्लेखनीय है मास्को का लेनिन पुस्तकालय, ताशकंद का अलीशेर नवाई पुस्तकालय, उज्बेक सो० स० जनतंत्र की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संस्थान के पुरालेख संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंडियन काउंसिल आफ बट्ट एफेयर्स, नई दिल्ली का पुस्तकालय और लन्दन का ब्रिटिश म्यूजियम। मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा पंजाब राज्य अभिलेखागार, पटियाला के अधिनारियाँ का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने रखाड़ मुझे देखने दिये और उनका प्रयाग करने की मुझे इजाजत दी।

१९६२ से १९६४ तक लेनिन राज्य विश्वविद्यालय ताशकंद की फताहिफ में मुझे मासिक सहायता से सामग्री जुटान में बड़ी सहायता मिली।

इस काम का पूरा करने में और जिन लोगों ने तरह तरह से योगदान दिया, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। परन्तु मूलांकन और व्याख्या मेरा अपनी ही और कुछ नुटियाँ रह गई हैं ता मैं उनकी पूरा जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ।

देवेन्द्र कौशिक

नई दिल्ली,

मार्च १९६८

श्री जे बगरहटा, श्री

श्री हरिजि

श्री यादव

श्री

भूमि

पाच सोवियत जनतंत्र - कजाखस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, गिजिस्तान और तुर्कमानिस्तान - एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं जिनके त्तर में पश्चिमी साइबेरिया दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान पश्चिम में वोल्गा और कास्पियन सागर और पूर्व में चीन है। इन जनतंत्रों में लगभग तीन करोड़ लोग रहते हैं, जो सोवियत संघ की कुल आबादी का दसवा हिस्सा है। इनका क्षेत्रफल ४० लाख वर्ग किलोमीटर है जो सोवियत संघ का छठा भाग है। कजाखस्तान का निकाल दिया जाये, तो मध्य एशिया का क्षेत्रफल कोई १३ लाख वर्ग किलोमीटर है। सच पूछिए तो सोवियत मध्य एशिया का नाम उपयुक्त पाच में से केवल चार पर ही लागू होता है और उसमें कजाखस्तान शामिल नहीं है, जो नसली और सांस्कृतिक समानता के बावजूद भौगोलिक दृष्टि से मध्य एशिया से भिन्न है। यह एक स्टेपी इलाका है और जारशाही के जमाने के तथा सोवियत लखवा ने भी इसे अलग माना है। इस पूरे क्षेत्र में मौसम तथा प्राकृतिक स्थितियाँ की अत्यंत विविधता पायी जाती है। पश्चिम और उत्तर में विशाल मैदान है। पूर्व और दक्षिण में काफी बड़ा इलाका पहाड़ी है। एक बड़ी पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम में कोपेत दाग से पूर्व में पामीर और तियान शान तक मध्य एशिया को शप

महाद्वीप से अलग करती है। इन इलाकों में बड़ा भेद पाया जाता है विशाल मरुत हैं जिनमें निचान समुद्र तल से नीचे पहुँच जाती है और पहाड़ों की चाटिया मरुत बर्फ से ढकी रहती है, घनी आबादीवाले नखलिस्तानों के चारों ओर निजान रगिस्तान है। पहाड़ों पर उत्तरध्रुवीय हिमपात है ता निचले मैदानों में उष्णदेशीय गर्मी। उत्तर में मौसम शीताण है और दक्षिण में गर्म है और गर्मियों में अत्यन्त शुष्क हो जाता है। समुद्रों में बहुत दूर होने के कारण मौसम वास्तव में महाद्वीपीय है। पहाड़ों की चाटिया साल भर बर्फ से ढकी रहती है और आर्कटिक की घाटी में तरमोज में तापमान छाव में $+50^{\circ}$ सेटीग्रेड तक पहुँच जाता है जो पूरे मावियत सघ में सब से अधिक गर्म है, जबकि मध्य तियांन शान और पामीर में जुलाई में औसत तापमान क्रमशः $+5^{\circ}$ और $+15^{\circ}$ है जो जाड़ा में -40° तक गिर जाता है। पर्वतीय इलाकों का छोड़कर हिमपात बहुत कम होता है। उत्तर में अराल सागर साल के कई महीने जमा रहता है और यही हान मिरदरिया के निचले मुहाने का है। अरब रगिस्तानी और रगिस्तानी इलाकों की आम विशेषता ठण्डी हवा है।

भौगोलिक दृष्टि में मध्य एशिया और कजाखस्तान को चार हिस्सों में बाँटा जा सकता है स्तपी ज़िगम उत्तर कजाखस्तान या परती-ज़मीन का द्वारा शामिल है अरब रगिस्तान, जो लगभग सारे शेष कजाखस्तान में फैला हुआ है इसमें दक्षिण में रगिस्तान का द्वारा, जो पश्चिम में रंगान और पूर में चान की सीमा तक फैला हुआ है, और पामीर और तियांन शान का पहाड़ी द्वारा।

मध्य एशिया का बड़ी और छोटी नदियाँ ज़िह बारह महीने वर्ष में पानी मिला देता है इसके नखलिस्तानों का हर भरा बनाय रहता है। २१ वीं नदियाँ आर्कटिक और सिर-डरिया हैं जिनके मात पामीर और तियांन शान में हैं छोटी नदियाँ में डरफगान, चू, मुगान, तजिक और अरार हैं। रजाखस्तान में इरति, ईसी उरान और इतिन नदियाँ बहती हैं। इन द्वारा की मरुतपूर्ण सीमा में अरार सागर बनाया सीत तथा इरती-अरार शान हैं।

हिमवत पर्वतो तथा मूखे रेगिस्तानो से मध्य एशिया के लोगो की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति मे कोई बाधा नहीं पड़ी। सुदूर अतीत स वहाँ अत्यन्त विरसित कृषि सभ्यता फलती फूलती रही है जिसका आधारा सिचाई था। अनुकूल प्राकृतिक स्थितियाँ, जैसे गर्मी के लम्बे मौसम, उपजाऊ लोएस भूमि सिचाई की गुंजाइश मैदानों और पहाड़ियों पर बड़े चरागाह और प्रचुर खनिज धन की बदौलत नाना प्रकार का आर्थिक कायकलाप सम्भव हुआ।

मध्य एशिया और कजाखस्तान की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए निष्पाद्य महत्त्व की रही है। समुद्री रास्ता की छाज स पहले पूर्वी तथा मध्य एशिया का पूर्वी यूरोप से तथा निकट पूर्व व देखा से जाड़नवाले मुख्य व्यापारिक रास्ते इसी इलाके स होकर गुजरते थे। आज के विमान और भू-संचार की मेवाए भी, जा सोवियत संघ को ईरान, अफगानिस्तान, भारत और चीन मे जोड़ती हे, मध्य एशिया और कजाखस्तान स होकर गुजरती है।

लोग

मध्य एशिया सभ्यता के सब से पुराने केन्द्रा म से एक है। यहाँ सोवियत पुरातत्वशा न अनेक अवशेषों की खुदाई की है जिनका सवध पुरापापाण युग स है। कजाखस्तान के तलस और जाम्बूल इलाके से और दक्षिण उज्बेकिस्तान म तशोक तारा से माउस्तेरियाई अवधि और उसस भी पहले के समय की चीजे मिली है। अनेक मध्य एशियाई कबीले उदाहरण के लिए दक्षिण तुर्कमानिस्तान म जेईतुन वस्ती के लोग नवपापाण युग म ही कृषि और पशुपालन करने लगे थे। दक्षिण तुर्कमानिस्तान म अनाठ सस्कृति व लोगो को ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी म ही कृषि का ज्ञान था। प्रारम्भिक लौह युग सस्कृति ईसा पूर्व पथम सहस्राब्दी म प्राचीन ख्वारज्म म मौजूद थी। यह सस्कृति मुख्यत कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी। ख्वारज्म म सिचाई की नहरा का जाल मा बिछा हुआ था। अन्य समकालीन सस्कृतियाँ मे, जा कृषि तथा शहरी जीवन व उच्च

स्तर पर पहुंच गई थी बैक्ट्रिया और सोगदियाना का उल्लेख किया जा सकता है। स्तेपी क्षेत्र के लोग ताम्रयुग में ईसाई बाल से एक हजार वर्ष पूर्व सिचाई से अवगत थे।

प्राचीन मध्य एशिया तथा स्तेपी क्षेत्र की आदिम आबादी उसी ईरानी वंशमूल की थी जिससे फारस बाले थे। मध्य एशिया के सबसे पुराने लोग जिनका हाल हम मालूम है—जरफ़शान घाटी के सोगदियान और आमू दरिया के निचले किनारे पर बसे हुए ख्वारज़्मी—इसी वंशमूल से थे। उनका इलाका अक्मेनिद राज्य का हिस्सा था। यह पहला विश्व साम्राज्य था जिसका इतिहास को ज्ञान है। राजा दारी ने (५२२-४८६ ई० पू०) अपने शिलालेखों में सोगदियानों और ख्वारज़्मियों की चर्चा करते हुए उन्हें अपनी प्रजा बताया है। उन्होंने यूनान के विरुद्ध उसकी लड़ाई में भाग लिया था।

सिवन्दर महान के आक्रमण के समय तक ख्वारज़्म फारस का प्रांत नहीं रह गया था। मगर सोगदियान उस समय तक फारस के शासन के अधीन थे और वे सिवन्दर के खिलाफ लड़े। अक्मेनिद राज्य को सिवन्दर महान ने नष्ट कर दिया और इसके इलाके यूनानी-मकदूनी साम्राज्य में शामिल कर लिए गए। उसी सदी में इसका पतन होने के बाद मध्य एशिया का काफी बड़ा हिस्सा सेल्युकस राज्य में मिला लिया गया। ईसा पूर्व तीसरी सदी में मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में सेल्युकस का तटस्थ स्थायी विद्रोह के कारण उलट गया। उनके स्थान पर पार्थी आये। लेनिन पाकिस्तान में हमने के बावजूद स्वतंत्र यूनानी-बैक्ट्रियाई राज्य १४०-१३० ई० पू० तक कायम रहा। कुछ अंशों बाद यूनानी-बैक्ट्रियाई राज्य के स्थान पर कुषान राज्य स्थापित हुआ। कुषान युग मध्य एशिया के लिए सांस्कृतिक तथा आर्थिक विस्तार का जमाना था। इस क्षेत्र का समृद्धि का कारण यह भी था कि वह चीन का फारस और रामन जगा से मिलाने वाले "महा रश्मी मार्ग" पर स्थित था।

तीसरी सदी ईसवी के अंत में कुषान सत्ता का पतन शुरू हो गया। चौथा सदी ईसवी में श्यापनार्द या श्या हूण नामक एक खोबरे ने जिनका कुषान में संबंध था और जो उनके शासन के अधीन था, बैक्ट्रिया पर

कब्जा कर लिया और मध्य एशिया में कुपान शासन की इट से इट बजा दी। परन्तु श्वेत कूणा का शासन बहुत दिन नहीं चला। ५६३-५६७ ईसवी में इफ़यलाइया को जैतीमुव व तुर्कों ने परास्त कर दिया और मचूरिया से बाले सागर तक फले खगान शासन में शामिल कर लिया। छठी सदी ईसवी के शत तक खगान शासन दो भागों में बंट गया और उसके पश्चिमी भाग पर मुसलमान अरबों का अधिकार कर लिया।

मध्य एशिया में अरबों का दखल आठवीं सदी के प्रारम्भ में इब्न मुस्लिम व नतत्व में हुआ। वह खुरासान का राजपाल था। सारे इलाके में वे तलवार और आग लेकर बढे और शानदार सांस्कृतिक खजाने नष्ट कर डाले जैसे पजीकन्द के मन्दिर में गिला और अन्य यादगारों। अरबों की इन सत्यानाशी हरकतों का वर्णन अल बरूनी ने बड़े आभोज के साथ किया है। उनके कथनानुसार इब्न मुस्लिम ने उन सारे विद्वानों को मार डाला जो ख्वारज़म के इतिहास और भाषा का ज्ञान रखते थे, जिससे इस्लामी युग से पहले के इतिहास के बारे में कुछ जानना असम्भव हो गया। स्थानीय जनगण ने जिन्हें तुर्कों कबीलों का समर्थन प्राप्त था, अरबों का बड़ा विरोध किया। यह जन विरोध कोई पचास वर्ष तक जारी रहा। इसके विपरीत सामाजी ईरान पर कब्जा करने में अरबों को केवल १५ वर्ष लगे थे। अरब शासन में बड़ा अत्याचार होता था। किसान करो के भारी बोझ से त्राहि-त्राहि कर रहे थे जबकि ज़मींदारों का सागी सुविधाएँ हासिल थीं। अरबों ने मध्य एशिया में तलवार के बल पर इस्लाम फलाया। इस धर्म परिवर्तन से उठाने स्थानीय लोगों में समान दृष्टिकोण के आधार पर एकता स्थापित करने का काम लिया। इस्लाम के साथ अरबी भाषा भी फैली, जो शासन, साहित्य और विज्ञान की भाषा बन गई। लेकिन आम लोग स्थानीय ईरानी और तुर्की बोलियाँ बोलते रहे। लोगों की नस्ली बनावट पर अरबों का कोई खास असर नहीं पड़ा। मध्य एशिया में आज जो अरब बसे हुए हैं, वे उन लोगों की सतान हैं, जो बहुत बाद में तैमूर के समय आकर आबाद हुए थे।

इस्लाम की विजय क़ाख़स्तान के केवल दक्षिणी भाग तक सीमित थी। स्टेपी इलाके व तुर्की कबीले उस समय तक स्वतंत्र थे। तुर्कों ने

पहले आठवीं सदी में जैतीसुव में तिमुरगेशियो से और बाद में (८वीं से १०वीं सदी तक) करलूका से एका कर लिया था। पश्चिम की ओर, सिर-दरिया के निचले भागों में तुर्क कबीलो और ओगुजा के शक्तिशाली सघ का प्रभुत्व था। इन कबीलो में आनाज की खेती के साथ पशुपालन भी होता था और शहरों में उनके व्यापार-केन्द्र भी थे। ओगुजा का कर्गं यगीवद शहर था। वे इफ्यलाह्यो की सत्तान थे, जो छठी और सातवीं सदी ईसवी में तुर्कों के प्रभाव में आ गये थे। इस मुख्य तुर्की इफ्यलाई नस्ली तत्व के अलावा ८वीं से १०वीं सदी के जमाने में ओगुजा में हिन्द-युरोपीय कबीले भी काफी संख्या में आ मिले जैसे तुखार और यासोव आलान।

ओगुजा के पड़ोस में, अराल सागर के इलाके में, इस दौर में पचेनेग कबीलों का सघ स्थापित हुआ। उनका नस्ली आधार पुराने शक-भसागात कबीले थे। उनपर भी तुर्कों का असर पड़ा था।

९वीं और १०वीं सदियों के दौरान में सामानियों का राज्य कायम हुआ (८७४-९६९ ईसवी) जिसमें ईरान और मध्य एशिया दोनों शामिल थे। इसका केन्द्र बुखारा था। सामानी राज्य में भावरान्हर, ह्वारख्म, सिर-दरिया के इलाके, तुर्कमानिस्तान का भाग ईरान और अफगानिस्तान शामिल थे। इसमें इस इलाके के नस्ली और सांस्कृतिक इतिहास में बड़ी भूमिका आती थी। सामानी शासनकाल में ताजिक फारसी भाषा दूर-दूर तक फैली और यही वह समय था जब महान कविया रूदकी और फिरदीसी ने अपनी अमर कृतियाँ लिखीं। परन्तु विज्ञान की भाषा अरबी बनो रहा।

८वीं सदी के अंत और ९वीं सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया में भगता साहित्यिक पुनरुत्थान हुआ। अरब गणित शास्त्र के संस्थापक मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिस्मी की कृतियाँ इसी दौर की हैं। उन्हीं की कृति "अल-जब्र" के शीर्षक से अल-जेन्ना नाम पड़ा। वह केवल गणित शास्त्र ही नहीं घमासून भूगोलशास्त्र तथा इतिहासकार भी थे। उनकी कृतियाँ में भारतीय वाङ्मय और यूनानी ज्यामिति का संश्लेषण था जो प्राचीन गणित विज्ञान का आधार है। अल-ख्वारिस्मी ने गणित शास्त्र की संख्या पुरानी फारसी परम्परा का उपयोग किया जिनपर भारतीय

तथा यूनानी सभ्यता का बड़ा असर पड़ा था और जिनकी उत्पत्ति सिचाई, व्यापार और निर्माण की व्यावहारिक आवश्यकताओं के आधार पर हुई थी। अरबा ने गणित विज्ञान उन्हीं की वितावा से सीखा। अरब नक्षत्र पारावी (मृत्यु ६५० ईसवी) ने दार्शनिक टीकाएँ लिखी और उन्हें कुछ लोग पूव का अस्तू कहते हैं। उनका दृष्टिकोण म भौतिकवाद का असर था जिस कारण मुस्लाहमा ने उनपर बड़ा अत्याचार किया। उनके भौतिकवादी विचारों ने मध्य एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक अरब अली इब्न-सीना (६८०-१०३७ ईसवी) का प्रेरित किया जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र और दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी। चिकित्सा शास्त्र पर उनकी वितावा में सबसे प्रसिद्ध 'अल-कानून फितीब' है जिसका अनुवाद १२वीं सदी में लातीनी में हुआ था और जिसे कोई छ सौ साल तक पूव और पश्चिम के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक मानते रहे।

स्वारज्य सभ्यता का एक और महान व्यक्ति अल-बेल्ही (६७३-१०४८ ईसवी) थे जो इब्न-सीना के समकालीन थे। इनका जन्म एक गाँव में हुआ था, जो आजकल कराकुरपाक स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र में है। उनकी "विताव उल हिद" एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक और मानव जाति ज्ञान संबंधी वृत्ति है जिसका जोड़ मध्ययुगीन साहित्य में नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ज्ञानवान व्यक्ति, भूगोलविद, खनिज विज्ञानी, जाति विज्ञानी, इतिहासकार तथा कवि के रूप में भी उन्हें बड़ी मायता प्राप्त थी। वह एक महान और निडर देशभक्त थे, जिन्होंने विजेताओं की सत्यानाशी हरकतों की बड़ी आलोचना की। इसका साथ-साथ वह अन्य जातियों की सभ्यता की बड़ी आलोचना की। इसका साथ-साथ उनका दृष्टिकोण सहज भौतिकवादी था। वह भौतिक जगत की परिघटनाओं और नियमों का ज्ञान प्राप्त करने में मानव-बुद्धि की भूमिका पर जोर देते थे। परंतु इब्न-सीना और अल-बेल्ही के वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी विचारों को प्रतिक्रियावादी धार्मिक विचारधारा से नुकसान पहुँचा, जो उस समय मध्य एशिया पर हावी थी। मावरान्-नहर में ११वीं और १२वीं सदियों में इराक से सूफी मत के रहस्यवादी विचारों का प्रचार हुआ।

मध्य एशिया में १०वीं और ११वीं सदियों में सामंती संस्था का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इससे इस इलाके के जातीय इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। अब जातीय समूहों की निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुई। ९वीं और १०वीं सदी के बीच के काल में एक जाति-समूह बन रूप में ताजिकों की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया की जातियों में सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। उनकी भाषा पहले ही सामान्य राज्यकारण में विकसित हो चुकी थी। सोगदियान और बैक्ट्रियान उनके पुराने पूज ५।

ताजिकों के वतन से मिले हुए इलाके में उज्बेक जाति की उत्पत्ति हुई। उज्बेकों के ऐतिहासिक पूज स्थानीय मध्य एशियाई जनगण जैसे खारजमी, सागदियान, मसागात और शक थे। इससे पहले के दौर में स्तेपी के तुर्की कबीले मावरान्हर के क्षेत्र की खरफशान, फरगाना, चार, खारजम आदि की वादिया में आकर बस गए थे। तुर्क इन स्थानीय कृषि लोगों में घुस मिल गए। उन्होंने उनका अधिक रहन-सहन और सांस्कृतिक आदर्श अपना ली। और स्थानीय लोग न जो ईरानी भाषा बोलते थे, तुर्की की भाषा अपना ली। जातीय मेलजोल की यह प्रक्रिया ११वीं और १२वीं सदियों में जारी से जारी थी। उसी समय आम और मिरानिया जातियों के बीच के इलाके में एक तुर्की भाषा बोलनेवाली जाति की बुनियाद पड़ी, जो आगे चलकर उज्बेक बनी जान लगी।

१०वीं सदी के अंत में सामानी साम्राज्य का पतन हुआ था। सुई हानिमान केन्द्र का हुकम मानने से इनकार कर दिया। अलग होने की प्रवृत्ति न जारी पड़ा। भारी बरा की यजह से विमानों में असंतोष का भाग भड़की और पूरे साम्राज्य में गहरा सामाजिक संकट पन गया। संयुक्तगीन न गजनी व राजवंश की स्थापना की और बागदाद घान न बागदाद और जनीमुन व इराक में बाराघानिया व शक्तिशाली तुर्क राजवंश की बुनियाद डाली। मध्य एशिया और रज्यास्तान में बाराघाना शासनका उग होन व जाना तथा सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। उगा समय में पूर्वी एशिया तथा मध्य एशिया व जातीय समूहों का सम्मिश्रण हुआ जिसमें परस्पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा।

उस जमाने में तुर्क कबीले जैतीमुव में और चाच इलाके के निकट सिर-दरिया के पास-पास बस हुए थे। उनमें सबसे शक्तिशाली करलूक कबीला था, जो तलस नदी की घाटी से पूर्वी तुर्किस्तान में तरीम नदी तक फैला हुआ था। ये बड़े सुसज्जित लोग थे, जो शहरो और गावों में रहते और पशुपालन, घेंतीवारी और शिकार करते थे। दूसरा बड़ा तुर्क कबीला चिगिल था, जो मुख्यतः इस्तीव-कूल झील के उत्तर-पूर्व ताराज में बसा हुआ था। इतिहासज्ञों का कहना है कि इस कबीले के पाम घोड़े, भेड़ बकरी और मवेशी बहुत थे और करलूको की तरह यों लाग भी शहरों और गावों में रहा करते थे। एक और तुर्की कबीला, याग्मा, जिसका पशु अधिकतर शिकार और पशुपालन था पूर्वी तुर्किस्तान में इस्तीव-कूल झील के दक्षिणी क्षेत्र में आबाद था। तियुरगेशी कबीले, जिनमें तुखसी और अरगी शामिल थे और जिनके राज्य की स्थापना ८वीं सदी में हुई, करलूको से पराजित हो गये थे। इन कबीलों का गहरा सांस्कृतिक संबंध मावरान-नहर के लोगों से था और उनकी तुर्की भाषा में संगठित होने का मिश्रण हो गया था।

इस अवधि में मध्य एशिया के स्थानीय लोगों की राजनीतिक एकबद्धता काराखानी राज्य में तुर्की कबीलों से हुई, जिसके फलस्वरूप गहरा परस्पर प्रभाव पड़ा। सम्य वृषि प्रधान इलाके के वासियों से खानाबदोश तथा अश्व-खानाबदोश तुर्क आप्रवासियों के सम्मिश्रण का सविस्तार वणन "बुदतकु विलीक" में किया गया है। यह बड़ी अच्छी ऐतिहासिक वृत्ति है जिसे युसूफ खास हाजिब बलसगूनी ने ११वीं सदी के आरम्भ में लिखा था। इस दौर में मध्य एशिया के नखलिस्तानों में तुर्की नस्ल के लोगों की संख्या बढ़ गयी और स्थानीय लोगों ने धीरे-धीरे तुर्की भाषा अपना ली। आज उर्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में तुर्की भाषा बोलनेवाले लोगों का बहुमत हो गया। महमूद वाशगरी - काराखानी तुर्क भाषाविद - द्वारा लिखित "दीवान-उल-लुगत अतुक" के अध्ययन से पता चलता है कि ११वीं सदी में उर्बेक भाषा के निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी।

इसी दौर में तुक्मान, कराकल्पाक और कजाख लोगों के जातीय निमाण में स्तेपी कबीलो तथा अराल सागर के निकट रहनेवाले जनगण के ज़ारतार स्थानांतरण ने भी निर्णायक भूमिका अदा की। तुक्माना का जातीय निमाण अराली कास्पियन स्तेपी के दाखो और मसागाता का क्वायली एक्बद्धता से हुआ जिनपर तुर्की प्रभाव पहले ही पड़ चुका था। इनकी बनावट में मुख्य नस्ली तत्त्व ओगुज़ कबीले थे जिनका एक भाग ताहिर मियर्वेज़ा के कथनानुसार १० वीं सदी के अंत में ही तुक्मान बहलाने लगा था। ११ वीं सदी में काराखानियों से उनके सघर्ष के दौरान में निचन सिर दरिया के ओगुज़ा में सलजूकी राज्य की उत्पत्ति हुई। उन्होंने न केवल काराखानी राज्य पर, बल्कि गज़नवी क्षेत्र पर भी कब्ज़ा कर लिया था। सलजूक तुक् ओगुज़ सिर दरिया के इलाके में वर्तमान तुक्मान सोवियत समाजवादी जनतंत्र के क्षेत्र में दाखिल हुए। ओगुज़ क्वायली नाम का रिवाज तुक्मानी कबीलो में २० वीं सदी के प्रारम्भ तक था। सलजूक के आगमन से उज़्बेक का भी जातीय निर्माण काफी प्रभावित हुआ। इस से हज़ारख़म और बुयारा के कुछ हिस्सा की आबादी पर तुर्की प्रभाव पड़ा। आज भी समरकन्द क्षेत्र में तुक्मान नाम का एक जातीय समूह बसा हुआ है। यह आगुज़ तुक्मान की सतान है, जो मिर-अरिया से आकर यहाँ बना और उज़्बेक में घुल मिल गया थे।

इसी अवधि में पचेनगा के पीछे-पीछे आगुज़ा के एक अन्य भाग का आगमन जिमकी जिहा दक्षिण रूसी स्तेपी की ओर थी, और अराल सागर क्षेत्र में ब्रिटिश से रिपचाता का प्रवेश कराकल्पाक जातीय समूह की निमाण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण गिद्ध हुआ। कराकल्पाक के पुराने पूर्वज अराल सागर क्षेत्र के कबीले (यानी सयका के शब्दों में "एरन्ना और डाया व मसागाता") और असागियान-पचेनगा के पूर्वज थे। पचागा और आगुज़ा का एक भाग के पश्चिम की ओर प्रवास कर जान के बाद अराल क्षेत्र में आकर बस गए और अंत में मिश्रित हो गए। इन आगुज़-मयनग सम्मिश्रण में कराकल्पाक जाति का विसरण हुआ। ११ वीं सदी में रिपचाता द्वारा अराल क्षेत्र का विजय में कराकल्पाक का मातृनिर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ। कराकल्पाक का आगमन का

भाषा स्वीकार कर ली और १२वीं सदी तक कराकल्पाक का जातीय नाम प्रचलित हो चुका था।

कजाख़ा का जातीय विकास मुख्यतः शक और उसुन नामक स्तेपी कबीला के आधार पर शुरू हुआ जिसमें दूण जातीय तत्त्वा का भी काफी बड़ा हाथ था। इसके अलावा तुर्क खगान शासन तथा दक्षिण कजाख़स्तान के प्रारम्भिक मध्ययुगीन राज्या न भी इस प्रक्रिया में सहायता की। १०वीं और ११वीं सदियों में किपचाक ने पश्चिमी और मध्य कजाख़स्तान में कई कवायली सघ स्थापित कर लिए थे जिनका प्रभाव १२वीं सदी में इरतिश से दनेपर तक फैल गया था। कजाख़ जातीय समूह की उत्पत्ति स्तेपी के तुर्क कबीला से किपचाक के सम्मिश्रण से हुई। उजबेक, किगिज़, कराकल्पाक और वाश्कीर जसी अन्य तुर्क जातियाँ की बनावट में भी किपचाक कबीले शामिल थे।

किगिज़ा का निर्माण मध्य एशिया से बाहर के क्षेत्र में, शायद पूर्वी तियान शान के तुर्क कबीला में शुरू हुआ। किगिज़ा ने ६वीं और १०वीं सदियों में ऊपरी येनिसेई में स्वयं अपना राज्य स्थापित कर लिया था जिसने मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। येनिसेई और तियान शान के किगिज़ों का संबंध आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। तियान शान के किगिज़ कबीला का, जो उस जगह बढ आये थे जहाँ आज किगिज़ सोवियत समाजवादी जनतन्त्र है, मध्य एशिया की स्थानीय आबादी से सम्मिश्रण मंगोल आक्रमण के समय शुरू हो गया था। मध्य एशिया के किगिज़ों पर अल्ताई, इरतिश, मंगोलिया और सिक्याग के लोगों का सांस्कृतिक असर स्पष्ट दिखाई देता है, यद्यपि उनकी संस्कृति की अनेक विशेषताएँ स्थानीय आबादी से उनके सम्मिश्रण के कारण उत्पन्न हुईं। १७वीं सदी में येनिसेई किगिज़ा की रूसियों से मुठभेड हुई और उनका बड़ा हिस्सा उस समय जुगारिया में बस गया और दूसरे साइबेरिया के खाकासियों और तुवानों में घुल मिल गये।

१२वीं सदी में खानाबदोश कराकित्ताई सुदूर पूर्व से चले आये और उहान जैतीसुब में एक राज्य स्थापित किया और भावरातनहर पर अधिकार कर लिया। उनके आने का मध्य एशिया की जातीय बनावट पर स्पष्ट

प्रभाव पड़ा। जाहिर है कि उनका एक हिस्सा तुर्क कबीला में विलीन हो गया और उनकी भाषा अपना ली। उनका कबायली नाम किताई उर्रेका, कराकल्पाको कजाखा और किगिजा में प्रचलित हो गया।

मध्य एशिया में कराकिताइयो का शासन बहुत दिन नहीं रहा और १३ वीं सदी के शुरू में उनका स्थान ट्यारज्म शाहा ने लिया, जिन्होंने सलजूकिया की सत्ता को नष्ट कर दिया और एक शानदार सामन्ती साम्राज्य की स्थापना की जिसमें मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और आज़रबैजान शामिल थे। ट्यारज्म शाहा के शासन में सामंतवाद का विकास की चरम सीमा पर पहुँच गया था जिसकी अभिव्यक्ति शहरों, व्यापार, दम्नकारी और सभ्यता के विकास में हुई।

चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमकों ने १२१६-१२२१ ईसा में ट्यारज्म शाहों के राज्य का नष्ट कर दिया। मंगोलों ने बड़ी तबाही और बर्बादी मचाई। इसका कारण ऐसा आर्थिक और सांस्कृतिक विच्छेदन था जिससे मध्य एशिया बहुत असें तक उबर नहीं पाया। मंगोल लश्करों का बड़ा भाग, जिसमें मध्य एशिया का पराजित किया, विपचार तथा अन्य तुर्की कबीलों पर आधारित था जिन्होंने मंगोल कबायली नाम जमे टूतगिरान लिया, मंगोल आदि स्वीकार कर लिए थे। इन नामों में अग्रश्रेष्ठ उर्रेका कजाखा और कराकल्पाका में रह गये हैं, मगर इस में उनका मंगोलों में उत्तम हाना कोई जरूर नहीं। मंगोल विजेता आगमनों से स्थानीय लोगों में घुल मिल गया और उन्होंने इस्लाम धर्म और तुर्की भाषा दादा का स्वीकार कर लिया।

१४वाँ सदी में बर्तग के मंगोल कबीलों में, जिसमें तुर्की प्रभाव पड़ा था मंगोल विजेता तैमूर का जन्म हुआ जिसने ३८ वर्षों में लगातार अभियानों में उसे एक राज्य स्थापित किया, जो भारत से चान्गा तक और शाम (सागिया) में तक फैला हुआ था। तैमूर भारत, ईरान और शाम में कबिलों और वास्तुशिल्पियों का दाग बनाने में माय में आया जिसने मंगोलों में अपनी गतिविधि का मंगोल और तुर्क अमीरों के मंगोलों का निर्माण किया। उसका पाता उलुग बेग विज्ञान का बड़ा प्रेमा था और उगा के शगान-जान में मंगोलों के मंगोल में अध्यापित विज्ञान का

१. पाठ्यक्रम होने लगा। आगे चत्तर हेरात और समराज्य गिान और विद्या
 २. व दो बड़े बद्र बन गये। उलुग बा १ समराज्य म एक गंगालीय
 वधशाला का निर्माण कराया। उगाता नाम काजी जान स्मी गियागुदीन
 जमगे और अनी कुरची जैम प्रगिद्ध गंगोनिका व साथ गजद है। उमकी
 गंगोलीय सागणिया अपनी गूमता व लिए धदभुत है। उलुग बन की
 दुयात मृत्यु धर्मोगत मुत्तामा १ हाथा स हुई।

प्रसिद्ध उरख वरि अनीजेर नवाई यही रहत थ। उनरी टुनिया म पुरानी
 उरख भापा अपनी शुद्धता १ त्रम बिन्दु पर गहन गई। उनकी गजला
 के "चार दीशान", "गमगा" तथा उनकी अय टुतिया मध्य एशिया
 तथा विरम साहित्य का वामृत्य दा ह। उनरा सपय अधाधिक विद्या
 शिक्षण तथा जीवन का गुपी बान व लिए था। उनका समवासीन
 व्यक्तिया म हफीजी आरु अन्दुरखान समरादी मीरखा और
 खोदमीर जस प्रतिष्ठित इतिहासकार थे जिनकी कृतिया स मध्य एशिया
 तथा अय दशा के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर अच्छी
 रोशनी पड़ती है।

स्वण ओर्दु का विघटन १६वीं सदी के अंत म शुरू हुआ। इस
 मध्य एशिया और बजायस्तान व लोग व जातीय विवास पर अर
 पडा। १५वीं सदी म देशी विपचाव म नय शक्तिशाली ववायली सध
 की उत्पत्ति हुई जिनमे से एक सिर-दरिया व निचल क्षेत्र म सफे ओर्दु
 के इलाके म स्थित था। इस सध म एक कबीला था जो १४वीं सदी
 म उरख के नाम स प्रसिद्ध हुआ। १५वीं सदी व अंत म इन स्तेपी कबीला
 ने शवानी खान व नेतृत्व म पतनोमुख तमूरी राज्य को पराजित कर
 लिया। शवानी खान के साथ जा उरख कबीले मध्य एशिया गये थे, वही
 बस गये और धीरे-धीरे तुर्क और ताजिक आवादी म घुल मिल गये। अब
 उरख शब्द का प्रयाग केवल आप्रवासिया के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय
 निवासिया के लिए भी किया जाने लगा। देशी विपचाव तुर्क कबीलो के
 मिल जाने के बाद उरख लोग का जातीय निर्माण पूरा हो गया।
 १५वीं सदी व मध्य म सामंती विघटन के कारण चू नदी के क्षेत्र

म छोटे छोटे प्रदेश स्थापित हुए, जो धीरे धीरे १६वीं सदी में बजाख खानशाही के रूप में विकसित हुए। इस से बजाख जातीय समूह का निर्माण पूरा हुआ। प्रारम्भ में इस के निवासियों को उज्बेक बजाख और बाद में केवल बजाख कहा जाता था।

इस प्रकार १५वीं से १६वीं सदी तक विकसित सामंतवाद की स्थिति में और दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप मध्य एशिया तथा बजाखस्तान के सभी प्रधान जातीय समूहों का गठन हो चुका था।*

मदिया के दौरान मध्य एशिया के लोगों ने स्वयं अपनी शानदार सृष्टि विकसित कर ली थी और कृषि, सिंचाई, कला तथा दस्तकारी, गणित विज्ञानों तथा साहित्य में और साथ ही युद्ध की कला में मुख्य सफलताएं प्राप्त कर ली थी, जो अन्य प्राचीन तथा मध्य युगीन सभ्यताओं की उपलब्धियों का मुकाबला कर सकती थी। मध्य एशिया के लोग न भारत, चीन, मेसापोटामिया और ईरान की सभ्यताओं से बहुत कुछ लिया और उसे स्वयं अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से और समृद्ध किया। उन्होंने इन पड़ोसी देशों की सभ्यताओं को प्रभावित भी किया। चीनियों ने अगूर की वास्तुशिल्प कला को अपनाया, जंगी घोड़े पालना और शीशे बनाना मध्य एशिया से सीखा। आज की मंगोल और मचूरियाई लिपियां पर सोगरियान लिपि का असर आज भी बाकी है, जिसे उन लोगों ने प्राचीन समय में अपनाया था। यूरोप और एशिया ने युद्ध में घुड़सवार रिसाल का उपयोग मध्य एशिया से सीखा। बागज बनाने की कला चीन से यूरोप में आई और मध्य एशिया के वास्तुशिल्प ने अरब गणित शास्त्र तथा गणित विज्ञान को विकसित किया जिसे आगे चलकर मध्ययुगीन यूरोप ने अपनाया। मध्य एशिया के वास्तुशिल्प ने भी पड़ोसी देशों का वास्तुशिल्प में विकास को प्रभावित किया।

मध्य एशिया की जातियां प्राचीन काल के विभिन्न नस्लों का सम्मिश्रण हैं। उज्बेक और ताजिकों की रचना में सोगरियानों का हिस्सा

*२० 'मध्य एशिया और बजाखस्तान के जनगण', भाग १, भाग १, पृष्ठ ८१-१०३। (अंग्रेजी संस्करण)

है। तुक्माना, करावल्पाका, बजाया, उखेका और किसी हद तक ताजिकों की रचना में शव और ममागात अश शामिल है। मध्य एशिया की अधिकांश जातियाँ की उत्पत्ति में, चाहे वे ईरानी भाषा बोलनेवाली हों या तुर्की, प्राचीन तुक् मवीला की भूमिका रही है। आगे चलकर उखेका, बजाया और किसी हद तक करावल्पाका और अश लोगों के गठन में विपचाव अश दाखिल हुआ। अतः मध्य एशिया की जातियाँ सभी एक दूसरे से संबद्ध हैं, उनमें पुराने नस्ली रिश्ते हैं। इसी कारण उनकी सभ्यता, अर्थतंत्र और जीवन पद्धति में अनेक बातें समान हैं। उनके समान ऐतिहासिक विकास तथा वदेशिक हमलावरों के पिलाफ संयुक्त सघर्ष ने एकता के इन रिश्तों का और सुदृढ़ बनाया है। परन्तु साथ ही यह बात नजरअन्दाज नहीं करनी चाहिए कि हर समूह ने अपनी अलग सांस्कृतिक विशेषताएँ कायम रखी हैं जिनके आधार पर मध्य एशिया के विभिन्न जातीय समूहों का गठन हुआ। सब ईरानवाद तथा सब-तुक्वाद के समयक लेखक इन प्रभेदों को विशेषताओं को कम करके आकृति या नजरअन्दाज करते हैं। सब ईरानवाद की धारणा मध्य एशिया की जातियों के विशिष्ट ऐतिहासिक विकास की स्पष्ट उपेक्षा है तथा उनकी सभ्यता पर ईरानी कला और वास्तुशिल्प के प्रभाव और छाप को अनावश्यक तौर पर बढ़ाकर पेश करना है। सब-तुक्वाद को भी ऐतिहासिक यथार्थ से कोई तौर पर एक इकाई में मिलाने का व्यर्थ प्रयास है, जो उनके स्वतंत्र ऐतिहासिक विकास की वास्तविकता को नजरअन्दाज करता है। ऐसे सिद्धान्त दूरवर्ती राजनीतिक कारणों से पेश किये जाते हैं।

मध्य एशिया की जातियाँ तीन सदियों के दौरान (१६ वीं सदी से १९ वीं सदी के मध्य तक) उखेका वंश के खान शासन के अधीन रही। उसके बाद ज़ारशाही के रूसी साम्राज्य ने उन्हें अपने अंदर मिला लिया। अंगरेजों ने कुछ समान बातें जैसे भाषा और सभ्यता पहल से मौजूद थी और राष्ट्रीय चेतना की कापल फूटने लगी थी, खान शासन के अंतर्गत स्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें और अधिक जातीय सुगठन हो सकता। ख्वारस्म शाहों के ब्रह्मवृत्त शासन के अंतर्गत जो प्रगतिशील विकास शुरू हुआ था

उमका मंगोल आक्रमण ने अस्त व्यस्त कर दिया और तब स सामंती विप्लव का युग प्रारम्भ हुआ। सामंती खान शासनों में विभाजित मध्य एशिया सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में बहुत पिछड़ गया। खान शासित प्रदेशों में लगातार परस्पर युद्धों के कारण इसके अर्थतंत्र का ज़रूरतमंद हो गया। उत्पादन शक्तियों के विकास का नीचा स्तर, कृषि और दस्तकारी में गतिराध न जातीय समूहों के गठन की तुलना पहुँचाया।

बुखारा खाना और कोकान के उज्बेक खान शासनों की जातीय बनावट में विषमता थी। खाना में उज्बेक, तुर्कमान, कराकताक और कज़ाख़ रहते थे। उज्बेक और कज़ाख़ थे, इनमें सात,* जो प्राचीन स्थानों निवासियों की सत्ताएं, और देशी विप्लव उज्बेक थे जिनमें अस्त-व्यस्त और निरले की विशेषताएँ अब भी मौजूद थीं। खाना के खान तुर्कमान और कराकताक का उत्पीड़न करते थे। उन्हें अनोपजाऊ जमान पर बसाने, भारी कर लगाते, उनसे बेगार लेते और अनिवार्य सैनिक गणों में भरती करते थे। उनका विद्रोह का बड़ी बरहमी से कुचल दिया जाता था। बुखारा के खानशाही में सामंती उज्बेक अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार प्राप्त था और वे ताजिकों पर अत्याचार करते थे।

कुछ पश्चिमी लेखकों का यह दावा कि मध्य एशिया की जातियों का गठन का विषमता की बात सब-तुल्यवाद का विरोध करने का लिए आगे उन्नत साम्राज्य शासन द्वारा मढ़ी गई है, तथा का सबका मिथ्या वृत्ति है। १८८३ में ही न० यानिकोव ने, जिन्होंने बुखारा की यात्रा की थी लिखा था कि वर्ग की यात्राही में मान त्रिलकुत विभिन्न समूह अपनी अलग-अलग पद्धति में जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें एक में बिनस है। बाद आया गया था।* यही सामंती लड़ाई के कारण जाना गया

* 'सात' का अर्थ आ १९१७ की यात्रा में पहले इस्तेमाल किया गया था, उज्बेकों में कोई संशय नहीं रहता। इनमें जातीय उत्पत्ति का वर्णन सामाजिक अर्थों में संभव होता था। इसका मतलब था 'साम्राज्य' या 'राज्य' और 'बहा' 'व्यापारी' या 'मौजद'। - स० १०. १० यानिकोव, 'बुखारा यात्रा का वर्णन', मध्य एशिया, १८८३, पृष्ठ १३, ७१। (रूसी संस्करण)

- बहुत घट गई थी। अध्यात्मिक साहित्य लुप्त हो गया था और धर्म का बोल
- वाला था। मध्ययुगीन मध्य एशियाई खगोलशास्त्रियों तथा
- चिकित्सा विज्ञानियों की शानदार उपलब्धियां भुना दी गई थी और
- प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन पाप समझा जाने लगा था। सामाजिक
- जीवन पर इस्लाम की सखीय रूढ़ियों का प्रभुत्व जातीय चेतना के विकास
- में बाधक बना हुआ था। अन्तर्गत अवस्था लागू मुल्लाओं के धार्मिक प्रचार
- का शिकार था जिसमें तमाम मुसलमानों की मिथ्या एकता पर जोर दिया
- जाता था। इससे आगे चलकर सब इस्लामवाद के समयका ने फायदा
- उठाना चाहा। इस तमाम अमहनीय सामाजिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक
- गतिराश के बावजूद जनगण की सज्जनात्मक प्रतिभा ने बितने ही दीप्तिमान
- कवियों और प्रगतिशील विचारकों का जन्म दिया जिन्होंने सामाजिक
- अराज्य और उत्पीड़न का विरोध किया और क्रायली परम्परा और
- धार्मिक विचारधारा से नाता तोड़ लिया। उनमें उदाहरण के लिए
- अद्भुत उर्दू कवि तुर्दी (१७वीं सदी के अंत और १८वीं के प्रारम्भ
- में) थे। उन्होंने केवल लड़ने का आवाहन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं
- बुधारा के सामंती जालिम सुबहान कुली खान के दुशासन के विरुद्ध
- जनगण के सशस्त्र सघर्ष में भाग लिया। इस सघर्ष में तुर्दी अलग अलग
- उर्दू कबीलों को एकताबद्ध करना चाहते थे। तुर्कमान कबीलों की एकता
- का ऐसा ही नारा महान तुर्कमान कवि और विचारक मखदुम कुली ने
- दिया था।

उस जमाने की प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद मध्य एशिया की जातियों में से हर एक ने अपनी एक समान भाषा, जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विवसित कर ली थी। परन्तु उच्चतर अवस्था में उनका जातीय विकास उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण रुक गया था। मध्य एशिया और कजाखस्तान के जारशाही के रूसी साम्राज्य में मिल जान के बाद ही वहां प्रारम्भिक पूँजीवादी तत्वा की उत्पत्ति होने लगी। कुल मिलाकर पिछड़े हुए खानशाहियों का अधिक विवसित रुस्त में विलयन वस्तुनिष्ठ दृष्टि से प्रगतिशील कदम था। लगातार परस्पर लड़ाइयों के अंत और पूँजीवादी सबंधों के प्रवेश ने सामंती गतिरोध को दूर करन

म सहायता की। रेलवे के निर्माण, व्यापार के विस्तार, और कपास जैसे विदेशी कृषिक पैदावारा के विकास न रूसी साम्राज्य के इस दूर स्थित नगरों का विश्व मंडी की मसलदार में पहुंचा दिया। इस नये पूँजीवाग विकास के आधार पर मध्य एशिया के ये जातीय समूह पूँजीवादी जातियों में गठित हान लगे।*

परंतु गठन की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और ज़ारशाहा का सैनिक साम्राज्यवाद तथा औपनिवेशिक उत्पीड़न की नीति इसमें बाधक हुई। इसका प्रति पूँजीवाद के आधार पर नहीं बल्कि अकतुवर समाजवाग जाति का विजय के बाद समाजवाद के आधार पर हुई। अकतुवर जाति न मध्य एशिया और कजाखस्तान की जातियों के लिए स्वतंत्र गढ़ाग विकास का रास्ता खाल दिया। सोवियत सरकार ने १९२४ में जातवाग राज्य सीमाग्रा का निर्धारण किया जिससे मध्य एशिया के जनगण का अपनी जातीय गठन के प्रयास में सहायता मिली। जातीय जनतंत्रा के निर्माण से उनकी साम्युक्तिक और आर्थिक उत्पत्ति तेज़ी से हुई। जैसा कि ऊपर कहा गया, न लागा का जातीय गठन वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रक्रियाग्रा का नतीजा था और सोवियत जातीय जनतंत्रा के कृत्रिम निर्माण के कारण जान-बूझकर गुमराह करने के लिए लगाय जाते हैं और उनके पाछ राजनयिक उद्देश्य काम कर रहा है।

साखिया गता की स्थापना के बाद में मध्य एशिया में छह समाजवाग जातियों की गठन हो चुकी थी। वे हैं उज़्बेक, कजाख ताजिक, किर्गिज़ तुंगगा और तगार-तार। उज़्बेक की जन-संख्या ६०,१४,००० है और ये साखिया सघ का चौथी बड़ी जाति है। इनमें १६,७३,००० मध्य एशिया और कजाखस्तान में रहते हैं (४०,३८,००० उज़्बेक साखिया समाजवाग जनतंत्र में)। साखिया सघ में कजाख की कुल मध्या ३६,२२,००० है जिसमें २७,६४,००० अपने जातीय जातंत्र, कजाख सा० में जात में रहे हैं। ताजिक का कुल मध्या १३,६७,००० है जिसमें १०,११,००० ताजिक सा० में जनतंत्र में रहते हैं। पूरे साखिया सघ

मे तुक्मानो की सख्या १०,०२,००० है जिनमे ६,२४,००० तुक्मान सो० स० जनतंत्र मे हैं। सोवियत सघ म किगिजा की कुल सख्या ६,६६,००० है, जिनमे किगिज सो० स० जनतंत्र मे ८,३७,००० रहते है। कराकल्पाकी की सख्या १,७३,००० है। इनका एक स्वायत्त जनतंत्र उज्बेक सो० स० ज० के भीतर है जिसमे १,६८,००० कराकल्पाव है।

इन प्रधान जातिया के अलावा कई और छोटी जातिया भी है। इनमे ६५,००० उईगूर हैं (जो अधिकतर कजाख सो० स० ज० के अत्मा अता क्षेत्र म और किगिज सो० स० ज० की फरगाना घाटी मे रहते ह) , २२,००० दूगान हैं, जो चीनी मुसलमान है, २,१२,००० कारियाई और ७,८०,००० तातार हैं (४,४५,००० उज्बेक सो० स० ज० मे और १,६२,००० कजाख सो० स० ज० मे रहते है) ।

मध्य एशिया तथा कजाखस्तान की आबादी मे कुछ स्लाव भी ह। इन मे रूसी (६२,१५,०००), उक्रेनी (१०,३५,०००) और बेलोरूसी (१,०७,०००) हैं।

सोवियत मध्य एशिया के बाहर १२,००,००० उज्बेक और २६,००,००० से अधिक ताजिक अफगानिस्तान मे है। ६,५०,००० तुक्मान ईरान, इराक और अफगानिस्तान मे हैं, और चीनी लोक जनतंत्र मे सिक्क्याग मे ५,०६,००० कजाख, ७१,००० किगिज, १४,००० उज्बेक और उतने ही ताजिक हैं।*

*ये सब आकड़े १९५६ की जनगणना पर आधारित है।
 दे० "मध्य एशिया और कजाखस्तान के जनगण", मास्को, १९६२, खण्ड १, पृष्ठ ११-१२। (रूसी संस्करण)

१९७० की जनगणना के अनुसार सावियत सघ मे ६१,६५,००० उज्बेक, ५२,६६,००० कजाख, २१,३६,००० ताजिक, १५,२५,००० तुक्मान तथा १४,५२,००० किगिज हैं। अत सोवियत सघ मे रूसियो तथा उक्रेनियो के बाद तीसरी सबसे बडी सख्या उज्बेको की है। दे० 'सोवियत सघ का अथतत्र, १९२२-१९७२', मास्को, १९७२, पृष्ठ ३१। (रूसी संस्करण)

मध्य एशिया के खान शासन

रूस का अधिकार होने से पहले मध्य एशिया की भूमि पर तीन खान शासन थे। ज़रफ़शान नदी के क्षेत्र में बुखारा और निचली आराल दरिया पर खोवा कोकान में अधिक पुराने थे जिसकी स्थापना १८वां सदी के अंत में हुई थी। १९वीं सदी के शुरू में कोकान में ताशकंद पर कब्ज़ा कर लिया जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापार-केंद्र था और जिसका अस्तित्व स्वतंत्र नगरराज्य के रूप में था। उपर्युक्त सिंध और उजाग्र खानाजाना की लहर का रोबने के लिए काज़ान खानाशाह ने सिरदरिया घाटी और ईस्ती नदिया पर अनेक किल्ले का निर्माण किया।

काज़ान खान शासन का संस्थापक मिन बश का आदिम खान था। वह १७६८-१७६९ में अपने पिता तारुक्ता खी के बाद गद्दी पर बैठा, जो १७८४ में पश्तात का बेग था। बुखारा खान शासन की स्थापना १७१३ में मंगित साबिश ने की। पहले शासन स्वयं अपने का खान कहा करता था। उनमें हैज़र (१८००-१८२६) पहला व्यक्ति था, जिसने अपने का छोड़कर कहा किया। उसका उत्तराधिकारी तमुक्ता एवं अयाचारा था, जिसकी भाँति पहली खानाशाह पर कब्ज़ा करने का था। खीश का खान शासन स्थायित्व में पुराने राज का उत्तराधिकारी था।

१८वीं सदी में इसपर उज्बेक इनाकों या शक्तिशाली जागीरदारों का शासन था, जो चंगेज़ खान की सतान खानों के अधीन शासन करते आ रहे थे। इनाक इलतुजेर ने १९वीं सदी के प्रारम्भ में अपने को खीवा का खान घोषित किया और अपने वंश की स्थापना की, जिसका शासन १९२० तक जारी रहा। १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रूसी प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में फैल गया और जारशाही रूस सर्वोपरि सत्ता बन गया। कोकान के खान शासित क्षेत्र पर उसने कब्ज़ा कर लिया और बुखारा और खीवा को अपना अधीन राज्य बना लिया।

१९वीं सदी के प्रारम्भ में तीनों मध्य एशियाई खान शासित क्षेत्रों की जनसंख्या ४० लाख थी, जो सदी के मध्य तक बढ़कर ५० लाख हो गयी थी। खान-शासित क्षेत्रों में बुखारा की आबादी सबसे अधिक, कोई ३० लाख थी, कोकान की १५ लाख, और खीवा की सबसे कम—केवल ५ लाख थी।* आबादी का बड़ा हिस्सा नखलिस्तानों और नदी घाटियाँ, खासकर सिर-दरिया, आमू दरिया, जरफ़शान, कशका दरिया और सुखान-दरिया की घाटियाँ में और ताशकन्द, बुखारा, कोकान और समरकन्द जैसे बड़े शहरों में बसा हुआ था। अरब रेगिस्तान, रेगिस्तान और पहाड़ों में, जो मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे, खानाबदोश कबीले आबारा घूमा करते थे।

तीनों खान शासन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामंती राज्य थे, जिनमें दास प्रथा के अवशेष चले आ रहे थे।

रूस, पारस तथा अन्य पड़ोसी देशों से पकड़ कर लाये हुए गुलामों का व्यापार बहा हुआ करता था। तुर्कमान, कज़ाख और किर्गिज़ खानाबदोशों में कबीला जिरगा व्यवस्था के प्रबल अवशेष थे। लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन और बागबानी था। कपास की उपज बहुत कम थी और जा भी थी, वह बहुत घटिया किस्म की थी। शहर दस्तकारी और व्यापार

*न० अ० खालफिन, "मध्य एशिया में रूस की नीति", मास्को १९६०, पृष्ठ १९ तथा उसी लेखक द्वारा "रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन", मास्को, १९६५, पृष्ठ ५२। (रूसी संस्करण)

का केन्द्र थे। बुधारा, कोकान, ताशकन्द और समरकन्द के दस्तकारों का बनाया हुआ सूती और रेशमी कपड़ा पूव के विभिन्न देशों तथा रूसी साम्राज्य में भी बिका करता था। प्राकृतिक साधनों की बहुतायत थी, मगर बहुमूल्य खनिज पदार्थ छोटे पैमाने पर निकाले जाते थे और इसी कारण उनकी लागत रूस से आयात किये हुए खनिज पदार्थों से अधिक होती थी।

करा का वास्तु भारी था और अधिकतर जिस के रूप में वसूल किये जाते थे जिसका मुद्रा-माल सवधानों के विकास पर द्वारा असर पड़ता था। सामन्ती उत्पीड़न और साहूकारों की लूट-पसोट के कारण दस्तकारी और कृषि की उन्नति रुकी हुई थी। सामन्ती विच्छेदन, लगातार परस्पर युद्ध तथा विभिन्न जातीय समूहों के आपसी संघर्ष से खान-शासित क्षेत्रों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो चुका था।

अमीरा और घाना, बेगों, खाइयो और बीगो* द्वारा भारी शोषण के विरुद्ध सभी जातीय समूहों के देहकानों का वग-संघर्ष सामन्तविरोधी जन विद्रोहों का रूप में उभर पड़ा, जो १९वीं सदी के पूर्वार्द्ध की आम विशेषता थी। ऐसे सामन्तविरोधी आन्दोलनों में १८२१-१८२५ में किताई विप्लव (बुधारा का एक उज्ज्वल कबीले) १८२६ में समरकन्द के दस्तकारों १८२७ और १८५५-१८५६ में चीना के गरीब शहरिया और किसानों १८१४ में ताशकन्द का विद्रोह तथा १८५६-१८५८ में दक्षिणी कजाखस्तान में इसी प्रकार के विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।** अन्त में यरगूली और कानान का अधिकांश, घासवर ताशकन्द बेगों के भ्रष्टाचार का कारण कजाख जनता ने विद्रोह किया और १८५८ में तुर्किस्तान शहर पर चढ़ा दी। रूसी यात्री न० अ० सवेत्सोव ने, जिस

* बेग—गुला का सामन्ती गवर्नर। खाई—घाटी जमीनदार या मयनिया के स्वामी। बी—कबीले या जिरगे का मुख्तार।—स०

** प० प० इवानोव, मध्य एशिया के इतिहास पर लेख (१६ वां खण्ड में १९५४ खण्ड का मध्य खण्ड), मास्को, १९५८, पृष्ठ १३५-१३६ १६७ २००, २१२। (रुग्ना संस्करण)

कोकान सिपाहियों ने पकड़ लिया था, इस उपद्रव को अपनी आखों देखा और ब्योरेवार इसके कारणों का वणन किया है।* सभी रूसी यात्री इस बात पर सहमत थे कि खान-शासित क्षेत्रों के लोगों में बड़ा असंतोष था, जिसका कारण सामंती उत्पीड़न की असहनीय स्थिति थी।** उनकी शहादत से ब्रिटिश लेखक जे० ह्वीलर का दावा कि खान शासनो में व्यापारिक जीवन में "बड़ी सरगर्मी" थी, झूठा साबित हो जाता है। उसका उद्देश्य ज़ारशाही रूस द्वारा मध्य एशिया पर कब्जे के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील पहलू से इनकार करना है।*** प० इ० नेवोलसिन ने १४ नवम्बर, १८५० को ओरेनबुर्ग से लिखा था कि खान शासित क्षेत्रों के लोग अत्यंत गरीब और उत्पीड़ित हैं, और धनी व्यापारी अधिकारियों की लूट-खसोट से बचने के लिए अपना धन छिपा कर रखते हैं।****

* न० अ० सेवेर्स्तोव, "एक महीने तक कोकान का कैदी"—'रुस्कोये स्लोवो', अंक १०, पृष्ठ २६०-२६२। (रूसी संस्करण)

** दे० न० मुराव्योव, "१८१६-१८२० में तुर्कमानिस्तान और खीवा की यात्रा", मास्को, १८२२, पृष्ठ १०१, अ० चेरन्यायेवा, "मध्य एशिया की चेरयायेव की यात्रा, १८५७-१८५६"—'इस्तोरीचेत्स्की वेस्तनिक', जून १९१५, पृष्ठ ८४४, व० व० वेत्यामीनोव-जेर्नोव, "कोकान खानशाही के बारे में कुछ तथ्य"—'वेस्तनिक रुस्स्कोगो गेओग्राफीचेत्स्कोगो ओब्श्चेत्त्वा', १८५६, भाग १, पृष्ठ ११३-११५, न० ग० ज़लसोव, "१८५८ में खीवा तथा बुखारा में कनल इग्नात्सेव का मिशन"—'रुस्की वेस्तनिक', अंक २-३, १८७१, पृष्ठ ५६ म० इ० इवानिन, "खीवा तथा अमू-दरिया"—'मोस्कोई स्वनिक', अंक ८-९, १८६४, पृष्ठ १६६। (रूसी संस्करण)

*** दे० G Wheeler, *The Modern History of Soviet Central Asia* London, 1964 pp 44 47

**** प० इ० नेवोलसिन, "मध्य एशिया से रूस के व्यापार के बारे में लेख"—'ज़पीस्की रुस्स्कोगो गेओग्राफीचेत्स्कोगो ओब्श्चेत्त्वा', पुस्तक १०, मास्को, १८६५, पृष्ठ १५। (रूसी संस्करण)

रूस और मध्य एशिया

खान शासित क्षेत्रों और रुस के बीच व्यापार और राजनयिक संबंध कमालेश नियमित रूप के थे। १६वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रुस से आठ प्रतिनिधि दल मध्य एशिया आये, १७वीं सदी में खीवा से बारह और बुखारा से तेरह प्रतिनिधि दल रुस आये। रुसी दल इस प्लान के बार में बहुमूल्य सूचनाएं ले गये। रुस और मध्य एशिया के संबंध केवल प्रतिनिधियों के आदान प्रदान और तिजारती कार्पिनो तक ही सीमित नहीं थे। १७वां सदी में बुखारा और ताशकन्द के उज्ज्वल बड़ी सध्या में साइबेरिया में बसे गये। इनमें व्यापारी किसान और कारीगर थे। रुसी सरकार ने उन्हें आरक्षण, आस्त्राखा और वाश्कीर इलाका में बसे सुविधाएं दी।*

य सत्र १८वीं सदी में और सबल हुए, जब लघु और मध्य बजाय आर की अपील पर बजाखस्तान का बड़ा भाग रुस में शामिल कर लिया गया। १९वीं सदी में रुस और मध्य एशिया के आर्थिक संबंधों में नया विस्तार पैदा हुआ। अगर १९वीं सदी के प्रारम्भ में रुस से सालाना निर्यात १० लाख रुबल का होता था, तो १८२५ में वह बढ़कर ४० लाख रुबल तक और सदी के मध्य में डेढ़ कराड रुबल तक पहुंच गया। मध्य एशिया में सामानों का आयात भी इसी के अनुकूल बढ़ा। उनका मूल्य लगभग २० लाख में प्रारम्भ हुआ और १८२५ में बढ़कर ४० लाख तक पहुंच गया।** बजत एवं रक्षा (१८४०-१८५०) में व्यापार में ६० प्रतिशत वृद्धि हुई।

१९वां सदी का पूरा रुस के आर्थिक जीवन में बड़े महत्त्व का उमाना था। पुरानी सामंती भण्डार प्रथा पर आधारित अर्थतंत्र का विघटन हो रहा था और उमरा सभ्यता नये पूजीमाली सत्र से रूढ़ थी। पुरानी किसान-कारिगर अर्थतंत्र तब भी न मान उत्पादन स्वरूप धारण कर रहा था और फसलियां की सम्पदा बराबर बढ़ रही थी। १८०४-१८२४

* 'मध्य एशिया और बजाखस्तान के जनगण' पृष्ठ १, पृष्ठ ६८।

गो. रजाराज 'रूस द्वारा मध्य एशिया का समामान' - रुस में मध्य एशिया के समामान के प्रगतिमान महत्त्व के विषय पर बजाखि प्रगतिगत के सत्र, ताशकन्द १९१६ पृष्ठ १२। (रूसी सम्पत्ति)

के बीच रूस में औद्योगिक उद्योगों की संख्या २४०२ से बढ़कर ५२६१ हुई और १८६० में १५,३८८ तक पहुंच गई। १८०४ में केवल ६५२ हजार मजदूर औद्योगिक उद्योगों में काम करते थे, १८२५ में उनकी संख्या २१०६ हजार और १८६० में ६५६१ हजार तक पहुंच गई थी।* रूस में पूंजीवाद के तीव्र विकास के इस दौर में मशीनों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अदरुनी मशीन छोटी थी और १९वीं सदी के चौथे दशक तक रूस के सूती कपड़े का निर्यात तेजी से कम होने लगा। छठे दशक तक मशीन निर्मित सस्ते ब्रिटिश और जर्मन सूती कपड़े ने रूसी कपड़े को संयुक्त राज्य अमेरिका की मदिया से बाहर निवाल कर दिया। और इससे अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं अपनी फ़ैक्टरिया खड़ी कर रहा था। ब्रिटेन और स्वीडन की बड़ी प्रतियोगिता के कारण धातु निर्यात भी कम हो गया था। ऐसी स्थिति में रूसी औद्योगिक हल्के इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि बाहरी मशीन के रूप में मध्य एशिया पर कब्जा करे। अतः हम अ. सेम्योनोव को मध्य एशिया में रूसी सूती कपड़े, रेशम और लोहे के सामान के लिए व्यापक मशीन प्राप्त करने की सिफारिश करते हुए पाते हैं।**

जोर निकोलाई प्रथम ने १८३६ में ही एशिया से रूस के व्यापार संबंधों के बारे में विभिन्न सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की थी। इससे सदस्यों में वैदेशिक मामला, युद्ध और वित्त-मंत्रि तथा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रधान थे। उसी साल अ. ३० वीं जहाँ रूस को अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा प्रतियोगिता का सामना नहीं करना था।*** मध्य एशिया से रूस के व्यापार के महत्व पर व्यापार

*प. ३०. त्याशेवको, "सोवियत संघ के अद्यतन का इतिहास", मास्को, १९४७ खण्ड १ पृष्ठ ५३५। (रूसी संस्करण)

**अ. सेम्योनोव, '१७वीं शताब्दी के मध्य से १८५८ तक रूस के विदेश व्यापार तथा उद्योग के बारे में ऐतिहासिक सूचनाओं का अध्ययन', सेंट पीटर्सबर्ग, १८५६, भाग ३, पृष्ठ ७२। (रूसी संस्करण)

***न. अ. खालफिन, "रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन", पृष्ठ ६६।

सन्धी पत्रिकाओं और आद्योगिक हल्को में जोर दिया जाने लगा। ग० ई० दानिलेम्स्की ने भी, जिन्होंने १८८२ में चीन की यात्रा की, मध्य एशिया के साथ रुस के व्यापार को विकसित करने के सुझाव का समर्थन किया। १८४६ में चिखाचोव नामी प्रमुख भूगोलविद और यात्री ने रुसी साम्राज्य के लिए मध्य एशिया के साथ व्यापार के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उनके म्याल में इस इलाके के साथ रुसी व्यापार बढ़ान के पक्ष में आग्न अमरीकी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति थी। उनके समयन उनके समकालीन य० व० खान्त्कोव ने किया। मध्य एशिया के साथ रुस साम्राज्य के आर्थिक संबंधों के विकास का एक कार्यक्रम १० ई० नरालमिन ने तैयार किया था। वह रुसी भौगोलिक समाज की ओर से व्यापार संबंधी सूचना जमा करने १८५० में ओरेनबुर्ग और वास्पियन क्षेत्र में गये। उक्त समाज के एक नेता मुराव्योव के नाम अपने एक पत्र में उन्होंने मध्य एशिया में सक्रिय नीति अपनाने का समर्थन किया। इसी के साथ उन्होंने यह सुझाव भी रखा कि आराम और सिरदरियाघ्रा का रण वास्पियन सागर की तरफ मोड़ दिया जाये, ताकि मध्य एशिया से व्यापार की सम्भावना बढ़ाई जा सके। यद्यपि यह सुझाव उस समय के लिए अव्यावहारिक था, परन्तु इससे यह तो अदाजा होता है कि मध्य एशिया के साथ व्यापार के विकास का उन दिना कितना महत्त्व दिया जा रहा था।

यद्यपि १९वां शती के छठे दशक तक रुस के पूर वैदेशिक व्यापार में मध्य एशिया के व्यापार का अनुपात बहुत कम था (२५ प्रतिशत से शायद ही कुछ ज्यादा ही) * मगर इसमें वृद्धि की सम्भावनाएँ उज्ज्वल थी।

मध्य एशिया में अप्रेता के मनसूबे

मध्य एशिया का ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य तथा राजनीति में गूँथ का भी निशाना बताया गया।

ब्रिटिश औपनिवेशिक हल्के अपने निमित्त सामाना के लिए बडी मडियो की खातिर और आसानी से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपने औपनिवेशिक इलाको मे विस्तार करन के इच्छुक थे। पूर्वी दशा के पिछडेपन के कारण उन्ह इम काम मे आसानी हुई। इस उद्देश्य से अग्रेजा ने एशियाई राज्यों के विरुद्ध अनेक औपनिवेशिक लडाइया लडी।

मध्य एशिया मे ब्रिटेन के विस्तारवादी उद्देश्य १८१२ म ही प्रकट हा चुके थे, जब ईस्ट इडिया कम्पनी के एक वरिष्ठ अधिहारी विलियम मूरक्राफ्ट ने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित एजेंटों का एक दल मध्य एशिया भेजा। मीर इज्जत-उल्ला ने इस दौत्र की विस्तारपूर्वक यात्रा की और जासूसी का काम किया। उसने अटक से कश्मीर, तिब्बत, थारकन्द, काशगर, कोवान, समरकन्द, बुधारा, बल्ख, खुल्मा, वामिया और काबुल तक लम्बा फासला तय किया। उमने बुधारा अमीरशासन का ब्योरेवार वणन किया जिसमे अधिहारिया की सख्या तक लिखी थी और दक्षिणी तुकिस्तान मे खुल्मा के शासक विलिच अली बेक से बातचीत मे अग्रेजों के समयन मे प्रचार किया।* इस तरह बडी हाशियारी के साथ मध्य एशिया मे अग्रेजों के औपनिवेशिक विस्तार के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। बाद मे १८१६-१८२५ मे मूरक्राफ्ट और जाज ट्रेवेक ने कम्पनी की सेना के लिए घोडे खरीदने के बहाने बुधारा की स्थिति की एक और जाच पडताल की।

चौथे दशक के प्रारम्भ मे अलेक्साद्र बन्स नामक एक अग्रेज गुप्तचर अधिहारी एक अभियान दन लेकर बुधारा पहुचा। उसने सैनिक तथा सामाजिक राजनीतिक सूचना जमा की जिसकी ज़रूरत अग्रेजा को मध्य एशिया मे अपनी अपहारक योजना के लिए थी। उसके साथ इस यात्रा मे एक कश्मीरी पंडित मोहन लाल भी थे। बन्स दल का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक तथा सैनिक सूचना प्राप्त करना था। यह बात मोहन लाल के अपने "सफरनामे" के बयान से स्पष्ट है। मोहन लाल का विचार

* *Travels in Central Asia by Meer Izzut Oollah in the Years 1812 13, Calcutta, 1872 pp 58—75 93*

या कि बुखारा के साथ अंग्रेजों के "व्यापारिक या राजनीतिक" संबंध स्थापित करने के लिए वातावरण बहुत अनुकूल था। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें "दर नहीं करनी चाहिये", क्योंकि "कोई शक्ति हमारे (अंग्रेजों के) इरादों का इस समय पहले से अड़ौआ नहीं कर सकेगी"।* मोहन लाल ने बुखारा की सैनिक शक्ति के बारे में काफी व्योरेवार सूचना इकट्ठा की। बुखारा में मूरशाफ्ट के मिशन के गैर-सरकारी स्वरूप पर अवमर जार दिया जाता है। कहा जाता है कि उसकी बुखारा यात्रा की सम्पत्ति भारत सरकार ने अनिच्छापूर्वक दी थी और गवर्नर-जनरल ने उसे वाइ गजनीतिज्ञ सत्ता देने से इनकार कर दिया था। परन्तु मूरशाफ्ट जिना दिना इस यात्रा में रहे उन्हें इसकी तनखाह दी गई और वागजात का अमान सरकार की सम्पत्ति माना गया।** जब बुखारा सरदार ने कहा कि 'अंग्रेजों सरकार ने भारत से तुर्किस्तान तक हर बड़े शहर में अपना जासूसी का जाल बिछा रखा है' और कई आदमियों का नाम दिया, जो यह काम करने थे, तो मूरशाफ्ट ने इससे इनकार नहीं किया बल्कि उनकी वैधियत यह कहकर पेश की कि "इसकी जरूरत फ्रांस के बाइशाह के इरादों का भंग करने के लिए पड़ी है जिन्होंने यह घोषणा की है कि वह ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। इसी कारण उनकी गतिविधि को रोकना उस देश की सरकार के लिए जरूरी हो गया।" * * * घाटे परीक्षण की बात जासूसी के लिए बहाना माना थी। यह हमें स्पष्ट होता है कि आगे चलकर अफगान सीमा कमिशन

* Mohan Lal *Travels in the Punjab Afghanistan and Turkestan to Balkh, Bucharah and Herat and a Visit to Great Britain and Germany* London 1846 pp 150—151

Horace Hayman Wilson *Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab by Mr William Moorcraft and Mr Geo Trebeck from 1819 to 1825 prepared for the press from original journals and correspondence* Vol I London p XXVI

नं० ११२ पृष्ठ ६३२-६३३।

वे अंग्रेज सदस्या न बहुत कम घाड़े घरीद और बनल रिजव ने जिमे भारत सरकार द्वारा 'प्रथम श्रेणी के तुक्मान घोड़े नस्त बढान क उद्देश्य से खरीदने पर ३०० पाउड घच करने का अधिकार दिया गया था, एव पेनी भी घच नहीं किया"।* घाड किसी काम के नहीं पाये गये। १८३८ म हेरात अंग्रेजी जामूसी और विध्वसी कारवाइया का वेद्व बन गया जिनका निदेशन मेजर ट'आरसी टाड कर रहा था। बनल स्टोडडाट का तेहरान की ब्रिटिश कौंसलेट स दुपारा भजा गया। दूसरे जामूस हेरात स घीवा और कावान भेज गय। १८३६ म मजर टाड न एक व्यक्ति मुत्ता हुसैन का घीवा भजा जिसन खान का एक राइफर भेंट की। शीघ्र ही कप्तान जेम्स ऐवट भी उसके पीछे पीछे वहा पहुचा। १ मई १८४० को जब वह नावा अलकमाद्राज्य के निक्ट सबका और किला की छान-धीन कर रहा था रूसिया ने उस पकड लिया। गिरफ्तार होने पर उसन यह जाहिर किया कि वह खान का आदमी है और इसक सबूत म एक जाली दस्तावेज भी पेश की। उसे ओरेनबुग और वहा स सेट पीटसवग स जाया गया। वहा से उस लटन भेज दिया गया। जब ऐवट के मिशन को अपना उद्देश्य पूरा करने, यानी रूस और खीवा का लढान म सफलता नहीं मिली, तो रिचमड शेक्सपियर को वहा विध्वसक कारवाई के लिए भेजा गया। सोवियत इतिहासकार खालफिन के अनुसार सावियत कद्रीय राज्य अभिलेखागार म शेक्सपियर के जो कागज सुरक्षित रखे गये है, उनस स्पष्ट है कि "भारत की सुरक्षा" करने के बहाने कुछ नयी "प्रतिरक्षात्मक" कारवाइया की योजना बनायी जा रही थी। अपने साम्राज्य क विस्तार के लिए अंग्रेजा को यह बहाना बहुत पसद था। वास्तव म इसका उद्देश्य दक्षिण तुकिस्तान के अद्व स्वतन्त्र राज्यों पर आसानी स कज्जा करना था। खीवा स रूस जान के लिए शेक्सपियर ने यह बहाना दिया कि वह रूसी गुलामों क साथ जाना चाहता है।

* G N Curzon *Russia in Central Asia* London 1889
pp 130—131 see Lt A C Yate *Travels with the Afghan*
Boundary Commission, 1887 p 457

था कि बुधारा ने गाय भद्रजा व "व्यापारि या राजाति" मन्त्र स्थापित करा व निग वातावरण पुनः प्रचलित था। उन्होंने गुप्तान् लिया कि इसमें "दर नहीं करना तात्पर्य", क्योंकि "वा" शक्ति हमारे (भद्रजा व) इरादा या उस समय पहले से भद्रजा नहीं कर सकता"।* मान्य लाल न बुधारा की सति शक्ति व वायु म काशी व्याख्या गूना इवत्ता की। बुधारा म मन्त्राष्ट ने मिता ने गरजगरारी स्वयं पर अनार जार लिया जाता है। कहा जाता है कि उसी बुधारा यात्रा या सम्पत्ति भारत सरकार ने अतिच्छापूर्वक था थी और गवराज-जनरल व उस बाद राजनीतिर सात दन म इनकार कर लिया था। परन्तु मन्त्राष्ट जितन दिना इस यात्रा म रह उत इसी तात्पर्य दी गई और वायुजान को बगाल सरकार की सम्पत्ति माना गया। * जब तुदुज सरकार व वन कि अंग्रेजी सरकार ने भारत स तुविमान तब हर बड़े शहर म अपन जासूसों का जाल बिछा रखा है "और कई आत्मिया का नाम लिया, जा यह काम करत थे, ता मन्त्राष्ट न इसमें इनकार नहीं किया बल्कि उसकी कैफियत यह बहुर पक्ष की कि 'इसकी जहरत प्राप्त के बादशाह के इरादा को भंग करने के लिए पड़ी है जिहाँ यह घाघना की है कि वह ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। नती कारण उसकी गतिविधि की खबर रखना उस दश की सरकार के लिए जरूरत हा गया"।*** छोटे खरीदन की बात जाम्सी के लिए बहाना मात्र थी। यह इस से स्पष्ट होता है कि आगे चलकर अफगान सीमा बमोशन

* Mohan Lal *Travels in the Punjab Afghanistan and Turkestan to Balkh Bolhara and Herat and a Visit to Great Britain and Germany* London 1846 pp 150—151

** Horace Hayman Wilson *Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Punjab by Mr William Moorcraft and Mr George Trebeck from 1819 to 1825 prepared for the press from original journals and correspondence, Vol I* London p XXVI

***वही खण्ड २, पृष्ठ ४७२-४७३।

के अंग्रेज सदस्या ने बहुत कम घाड़े खरीदे और वनल रिजवे ने, जिसे भारत सरकार द्वारा "प्रथम श्रेणी के तुक्मान घोड़े नस्ल बढ़ान के उद्देश्य से खरीदने पर ३०० पाउंड खर्च करने का अधिकार दिया गया था, एक पैनी भी खर्च नहीं किया'।* घोड़े किसी काम के नहीं पाये गये। १८३८ में हेरात अंग्रेजी जासूसी और विध्वंसी कारवाइयाँ का केंद्र बन गया, जिनका निदेशन मजर ड आरसी टाड कर रहा था। वनल स्टाडडाट को तेहरान की ब्रिटिश वासलेट से बुखारा भेजा गया। दूसरे जामूम हेरात से खीवा और कोकान भेजे गये। १८३६ में मजर टाड ने एक व्यक्ति मुला हुसैन को खीवा भेजा जिसने खान का एक राष्ट्रपति मट को। शीघ्र ही कप्तान जम्स एबट भी उसका पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। मई १८४० का, जब वह नोबो अलकसांद्रास्क के निकट सड़का और किला की छान-चीन कर रहा था रुसिया ने उस पकड़ लिया। गिरफ्तार होने पर उसने यह जाहिर किया कि वह खान का आदमी है और इसका सबूत में एक जाली दस्तावेज भी पेश की। उस ओरेनबुर्ग और वहाँ से सेट पीट्सबर्ग ले जाया गया। वहाँ से उस लंदन भेज दिया गया। जब एबट के मिशन को अपना उद्देश्य पूरा करने यानी रुस और खीवा का लंदन में सफलता नहीं मिली, तो रिचमंड शेक्सपियर को वहाँ विध्वंसक कारवाई के लिए भेजा गया। सोनियत इतिहासकार खालफिन के अनुसार सावियत के द्रीय राज्य अभिलेखागार में शेक्सपियर के जो कागज सुरक्षित रखे गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि "भारत की सुरक्षा" करने के बहाने कुछ नयी "प्रतिरक्षात्मक कारवाइयाँ की योजना बनायी जा रही थी। अपन साम्राज्य के विस्तार के लिए अंग्रेजों को यह बहाना बहुत पसंद था। वास्तव में इसका उद्देश्य दक्षिण तुर्किस्तान के अख्त स्वतंत्र राज्या पर आसानी से कब्जा करना था। खीवा से रुस जान के लिए शेक्सपियर ने यह बहाना किया कि वह रुसी गुलामा के साथ जाना चाहता है।

* G N Curzon *Russia in Central Asia* London 1889
pp 130—131 see Lt A C Yate *Travels with the Afghan*
Boundary Commission 1887 p 457

सितम्बर १८४० में वह आरेनबुग पहुँचा, मगर उसे निगरानी में रखा गया और लन्दन भेज दिया गया।*

रालिनसन का कहना है कि जेम्स ऐवट को हरात में अग्रजों द्वारा मेजर टाड न छोड़ा रखना दिया था। ऐवट ने मैन्म और एल्फिन्स्टन के समय के रिवाज के अनुसार गुगान रखा कि रगिया को इन इनामों से हमेशा के लिए निवाल बाहर करना चाहिए "और समान दुश्मन से नाता ताड़ने के लिए पुरस्कार के रूप में इंगलैंड के साथ प्रतिरक्षात्मक आश्रमक संधि का प्रस्ताव रखा गया"। लेकिन रालिनसन का कहना है कि ऐसा करने का ऐवट का आदेश नहीं दिया गया था। आदेश में बबन रूसी गुलामों को मुक्त करने की बात थी।** वैम्बरी का कहना है कि अग्रजों ने तीन खान शायी के साथ रूस के खिलाफ "आश्रमक प्रतिरक्षात्मक संधि" करने की योजना बनाई थी।*** लेकिन उसकी राय में दोष स्ट्राइडट और कानाल्ती का था, जो इस उद्देश्य का प्राप्त करने के योग्य नहीं थे।

रालिनसन ने लिखा है कि चौथे दशक के अंतिम वर्षों में अग्रज "हिंदूस्तान की उत्तरी ढलान पर सिंगान पर कब्जा करने और आगे बढ़ने तक बढ़ने की तैयारी" कर रहे थे।**** लेकिन बहादुर अफगानों के कड़े प्रतिरोध के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सका। ओमियाई युद्ध के दौरान में इंगलैंड ने जाजिया के रास्ते मध्य एशिया में एक बड़ी सेना भेजने की योजना बनायी थी। लेकिन चूँकि वे "फ्रांसीसी सहयोग पर भरोसा नहीं कर सकते थे", इसलिए इस योजना को त्यागना पड़ा।****

*दे० न० अ० खालफिन का लेख '१९वीं सदी के चौथे तथा पाँचवें दशकों में मध्य एशिया में अग्रजों का विस्तार तथा रिचमंड शेक्सपियर का मिशन'—'इस्तोरिया एस० एम० एस० एर०' १९५८, अंक २। (रूसी संस्करण)

** H Rawlinson *England and Russia in the East* London 1875 pp 153—154

*** A Vambery *History of Bokhara* London, 1873 pp 384—388

**** ह० रालिनसन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५२।

***** वही, पृष्ठ १८२-१८३।

की सहायता व निष्पत्ति विशेष रूप में प्रशिक्षित भारतीय एजेंटों का एक दल बनाया गया था जिसमें प्रमुख थे पटित भापन, पञ्च माहन्, भाई दावान सिंह और गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी की डायरी या अनुवाक पत्रियाल में पंजाब राजसीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। यह वृत्त लिखन्य दस्तावेज है। गुलाम रब्बानी १० मितम्बर, १८६२ का पंजाब से खाना हुआ और १८६७ के प्रारम्भ में नोटा। इस मुद्दे में उमन बुधारा, कानान, घाजन्, समरान् और ताशान् की यात्रा की। यह बुधारा में दो महीने आठ दिन रहा और वहाँ से फरवरी १८६६ में कानान गया। वहाँ वह एक महीना रहा। बुधारा में उसने "बुधारा दरबार के सदस्यों से परिचय किया और उसकी विस्तारपूर्ण रिपोर्ट लिखी।" अपनी रिपोर्ट में उसने आस-पास के इलाका शहर के परिवेश, इनका बाह्य दरवाजावाली दीवारों की चौड़ाई का व्याख्यान बणन किया है। उसकी राय में यह 'सुरक्षा करने में काम नहीं थी'। उसने यह भी लिखा कि "सना में कोई अनुशासन नहीं और उससे पास २०० तापें थी, जो विलुप्त बेवार थी। उसने चिरागची और शहरिसब्ज (बुधारा में) के सनिक उपकरण और प्रतिरक्षा-शक्तता तथा जिज्जक के निवट हसी किलाबन्दी के बारे में भी रिपोर्ट भेजी।" मुल्ला इब्ज मुहम्मद, मिज्जा बाबा किलाबन्दी और खबरनवीस मुहम्मद तियाज की सहायता से उसने खान घुदावार खान से भेंट की। कानान से गुलाम रब्बानी ने ताशानन्द की तीन यात्राएँ की जिनके दौरान उसने किलाबन्दी, जलागार आदि का ठीक-ठीक अध्ययन किया। उन्होंने नदियाँ के पानी के रंग तथा पत्थरों और खनिज पदार्थों की प्रकृति तथा का उल्लेख किया। ताशानन्द पर हसी बरजे से व्यापारियों में आतंक फैला हुआ था। इससे फायदा उठाकर गुलाम रब्बानी ने उनकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी दिलाने के लिए हसी जनरल बेरयायेव के पास जाकर बहने सुनने की तत्परता व्यक्त की। कानान के व्यापारियों के

लिए इस "मानवीय" सेवा का यह स्वेच्छापूर्ण प्रस्ताव भी दरअसल एक वहाना था, जसाकि पहले के अवसरा पर "घाटा की खरीदारी" और "रूसी गुलामा की मुक्ति" थी। रूसवा राजनीतिक उद्देश्य कुछ और था। गुलाम रब्बानी ने अपनी जान का जायिम भी नहीं डालेगा, परन्तु लेसक यात्रा करके वार्ड अपनी जान का जायिम भी नहीं डालेगा, परन्तु लेसक के सामने एक उद्देश्य था (बल जाड़ा गया है) इसलिए उसने छुद इसकी इच्छा प्रकट की। * उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, जब हम दपत हैं कि वह जनरल चेरन्यायव के साथ साथ ताशकन्द के पास चिरचिव दी तब गया और उनकी गतिविधि पर नज़र रखता रहा। जब वह भारत लौटा, तो दुषारा दरबार का एक बकील उसका जा था। बल्क में वह इस बकील का साथ लेकर फ़ैज़ माहद (एक दूसरे अग्रेज़ एजेंट) से मिला। और भाई दीवान सिंह के जल्दी बुलान पर बदख़शान चला गया। बकील स्वयं काबुल रवाता हुआ जहा रब्बानी बाद में आवर उससे मिला। मध्य एशिया में अग्रेज़ा के आनामक मनसूबा से रूसी शासक हल्का में काफी परशानी हुई। विवातमान पूजीवाद की जरूरत के हेतु रूसिया ने शीघ्रतापूर्वक मध्य एशिया पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह के अग्रेज़ा पर बाज़ी ले गये।

* वही, पृष्ठ ३६-३७।

रूसी विस्तार

एशिया में रूस का विस्तार १६ वीं शताब्दी में शुरू हुआ। मॉस्को महान राज्य ने मंगोला का जघन उतार फरने के बाद तुरंत ही एशिया पर छाया डाल दिया। १५५२ में इवान भयानक ने कज़ान पर और १५५६ में वात्गा के दहाने में आस्त्राखा पर अधिकार कर लिया। सत्रहवीं शताब्दी के अंत में रूसी प्रशासक मठासागर तक जा पहुँचे। इस विस्तार का बाढ़ा कज़ाखों ने उठाया था। उन्हें आदिम तबीला के प्रतिरोध का कम ही सामना करना पड़ा और थोड़े ही दिनों में रूसी अधिपतियों की सगंगा उनसे बढ़ गयी। साइबेरिया से दक्षिण की ओर बढ़ाव अठारहवीं शताब्दी में शुरू हुआ, पहले स्टेपी क्षेत्र में और फिर तुर्किस्तान में। यह कहा जा सकता है कि स्टेपी इलाके में रूस का विस्तार १७३० में शुरू हुआ, जब लघु ओर्दु के खान, अबुल खैर ने रूसी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। खान प्रदेशों की ओर रूसिया का बढ़ाव उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में शुरू हुआ।

१८२४ में कास्पियन और अराल सागरों के बामुम्डलीय दाव का अध्ययन करने के लिए एक "वैज्ञानिक" दल भेजा गया जिसके समयन के लिए कज़ाख पैदल सेना का आधा बटालियन और छह तोपें थीं। १८३४ में कास्पियन सागर के उत्तरपूर्वी तट पर नावो अलेक्सांद्रोव्स्क के किले में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई जिसका उद्देश्य खोवा से

व्यापार को बढ़ाना था। १८३६ म जनरल व० पेरोव्स्की के नेतृत्व म
खीवा अभियान शुरू हुआ जिसम ५,००० सैनिक, २२ तापें, १००००
ऊट और २,००० किंगिज़ बुली और ऊटवान थे। यह अभियान भी
बेकाबिब और मुराव्योव के अभियाना की तरह असफल रहा। बंबल एव
हजार सैनिक किसी प्रकार लौट सके और बाकी असाधारण रूप स बड़े
जाड म मर गये। तुरंत ही एक और अभियान की तैयारी शुरू हुई और
खीवा के खान न इसकी सूचना पाकर शांति का आग्रह किया। उसने
खीवा म सभी रूसी बन्दिया को रिहा कर दिया और अपनी प्रजा म उन
लोगा का, जा रूसी व्यापारिया पर हमला करगे, मृत्यु-दंड की धमकी
दी। खीवा के साथ एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर भी हुए, जिसके
अनुसार खीवा ने वादा किया कि वह रूसिया पर हमला नहीं करेगा
और उह गुलाम बनाना बन्द कर देगा। मगर रूस के प्रति खीवा की
शत्रुता जारी रही। खान न पुल्लम-पुल्ला वजाय विद्रोहिया का साथ दिया
और उह रूस के खिलाफ भड़काया।

रूसी सरकार ने अब मध्य एशियाई खान शासना से अपने व्यवहा
का तरीका बदल दिया। इसने रेगिस्तान के रास्ते सैनिक अभियान भेजने
के बजाय, जिसम बार-बार असफल होना पडता था, धीरे-धीरे, मगर
नियमित रूप से बढ़ने का निश्चय किया। १८४६ म ओरेनबुर्ग के गवरनर
ने अराल सागर के निकट सिर-दरिया पर एक किले का निर्माण किया,
जहा बढ़नेवाले रूसी दस्तों की सहायता के लिए एक जहाज़ी बेंडा खडा
था। उस समय तक वेनिस्सारी के नेतृत्व म वजाय विद्रोह कुचल दिया
गया था। १८५३ मे जनरल पेरोव्स्की ने आक मस्जिद पर अधिकार कर
लिया, जो कोकानवालों का एक किला था। यहा क्रीमियाई युद्ध के कारण
रूसिया का आगे बढ़ना कुछ अर्से के लिए रूक गया।

क्रीमियाई युद्ध मे ज़ारशाही रूस की हार के कारण बात्कन और
निकट पूव से रूस की दिलचस्पी का रख मुद्दर पूव और मध्य एशिया
की आर मुड गया। यूरोप म रूसी साम्राज्य का रास्ता, जैसा काल माक्स
न लिखा था, अब बन्द हो गया था। रूसी साम्राज्य के विदेश मंत्री
अ० गोर्चाकोव ने १८५८ म लंदन स्थित रूसी राजदूत शुन्नोव को आदेश

भेजे जिनसे यह नीति-परिवर्तन त्रिप्रायी देता है। विदेश मंत्री न पूव म
रूस के लिए वदम बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करन की इच्छा पर
घल दिया। ब्रिटेन से दृष्टापूर्वक यह वह देना था कि अगर वह रूस व
साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो उसे पूव म रूस के हिता को उचित
मायता देनी हागी। तदन स्थित रूसी राजदूत के नाम आदेश म यह
निर्धारित कर दिया गया कि रूसी नीति का मुख्य उद्देश्य "एशिया में
रूसी उद्योग, व्यापार और ससृति के प्रभाव का सबल बनाना था"।*
जनवरी १८५६ मे जनरल ब्लारम्बग न घोषणा की कि रूस का भविष्य
यूरोप से संबंधित नहीं है और इसलिए उसे अपनी दिलचस्पी का रज
एशिया की ओर मोड़ना चाहिये। १८५७ म यू० अ० गागेमाइस्टर ने
लिखा कि यूरोप की तुलना म एशिया के साथ रूस के व्यापार की वृद्धि
की दर वही अधिक है और जहा निमित सामान यूरोप म उसके नियान
का बहुत छोटा भाग था, वहा एशिया मे वह उसके नियान का आधा
था। उसने सिफारिश की कि आर्थिक कारणों से मध्य एशिया पर कब्जा
कर लेना चाहिये। वह इलाका कपास की खेती के लिए बहुत अनुकूल है
और सिरदरिया मे ताश्कन्द के निकट तक जहाजरानी हो सकती है।**
मध्य एशिया पर रूस के कब्जे के आर्थिक परिणामों का विषय रूस के
राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, जनरलों और पत्रकारों मे सवप्रिय था। रूसी
साम्राज्य के वैदेशिक व्यापार और उद्योग के बारे मे अ० सेम्योनोव का
कृतियों और साथ ही वित्त मंत्री के सलाहकारों, यू० गागेमाइस्टर और
फ० तनर, प्रसिद्ध उद्योगपति और व्यापारी अ० शिपाव प्राच्यवेत्ता
ई० बेरज़िन और व० प्रिगोर्नोव, यात्री-लेखक म० इवानिन की वृत्तियां
ने रूस म मध्य एशिया के प्रति बड़ी दिलचस्पी पैदा की। "रुस्की वेस्तनिक",
मोस्कोई स्वनिक और "एकोनोमिचेस्की उवाज़ातेल" जैसी पत्रिकायां

* व० नोल्डे, "बिस्माक का पीट्सबर्ग मिशन, १८५६-१८६२",
प्राग, १९२५, पृष्ठ ६४-६५ (रूसी संस्करण), न० अ० खालकिन,
रूस द्वारा मध्य एशिया का समामेलन पृष्ठ ८३।

** य० अ० गागेमाइस्टर, 'रूस के उद्योग तथा व्यापार पर विचार',
- 'रुस्की वेस्तनिक', १८५७ अंक १ पृष्ठ ३८-३९।

न अनव पृष्ठ मध्य एशिया की गतिविधिया के बारे में दिये। अ० शिपोव ने रूस का कच्चे सामान, खासकर कपास के भावी प्रदाता के रूप में मध्य एशिया की भूमिका पर जोर दिया।*

पूजीपति वग से गहरे संबंध रखनेवाले शासक हल्का ने मध्य एशिया का रूसी साम्राज्य में मिला लेने के इस व्यापक आन्दोलन का समर्थन किया। १८५६ में काकेशियाई कमांडर अ० ई० बर्गातिन्स्की ने ज़ार अलक्सान्द्र द्वितीय के सामने यह सुझाव पेश किया कि कास्पियन से अराल सागर तक पुराने कारवान-पथ के बजाय रेलवे का निर्माण किया जाये। बर्गातिन्स्की का ईरान में अंग्रेजों की कारवाइया से चिन्ता हो गई थी और उनके सुझाव का उद्देश्य उनके प्रभाव का दूर करना था। इस सुझाव पर असाधारण समिति में विचार किया गया जिसने विदेश मंत्री गोर्चाकोव और जनरल परोव्स्की के विरोध के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया। समिति ने कास्पियन से अराल सागर तक और फिर उसको बढ़ा कर बामू और सिर-दरिया तक सीधा संबंध स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली, मगर उसका कार्यालयन अधिक् अनुकूल समय तक के लिए स्थगित कर दिया।

क्रीमियाई युद्ध के पहले ही मध्य एशिया से व्यापार करनेवाले औद्योगिक पक्ष, व्यापारी कम्पनिया और परिवहन संगठन कायम होने लगे थे। सरकार ने मरकरी स्टीमर कम्पनी (१८४६ में स्थापित) तथा बरानोव और येनिजारोव के व्यापार-गृहों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया। एक प्रमुख रूसी उद्योगपति कोकोरेव और सेवास्तोपोल के वीर धूलोव ने कास्पियन मार्गों पर एक स्मरण-पत्र पेश किया और मध्य एशिया के खानशासित प्रदेशों से व्यापार के लिए उनके विशेष महत्त्व पर जोर दिया। ट्रांसकास्पियन व्यापार सत्था २० लाख रूबल की पूंजी संगठित की गई। इसे बर्गातिन्स्की और ग्राड प्रिंस बोसततीन निकोलायविच का समर्थन प्राप्त था। १८५८ में बेनरदावी ने फ्रांसोवोदस्क में मछली पकड़ने का एक केंद्र कायम करने का सुझाव पेश किया।

*अ० शिपोव, "सूती कपड़े का उद्योग तथा रूस के लिए इसका महत्त्व", मास्का, १८५७-१८५८, पृष्ठ ४२। (रूसी संस्करण)

उन्होंने तुक्मान कबीला से व्यापार करने का भी सुझाव रखा जिस ओरेनबुर्ग के गवर्नर-जनरल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय उसपर अमन नहीं किया जा सका।

गोचाकोव न वोवालेव्स्की का वैदेशिक मामला के मंत्रालय में एशियाई विभाग का निदेशक नियुक्त किया। उनकी देखरेख में पड़ामी देश का सबव्यापी अध्ययन किया गया और मध्य एशिया में जारशाही रुस के विस्तार के लिए रास्ता साफ किया गया। १८५८ में व्यापारिक, राजनीतिक और गुप्तचर मंडल ईरान, मध्य एशिया के खान शासित प्रदेशों और काशगर में भेजे गए। तीनों रूसी मंडला (जिनके प्रमुख नि० खानिकाव, न० इम्नात्येव और च० क्लीछानाव थे) का रूप यद्यपि भिन्न था (खानिकाव "वैज्ञानिक" छाजयात्रा तथा इम्नात्येव सरकारी राजनयिक मंडल के नेता थे और क्लीछानोव मुसलमान व्यापारी के रूप में गया था) मगर उनका उद्देश्य एक ही था—पड़ामी देश का राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ का गहरा अध्ययन करना। इन मंडलों ने खुरासान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया के खान शासित प्रदेश और पश्चिमी चीन के लोगा और साथ ही इन इलाका में अंग्रेजों की घुमपठ के बारे में बहुमूल्य सूचना जमा की। इसी के साथ उन्होंने वहाँ रुस का असर फैलाने का भी प्रयास किया। खीवा और बुखारा से इम्नात्येव के मिशन के लौट आने पर जारशाही सरकार ने मध्य एशिया में प्रत्यक्ष विस्तार की सक्रिय तैयारियाँ शुरू कीं। दोनों इम्नात्येव तथा ओरेनबुर्ग के गवर्नर-जनरल कातेनिन पश्चिमी साइबेरिया लाइन का ओरेनबुर्ग की लाइन से मिला देने के समर्थक थे। १८६० में जारशाही सरकार ने इस्तीक-कूल और पिश्पक इलाकों में गुप्तचर मंडल भेजे।* १८६१ में मेजर जनरल त्सिमेरमन ने कोकान खान शासित प्रदेश की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजी। उन्होंने मध्य एशिया की भड़ी में अधिकांश रूसी सामान के परिवहन के लिए खान प्रशासन पर अधिक दबाव डालने की सिफारिश की।

* न० अ० चालफिन, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ११७-११८।

कोकान के खिलाफ जोरदार कारवाई के एक और प्रभावशाली समर्थक युद्ध मंत्री द० अ० मिल्यूतिन थे। वह आरेनबुर्ग के गवर्नर जनरल बेज़ाक की सलाह पर काम करते थे। बेज़ाक ने १८६१ में सिर-दरिया की लाइन की यात्रा की और यह राय बनायी कि ताशकंद पर जितनी जल्दी हाँ सके कब्ज़ा कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इससे कोकान के साथ रुस की सीमा सुविधाजनक हो जायेगी और ताशकंद पर कब्ज़ा होने से व्यापार को बढ़ाने में आसानी होगी। बुखारा, चीन और रुस के व्यापारी रास्ते ताशकंद से होकर गुजरते थे। इसलिए इस शहर पर रुस का कब्ज़ा होने से इन देशों से, खासकर चीनी तुकिस्तान से व्यापार में वृद्धि हो सकती थी और बुखारा पर उसका असर भी बढ़ सकता था।

वैदेशिक मामलों के मंत्रालय को भय था कि मध्य एशिया में अति सक्रिय नीति से ब्रिटेन की शत्रुता बढ़ जायेगी। लेकिन बेज़ाक का विचार था कि सिर-दरिया तक रुस का विस्तार होने से ब्रिटेन कोई असाधारण प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, जो वह आमु-दरिया तक बढ़ने की शूरत में व्यक्त कर सकता है। यद्यपि ज़ार ने बेज़ाक के विचारों को स्वीकार किया, फिर भी केवल चार साल गुजरने के बाद ही ताशकंद को रुसी के नियंत्रण में लाया गया। अतः में ताशकंद पर कब्ज़ा स्थानीय कमांडर जनरल चेरन्यायेव की फौरी कारवाई द्वारा हुआ, जो बड़ी हद तक अनाधिष्ठित थी।

अक्तूबर १८६४ में, ठीक उही दिनों में, जब जनरल चेरन्यायेव ने ताशकंद पर अपना पहला असफल हमला किया, इस कारवाई के औचित्य को इस बुनियाद पर स्पष्ट रूप में अस्वीकार कर दिया गया कि इससे अनिवायत रुसी साम्राज्य सभी मध्य एशियाई झगड़ों में फँस जायेगा। लेकिन वैदेशिक कार्यालय के सरकारी स्मृतिपत्र में, जहाँ “हमला करके रुसी प्रभाव की सीमाओं को फैलाने” की इच्छा से इनकार किया गया था, बहुत सी गोलमोल बातें भी कही गई थीं। अतः जहाँ १८६४ में ज़ार द्वारा स्वीकृत मध्य एशिया में कारवाइयों की योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि मध्य एशिया में और अधिक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना ज़रूरी है, वहीं यह वक्तव्य भी दिया गया था कि पूरे

काकान खान शासित प्रदेश पर अधिचार करना "अनिवार्य" है। इसमें "साम्राज्य के और अधिक विस्तार" के अनौचित्य की सारी बात बमानी होकर रह गई।

जब जून १८६५ में चेरयायेव ने ताशकन्द पर कब्जा कर लिया, तो खालफिन के कथनानुसार वह ऐसा काम कर रहा था, "जो वास्तव में रूसी साम्राज्य की सरकार और सैनिक-नामती अभिजात वर्ग तथा व्यापार और औद्योगिक हल्का के विचारों के तदनुरूप था"। वह भलाभागी समझता था कि राजनयिक विभाग की यह अपील कि मध्य एशिया में विस्तार रोक दिया जाये, एक विशेष प्रकार की चाल थी, घाघे की टट्टी जो ब्रिटेन के विरोध के डर से पड़ी की जा रही थी। विस्तारवादी तत्वों की राजधानी में और स्वयं उसने निवृत्ततम साधिया में जो समयन प्राप्त था, उससे चेरयायेव ने लाभ उठाया। वह जानता था कि "उसका इस 'स्वतंत्र' कारवाई के लिए उससे कोई पूछताछ नहीं की जायेगी, बल्कि उल्टे उसे पदक और तरक्की मिलने का विश्वास था"।*

जब चेरयायेव ने ताशकन्द पर कब्जा किया, तो कुल २५ रूसी मारे गये और ८६ घायल हुए। विरोध बहुत सीमित था। पहले वदेशिक मामलों के मन्त्रालय ने इस बात से इनकार किया कि ताशकन्द का रूसी साम्राज्य में मिला लेने की उसकी कोई इच्छा है। उसका विचार था कि ताशकन्द और उसके आस-पास के इलाके को एक अलहदा खान प्रशासन में परिणत कर दिया जाये जिसपर जारशाही का पूरा नियन्त्रण हो और जो रूसी साम्राज्य और बुखारा के बीच मध्यवर्ती राज का काम करे। चेरयायेव ने इस राय का विरोध किया, मगर आरेनबुर्ग के नवनियुक्त गवर्नर जनरल त्रिजानोव्स्की ने इसका समर्थन किया। ताशकन्द के लोगों से जब अपना खान चुनने को कहा गया तो उन्होंने चेरयायेव के नाम वक्तव्य में इस बात को ज्यादा पसन्द किया कि ताशकन्द की नागरिक सरकार चेरयायेव के हाथ में रहे और धार्मिक और अदालती प्रशासन काही

* न० अ० खालफिन, "मध्य एशिया में रूस की नीति", पृष्ठ १७८-१७९।

कत्ता, या धार्मिक कानून के सर्वोच्च आयाधीश के सुपुद कर दिया जाये जिसके लिए चेरन्यायेव की मजूरी जरूरी हो। अगस्त १८६६ में ताशकंद का रूस का अंग घोषित कर दिया गया।

१८६७ में तुकिस्तान के गवर्नर जनरल का क्षेत्र स्थापित किया गया, जिसका प्रधान केन्द्र ताशकंद था। जनरल व० प० काउफमन को पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। मार्च १८६८ में बुखारा के अमीर मुजफ्फरुद्दीन ने रूसियों के खिलाफ जेहाद का एलान कर दिया। जनरल काउफमन ने अप्रैल १८६८ में समरकंद पर धावा बोल दिया और बुखारा की सेनाओं को पराजित करके २ मई को शहर में प्रवेश किया। समरकंद की पराजय से बुखारा की शान मिट्टी में मिल गई और उसे एक सधि स्वीकार करनी पड़ी जिससे खान प्रशासन पराधीन हो गया।

१८६४-१८६८ के दौरान में मध्य एशिया के दो सबसे बड़े खान-शासित क्षेत्रों काकान और बुखारा की बिल्कुल शिक्स्त हो गई। राजनयिक कारणों से उनको मिला लेने का निश्चय उस समय नहीं किया गया। १८६८ में कोकान के खान खुदायार खान और बुखारा के अमीर मुजफ्फरुद्दीन के साथ शांति-संधियां की गई जिनके अनुसार उन्होंने रूस द्वारा वास्तव में जीती हुई भूमि छोड़ दी, अपनी पराधीन स्थिति स्वीकार की और रूसियों को अत्यंत लाभदायक शर्तों पर व्यापार का अधिकार दिया।

कोकान की सधि से रूसी व्यापारियों को खान शासित प्रदेश के सभी शहरों में जान, कारवान-सराये स्थापित करने और व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। आयात कर के मामले में रूसी और मुसलमान व्यापारियों में अंतर मिटा देने का निश्चय किया गया और पड़ोसी राज्यों को जानेवाले रूसी कारवानों को बिना रोक-टोक आने जाने का अधिकार मिल गया। रूसियों को केवल २५ प्रतिशत महमूल दना था। उतना ही मुसलमान व्यापारी दिया करते थे। और इसके अलावा अन्य विदेशियों के मुकाबले में रूसियों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हुईं। खान शासित प्रदेश का आधा इलाका हाथ से निकल गया और बाकी आधा रूस का संरक्षित क्षेत्र हो गया। बुखारा के साथ सधि पर अमीर न जून

१८६८ में हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार समरकन्द, तत्ता-बुगान और ज़रफ़शान का पूरा ज़िला रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया और इसके अलावा पाँच लाख रुबल का हरजाना देना पड़ा। इसमें व्यापार का सुविधाओं के सबंध में कई धागाएँ भी थीं। रोज़ाना की तरह बुगरा भी रूस के अधीन हो गया।

चीवा की चारों पाँच वर्ष बाद आयी। १८७३ के वसंत में रूस ने उसको परास्त कर लिया और उसे अपनी शर्तों मानने पर मजबूर कर दिया। अगस्त १८७३ में ज़ारल वाउफ़मन और चीवा के शासक सयद माहम्मद रहीम खान १ शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इस संधि में खान को यह स्वीकार करने पर विवश कर दिया कि वह "तमाम रूस के सम्राट का भदना चाकर" है और "पड़ोस के शासकों और खानों से सभी प्रत्यक्ष और दोस्ताना संबंधों का परित्याग करता है। आमू-नरिया का पूरा दाहिना तट और उससे मिला हुआ चीवा का इलाका रूस को दे दिया गया और उसे आमू-नरिया में बिना रोक-टोक जहाज़रानी का अधिकार भी मिल गया। रूसियों को आमू-नरिया के बायें तट पर गादाम और घाट बनाने और फ़ैक्टरियाँ कायम करने का अधिकार मिल गया। रूसी व्यापारियों और कारवानों को पूरे खान शासित प्रदेश में यात्रा की आज़ादी मिल गई और खान ने उनकी विशेष सुरक्षा का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इसके अलावा उन्हें चुगी-कर भदा करने से भी मुक्ति मिल गई। संधि में ऐसी धारा भी निहित थी जिसके अनुसार चीवा में रूसिया का अतिरिक्त देशीय अधिकार प्राप्त था। चीवा में दास पथा मिटाने और १८६३ तक कुल मिलाकर २२ लाख रुबल युद्ध का हरजाना अदा करने के सबंध में भी धाराएँ थीं। चीवा के साथ यह संधि बिल्कुल औपनिवेशिक संधि थी जैसी पश्चिमी शक्तियाँ ने चीन पर थोपी थी। इस संधि से और इसके पहले कोकार और बुखारा के साथ संधियों से इन तीनों खान शासित प्रदेशों पर रूस का आधिक्य अधिकार निश्चित हो गया।

ज़ारशाही रूस द्वारा खान शासित प्रदेश के मिला लिये जाने पर चीवा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसपर दिलचस्प रोशनी एक समवालीन

अंग्रेज ने डाली है, जो मध्य एशिया की घटनाओं का साक्षी था। मक्गाहन ने लिखा था कि उसे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरजाने की रकम अदा होने से पहले ही खान की मृत्यु या किसी और घटना के कारण शायद स्वयं सोगो के अनुरोध पर, रूसिया को अपने हाथों में सत्ता लेने का मौका मिल जायेगा।*

इसके बाद तेव्हे तुक्मानो की, जो अतरेक घाटी में बसे हुए थे और मव नखलिस्तान में रहनेवाले सरापा की बारी आयी। खीवा को अधीन कर लेने के बाद रूस के विस्तार के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। रूसी हमले के प्रति संगठित विरोध का अंतिम आभास भी गायब हो जाता रहा और ज़ार महान खान शासित प्रदेशों का निर्विरोध अधिपति बन गया। पश्चिम की ओर रूस का प्रभाव आस्नोबोदस्क की कास्पियन बंदरगाह में, जिस जनरल स्तोलेतोव ने १८६६ में कायम किया था, मजबूती के साथ जम चुका था। आमू-दरिया पश्चिम की नयी सीमा थी। परन्तु आमू दरिया और कास्पियन के बीच का इलाका अपराजित रह गया था। यहाँ कोई संगठित राज्य नहीं था और इस इलाके में तुक्मान बसे हुए थे, जिनकी पराजय की कहानी मध्य एशिया पर रूसी बच्चे के इतिहास का अंतिम अध्याय है।

लेकिन इससे पहले कि रूस तुक्माना पर चढ़ाई करता, कोकान में विरोधी आन्दोलन फैल गया। खान खुदायार खान के बेटे नसीरुद्दीन खान के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचल दिया गया और कोकान के खान-शासित प्रदेश को २ मार्च, १८७६ को रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका नया नाम रखा गया—सूवा फरगाना। ट्रांसकास्पियन सैनिक जिले का निर्माण १८७४ में मेजर-जनरल लोमाकिन की मातृहती में किया गया था। १८७७ में लोमाकिन ने आस्नोबोदस्क से २०० मील पूर्व किज़िल अरवात के तेव्हे किले पर चढ़ाई की, मगर बड़े प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। उसने अखाल नखलिस्तान

* T A MacGahan *Campaigning on the Oxus and the Fall of Khiva* London, 1874, p 295

मे गेआफ-त्तेपे ज़िले म दागिल-त्तेप पर चढ़ाई करन की चेष्टा की, मगर तुक्मान यादवाआ न उसे विफल कर दिया। प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करन के लिए जनरल म० स्वात्रेलेव का तुक्माना का पराजित करन के लिए भेजा गया (वह रीवा और ब्रावान के विरुद्ध अभियाना म भाग ल चला था और रूसी-तुर्की युद्ध के दौरान एद्रियाणायन और प्लेवना पर कब्जा किया था) ।

लोमाकिन ने ऊटा का प्रयाग किया था, जो उस लम्बी कठिन राह म हजारों की सख्या में मर गया। इसलिए स्वात्रेलेव ने वाष्प का सहारा लिया। एक विशेष रेलवे बटालियन की स्थापना की गई जिसन अभियान की प्रगति के साथ-साथ ट्रांसकाम्पियन रेलवे का निर्माण किया। फ्रांसोवोदस्क में एक जल शोधक यंत्र स्थापित किया गया ताकि पान के पानी की कमी नहीं हो। सारी तयारियां हो जाने के बाद तुक्माना के खिलाफ हमला बोल दिया गया। धीरे धीरे तुक्माना न वीरतापूर्वक लड़ाई की और गेओफ-त्तेप भारी लड़ाई के बाद पराजित हुआ। इसके पतन के बाद अखाल नखलिस्तान पर रूसिया का कब्जा हो गया।

अब केवल मव पर कब्जा करना रह गया था। उसको रूसी साम्राज्य म बड़ी चतुर कूटनीति से एक हाशियार काकेशियाई मुसलमान अलीखानोव की काशिश से मिलाया गया। उस गुल जमाल का सहयोग मिल गया जो अंतिम महान तुक्मान सरदार नूर वदी खान की विधवा थी। २१ जनवरी, १८८४ को तुक्मान कबायली सरदार अशकावाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने जार की वफादारी की प्रतिज्ञा की। उसके कुछ ही दिनों बाद मव के दक्षिण मसगीक कबीले न हथियार डाल दिये और इस प्रकार पूरा इलाका पराजित हो गया।

रूसी विजय और मध्य एशिया पर कब्जे के ऐतिहासिक महत्त्व पर सावधान और पश्चिमी इतिहासज्ञ बहुत भिन्न विचार पकट करते हैं। जारशाही रूस द्वारा मध्य एशिया पर कब्जे से जारशाही का औपनिवेशिक उत्पीड़न बढ़ गया। लेकिन रूसी साम्राज्य में इन लोगों के मिता लेने का एक दूसरा पहलू भी था। इससे उनकी नियति रूस की प्रगतिशील शक्तियों से, रूसी नातिकारी आन्दोलन से सबद्ध हो गयी। इसलिए रूस म मध्य

एशिया के मिला लिये जाने का वस्तुनिष्ठ दृष्टि से प्रगतिशील स्वरूप था। रूसी कब्जे के इस प्रगतिशील ऐतिहासिक स्वरूप को कभी कभी कुछ सोवियत लेखक अतिशयोक्ति के साथ पेश करते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ तक कह जाते हैं कि रूस में विलयन मध्य एशिया के जनगण का “सदियों पुराना स्वप्न” था। लेकिन बहुतेरे सोवियत इतिहासज्ञों ने इस सबाल पर वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए, एक सोवियत उर्बेक विद्वान अ० म० अमीनोव ने रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के “प्रगतिशील महत्व को बड़ा चढ़ा कर पेश करने की प्रवृत्ति” की निंदा की।* वह लिखते हैं

“इसका यह नतीजा नहीं होना चाहिये कि साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी सार पर, जारशाही की औपनिवेशिक नीति के स्वरूप और उद्देश्यों पर परदा डाल दिया जाये, जो मध्य एशिया के धन को लूटकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्न कर रही थी।”**

जारशाही ने मध्य एशिया में कठोर औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रखा था जिसका हित स्थानीय जनता और रूसी मजदूर वगैरहों के हितों के विरुद्ध था। हाल ही में मध्य एशिया के विलयन के प्रगतिशील स्वरूप पर ज़रूरत से ज्यादा जोर देने की प्रवृत्ति को सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सहसदस्य म० प० किम ने आलोचना का विषय बनाया है। किम ने सोवियत लेखकों पर इस मामले में दृष्टिकोण के “कुछ आधुनिकीकरण” का आराप लगाया है। उन्होंने इस तक की आलोचना की है, जो सोवियत साहित्य में अक्सर पश किया जाता है, कि अगर मध्य एशिया की जातियों का विलयन रूस में नहीं हुआ होता, तो वे अकतूबर क्रांति के बाद सोवियत जातियों के विरादराना संघ में एकताबद्ध नहीं होती। उन्होंने कहा

“हर एक सत्य की तरह, ऐतिहासिक सत्य भी ठोस होता है। जब हम रूस के साथ जातियों के विलयन के प्रगतिशील परिणामों की बात

* अ० म० अमीनोव, “मध्य एशिया का आर्थिक विकास”, ताशकन्द, १९५६, पृष्ठ १६। (रूसी संस्करण)

** वही, पृष्ठ १७५-१७६।

करते हैं, तो हमारे मन में वे प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जो इन जातियों के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुराने सामंती या पूँजीवादी जमींदार रूप की ठोस ऐतिहासिक स्थितियों में हुए। हम जब प्रगतिमान परिणामों की बात करते हैं, तो साथ ही हम यह स्वीकार करते हैं कि जातीय स्वतंत्रता के छिन जाने से उनका कितना नुकसान हुआ।”*

मध्य एशिया में

आंग्ल-रूसी प्रतिद्वंद्विता

१९ वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भी जबकि मध्य एशिया में रूस का मुख्य प्रभाव अभी शुरू नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने आंग्ल-रूसी संबंधों की अपनी अनूठी व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी। अंग्रेजों के अनुसार रूस बराबर एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करते हुए भारत की सीमाओं की ओर बढ़ता जा रहा था। कहा जाता था कि रूस के बढ़ने का लक्ष्य भारत था और इसलिए ब्रिटेन जो कुछ कर रहा था, वह भारत की सुरक्षा और तुर्की साम्राज्य की अखंडता के लिए, जो यूरोप और भारत के बीच में एक पुल के समान था, कर रहा था। ३० जून १८०६ और बाद में २० जून १८०८ जैसे लेखकों ने इस विचार को बराबर फैलाने का प्रयास किया।

लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर पूर्वाग्रह पर आधारित था। बात ऐसी नहीं थी कि रूस बस बराबर बढ़ता जा रहा था और ब्रिटेन केवल प्रतिरक्षा कर रहा था। वास्तव में मध्य एशिया में दो आक्रामक लहरें आकर मिलीं।** मध्य एशिया के प्रति ब्रिटेन और रूस दोनों की नीति आक्रामक थी, और हर एक दूसरे पर आरोप लगाता था।

* “इतिहास और समाजशास्त्र”, मास्को, १९६४, पृष्ठ १२७-१२८।
(रूसी संस्करण)

** “कूटनीति का इतिहास”, मास्को, १९६३, खण्ड २, पृष्ठ ६०।
(रूसी संस्करण)

दोनों शक्तियों में प्रतिद्वंद्विता का असली कारण सामरिक विचार और व्यापारिक हित थे और साथ ही अपने अधीन देशों पर नियंत्रण और दृढ़ करने की इच्छा भी थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को डर था कि किसी विदेशी मेना के सीमा के निकट आने से अनिवार्यतः उनके शासन के विरुद्ध जन का क्रोध उठ जायेगा। इसलिए वे आस-पास के देशों—फारस, अफ़ग़ानिस्तान, तिब्बत और बर्मा में अपना प्रभाव फैलाना और अगर सम्भव हो तो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इन दोनों शक्तियों द्वारा कब्ज़ा करने का कारण आम तौर पर कच्चे सामान के स्रोत और उनके पूँजीवादी उद्योगों के तैयार माल के लिए मंडी हासिल करने की जरूरत होती थी। इस दृष्टि से मध्य एशिया की कपास रूसी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गयी।

मध्य एशिया के लिए आम नीति लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा निर्धारित होती थी, मगर उसका ठोस रूप में अमल में लाने का काम भारत में वाइसरॉय के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रिटिश एजेंट, जो माध्यस्थ गुप्तचर अफसर होते थे, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पश्चिमी चीन जाते और वहाँ अक्सर स्थानीय एजेंटों को भरती करते थे। तुर्की के सुलतान के एजेंट भी अफ़ग़ानों की सक्रिय सहायता किया करते थे। मध्य एशिया में जामूसी और विध्वंसक कारवाइयों की ब्रिटिश नीति सरकारी कूटनीति से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। रूसी पक्ष में भी तुर्किस्तान का गवर्नर-जनरल सेट पीटसबर्ग के नियंत्रण से काफी हद तक स्वतंत्र था और स्थानीय मामलों का शासक और कबायलों के सरदारों में उसने अपने जामूसा का जाल बिछा रखा था।

मध्य एशिया में ब्रिटिश विस्तार का मुख्य विषय अफ़ग़ानिस्तान था। वहाँ से अफ़ग़ान तुर्कमेनिस्तान में घुसने की तैयारी कर रहे थे। अफ़ग़ानों ने पहला अफ़ग़ान युद्ध १९वीं सदी के चौथे दशक में चलाया, जब रूस का फैसला हुआ साम्राज्य अभी भारत की सीमाओं से दूर था। यह आक्रामक युद्ध अफ़ग़ानिस्तान पर, जो दुश्मन नहीं था, ऐसे समय थापा गया, जबकि फारस में हेरात की घेराबंदी उठा ली थी और रूसी एजेंट वित्तवैचिक को वापस बुलाकर अनाधिकृत घोषित कर दिया गया था।

१८६६ म सामती सघर्षों का दौर समाप्त हो गया था, जा विगत छह वर्षों से अफगानिस्तान म जारी थे। अमीर शेर अली ने अपने विराट्पिता को परास्त कर दिया और अफगानिस्तान म अपने नियंत्रण म कद्रोपकृत राज्य स्थापित कर लिया था। लाड मेयो न अमीर का अपना ताकत और अफगानिस्तान म ब्रिटिश प्रभाव का यत्न बनान का निश्चय किया। लाड मेयो ने शेर अली का भारत आने का निमंत्रण दिया और मार्च १८६६ म अम्बाला मे वे मिले। अमीर ने यह माग की कि मन्त्री-संघि कर ली जाये और अंग्रेज उसके छोटे बेटे अब्दुल्लाह खान को अफगान राज गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी मान ले। परन्तु लाड मेयो इस पर राजी नहीं हुआ। अंग्रेज राज गद्दी के विभिन्न दावेदारों को एक दूसरे से लड़ान का खेल छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उसन अमीर को अपना दोस्ती का विश्वास दिलाया।

१८६६ के शुरू म ब्रिटेन मे ग्लैंडस्टन के नेतृत्व म लिबरल पार्टी की सरकार ने जारशाही सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि मध्य एशिया म ब्रिटेन और रूस के अधीन इलाकों के बीच तटस्थ क्षेत्र का निर्माण किया जाये। दोनों शक्तियाँ इस तटस्थ क्षेत्र का सम्मान करें। इसका उद्देश्य यह था कि दोनों के इलाका की समान सीमा नहीं होने पाये। रूसी सरकार ऐसे तटस्थ क्षेत्र के निर्माण पर राजी हो गयी और उसन सुझाव दिया कि इसमे अफगानिस्तान को शामिल करना चाहिये। मकसद यह था कि ब्रिटेन उसको हडप न कर सके। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर की ओर उस क्षेत्र का विस्तार करने का सुझाव दिया। इसपर दोनों सरकारों ने पत्र-व्यवहार का लम्बा सिलसिला चला, जिसका फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसे “क्लैरेडन गोर्चakov समझौता” कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की राय थी कि अफगानिस्तान तटस्थ क्षेत्र की शत पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सीमाएँ ठीक से निधारित नहीं हैं।

इसके बाद आंग्ल और भारत म उसके सहकारियों ने तजवीज पेश की कि ऊपरी आक्सस को वह सीमा हानी चाहिए जिसे किसी शक्ति की सेनाएँ नहीं पार कर सके। तटस्थ क्षेत्र के संबंध म बातचीत फिर शुरू हुई, जब भारतीय प्रशासन का एक अधिकारी ट० ड० फोर्साइथ

नवम्बर १८६६ में सेट पीट्सबर्ग गया। उसके साथ एक समझौता हुआ जिसकी पुष्टि बाद में जार और ब्रिटिश सरकार ने की। इस बात पर सहमति हुई कि जो सूबे दरअसल शेर अली के कब्जे में थे, उन्हें अफगानिस्तान का इलाका मान लिया जाये। यह भी तय हुआ कि ब्रिटेन अफगान अमीर पर अपना प्रभाव डाले और उसे बुखारा और अन्य मध्य एशियाई राज्यों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने से रोके। इसी प्रकार रूस की जिम्मेदारी बुखारा को रोके रखना और अपना सारा प्रभाव शांति के हित में इस्तेमाल करना था।

लेकिन शेर अली के अधिकार में वास्तव में कितना इलाका था, यह एक विवादस्पद सवाल था और किसी को भी, स्वयं अमीर को भी उसकी लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान नहीं था। इसलिए यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष इसके बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव से दोनों पक्षों को समय मिल गया और व्यापक पैमाने पर झगड़े और समझौते की गुंजाइश पैदा हो गई। शीघ्र ही दोनों शक्तियों ने १८६६ के समझौते के बारे में झगड़ा शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वह सारा इलाका, जो कभी शेर अली के पूर्ववर्ती अमीर दोस्त मोहम्मद के अधिकार में था, *ipso facto* अफगान गद्दी के वर्तमान पदग्राही के कब्जे में माना जायेगा। भारत के वाइसराय लार्ड मेयो का यह मत, जैसे भारत के लिए राज्यमंत्री डयूक आफ आगिल के नाम पत्र में व्यक्त किया गया था, रूसी सरकार के पास उसके लंदन स्थित राजदूत के जरिये पहुंचा लिया गया। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि कुछ खान शासित प्रदेश, जिनपर दास्त मोहम्मद प्रशासन करता था शेर अली के अधिकार में नहीं थे।

रूसी सरकार उन्हें नये अमीर शेर अली के कब्जे में मानना नहीं चाहती थी, जिसे वह अंग्रेजों का एजेंट समझती थी। १७ अक्टूबर, १८७२ का अल ग्रनविल के लार्ड ताफ्ट्स के नाम एक लम्बे नोट में, जिसे उसने साम्राज्यी रूसी सरकार के लिए लिख कर दिया, शेर अली के अधिकार में अफगान इलाका की सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसमें ऐसा सुझाव पेश किया गया कि बदख़शान और बख़ान सूबे अफगानिस्तान का अंग हो जायें। रूसी सरकार ने ७ दिसम्बर, १८७२ के इस नोट के अपने जवाब

में अफगानिस्तान की सीमा अमू-दरिया पर बदख़शान और बख़ान के नीचे राजा सालेह तब स्वीकार की। परन्तु उसने इन दो नूवा को अफगानिस्तान का अंग मानने से इनकार कर दिया। मगर आगे चलकर ज़ारशाही सरकार ने अपना मत बदल दिया और ३१ जनवरी, १८७३ को ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित रेखा का अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा मान लिया।

इस प्रकार अफगानिस्तान के सबंध में आग्ल रूसी वार्ता और पत्र व्यवहार, जो १८६६ में शुरू हुआ था, सम्पन्न हुआ। इस १८७३ का समझौता कहा जाता है और इसमें अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा निर्धारित कर दी गयी थी। ब्रिटेन ने इस समझौते के ज़रिये रूस से एकतरफ़ा रियायत हासिल कर ली और वह यह कि रूस ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर मानने का बार बार और पक्का विश्वास दिलाया। परन्तु जहाँ तक दाना शक्तियाँ के अधिकृत इलाका के बीच "तटस्थ" या "मध्यस्थ" क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्न का सबंध है, इस विचार को १८७३ में निश्चित रूप से त्याग दिया गया। ब्रिटिश, जो अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए नज़र गढ़ाये बैठे थे, दरअसल उस सुझाव के लिए तैयार नहीं थे। लाड मेयो की सरकार शुरू ही से उसको स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी। लाड मेयो ने लॉन को लिखा था 'सबसे अच्छा यह हो कि रूस और इंग्लैंड दोनों एक दूसरे के हितों में परस्पर हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दें, जिसकी पुष्टि किसी निश्चित संधि द्वारा नहीं की जाये।'*

ज़ारशाही सरकार ने बदख़शान और बख़ान का अफगानिस्तान का अंग मानकर ब्रिटेन को रियायत दी, तो इसमें उसका अपना उद्देश्य था। वह चाहती थी कि ख़ीवा पर उसके अधिकार करने के प्रति ब्रिटेन का विरोध कमजोर पड़ जाय। ज़ार अलेक्सांद्र द्वितीय की अध्यक्षता में असाधारण समिति की एक बैठक ने ४ दिसम्बर, १८७२ को ख़ीवा पर चढ़ाई करने का निणय किया था।**

* Quoted by D K Ghosh *England and Afghanistan* Calcutta 1960 p 165

** 'कूटनीति का इतिहास', खण्ड २, पृष्ठ ६६।

जब रूस ने खीवा पर अधिकार कर लिया, तो कोई खास अंतर्राष्ट्रीय उलझनें नहीं पैदा हुईं। फिर भी ब्रिटिश अखबारा में इसका कुछ विरोध अवश्य हुआ। छह महीने से अधिक समय हो जाने पर ब्रिटिश विदेश मंत्री लाड ग्रेनविल ने सेट पीट्सबर्ग में ब्रिटिश राजदूत के नाम एक पत्र भेजा और आदेश दिया कि वह उसकी नवल जारशाही सरकार को भी दे द। इस चिट्ठी में बताया गया था कि अगर रूस भव की तरफ आगे बढ़े, तो हो सकता है कि तुर्कमान कबीले अफगानिस्तान में शरण ले और इससे रूसी और अफगान सैनिकों में झड़पें हो सकती हैं। ब्रिटिश सरकार ने आशा प्रकट की कि रूसी सरकार ब्रिटिश इंडिया की सुरक्षा और एशिया में शांति की एक महत्वपूर्ण शक्त के रूप में अफगानिस्तान की "स्वतंत्रता" का सम्मान करेगी। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने खीवा पर रूस के बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। गोर्चाकोव ने अपने उत्तर में ब्रिटेन को विश्वास दिलाया कि रूस अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र से बाहर मानता है। उसने सुझाव दिया कि अगर अफगान अमीर वास्तव में रूस से झगडा नहीं करना चाहता, तो उसे तुर्कमान सरदारों के लिए यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वे उसके समर्थन की आशा नहीं करें।

ब्रिटेन से आगे वार्तालाप के दौरान गोर्चाकोव ने २६ अप्रैल, १८७५ को अपने स्मरण पत्र में लिखा था कि दोनों शक्तियों में प्रतिद्वंद्विता उनके परस्पर हितों के लिए हानिकारक है। उसकी राय में यह वाछनीय था कि इस प्रतिद्वंद्विता से बचने के लिए दोनों के अधिवृत्त इलाकों के बीच में "मध्यवर्ती क्षेत्र" कायम किया जाये। अफगानिस्तान एक आदशमूलक मध्यवर्ती राज्य हो सकता है और इसके लिए दोनों पक्षा द्वारा उसकी स्वतंत्रता की मान्यता मात्र जरूरी है।

डिज़रेली की कज़र्वेंटिव सरकार ने १८७४ में ग्लैंडस्टन की लिबरल सरकार को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। उसने सत्ता इस नारे के साथ सभाली थी कि वह ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करेगी। आठवें दशक में औपनिवेशिक विस्तार में ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। उपनिवेशों की ओर यह ध्यान विश्व मंडिया के लिए प्रतियोगिता तीव्र होने के साथ, खासकर जमनी की ओर

से, बढ़ने लगा था। इस नयी परिघटना का सबध पूजीवाद के साम्राज्यवादी अवस्था में सन्नमण के प्रारम्भ से था। डिजरेली की सरकार ने विश्व के भिन्न भिन्न इलाकों में—दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, तुर्की और मध्य एशिया—विस्तार और औपनिवेशिक वज्जे का माग अर्पनाया। ब्रिटिश सरकार ने पारस और तुर्कमानिस्तान में अपने एजेंटों की कारवाइया तेज कर दी और वहाँ सैनिक तथा राजनीतिक जामूसी कराने लगी। उसने इस सत्र के मुसलमान शासकों का समुक्त मोरचा रूस के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। डिजरेली की सरकार अफगानिस्तान का भी अपने अधिन करने की तैयारी कर रही थी।

दोनों शक्तियाँ इस अवधि में मध्य एशिया के विभाजन के बारे में आपस में कोई समझौता कर सकती थीं। मई १८७५ में जर्मनी के विरुद्ध दोनों मिल गईं और कुछ समय तक दोनों शक्तियों के सबध सुधरते मालूम पड़ रहे थे। लाड डरबी ने लन्दन स्थित रूसी राजदूत के सामने घोषणा की कि रूस और इंग्लैंड को एशिया में समझौता करने से कोई चीज रोक नहीं सकती क्योंकि दोनों के लिए काफी जगह है।* परन्तु ब्रिटिश सरकार ने रूस से वाता के आधार के रूप में मध्यवर्ती राज्य का विचार को अस्वीकार कर दिया। वह अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता की सम्यक् पुष्टि के लिए रूसी सुझाव से सहमत नहीं हुई। अक्टूबर १८७५ में ब्रिटिश कैबिनेट ने घोषणा की कि अफगानिस्तान के सबध में कारवाई करनी का उसे पूरा अधिकार है। इसका उत्तर गोर्चाकोव ने फरवरी १८७६ में दिया और रूस के इस पुराने मन की पुनः पुष्टि की कि अफगानिस्तान को वह अपने पभाव क्षेत्र से बाहर मानता है। उसने यह भी घोषणा कर दी कि रूसी सरकार के मतानुसार मध्यस्थ क्षेत्र का सबध में वार्तालाप समाप्त हो चुका है। दोनों शक्तियों को इस इलाके के देशों के प्रति अपनी कारवाई की स्वतन्त्रता पूरी तरह कायम रखते हुए भी एक दूसरे के हितों का उचित ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के इलाकों में सीधा सम्पर्क नहीं होने देना चाहिए।

*“कूटनीति का इतिहास”, खण्ड २, पृष्ठ ६८।

रूस ने तुरत इस "कारवाई की स्वतंत्रता" का प्रयोग किया, जिसकी घोषणा पहले ब्रिटेन ने की थी। १७ फरवरी, १८७६ को ज़ारशाही सरकार ने एक आज्ञा जारी की, जिसके अनुसार कोकान खान-शासित प्रदेश को रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत का वाइसराय लाड मेयो और उसका उत्तराधिकारी नाथब्रुक अफगानिस्तान पर तुरत कब्ज़ा करने के विरोधी थे। वे "धैर्य" और "प्रतीक्षा" की नीति के समर्थक थे। इस नीति पर "अग्रिम नीति" के समयको ने आक्षेप किया, जिनमें रालिनसन था। डिजरेली ने सत्ता सभालने पर इसी नीति पर अमल किया। भारत सरकार को आदेश दिया गया था कि वह अफगान अमीर से हेरात और कन्दहार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की आज्ञा की माग करे। लाड नाथब्रुक को, जो इस नयी नीति का विरोधी था, त्यागपत्र देने पर मजबूर किया गया। अप्रैल १८७६ में उसके स्थान पर लाड लिटन वाइसराय बनकर आया। मई १८७६ में लिटन ने माग की कि शेर अली काबुल में ब्रिटिश मिशन से मिले। इस प्रश्न पर वाइसराय के पत्रों का अध्ययन करने से मन की व्यग्रता और हठधर्मी की झलक मिलती है। चौथे दशक का कहानी दूसरे अफगान युद्ध में पुनर्दोहराई गई, और फिर यह सब हम व आनामक इरादा के मुकाबले में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के नाम पर किया गया। इस सिलसिले में यह बात उल्लेखनीय है कि वाइसराय का भारत की सुरक्षा की तो बड़ी चिन्ता थी, मगर उस महान अकाल व प्रति वह बिल्कुल उदासीन रहा जिसमें ५० लाख व्यक्ति मौत के घाट उतर गये। ब्रिटिश राजमुकुट की महिमा प्रदर्शित करने के लिए उसने तिल्ली में शानदार दरबार ऐसे समय रचाया, जब करोड़ों भारतवासी दश व हर शहर और हर गांव में प्लेग और भूख से मर रहे थे।

तुकमानिस्तान में ब्रिटिश एजेंटों ने रूस के विरुद्ध स्थानीय सरदारों का उभारा। ज़ारशाही रूस को ईरान और अफगानिस्तान से, जहाँ ब्रिटिश प्रभाव बढ़ रहा था, तुकमानिस्तान के लिए ब्रिटिश खतरे का इहसास था। १९वीं सदी के आठवें दशक में खुरासान मध्य एशिया में ब्रिटिश सैनिक विस्तार का भ्रष्टा बन गया। १८७३ में कनल बेकर, कैप्टन ब्लैटन और लेफ्टिनेंट गिल अतरेक नदी क्षेत्र का अध्ययन करने भेजे गये। बेकर

ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की जिसमें तुर्कमानों के लड़ाकू गुणों की प्रशंसा की गई थी। उसकी राय में १२० हजार ब्रिटीश तुर्कमान घुड़सवार यूरोपीय अफसरों की कमान में एक बड़े इलाके को रखा कर सकते हैं।* बेकर ने इस इलाके के सैनिक भूगोल के संबंध में लगन से लेख भी प्रकाशित किये। १८७४ में नेपियर को कहा यह अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि रुस के विरुद्ध ब्रिटेन के संधि में "मुद्दबलि" के रूप में तुर्कमान कबीलेवालों का प्रयोग करने की क्या सम्भावनाएँ हैं। वह ब्रिटेन के अनुयायी खानों से मिला, उनमें हथियार बाँटे, सबको का नक्शा तैयार किया और कास्पियन सागर में जहाज़रानी के संबंध में सूचना इकट्ठा की। वापस आने पर उसने सरकार से आग्रह किया कि वह ईरान तुर्कमानिस्तान की सीमा पर होनेवाली घटनाओं में अधिक सैन्य हस्तक्षेप करे।

१८७५ में कप्तान मकग्रेगर मशहद से मव खाना हुआ। उसने तुर्कमान सरदारों का विश्वास दी ताकि मव पहुँचने में वे उसकी सहायता करें। वह मव तक नहीं जा सका क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसे रूसी सरकार के प्रतिरोध का डर था। लेकिन वह तेज़ेन नदी पार करके मव की ओर २० मील तक गया। बाँ में कप्तान वर्नाबी को खीबा से मव जाने का काम सौंपा गया। परन्तु वह भी इसे पूरा नहीं कर सका। रूसी अधिकारियों ने उसे मव जाने नहीं दिया और मध्य एशिया से चले जाने पर मजबूर किया। १८७६ के अंत में नेपियर एक बार फिर तुर्कमानों में अपना विध्वंसक काम करने मशहद पहुँचा।

१८७७ में कैप्टन बटलर ने जिसने चीन में तार्त्तार विद्रोह को कुचलने में भाग लिया था, अतरेक नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उसे अखाल और मव के नखलिस्तान के तुर्कमानों को रूसियों के विरुद्ध संगठित करने का व्यक्तिगत आदेश भारत के वाइसराय लार्ड लिटन से मिला।

* V Baker, *Clouds in the East Travels and Adventures on the Perso Turkmen Frontier* London, 1876 pp 341—342

परन्तु रूसी अधिकारियों को उसके मिशन की सूचना मिल गई और उनके प्रतिरोध के कारण उसे वापस बुलाना पड़ा। बाद में जब लाड लिटन ने तुर्कमानिस्तान में हुआ उसका खच भ्रदा करने से इनकार दिया, तो उसने अपने मिशन का कच्चा चिट्ठा अफवाग में छपवा दिया और लाड लिटन को विध्वंसक कारवाइया के संगठनकर्त्ता के रूप में बेनकाब किया। २५ जनवरी, १८८१ को "ग्लोब" में प्रकाशित अपने लेख में उसने बताया कि कस उसने आधुनिकतम यूरोपीय तकनीक के अनुसार गैंग्रोव-तेपे की किलाबानिया के पुनर्निर्माण में भाग लिया। अंग्रेजी पत्रवार चाल्स भाविन ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि यदि बेकर, मक्ग्रेगर, नेपियर और क्लर फारस के उत्तर-पूर्वी सीमा पर न पहुँच गये होते, तो रूस को अनेक लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।* १८७३ से लेकर १८८१ तक शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता होगा जब तुर्कमानो में उपद्रव फलाने के लिए ब्रिटिश एजेंट न भेजे जाते हों। लाड लिटन ने मक् पर अधिकार करने की एक योजना बनाई थी। १८७८ में ही, जब अंग्रेज अफगानिस्तान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, लाड लिटन ने भारत के लिए राज्य मंत्री को अपना मुझाव लिख भेजा कि एक अलग पश्चिमी अफगान राजतन्त्र स्थापित किया जाये जिसमें मक्, मँमेना, वल्ख, कन्हार और हेरात शामिल हों, उसका शासक अंग्रेजों की पसंद का आदमी हो और कि यह राजतन्त्र अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटेन के समर्थन पर निर्भर हो।** यह था उस "मक् पीडा" का असल कारण, जिसने मक् पर रूसी कब्जे के समय भारत सरकार को दबोच लिया था। जारशाही सरकार ने तुर्कमानिस्तान पर कब्जा करने में जल्दी की ताकि अंग्रेज अफगानिस्तान से आगे उत्तर में न जायें। ब्रिटिश सरकार

* C Marvin *Reconnoitring Central Asia* London 1886, pp 246-249, न० अ० खालफिन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३३८-३३९।

** B Balfour, *The History of Lord Lytton's Indian Administration* London, 1899, p 247

ने रूस से १८८० की संधि के आधार पर अफगानिस्तान के सामा निधारण का सवाल उठाया। सीमा निर्धारण के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग के अग्रेज सन्ध्या ने रूस के विरुद्ध अमर अब्दुरहमान का भड़काया। ब्रिटिश सरकार अवश्य ही यह नहीं चाहती थी कि रूस और अफगानिस्तान में अच्छे पड़ोसी के संबंध कायम हों। १८८४ में अंग्रेजों के उकसावे पर अफगानों ने अपनी सेना पंजदेह व नखलिस्तान में भेज दी जिसमें सराख कबीले के तुक्मान बसे हुए थे। रूसन फलस्वरूप रूसियों से जबरदस्त झड़प हो गई जिसमें अफगानिया को हार खाकर पीछे हटना पड़ा। इस थगड़े के पीछे अंग्रेजों का हाथ था, यह बात अफगानों के नाइव सालार के वक्तव्य से जाहिर है

“मुझे प्यारी है कि पंजदेह में हम रूसिया में लड़े, क्योंकि अब हम मालूम हो गया कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु। कम से कम व, जिहान हमें लड़ने पर आमादा किया और मरण के लिए छान्द दिया हमारे सच्चे दोस्त नहीं है।”*

इस लड़ाई का दोष रूस पर नहीं लगाया जा सकता। वह सामा निर्धारण सीमावर्ती इलाके की भौगोलिक और जातीय स्थितियों के अनुसार करना चाहता था। ब्रिटेन ने रूस के पक्ष किये हुए जातीय आधार को सीधे अस्वीकार कर दिया।

परंतु ब्रिटिश उकसावों के बावजूद अफगानी अमीरों ने सीमा के झगड़े में संतुलन से काम लिया। वह रूस से लड़ाई में नहीं फसना चाहता था। अंग्रेजों ने पंजदेह नखलिस्तान को रूस का अधिकृत इलाका मान लिया। इसके बदले में रूस अफगानिस्तान को जुलफिकार क्षेत्र दत्त पर राजा हो गया। लंदन में १० सितम्बर, १८८४ को एक राजीनामे पर हस्ताक्षर करके यह समझौता कर लिया गया। १८८६-१८८८ में इस इलाके में सीमा रखा रूसी अफगान आयोग ने नहीं, बल्कि आंग्ल-रूसी आयोग ने छोड़ी।

* Quoted by D K Ghosh *India and Afghanistan*
pp 196—197

—११— १९ वीं सदी में आग्ल रूसी संघर्षों की अंतिम जटिल समस्या पामीर का प्रश्न था। नव दशक के अंत और दसव दशक के प्रारम्भ में आग्ल-रूसी प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र "ससार के शिखर" पर पहुंच गया। जारशाही सरकार कोकान खान प्रशासन के उत्तराधिकारी की हैसियत से पूर्वी पामीर पर अपने अधिकारों का दावा करती थी। जहां तक पश्चिमी पामीर के देव शासनो का संघ था, ब्रिटेन के साथ १८७३ के समझौते के अनुसार वही रूस के प्रभाव-क्षेत्र में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे आमू-दरिया के उत्तर में थे। यह क्षेत्र अंग्रेजों के उससावा का क्षेत्र बन गया क्योंकि

—१२— जारशाही रूस तुक्मान कारवाइया में उलझा रहा था। रूस कोकान को पराजित करने के वाद पामीर पर भी अधिकार कर ले सकता था लेकिन यह दरिद्रता भरा वीरान इलाका उस समय उसे किसी आर्थिक महत्व का नहीं जान पड़ा। परंतु उसने पामीर पर अपने अधिकारों को कभी त्यागा नहीं। १८७६ के आलाई अभियान में पामीर पर अधिकार जमान की उसकी इच्छा पहली बार व्यक्त हुई।

—१३— रूसी भौगोलिक सत्या पामीर के वैज्ञानिक अध्ययन में दिलचस्पी लेने लगी थी। अंत १८८२ में उसने थ० रेगेल को वहां भेजा। शुगनान के शासक युसूफ अली ने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। रेगेल ने वदखशान भी जाना चाहा, मगर अफगानी अधिकारियों ने उसकी आज्ञा नहीं दी। १८८३ में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुरहमान ने शुगनान और रूशान पर कब्जा करने के लिए सन्ना भेजी। शुरू में रूसी अधिकारियों ने इसपर कोई जारदार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। परंतु जब रूसी अखबारा ने सवाल उठाया, तो दिसम्बर १८८३ में ब्रिटिश सरकार के पास एक नोट भजा गया था। कहा गया था कि अफगान कब्जा १८७३ के समझौते की प्रत्यक्ष अवहेलना है। पांच महीनों तक अंग्रेज चामोश रहे और जब फिर स्मरण पत्र भेजा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अफगानिस्तान शुगनान और रूशान को वदखशान का भाग मानता है जो उसे १८७३ के समझौते के अनुसार दे दिया गया था। रूसी सरकार उस समय तुक्मानिस्तान में पूरी तरह व्यस्त थी इसलिए वह इस मामले पर और अधिक ध्यान नहीं दे सकी। इस बीच शुगनान के लागा में असतोप बढ़ता

रूस द्वारा देशजय और आग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता ७३

निधिमंडल भेजे। मगर जारशाही सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के मामले में दखल देने से बराबर इनकार किया।*
कजत इलाके पर १८६१ में अंग्रेजों के कब्जे से सेट पीटसवग में छतरे का इहसास पदा हुआ। १२ जनवरी, १८६२ को साम्राज्यी परिषद की एक बैठक में एक गुप्तचर अभियान पामीर भेजने का निश्चय किया गया। इसमें यह भी निफारिश की गई कि पामीर इलाके के सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटन और चीन से बातचीत की जाये। पामीर समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल १८६२ में बुलायी गयी एक और बैठक में युद्ध मंत्री और प्रतिवाणी दम्तिकोण अपनाया, मगर वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय के अधिकारियों ने सावधानी की नीति पर जोर दिया। निणय लिया गया था कि हिंदूकुश के दरों की ओर न बढ़ा जाये और १८७३ के समझौते के आधार पर सीमा निर्धारण के लिए वार्तालाप किया जाये।**
अप्रैल १८६४ में रूस और चीन पामीर इलाके में वर्तमान अवस्था का कायम रखने और एक दूसरे की स्थिति का परस्पर सम्मान करने पर राजी हो गये। तब रूसी सरकार ने अंग्रेजों से बातचीत करने का आग्रह किया। ११ मार्च १८६५ को ब्रिटिश विदेश मंत्री अल आफ किम्बरले और लंदन स्थित रूसी राजदूत म० दे स्ताल के बीच पत्रों के आदान प्रदान के पत्राचार एक समझौता हुआ। अफगानिस्तान ने शुगनान और रुशान क्षेत्रों को रूस के हवाले कर दिया। बाद में रूस ने उन्हें बुखारा को दे दिया। बुखारा ने अमू-दरिया के बायें तट पर स्थित दरवाज का एक भाग अफगानिस्तान को दे दिया। विक्टोरिया झील के पूर्व ब्रिटन और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों को एक रेखा से विभाजित करना था, जो उस झील के पूर्वी सिरे पर एक बिंदु से शुरू होकर एक पहाड़ी रास्ते से होती हुई चीन की सीमा तक चली जायेगी। इस रेखा का निर्धारण एक समुचित तकनीकी आयोग द्वारा करना था। ब्रिटन और रूस दोनों ने यह वादा किया कि पहला इस सीमा रेखा के उत्तर और दूसरा इस के दक्षिण कोई

*वही, पृष्ठ ३६३।

**वही, पृष्ठ ३६६।

गया। १८८८ में अफगानिस्तान की अदरूनी गडबड से फायदा उठाकर शुगनान के लोगो न अपने भूतपूर्व शासक की सत्ता को बुखारा से वापस आन का निमन्त्रण दिया। उन्होंने जारशाही रुम से भी सहायता मागी। परन्तु अब्दुरहमान ने शीघ्र ही शुगनान के विद्रोह को बडाई से कुचल लिया।

अंग्रेजो न पामीर के इलाके में अपनी कारवाइया तेज कर दी। १८८६ में कनल लाकाट ने हिंदूकुश से पामीर जानेवाले दरों का अध्ययन किया। गिलगित से अ० दूराट १८८८ और १८८९ में यह गुप्तचर काम करता रहा। मेजर कम्बरलैंड और लेफ्टिनेंट बावर ने १८८९ में तगदुम्बश पामीर की यात्रा की। शिकार के बहाने लिटलडेल भी उनके पीछे पीछे गया। १८९० में कैप्टन फ्रांसिस यगहस्वड के नतत्व में एक विशेष अभियान मडली पामीर भेजी गई। काशगर में रूसी कौन्सल न० पेत्रोव्स्की ने वैदेशिक मामला के मन्त्रानय का खबर दी कि अंग्रेज आधा पामीर अफगानिस्तान को दे देना चाहते हैं और गुप्त रूप से चीन से भी समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।* यगहस्वड मडल के कारण जारशाही सरकार, जो कुछ समय से पामीर के मामले में “ठहरो और देखो” की नीति पर चल रही थी, सक्रिय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि तुकिस्तान के गवर्नर जनरल अ० वेस्की ने आलाई घाटी की यात्रा की। म० इयानोव को एक कज्जाक बटालियन के साथ पामीर भेजा गया। कनल व्योतोव ने कैप्टन यगहस्वड को बोजाई गुम्बज घाटी से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब यह था कि जारशाही रुम राजनयिक पत्र व्यवहार के बदले अब निष्पायक कारवाई पर उतर आया था। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पामीर में इस नयी जारनगर नीति के बावजूद हिंदूकुश की दक्षिणी ढलान पर स्थित छोटे राज्यो हुआ और नगर पर अधिकार करने का जारशाही रुम का कोई इरादा नहीं था। इन राज्या के शासक न अंग्रेजो के खिलाफ रूस की सहायता प्राप्त करने के लिए कइ प्रति

रूस द्वारा देशजय और आग्ल हसी प्रतिद्वंद्विता ७३

निधिमडल भेजे। मगर जारशाही सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के मामलों
म दखल देने से बराबर इनकार किया।*
कजूत इलाके पर १८६१ में अंग्रेज़ों के कब्जे से सट पीटसवग में खतरे
का इहसास पैदा हुआ। १२ जनवरी, १८६२ को साम्राज्यी परिषद की एक
बैठक में एक गुप्तचर अभियान पामीर भेजने का निश्चय किया गया।
इसमें यह भी सिफारिश की गई कि पामीर इलाके के सीमा निर्धारण के
लिए ब्रिटेन और चीन से बातचीत की जाये। पामीर समस्या पर विचार
करने के लिए अप्रैल १८६२ में बुलायी गयी एक और बैठक में युद्ध मंत्री
ने अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया, मगर वैदेशिक मामलों के मंत्रालय के
अधिकारियों ने सावधानी की नीति पर ज़ोर दिया। निणय किया गया
था कि हिंदूकुश के दरों की ओर न बढ़ा जाये और १८७३ के
समझौते के आधार पर सीमा निर्धारण के लिए बातलाप किया जाये।**
अप्रैल १८६४ में रूस और चीन पामीर इलाके में वर्तमान अवस्था
को कायम रखने और एक दूसरे की स्थिति का परस्पर सम्मान करने पर
राज़ी हो गये। तब रूसी सरकार ने अंग्रेज़ों से बातचीत करने का आग्रह किया।
११ मार्च १८६५ को ब्रिटिश विदेश मंत्री अलफ्राड किम्बरले और लॉन
स्थित रूसी राजदूत में दो स्ताल के बीच पत्रों के आदान प्रदान
के फलस्वरूप एक समझौता हुआ। अफगानिस्तान ने शुगनान और रुशान
क्षेत्रों को रूस के हवाले कर दिया। वाद में रूस ने उन्हें बुखारा को दे
दिया। बुखारा ने अमू-दरिया के बायें तट पर स्थित दरवाज़ का एक
भाग अफगानिस्तान को दे दिया। विक्टोरिया झील के पू्व ब्रिटेन और
रूस के प्रभाव-क्षेत्रों को एक रेखा से विभाजित करना था, जो उस झील
के पूर्वोत्तरे पर एक बिंदु से शुरू होकर एक पहाड़ी रास्ते से होती
हुई चीन की सीमा तक चली जायेगी। इस रेखा का निर्धारण एक समुक्त
तकनीकी आयोग द्वारा करना था। ब्रिटेन और रूस दोनों ने यह वादा
किया कि पहला इस सीमा रेखा के उत्तर और दूसरा इस के दक्षिण कोई

* वही, पृष्ठ ३६३।
** वही, पृष्ठ ३६६।

राजनीतिक प्रभाव या नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने जाहिर किया कि ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र और हिंदूकुश तथा विक्टोरिया झील के पूर्वी सिरे से चीनी सीमा तक की रेखा के बीच का इलाका अफगानिस्तान के अमीर के इलाके का हिस्सा होगा और ब्रिटेन उस पर कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वह इस इलाके में किसी सैनिक चौकी या किले का निर्माण नहीं करेगी।

पामीर क्षेत्र में संयुक्त आयोग ने वास्तविक सीमा निर्धारण का काम आसानी से पूरा कर लिया। इस ने भारत और रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में आठ मील चौड़ी “अफगानिस्तान की लम्बी पतली बाहु, जो अपनी उगलिया की नोक से चीन को छ रही थी”, निमित्त की। १८६५ का पामीर समझौता “घटनाओं की महत्वपूर्ण शृंखला की एक कड़ी था”। उस दशक में व्यापक अविश्वास के बावजूद एक और दोस्ताना समझौता हो गया था। मध्य एशिया की घटनाएँ आखिरकार उस मैत्री-संधि के लिए रास्ता साफ कर रही थी, जो १९०७ में सम्पन्न हुई।

पामीर समझौते के बाद के वर्षों में आग्ल रूसी तनाव धीरे-धीरे कम होता गया। १८८५ से १८९५ तक के समझौतों के बाद अफगान सीमाओं के बारे में और किसी झगड़े की गुंजाइश कम ही रह गई थी। शताब्दी के मोड़ पर दोनों शक्तियों के संबंध फिर से बिगड़े हुए थे। लाड कज़न ने फिर “अग्रिम नीति” को अपनाया। रूस से प्रतिद्वंद्विता मचूरिया से पारस तक फैल गई और यहाँ तक कि तिब्बती पठार भी उसमें शामिल हो गया। रूसी-जापानी युद्ध से आग्ल रूसी संबंधों में दबाव और तनाव का नया दौर शुरू हो गया। जब रूसी समुद्री बेड़े न लाल सागर में ब्रिटिश जहाज “मत्ताक्का” पकड़ लिया और मछेरों की नौकाओं के संबंध में डागर तट झगड़ा हुआ, तो पुरानी शत्रुता पुनः जाग उठी।

परन्तु रूसी-जापानी युद्ध आग्ल रूसी संबंधों में एक मोड़ बिंदु साबित हुआ, क्योंकि इससे रूसी साम्राज्य का खोखलापन ब्रिटेन के लिए स्पष्ट हो गया। ब्रिटेन का ध्यान अब एक नये और ज्यादा बड़े खतरों की ओर आवृष्ट हुआ। यह खतरा धीरे-धीरे उभरते हुए अधिक शक्तिशाली और जोरदार साम्राज्यवादी जर्मनी की ओर से था, जो अपनी *Flottenpolitik*

Weltpolitik और Drang nach Osten नीति के कारण ब्रिटेन के लिए एक दबंग प्रतिद्वंद्वी हुआ जा रहा था। बोअर युद्ध के दिना में उसका खतरनाक दख हो गया था और बलिन-बगदाद रेलवे बनाने की उसकी योजना पूरा में ब्रिटेन के प्रभुत्व को जोखिम में डाल रही थी। इसलिए एडमंड ग्रे का विश्वास था कि रूस से सम्बन्धों का बिल्कुल जरूरी है। इससे मोरक्का सक्क से, जिसके फलस्वरूप अलजेसिरास सम्मेलन आयोजित हुआ, प्रोत्साहन मिला। रूस फ्रांस का मित्र था, जिससे ब्रिटेन अपने सारे औपनिवेशिक झगड़े निपटा चुका था। फरवरी १९०७ में ब्रिटिश राजनयिक निक्सन ने रूस के विदेश मंत्री डजवोल्स्की के सामने ब्रिटिश सरकार के विचार की स्पष्टता पेश की। अनेक मसविदों के आदान प्रदान के बाद दोनों शक्तियां ने ३१ अगस्त, १९०७ को सेट पीटर्सबर्ग में एक इकरारनामा (मनवेनशन) पर हस्ताक्षर किये। यह "फारस, अफगानिस्तान और तिब्बत के संबंध में इकरारनामा" के नाम से प्रसिद्ध है। १९०७ का संधि ने "दो ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वियों के बीच झगड़े के कारणों को" दूर किया था।

१९०७ के इकरारनामा में तीन समझौते थे। इनमें पहला फारस के बारे में था। भूमिका में दोनों शक्तियों के बीच "फारस की अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करने", "सुख्यवस्था बनाये रखने" तथा "अपने सभी राष्ट्रों के लिए व्यापार के समान अवसर प्रदान करने" की बाबत समझौते की बात की गई थी। इन आडम्बरपूर्ण सिद्धांतों के बावजूद ब्रिटेन और रूस फारस को तीन भागों में बांटने पर सहमत हो गये थे। उत्तरी और दक्षिणी भाग क्रमशः रूस और ब्रिटेन के खास प्रभाव-क्षेत्र मान लिए गये थे और बीच का क्षेत्र तटस्थ छोड़ दिया गया था। दूसरा समझौता अफगानिस्तान के बारे में था। रूसी सरकार ने घोषणा की कि अफगानिस्तान रूसी प्रभाव-क्षेत्र के बाहर है और इस बात पर सहमत हो गई कि उस देश में सारा राजनीतिक सम्पर्क ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता के जरिये रखेगी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी धार से घोषणा की कि अफगानिस्तान की राजनीतिक हैसियत का बदलने या उसके अदखली प्रशासन में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ब्रिटिश और रूसी सरकारों

ने इस बात की पुष्टि की कि अफगानिस्तान में वे व्यापार के समान अवसर के मिद्धात का पालन करती है। तीसरा समझौता तिब्बत के बारे में था। ब्रिटेन और रूस दोनों ने तिब्बत में चीन के अधिराजकीय अधिकारों का माना और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वादा किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि इसके अदरुनी प्रशासन में कोई दखल नहीं देंगे और चीनी सरकार की मध्यस्थता के बिना तिब्बत से वार्तालाप नहीं करेंगे।

१९०७ के इकरारनामे से दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के सद्भावनापूर्ण संबंधों के युग का श्रीगणेश हुआ,* मगर फारस और अफगानिस्तान के लोका में इससे नाराजी फैली, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था से उनकी प्रभुसत्ता प्रतिबद्धित और सीमित होती थी। तिब्बत में लामा शासन ने लोका को अधविश्वास और अज्ञान की कालकोठरी में बंद कर रखा था। उनमें इतनी चेतना नहीं थी कि प्रतिराध करते। और लामा, जो पहले अंग्रेजा की चोट सहते रहते थे, इससे प्रसन्न ही हुए कि दो महान यूरोपीय शक्तियों ने तिब्बत पर चीन के अधिराज की पुष्टि कर दी। लेकिन अब जबकि चीनियों ने उनपर अपनी पकड़ और कड़ी कर दी है, उन्होंने भारतीय हिमालय में अपन प्रवास से उस समझौते की निंदा की है और कहा है कि वह साम्राज्यवादी था। अफगानिस्तान में अमीर हवीबुल्लाह ने १९०७ के इकरारनामे को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति-सम्मेलन से अपने देश की स्वतंत्रता की मान्यता की मांग की। उनके उत्तराधिकारी अमानुल्लाह ने अंग्रेजा के खिलाफ सिर उठाया। इंग्लैंड के साथ वास्तविक समानता के आधार पर नये संधि संबंधों के लिए अपने संधप में उस रूस की नयी सोवियत सरकार की नीति से प्रोत्साहन मिला। २७ मार्च, १९१९ को सोवियत सरकार ने

* सच कहा जाये तो १९०७ के इकरारनामे से आगत रूसी प्रतिद्वंद्विता केवल कुछ समय के लिए दूर हो सकी थी। दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच पूर्व में अपना प्रभाव स्थापित करने का संधप खत्म नहीं हुआ, पासपर, ब्रिटेन इस संधप में सक्रिय रहा।—स०

है”।* १८९५ में कांग्रेस के ग्यारहवें अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में चित्राल पर कब्जा करने की बड़ी आलोचना की। उन्हें विश्वास नहीं था कि रूस भारत पर हमला करेगा। इसी प्रकार १८९७ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपना गहरा और गम्भीर विश्वास प्रकट किया कि सरकार की सीमा-नीति से देश के मूल हिता को हानि पहुँचती है और इसको त्यागने का आग्रह किया।** कांग्रेस के १८९८, १९०३ और १९०४ के अधिवेशनों में भी “अग्रिम नीति” का विरोध किया गया।

अग्रेज १९०७ के आग्ल रूसी इकरारनामे के बाद भी भारत में रूसी हीए की रट लगाते रहे। पंडित नहरू ने १९२८ में लिखा था

‘हम रूस के प्रति शत्रुता की परम्परा में बड़े हुए हैं जिसे अग्रेजों ने बहुत ध्यानपूर्वक सीखा। कितने ही बरसातों से हमारे सामने रूस के आक्रमण का हौआ खड़ा किया जाता रहा है और इसे हमारा शस्त्रास्त्र पर विशाल खर्च का बहाना बनाया गया है। जारों के जमाने में हम से कहा जाता था कि रूस का साम्राज्य सदा दक्षिण की ओर बढ़ता आ रहा है, समुद्र के रास्ते या स्वयं भारत की लालसा से अधीर हो रहा है। जार जा चुका, मगर इगलड और रूस की प्रतिद्वंद्विता जारी है और अब हम से कहा जाता है कि भारत को सोवियत सरकार से खतरा है।’***

स्वतंत्र भारत ने इस “परम्परा” से नाता तोड़ लिया है।

* *Report of the Seventh Indian National Congress* pp 28—36

* चिमल प्रसाद, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४३-४४।

** J Nehru *Soviet Russia* Allahabad 1928 p 191

सामाजिक आधिकार

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ज़ारशाही रूस में बोकान के खान गामिन प्रदेश को पराजित और उसपर कब्ज़ा कर लिया तथा दो और खान गामिन प्रदेशों—बुखारा और चीवा—के क्षेत्रफल को कम कर दिया, जो अधीन राज्यों के रूप में साम्राज्य के दायरे में शामिल कर लिये गये थे। मध्य एशिया और दक्षिण कजाखस्तान में अधिवृत्त इलाक़ों को गवर्नर-जनरल द्वारा प्रशासित तुकिस्तान नामक क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया। १९१६ में रूसी तुकिस्तान की जनसंख्या ७४,६६,१००, बुखारा का २२,२६,८३३ और चीवा की ६,४०,००० थी।*

तुकिस्तान भी बुखारा और चीवा के खान प्रजासिद्ध राज्यों की तरह बहुजातीय था। उनमें उज़बेक, ताजिक, तुर्कमान, कज़ाख, किर्गिज़, कराकल्पाक तथा अन्य जातियाँ थीं। चीवा और बुखारा का अपने अधीन बनाने के बाद ज़ारशाही रूसी सरकार ने दृढ़ मान और धर्म की गद्दी की रक्षा अपनी सेना द्वारा की और इन मामलों में निरंकुश शासन हटकों की मेहनतकश जनता को दृढ़ रूप से मान्य करने के सहायता की।

*अ० अ० गार्दियेका, "रूसी राज्यों में सामाजिक जीवन की स्थापना", मास्को, १९१६, पृष्ठ १३। (रूसी संस्करण)

औपनिवेशिक काल में तुकिस्तान, बुखारा और खीवा कृषिप्रधान क्षेत्र थे। १९१३ में कुल १९ फी सदी आबादी शहरो और शहरी वस्तिया में रहा करती थी।* १९१७ की अखिल रूसी कृषि जनगणना के अनुसार तुकिस्तान में कृषिक धंधा में काम करनेवाला की संख्या ५३,७५,५३८ थी, जिनमें ३५,८१,८७३ खेती करते थे और बाकी खानाबदोश पशुपालक थे। तुकिस्तान में और उससे कहीं अधिक खीवा और बुखारा में सामंती सामाजिक संबंधों का प्रभुत्व था। कुछ इलाकों में, जैसे तुकिस्तान के कज़ाख किगिज़ इलाकों और खीवा और बुखारा के तुकमान इलाकों में अभी भी खानाबदोश लोगों में पितृसत्तात्मक बर्बाद जीवन पद्धति के अनेक अवशेष दिखाई देते थे।

तुकिस्तान, लेनिन के शब्दों में, सीधा उपनिवेश था।** बुखारा और खीवा के खान शासित प्रदेशों का अस्तित्व यद्यपि “स्वतंत्र” रूप में था, वास्तव में वे तुकिस्तान से बहुत कम भिन्न थे और “उपनिवेशों की ही तरह थे”।*** मध्य एशिया में पूँजीवादी विकास की प्रक्रिया बहुत धीरे और असमान रूप से चल रही थी, क्योंकि ज़ारशाही तथा बुखारा और खीवा के सामंती शासन जान-बूझकर सामंती और पितृसत्तात्मक संबंधों को बनाये रखने के प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए यह इलाका अक्टूबर क्रांति तक ज़ारशाही रूस का अत्यंत पिछड़ा हुआ कृषिक उपनिवेश था। यह उन पिछड़े हुए देशों में से था, जहाँ “पूँजीवाद-पूर्व संबंध”**** अभी प्रधान थे।

यह सही है कि ज़ारशाही सरकार ने तुकिस्तान में कुछ भूमि-सुधार किये थे, जिनसे मध्य एशिया के गाँवों में पूँजीवादी संबंधों का विकास का रास्ता खुल गया था। परन्तु इन सुधारों ने श्रमजीवी किसानों को उनकी सामंती अधीनता और गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाई। बड़े जमींदार

* १९६३ में मध्य एशिया का अद्यतन, सांख्यिकीय सर्वेक्षण” ताशकंद, १९६४, पृष्ठ ८। (रूसी संस्करण)

** V I Lenin *Collected Works*, vol 22, p 338

*** वही, खण्ड २५, पृष्ठ २७।

**** वही, खण्ड ३१, पृष्ठ २४२।

बटाईदारों का शोषण करते रहे। सबसे प्रचलित रूप चैरीकारी था, जिसका मतलब यह था कि किसान को पैदावार का चार भाग में से सिर्फ एक भाग मिलता था। चूंकि अधिकांश किसानों के पास खेती के लिए अपने जानवर कृषि के औजार और बीज आदि नहीं होते थे, वे ज़मींदारों और माहूबागों के शिकार में पड़ जाते थे। सिचाई के क्षेत्र में औपनिवेशिक काल में बहुत कम प्रगति हुई थी। १९१० में पूरे मध्य एशिया में केवल ४७५८०००० हेक्टेयर (१ हेक्टेयर = १.०८ हेक्टेयर) जमीन पर सिचाई होती थी जो पूरे इलाके का केवल २६ प्रतिशत था। तुर्किस्तान में पांच ओब्लास्तों (प्रान्तों) में सिंचित भूमि का पूरा क्षेत्रफल २८०८००० और बयारान में १६००,००० हेक्टेयर था।* टासकास्पियन ओब्लास्त में और ताशकंद के दक्षिण-पश्चिम वज़र स्तपी में कुछ सिचाई का काम शुरू किया गया था। रिचर्ड ग्र० पियस सिचाई के क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए लिखता है

‘मध्य एशिया में सम्पन्न की जा सका—एक वज़र स्तपी में और दूसरी मर्गवि में। इनमें से किसी में भी उनका डिजाइन बनानेवाला की प्रारम्भिक ज़म्मीदारी उन लोगों की महान आशाएँ पूरी नहीं की, जिन्होंने इस पूरे इलाके में बड़ी विशाल उपलब्धियों की योजना १८७४ में गवर्नर वज़र स्तपी में व्यापक नहर निर्माण की योजना १८७४ में गवर्नर जनरल फान काउफमन का आदेशानुसार शुरू की गई, मगर अंत में १८७६ उस त्याग देना पड़ा। स्थानीय लोग इस तगुज़ आरीक या ‘सुअर की नहर’ कहा करते थे। १९१२ में ग्र० व० त्रिनाश्वर्न ने एक भारी भ्रमक योजना रखी जिसमें नयी सिंचित भूमि पर १५००००० हेक्टेयर किसानों की बसाने की योजना भी शामिल थी। इसपर कभी अमल नहीं हुआ।

*५० इ० त्याशचको “सोवियत संघ के अथर्व का इतिहास” मास्को १९४८, खण्ड २ पृष्ठ ५४३।
 ** R A Pierce *Russian Central Asia 1867—1917* Berkeley and Los Angeles 1960 p 181

तुर्किस्तान में और उससे ज्यादा खीवा और बुखारा में कृषि और पशुपालन दोनों ही पुराने जमाने के थे। कृषि में प्रयुक्त औजार आदिकालीन थे जिससे श्रम उत्पादनता और भूमि की पैदावार बहुत कम थी। किसानों का कृषि-तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने पशु-चिकित्सा विज्ञान का नाम भी नहीं सुना था। भूमि जल और पशु जमींदारों और कुत्तों के हाथों में सकेन्द्रित थे। तुर्किस्तान के कुल किसान परिवारों में ६५ प्रतिशत भूमिहीन किसान थे।* खीवा और बुखारा में सामंती प्रभुत्व की प्रधानता थी। खीवा में खानों तथा अन्य सामंती जमींदारों की निजी जमीन कुल सिंचित और उपजाऊ जमीन का दो तिहाई थी, सातवा भाग राज्य की तथा बक्फ जमीन थी और किसानों के स्वामित्व में केवल दसवा भाग जमीन थी।** बुखारा में कुल खेती योग्य जमीन का ६५ प्रतिशत जमींदारों की और २४ प्रतिशत बक्फ जमीन थी।*** करो का बड़ा बाज़ किसानों के ऊपर था। खीवा में किसानों का २५ किस्म के और बुखारा में ५५ किस्म के कर देने पड़ते थे। किसानों को नहरों के निर्माण और मरम्मत का काम करना पड़ता था और इस प्रकार के श्रम का प्रयोग सामंती बग अक्सर अपने निजी फायदे के लिए करते थे। खीवा में दास प्रथा भी थी। जे० ह्वीलर ने जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ रिक्मेर-रिक्मेस के कुछ अर्चित वाक्यों तथा बरतोल्ड के अप्रासंगिक उद्धरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का जो प्रयास किया है कि बुखारा में जीवन "समृद्ध" था, बिल्कुल विश्वासप्रद नहीं है।**** यह कह देना जरूरी है कि बरतोल्ड ने भी शतर की राय का उल्लेख किया है कि बुखारा के अमीर मुज़फ्फर

* अ० अ० गादियेवो उपराक्त पुस्तक पृष्ठ २३।

** म० य० यूल्गाशेव, "प्राच्यविदों के पहले अखिल सघीय वैज्ञानिक सम्मेलन की लेख-सामग्री", ताशकन्द, १९५३, पृष्ठ २०५। (रूसी संस्करण)

*** म० ह्विमानोव, 'जरफशान प्रदेश में भूमि सुधार तथा सिंचाई व्यवस्था', ताशकन्द, १९५३ पृष्ठ ३-४। (रूसी संस्करण)

**** G Wheeler *The Modern History of Soviet Central Asia* London 1964 p 85

जारशाही का औपनिवेशिक शासन

से लोग "घणा करते थे क्योंकि वह अन्यायी और अत्याचारी था"। बरतोल्द लिखते हैं कि उसने शासन काल में 'जबरदस्ती बसूली की व्यवस्था की जिससे लोग तबाह हो जाते थे'।* वह बताता है कि रूसी अखबारों में अमीर की लम्बी चौड़ी प्रशंसा का जो विरोध किया गया है, वह न्यायपूर्ण है।**

मध्य एशिया पर कब्जा होने के बाद उसको प्रधान देश के उद्योगों के लिए कच्चा सामान सप्लाई करने का स्रोत बना दिया गया। जारशाही प्रशासन कपास की खेती पर बहुत ध्यान देता था और गेहूँ तथा कृषि की अन्य पैदावार के बदले उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करता था। तुकिस्तान में भूमि प्रशासन के निदेशक ने १९१३ में लिखा था तुकिस्तान के हर पूड़ (१ पूड़ = १६३८ किलोग्राम) गेहूँ का मतलब है रूसी और साइबेरियाई गेहूँ से प्रतियोगिता, हर पूड़ कपास का मतलब है अमरीकी कपास से प्रतियोगिता। इसलिए यह कहीं अच्छा है कि इस इलाक में खाद्यान्न का आयात किया जाय और वहाँ की सिंचित जमीन को कपास की खेती के लिए छोड़ दिया जाये।*** बाहर से मगवाये हुए कपास पर अधिक चूगी लगी होने के कारण अदरूनी मंडी में प्रशासन ऊँचा दाम बसूल करता था, तथा कपास की खेती तथा अन्य कम लाभदायक खाद्यान्न के लिए प्रयुक्त भूमि पर समान कर लगाने की नीति से कपास की खेती को बढ़ावा मिला जिससे वह कृषि की मुख्य नकदी फसल हो गई। इसके अलावा प्रशासन ने अनेक कृषि-संबंधी कदम उठाये जिनसे कपास की खेती के विकास में सहायता मिली। १८६२ में ३० लाख पूड़ अमरीकी किम्म का कपास तुकिस्तान से रूस में निर्यात किया गया। कपास का निर्यात १८८० में ८७३००० पूड़ से बढ़कर १९०० में ४९६०००० पूड़ और १९१३ में १,३६६७,००० पूड़ हो गया। उसके बाद की धरती मध्य एशिया

* व० व० बरतोल्द रचनाएँ, खण्ड २, भाग १, मास्को, १९६३, पृष्ठ ४२०-४२१। (रूसी संस्करण)

** वही पृष्ठ ४२४।

*** 'उज़बेकिस्तान के जनगणना इतिहास', ताशकन्द, १९५०, खण्ड २, पृष्ठ २६१। (रूसी संस्करण)

के कपास-क्षेत्र का केन्द्र बन गयी, यद्यपि कपास की खेती दक्षिणी किर्गिजस्तान तथा आधुनिक तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाकों में भी होती थी।

परन्तु कपास की खेती के विकास से देहकानों (किसानों) की भौतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब प्रधान दशिय पूँजी स्थानीय फर्मों के जरिये कपास की खेती के लिए वित्त प्रदान करने लगी तो एक नया शोषक सामने आ गया। कपास का खरीदार, जो उद्योगपति और कपास उत्पादक के बीच एक प्रकार के मध्यजन का काम करता, उनका शोषण करता था। देहकानों को जो ऋण लिया जाता था, उसके सूद की दर इन मध्यजनों के नाते बहुत ऊँची होती थी। मध्यजन निजी बका और कपास फर्मों से ८-९ प्रतिशत दर पर ऋण लेते और उसे कपास उत्पादकों को ४०-६० प्रतिशत सूद पर दिया करते थे।* अद्विकाश छोटे किसानों पर कज का इतना बोझ हो गया था कि यह जीवन भर अदा नहीं किया जा सकता था। अपना कज चुकाने के लिए उन्हें अक्सर बाई के हाथ अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी।

१९१४ में सरकारी आकड़ा के अनुसार फरगाना क्षेत्र में कुल किसान परिवारों में २५ प्रतिशत अपनी जमीन की बिनी या बंधक रखने के कारण भूमिहीन हो गये थे।** समरकन्द प्रदेश में कुल किसान परिवारों में ३५७ प्रतिशत और फरगाना में ५४५ प्रतिशत के पास अक्तूबर आति से पहले केवल एक देसियातीना जमीन थी। कपास की खेती के विकास के साथ कृषिक अयतन की विन्येयता बनी, जिससे गावों में प्रारम्भिक पूँजीवादी संघर्ष का दखन हुआ परन्तु उत्तरती श्रम का प्रयाग करनेवाले कपास के बड़े पूँजीवादी बागानों की उत्पत्ति नहीं हुई। मध्य एशिया में बटाई की व्यवस्था ही प्रधान व्यवस्था बनी रही।

*अ० ब० फिरोशेद्दीन '१९१२ में तुर्कमान क्षेत्र की यात्रा का विवरण, पृष्ठ १८। (रूसी संस्करण)

**उ० नपोमनिन, "उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, ताशकन्ट १९६० पृष्ठ ४०। (रूसी संस्करण)

तुक्कमान, किगिज और कजाय खानाबदोश तथा कराकल्पाको और भीतरी इलाके की पहाडियां में रहनेवाले ताजिका की सामाजिक संरचना की ध्यानपूर्वक खानवीन करने की आवश्यकता है। इन खानाबदोश लोगों में पितृसत्तात्मक कबायली सामाजिक संस्थाओं का अवशेष काफी प्रबल था। उनमें जटिल कबीला-कुल व्यवस्था का अस्तित्व से कुछ लेखकों को यह कहने का आधार मिल गया कि कबायली व्यवस्था २० वीं सदी के प्रारम्भ तक कायम थी। परन्तु वास्तव में इन लोगों में कबायली व्यवस्था कई सदी पहले नष्ट हो चुकी थी और १८ वीं और १९ वीं सतियों में उसकी सामाजिक संरचना में केवल उसकी परम्पराएँ रह गई थी। उनके खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश पशुपालन अथवा उनके कारण पितृसत्तात्मक परम्पराओं के अवशेष बहुत दिना तक बने रहे। तुक्कमानों में खान और बेंक, किगिजों में मानप* और बी और कुलक बाई जैसे शोषक वर्ग की प्रबल इच्छा थी कि पितृसत्तात्मक-कबायली परम्पराओं को कायम रख ताकि उनके द्वारा गरीबों के शोषण पर परदा पड़ा रहे। ऐसे समाज में जहाँ आर्थिक असमानता बहुत हो, चरागाहों भूमि और जल के समान स्वामित्व का कोई अर्थ नहीं हो सकता था। गरीब खानाबदोशों के शोषण का रूप यद्यपि पितृसत्तात्मक था मगर उसका सार फिर भी सामंती था।

तुक्कमानों में कृषि याग्य भूमि और पानी का बटवारा ग्रामीण समुदाय द्वारा हर साल होता था। उस रिवाज को सनानशिक कहा जाता था और इसका आधार था भूमि और पानी का समान कबायली स्वामित्व का यायिक भ्रम। कबीले के सदस्य नहरों की सफाई और युद्ध में अपने आजल (गाव) की रक्षा करते थे। इसलिए भूमि और पानी का बटवारा बड़ी आयु के लोगों में किया जाता था जो नहरों साफ करने और खोदने के योग्य हों और हथियार उठा सकें। आगे चलकर यह परम्परा बदल गई और भूमि और पानी में हिस्सा केवल कबीले के विवाहित सदस्यों को दिया जाता था। धनी खान बेंक और बाई लोग अपने छोटे बच्चों का भी विवाह कर देते थे और इस प्रकार उन्हें भूमि अपने हाथों में संकेंद्रित करने का अवसर

* मानप - कृषि योग्य भूमि तथा चरागाहों के धनी स्वामी।

मिल गया। इसके विपरीत गरीब तोग वध का ऊँचा दाम होने के कारण विवाह नहीं कर सकते थे, अधिकतर भूमिहीन होने जाते थे। चरागाहों का उपयोग कबायली परम्परा के अनुसार कबीले के सभी सदस्य कर सकते थे परन्तु कुआँ और कुड जिनके बिना पशुपालन नहीं हो सकता था, धनी लोगों के कब्जे में थे।

इसी प्रकार किगिज शापक वग भी अपने दरअसल सामंती शोषण पर परदा डालने के लिए कबायली पितृसत्तात्मक परम्पराओं का प्रयोग करते थे। चरागाह यद्यपि कबीले की सम्पत्ति थी मगर वास्तव में उनपर बौ और मानपो न अधिकार जमा रखा था, जा लोगों का सामंती शोषण किया करते थे। पशुधन बहुत थोड़े हाथों में केंद्रित हो गया था। इसकी पुष्टि एक छानबीन के नतीजे से भी होती है, जो पिस्पक उयेरद (जिला) में १९१२-१९१३ में की गई थी। कुल परिवारों में ५ ५२ प्रतिशत उच्च वग के मानपो, बौ और बाई लोगों के परिवार थे जिनके पास ३३ ५१ प्रतिशत पशु थे, जबकि ४९ २२ प्रतिशत परिवारों के पास केवल ११-१२ प्रतिशत पशु थे।* ४७ ७५ प्रतिशत परिवारों के पास खेती के औजार नहीं थे। इससे जाहिर होता है कि किगिज ग्रामीण समाज में वग भेद किस हद तक बढ़ चुका था। चरागाहों के समान प्रयोग तथा भूमि पर समान कबायली स्वामित्व के अनेक परम्परागत अधिकारों के बावजूद य भेद कम नहीं थे।

तुकिस्तान का प्रशासन गृह मन्त्रालय के नहीं, बल्कि युद्ध मन्त्रालय के अधीन था। जार द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उस क्षेत्र का सारा सैनिक और नागरिक प्रशासन उसने हाथों में केंद्रित था। बुजारा और खीवा के मामले में भी उसे बड़ा अधिकार था। स्थानीय अभिजात वग तथा सैनिक अफसरों में से वह ओब्लास्त और उयेरद के अधिवासियों को नियुक्त किया करता था।

* "मध्य एशिया और कजाखस्तान के जनगणना" भाग २, मास्का, १९६३, पृष्ठ १७८। (रूसी संस्करण)

ओब्लास्त प्रशासन का प्रधान सैनिक गवर्नर था, जिसके हाथों न सभी सैनिक और नागरिक मामले, यहाँ तक कि न्याय प्रशासन भी केंद्रित था। उयेस्द और नगर प्रशासन के प्रधान साधारणतः सैनिक अफमरो में से नियुक्त किये जाते थे। ओब्लास्त और उयेस्द स्तर पर सैनिक प्रशासन के अलावा जारशाही सरकार ने तयामित जननिर्वाचित ग्राम प्रशासन का भी उपयोग किया। थोलोस्त (चन्द गावों की निम्नतम प्रशासकीय इकाई) शासक तथा ग्राम अधिकारियों—स्तारशोना, आकसकल और क्लावी की नियुक्ति चुनाव के जरिये होती थी। परन्तु इन नियुक्तियों की मजूरी ओब्लास्त के सैनिक प्रशासक से लेनी पड़ती थी। ये नियुक्त किये गये अधिकारी उयेस्द शासकों के नियंत्रण में काम करते थे। अपने धन और प्रभाव का, क्योंकि केवल धनी लोग ही चुने जा सकते थे। अपना धन और प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए और सामान्य जमींदार हमेशा इन पदों पर कब्जा किये रहते थे। इन चुनावों में रिश्वत का भी बड़ा हाथ था, इसे काउंट पलेन ने तुकिस्तान की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में स्वीकार किया है।* इससे अलावा सैनिक गवर्नर को अधिकार था कि चुनाव के नतीजे बदल दे या चाहे तो थोलोस्त प्रशासक ग्राम स्तारशोना (प्रधान) और क्लावी को बिना किसी चुनाव के स्वयं नियुक्त कर दे। चूँकि इन निर्वाचित अधिकारियों तथा औपनिवेशिक प्रशासन का वगैरह एक ही था, यानी गरीबों का शोषण करना इसलिए उन्होंने एक दूसरे से अच्छी तरह सहयोग किया। निर्वाचित स्थानीय अधिकारी अपनी महानतकश जनता के खिलाफ रूसी उपनिवेशवादियों से मिल जाते थे। उससे तरह-तरह की बलपूर्वक वसूलिया तथा उसके विरुद्ध अधिकार का दुरुपयोग रोजमर्रा की बात थी। प्रार० पियस लिखता है कि अधिकार उयेस्द अधिकारी "स्थानीय लोगों से अतिरिक्त कर वसूल करते थे जिससे न केवल सामान्य पच ही पूरा होता था, बल्कि व आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे"।** यूरोपीय

* व० क० पलेन "तुकिस्तान क्षेत्र की निरीक्षण रिपोर्ट। ग्रामीण शासन", सेट पीटसबग १९१० पृष्ठ ६७-१०३। (रूसी संस्करण)

** प्रार० पियस, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०।

रूस का सैनिक प्रशासन अपन सबसे खराब अफमरो से मुक्ति पान क
लिए साधारणत उह तुकिस्तान भेज दिया करता था।”*

खीवा और बुखारा के खान प्रशासन सामती निरकुश बादशाही का
नमूना थे। खान और अमीर को अपनी प्रजा पर जीवनमरण का पूरा
अधिकार था। वे जमीदार अभिजात वग तथा मुल्लाओ को सत्रिय सहायता
स उनपर शासन करते थे। खीवा का खान शासित प्रदेश २२ बेकदारियों
में बटा हुआ था और बुखारा का २६ हाकिमदारियों में। बेकदारों का
प्रधान बेक होता था और हाकिमदारी का प्रधान हाकिम, जिनको खान
और अमीर नियुक्त करते थे। यह अधिकारी मनमान ढंग से अनक छात्र
अधिकारियों की सहायता से शासन करते थे।

अगरचे जारशाही जान-बूझकर मध्य एशिया को अपना कृषिक वच्च
सामान का स्रोत बनाये रखना चाहती थी पर अपन सैनिक और रणनीतिक
हितो और रूसी पूजीपति वग के सक्ती हितो से मजबूर हाकर उसे ३,३७७
किलामीटर रेलव लाइन और १४ रेलवे मरम्मत वकशाप और टिपा बनाने
पडे, जिनमे सब मिलाकर लगभग २४,००० मजदूर काम करते थे। मध्य
एशिया में रेलवे का निर्माण पिछली सदी के नव दशक के मध्य में शुरू
हुआ। १८८८ में समरकंद का रेल द्वारा त्रास्नोवोदस्क से १८९८ में
अदीजान से और एक साल बाद ताशकंद से जोड दिया गया था। १९०६
में ताशकंद को एक शाखा लाइन के जरिये आरेनवुग से मिला दिया गया
था। रेलवे के निर्माण से मध्य एशिया के भीतर विभिन्न इलाको के आर्थिक
अलगाव का और पूर मध्य एशिया के अलगाव का भा अत हाने लगा।
परंतु विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्नी एकत्रीकरण पर रेलवे का प्रभाव अभी
नगण्य था। फिर भी यह एक नयी परिघटना थी जिससे इस क्षेत्र के
भविष्य के लिए नयी सम्भावनाएं उत्पन्न हो गई।

रूसी पूजीपति वग का इस इलाके में वच्च माल की तयारी का उद्योग
विकसित करना पडा। यह उसके अपन हित के अनुसार था और उसे
उससे प्रतियोगिता का कार्द खतरा नहीं था। कपास आटाई, तल, साबन,

वग की उत्पत्ति धनी बाई लोगो, साहूकारो और व्यापारियो से हो रही थी, परंतु अभी वह कमजोर था और अपने बड़े उद्योग नहीं स्थापित कर सकता था। इसलिए उसने रूसी पूँजीपति वग पर अपनी निर्भरता का स्वीकार कर लिया। मध्य एशिया की जातियो मे केवल उज्बेक और कजाख मे राष्ट्रीय पूँजीपति वग की उत्पत्ति हो चुकी थी, किगिज़, ताजिक और तुक्मान मे इसका कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। औद्योगिक सवहारा भी सख्या की दष्टि स कम था। उज्बेको मे भी जहा इसका सख्या दूसरी जातियो की तुलना म अधिक थी, पूरी आबादी मे यह नगण्य था। ताति स पहले केवल १२,७०२ उज्बेक औद्योगिक मजदूर थे।* जहा तब तुक्मानो किगिज़ा और ताजिको का सवाल है, उनके पूँजीवाद विकास का स्तर और कम था। किगिज़स्तान मे कोई उल्लेखनीय राष्ट्रीय पूँजीपति वग नहीं था और सभी खनन उद्योग रूसी और तातार पूँजीपतियो के हाथ मे थे। किगिज़ मजदूरों की सख्या १९१३ मे केवल ११४४ था।** तुक्मानिस्तान म औद्योगिक विकास केवल ट्रासकास्पियन इलाके तब सीमित था और तुक्मान मजदूरों की सख्या कम थी। १९१६ मे केवल २४२ तुक्मान औद्योगिक मजदूर थे जिनमे निपुण केवल सात थे।*** ताजिकिस्तान मे कोई आधुनिक उद्योग नहीं था और वर्तमान लेनिनाबाद इलाके के उत्तर मे कपास शोधन और तेल और कायला खनन के जो छह छोटे उद्यम थे, उनमे केवल २०६ ताजिक औद्योगिक मजदूर काम करते थे।****

अतः ताति से पहले मध्य एशिया की अथ व्यवस्था ऐसी अथ व्यवस्था थी जिसपर सामंती उत्पादन-संबन्धों का प्रभुत्व था। लेनिन ने कहा कि तुकिस्तान उन दशों म था, जो पूँजीवादी विकास के रास्ते पर उन्नति नहीं कर सके थे और जहा "औद्योगिक सवहारा" किसी महत्व का नहीं

*म० बहादुर उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४५।

** "सावियत सघ मे समाजवादी जातियो का निर्माण", मास्को, १९६२ पृष्ठ ४९९। (रूसी संस्करण)

*** वही, पृष्ठ ५९७।

**** अ० अ० गोदियेका, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ २४।

था। लेकिन हमारा मतलब यह नहीं कि ~~कोई व्यक्ति~~ मध्य एशिया में पूजावादी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ था। ~~यदि यह था~~ कि यह हुआ पूजावादी विभाग की पूरी प्रक्रिया में ~~कोई सुधार था~~ और भी वह रेखा तथा कृषि बच्चे सामान के ~~प्रक्रिया~~ प्राथमिक यंत्रणा की उत्पत्ति का बोलना पूजावादी विभाग के ~~कोई~~ दर प्रत्यक्ष रूप से था।

भारताचा जननिवर्तनासाठी मला बहूत प्रयत्न करावे लागले. मला माहित होते की
 को सोना का स्वास्थ्य रक्षा की विधि नहीं, मैं सोना न खाऊँगा।
 विकास की। तुम्हारा म बंदर २१० मीटर म जो मगलम मय।
 सब शहरों म काम करूँगे। मैं न मगलम का निर्माण भी पाऊँ
 सुविधा रहा पा। बहूत प्रयत्न म मगलम म मगलम म निर्माण निर्माण
 सेवा का कोई प्रयत्न ही नहीं किया म सोना न खाऊँगा म मगलम म मगलम
 नीमूनीमों और पाणीमों के निर्माण म मगलम म मगलम म।

पिप्पा व क्षेत्र में स्थिति का केन्द्र = ३. उत्तर दिशा में ११११ मी. गतिमान
 के राज्य-वर्ग का केन्द्र = ३. उत्तर दिशा में ११११ मी. गतिमान
 किया जाना था और ३. उत्तर दिशा में ११११ मी. गतिमान
 प्रशासकीय कानून के लिए निर्धारित है। ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 ११११ राजकाय पिप्पा क्षेत्र में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उत्तर दिशा में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 और खावा मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 की मन्ना ४० मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 सुमानों में ०. ३ उत्तर दिशा में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 ब्रह्मपात्रों में ०. ३ उत्तर दिशा में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 और खावा मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 और चित्रों में ०. ३ उत्तर दिशा में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.
 सुमानों का ०. ३ उत्तर दिशा में ११११ मी. ११११ मी. ११११ मी.

सांस्कृतिक विकास

औपनिवेशिक काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता है, यद्यपि आम तौर पर यह सांस्कृतिक पिछड़ेपन का काल था। तुर्किस्तान में लौकिक स्कूलों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थानों का खुलना बहुत महत्वपूर्ण था। पहला रूसी स्कूल समरकन्द में १८७० में खुला।* तत्कालीन गवर्नर-जनरल काउफमन ने इस बात का बहुत महत्व दिया कि स्थानीय लोग अपने बच्चा को रूसी स्कूल में भेजे, जहाँ लौकिक तथा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु रूसी स्कूलों में बहुत कम स्थानीय विद्यार्थी गए। ज्यादातर वेप वीरते गये उनकी लोकप्रियता और कम होती गई। इसका कारण यह था कि रूसी छात्रों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, परन्तु मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था।**

स्थानीय छात्रों का स्कूलों में आकर्षित करने के लिए एक और तरीका मिश्रित रूसी-स्थानीय स्कूलों की स्थापना था। ऐसा एक स्कूल ताशकन्द में दिसम्बर १८८४ में एक धनी उज्बेक सैन्य गनी की पहलवदमी पर स्थापित किया गया।*** १९११ तक १०५ ऐसे स्कूल कार्यरत हो चुके थे। स्कूल का पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा था, यानी रूसी भाषा और गणित शास्त्र आदि, जो रूसी शिक्षक पढ़ाता था, और मुस्लिम धार्मिक शिक्षा मुफ्त दिया करता था।****

स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन में ये नयी गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। रूसी संस्कृति के प्रभाव में पुराने स्कूलों के सुधार का स्थान पैदा हुआ, ताकि उन्हें जीवन की नयी स्थितियों के अनुरूप बनाया जाय। नये स्कूलों को नयी प्रणाली के स्कूल कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अध्ययन की धार्मिक प्रणाली अपनायी थी। इस उसूल ए जदीद (नये उसूल)

* व० व० वरतोव, रचनाएँ, खण्ड २ भाग १, पृष्ठ २६६।

* वही पृष्ठ ३०२।

* वही पृष्ठ ३०५।

*** 'उज्बेकिस्तान के जनगणना का इतिहास' खण्ड २, पृष्ठ ३२६।

भूगोलविद, भूविज्ञ तथा जीवविज्ञानी आये, जसे उदाहरण के लिए, प० प० सेम्योनोव तियानशानस्की नि० अ० सेवेत्सोव, अ० प० फेचनको, इ० व० मुष्वेतोव, ग० द० रोमानोव्स्की वगैरह। य० व० बरतोव और न० इ० वेसेलाव्स्की ने मध्य एशिया के इतिहास और सस्कृति के बारे में बहुमूल्य सामग्री जमा की तथा उसका अध्ययन करने में अग्रणी भूमिका अदा की। ताशकंद में १८७० में एक सांजनिक पुस्तकालय खोला गया जिसके लिए सेट पीटसवग और मास्को की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं ने तथा अनक रूसी विद्वानों ने पुस्तकें दान की। अ० प० फेचनको की पहलकदमी पर १८७१ में ताशकंद में एक संग्रहालय आयोजित किया गया था। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का मुद्रण भी उस इलाके के जीवन में एक महत्वपूर्ण नयी घटना थी। रूसी विद्वानों की पहलकदमी पर भूगोल मानव विज्ञान पुराविद्या, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक वैज्ञानिक संस्थाएँ संगठित की गईं। इन सब बातों से मध्य एशिया के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में अवश्य ही योगदान मिला।

इन गतिविधियों का स्थानीय बुद्धिजीवियों पर प्रबल असर पड़ा और स्थानीय लोगों में बौद्धिक जागरण तेजी से फैला। प्रगतिशील रूसी संस्कृति के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क से उनमें नये लौकिक ज्ञान की आकांक्षाओं की प्रोत्साहन मिला और इसके अध्ययन के लिए उनमें शीघ्र ही एक आन्दोलन चल पड़ा। नयी सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए इस आन्दोलन को अक्सर भ्रामक रूप में जदीदियत से जोड़ दिया जाता है। जदीदियत का यह मूल्यांकन कि वह स्थानीय बुद्धिजीवियों का प्रगतिशील आन्दोलन था इस ऐतिहासिक गलतफहमी का नतीजा है कि २० वीं सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया में ज्ञान प्रसार का जनवादी आन्दोलन लुप्त हो चुका था और उसका स्थान जदीदियत ने ले लिया था। इसके अलावा कुछ अनुसंधानकर्ता जदीदियत को प्रगतिशील आन्दोलन के रूप में इसलिए भी समझन लगे हैं कि अनेक देशों में जिन्होंने हाल ही में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त की है, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय

था। कुछ मुद्दत में एक विचारधारात्मक तथा राजनीतिक आन्दोलन की रचना हुई, जिसमें ऐतिहासिक साहित्य में जदीदियत का नाम पाया। प्रसिद्ध सोवियत उज्बेक इतिहासकार म० ग० वहाबाव के शब्दों में 'जदीदियत औपनिवेशिक मध्य एशिया के स्थानीय पूजोपति वर्ग का राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में उत्पन्न हुई।' उनके अनुसार "इस विचारधारा की उत्पत्ति मजदूरों के नातिकारी आन्दोलन तथा जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के दौर में हुई, जब स्थानीय पूजोपति वर्ग ने आम जनता से नाता तोड़ लिया और जारशाही तथा रूसी पूजोपति वर्ग का समर्थन करने लगा।"*

मध्य एशिया की पूजोवादी राजनीतिक विचारधारा का जिस चोखने में एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों की राजनीतिक विचारधारा से अलग किया वह मध्य एशिया की विशेष औपनिवेशिक परिस्थिति था। एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में पूजोवादी राजनीतिक विचारधारा का विकास ऐसी स्थिति में हुआ, जब मजदूर आन्दोलन कमजोर था, परन्तु मध्य एशिया में जो जारशाही रूसी साम्राज्य का अंग था, स्थानीय और रूसी दोनों ही पूजोपति वर्ग रूसी मजदूर वर्ग के शक्तिशाली आन्दोलन से भयभीत थे। इसमें अलावा मध्य एशिया में राष्ट्रीय पूजोपति वर्ग इतना निबल था कि कोई स्वतन्त्र भूमिका नहीं अदा कर सकता था। वह केवल साम्राज्यवादी रूसी पूजोपति वर्ग के एजेंट का काम करता था।

१९०५-१९०७ की क्रांति के वर्षों में जदीदियो का कायकलाप व्यापक रूप से पता हुआ था। १९०६ में १९०९ तक उन्होंने कई पत्र प्रकाशित किये जिनमें 'तरक्की', 'खुरशेद' 'शोहरत' और 'एशिया'। जदीदी अखबारों ने सब-नुक़्दाद तथा सब इस्नामवाद का प्रचार किया और प्रभावशाली व्यापारियों और ब्राई लोगो को इस्तेमाल करके जनगण को

* म० वहाबाव जदीनियत का प्रतिनिध्यावादी चरित्र तथा जन विरोधी भूमिका - महान अकनूवर समाजवादी क्रांति में पूरे तथा इसके दौरान में जातीय प्रश्न (सांख्यिक विज्ञान अकादमी की वार्षिक सम्मेलन की बैठक के लिए लखनऊ-सम्मेलन), पहला भाग मास्को, १९६४ पृष्ठ ५०-५३। (रूसी संस्करण)

इस प्रकार तले इकट्ठा करने का प्रयास किया। जदीदी अखबार जनगण का मुसोबतो, श्रमजीवी किसानों और कारीगरों की बढ़ती हुई दरिद्रता, बाई लोगों तथा साहूकारों द्वारा उनके शोषण तथा औपनिवेशिक प्रशासन का मनमानी धावली के बारे में कुछ नहीं लिखा करते थे। परन्तु लोगों को तो ठीक यही सवाल विचलित कर रहे थे। इस लिए कोई आश्चर्य नहीं कि जदीदी अखबारों का जनगण में कोई प्रभाव नहीं था। १९१६ के विशेष के समय जदीदियों ने जनगण का विरोध किया, ज़ारशाही सरकार ने तामबन्दी अभियान का समर्थन किया। उन्होंने जनता को अपना विरोधी बना दिया, जो उनकी प्रतिक्रियावादी भूमिका को समझने लगी थी।

यह सही है कि धार्मिक तथा सामंती तत्वों के मुकाबले में जदीदियत में कुछ उदारवादी प्रवृत्तियाँ थीं। जदीदी नई यरापीय संस्कृति का समर्थन तथा पुरानी सामंती प्रणाली का विरोध करते थे। यह बात उनमें और अन्य प्रबुद्ध जनवादियों में समान रूप से पायी जाती थी। परन्तु इन दूसरों के विपरीत वे समस्त जनता के हितों की रक्षा नहीं करते थे। वे अपने वग—पूजोपति वग के हितों—का समर्थन करते थे। धार्मिक तत्वों के विरुद्ध सधम में भी वे दृढ़ सैद्धांतिक स्थिति पर जमे नहीं रहे। बल्कि वे इस्लाम के उसूलों का राष्ट्रीय पूजोपति वग के हितों के अनुकूल बनाना चाहते थे।

जदीदियों को राष्ट्रीय स्वाधीनता आति का बौद्धिक अग्रदूत कहना गलत होगा। उनका उदारवाद भी ऐसी अवस्था से संबध रखता था, जिसमें मध्य एशिया के लोग आगे बढ़ चुके थे। वे अब सबहारा आति के द्वार पर खड़े थे। औपनिवेशिक भारत में राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित ब्रह्म समाज आन्दोलन से, जो सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का आन्दोलन था, जदीदियों की तुलना करना बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि भारत और मध्य एशिया का ऐतिहासिक विकास भिन्न था। राजा राम मोहन राय प्रगतिशील समाज-सुधारक और प्रबुद्ध जनवादी थे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक उदारवादी विचारों का प्रचार उस समय किया, जब समाज के आतिवारी रूपांतरण की शक्तियाँ भारतीय राजनीति के मंच पर नहीं आयी थी। परन्तु जब वेय बुदी ने मुसलमानों से अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने और सामाजिक

के विरुद्ध वैधानिक सम्राटवादियों का समर्थन करने की अपील की, ता वह मात्र सुधारक तथा शिक्षा प्रचारक नहीं रहा, बल्कि सक्रिय प्रतिक्रियावादी हो गया। जदीदी नेताओं ने मेहनतकश जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि "मुस्लिम कौम" यानी सारे मुसलमान एक हैं और उनके विभिन्न वर्गों में कोई भेद नहीं है। यह वे ऐसे समय कर रहे थे, जब वर्गीय विरोध दिनोदिन तीव्र होते जा रहे थे और क्रांतिकारी परिस्थिति तेजी से विकसित हो रही थी। यह नई क्रांतिकारी ऐतिहासिक परिस्थिति और इसमें उनकी प्रतिक्रियावादी भूमिका मध्य एशिया के जदीदियों को भारतीय समाज-सुधारकों से जुदा करती है।

मध्य एशिया की जातियाँ के सामाजिक और वर्गीय ढाँचे तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास स्तर के बारे में ऊपर की बहस का खुलासा करते हुए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बावजूद इसके कि औपनिवेशिक काल में उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये थे, जैसे उदाहरण के लिए, नये शहरों का जन्म, रेलवे का निर्माण, कृषि में पूँजीवादी संस्था की उत्पत्ति, हल्के पूँजीवादी उद्योग की उत्पत्ति और एक आम बौद्धिक जागरण। फिर भी पूँजीवाद पूर्व संस्थाओं का प्रभुत्व, सांस्कृतिक पिछड़ापन और अनानता तथा इसलाम का प्रभुत्व रह गया था। परन्तु सामंतवादियाँ, मुल्ताओं और नवजात राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग से जनता का विलगाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। यह विशेष रूप से १९०५-१९०७ में मजदूरों के क्रांतिकारी आन्दोलन के समय और आगे चलकर १९१६ में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के सक्रिय दौर में और बाद के वर्षों में स्पष्ट हो गया था। १९१७ का फरवरी आति के बाद के दौर में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया।

राष्ट्रवादी तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन

औपनिवेशिक काल में जारशाही शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोह और बगावत हुई। परन्तु उन सभी को राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन कहना सही नहीं होगा। इन संस्था में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक शासन के प्रारम्भिक वर्षों में लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में

अनेक प्रगतिशील परिवर्तन हुए। खान-दुशामन की निरकुशता और खुली लूट-छमाट के तारीफ़ दिना के बाद जनगण ज़ारशाही शासन की लाई हुई नई तब्दीलियाँ को पसन्द किये बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए जब सामंती और धार्मिक नेताग्रा ने ग़सबवात या धार्मिक युद्ध के प्रतिक्रियावादी नारे के तहत खान प्रशासन को बहाल करने का धार्मिक-राष्ट्रवादी आन्दोलन खड़ा किया, तो जनगण ने उनका साथ नहीं दिया।

१६वीं सदी के आठवें और नव दशकों में फरगाना घाटी में “नवली खाना” ने ऐसे विद्रोहों को भड़काने का प्रयत्न किया। इन विद्रोहों का समयन केवल कुछ अधिकारप्राप्त सामंतवादियाँ और मुल्लाग्रा न किया, जिनके विशेषाधिकारों पर ज़ारशाही प्रशासन की कुछ बारवादियाँ से चोट पड़ती थी। १८८५ में दरवेश खान तियुरा ने खान शासन की बहाली के लिए आन्दोलन चलाया। उसके साथ मोमिनवाई आ मिला, जिसने फरगाना क्षेत्र में एक सशस्त्र दस्ता संगठित किया। ज़ारशाही सेना ने इस विद्रोह को आसानी से कुचल दिया। दरवेश खान भागकर काशगर चला गया और मोमिनवाई गिरफ्तार हो गया।

दरवेश खान के विद्रोह को जन-समयन नहीं प्राप्त था। इसी तरह मदाली ईशान का विद्रोह या तय्यारखित अदीजान बगावत भी जनप्रिय आन्दोलन नहीं था। मदाली ईशान बुखारा का रहनेवाला था जहाँ उसने अध्ययन किया और कुछ दिन अमीर की चाकरी की। आठवें दशक के प्रारम्भ में वह अदीजान आया और यहाँ उसने जैसे-तैसे करके बहुत धन अर्जन कर लिया और अपने मुरोदों या चेनो के ज़रिये कुछ स्थानीय प्रभाव भी हासिल कर लिया। ईशान मिग-तेपे गाँव में बस गया, जहाँ उसने एक धार्मिक समुदाय की स्थापना की। परन्तु साधारण लोगों से उसका दूर का भी संबंध नहीं था और उसके चले अधिकतर सामंती क्षेत्र के लोग थे। रूसियों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध का जो नारा उसने १७ मई, १८६८ का दिया, उसका लोगों ने समयन नहीं किया और जब उसने अदीजान पर घावा किया, तो वह मात्र १००० आदमियों से अधिक को साथ नहीं ला सका। उसके विद्रोह का बिना किसी बठिनाई के कुचल दिया गया और वह पहाड़ों में भाग गया। औपनिवेशिक प्रशासन ने इसके

बाद बड़ा अत्याचार किया। वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन से लोगों का भयभीत करके अपना ताबेदार बनाना चाहता था। तोपा की गालाबार से मिग-तेपे को मटियामट कर दिया गया और मदाली ईशान के २०५ अनुयाइयों को मार डाला गया।

जारशाही शासन के विरुद्ध इन प्रारम्भिक विद्रोहों का वास्तविक स्वरूप सोवियत ऐतिहासिक लेखों में बड़े बाद विवाद का विषय बना रहा है। “उज्बेकिस्तान के जनगण का इतिहास” के लेखकों में मदाली ईशान के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की सजा दी है।* “इज्वस्तिया” अखबार ने इस पुस्तक की समीक्षा की और मसलमान धर्मगुरुओं द्वारा निदेशित और साम्राज्यवादी शक्तियों के दलालों द्वारा उकसाय गये सामान्य राष्ट्रवादी विद्रोहों को जन नातिकारी आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत करने की कड़ी आलोचना की।

ऐतिहासिक घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन सप्ताह के सभी देशों में ऐसी प्रक्रिया है, जो बराबर जारी रहती है। यह बात उन घटनाओं और आन्दोलनों के बारे में खामखोर सही है जिनको हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है। सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण समय गुजरने पर ही होता है। यह सचचा नियमित प्रक्रिया है और सावधान्य इतिहास-लेखन काई अपवाद नहीं है।

निस्सन्देह एक समय ऐसा था, जब सोवियत इतिहासकार (उज्बेक और रूसी दोनों ही) रूस के साथ मध्य एशिया के विनयन के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील महत्त्व का कुछ कम करके आकते थे। यह कुछ हद तक अक्षुण्ण नाति के तुरत बाद के दौर का अनिवार्य नतीजा था, जब उस हर चीज की अवहेतना और निंदा की जाती थी, जिसका नातिपूय अतात से संवध था। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक सोवियत लेखकों में जारशाही शासन के विरुद्ध औपनिवेशिक काल के सभी आन्दोलन का स्वाधीनता का नातिकारी जन-संघर्ष बना कर पेश किया। तीसरे और चौथे दशकों के कई सोवियत लेखकों की श्रुतियाँ का हवाला दिया जा सकता है, जिन्होंने यह

* “उज्बेकिस्तान के जनगण का इतिहास”, ताशकन्द, १९६७, पृष्ठ १, पृष्ठ ३६८।

दृष्टिकाय अपनाया है। यू० फ्यादोरोव ने अपनी पुस्तक* में औपनिवेशिक काल के सभी आन्दोलनों को, उनका भी, जिनका नेतृत्व मुस्लिम धार्मिक गुरु कर रहे थे और जिनको कोई जन-समर्थन प्राप्त नहीं था, एक ही शीर्षक "राष्ट्रीय धार्मिक मुक्ति आन्दोलन" के अन्तर्गत जमा कर दिया है। उहान १८६८ के अन्दोजान विद्रोह को भी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन बताया है। ५० ग० गलुजो ने अपनी पुस्तक** में जारशाही शासन के प्रति हर विरोध का आपस बंद करके राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष माना है, जिसमें उन्होंने पन शताब्दी के चौथे दशक में सुलतान बेनिस्सारी के विद्रोह, १८६८ में समरकन्द में विद्रोह, शहरिस्मन्द बेकशाही के विद्रोह, १८७५ और १८७६ बकान में विद्रोह, ताशकन्द में १८९२ में हैजा उपद्रव, १८९८ में मदाली रैशान के विद्रोह से लेकर १९१६ के विद्रोह तक को जोड़ लिया है।

यह दृष्टिकोण उस समय सोवियत इतिहास लेखन में आम था और इसका कोई संघर्ष कुछ उल्लेख लेखकों के "पूँजीवादी राष्ट्रवादी भटकाव" से नहीं था, क्योंकि फ्यादोरोव और गलुजो उल्लेख नहीं हैं। यह ऐसे दौर की पैदावार था, जब अतीत की संपूर्ण निंदा करने की प्रवृत्ति हावी थी। "उज्बेकिस्तान के जनगण या इतिहास" ने इस परम्परा का ऐसे दौर में जारी रखा, जहाँ सोवियत इतिहासकारों से अतीत की पन्नाओं के अधिन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की आशा की जाने लगी थी और वही लिए "इज्वेस्निया" ने सही ही इसकी आलोचना की। यहाँ यह बता दिया जाये कि इस दृष्टिकोण की आलोचना उस प्रारम्भिक दौर में भी की जा रही थी, जब उसे अधिकृत दृष्टिकोण माना जाता था।***

* यू० फ्यादोरोव, "मध्य एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का विवरण", ताशकन्द, १९२५, पृष्ठ १४-१८। (रूसी संस्करण)

** ५० ग० गलुजो, "तुकिस्तान-उपनिवेश", ताशकन्द, १९३५। (रूसी संस्करण)

*** दे० ५० अलोपाव, "मध्य एशिया के नातिकारी आन्दोलन के इतिहास और पाठियों के प्रारे में क्या और किम तरह पढ़ना है", समरकन्द-ताशकन्द, १९२६, पृष्ठ ३०। (रूसी संस्करण), ग० तुकिस्तानरकी द्वारा लघु 'काम्मुनिस्तीचेस्वाया मीस्न' में, १९२७ अंक ३, पृष्ठ १६०-२२२। (रूसी संस्करण)

जारशाही के विरुद्ध आंदोलना का वर्तमान सोवियत मूल्यांकन "महान रूसी अधिराष्ट्रवादी भटकाव" का नतीजा नहीं है, जैसा कि रिचर्ड पाप्स और सीटन वाट्सन हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। पाइप्स ने मध्य एशिया पर रूसी कब्जे की प्रगतिशील भूमिका पर हाल में जोर देने का "सोवियत उपनिवेशवाद" विषयक गोष्ठी में मध्य एशियाई जातियों के "रूसीकरण" का "इतिहास लेखन सबधी पहल" घोषित किया है। सीटन वाट्सन ने सोवियत इतिहासकारों के तर्कों के बारे में कहा है कि यह "गार आन्नी के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का नकली मार्क्सवादी रूप है, जिसे किपलिंग समझ लेता"।* लेकिन इन दावा में रस्ती भर सच्चाई नहीं है। मध्य एशिया पर जारशाही के कब्जे के प्रगतिशील चरित्र के बारे में सोवियत इतिहासकारों का हाल का विचार अच्छी तरह सोचा-समझा हुआ विचार है, जो कुछ अतिशयास्तियों के बावजूद तथ्यों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित है।

वह दृष्टिकोण, जो जारशाही के विरुद्ध सभी आंदोलनों को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में मानता है, सही नहीं है, क्योंकि वह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि इन सभी आंदोलनों में से कुछ को छोड़कर, जैसे १८६२ में ताशकन्द में हैजा उपद्रव और १९१६ का विद्रोह, किसी में भी जनता ने भाग नहीं लिया। सुलतान केनिस्मारी के विद्रोह का कजाखों का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि शुरू में केनिस्मारी ने अनेक कजाख खानाबदोशों को इकट्ठा कर लिया था, परंतु उसका सामंती चरित्र समझ लेने के बाद वे उससे अलग हो गए और वह अंत में जार के रूसी सैनिकों से नहीं, बल्कि किगिजा से लड़ने हुए मारा गया। बुखारा की राजगद्दी के लिए शहरिमन्ज के बेका के पड़ोसियों का तथा जारशाही शासन के विरुद्ध धार्मिक युद्ध के नारे के तहत लोगो का उभारने के लिए मुस्लिम मुत्तावा और रईसों के नाकाम प्रयत्नों को जसा कि उन्होंने १८७५ और १८७६ में बोकान में, १८८५

म फरमाना म और १८६८ म अदीजान मे बिया था, राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन कहना ऐतिहासिक तथ्यों को बिगुल ताड़-मराड कर पेश करना है।

मध्य एशिया म औपनिवेशिक काल मे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के बारे म कुछ सामान्य टिप्पणियों से शायद उस आन्दोलन को स्यादा अन्धी तरह समझना आसान हो जायेगा। खान प्रशामन काल मे मध्य एशिया के लोग आपस के बिनाशकारी युद्धो से ऊब गये थे। इसलिए प्रारम्भ म उन्होंने जारशाही द्वारा ऐसे शासन की स्थापना का स्वागत किया, जिनमे अदरुनी मुख्यवस्था और व्यक्ति की सुरक्षा कायम की। ताशकन्द पर, यह पाद रहे, दो हजार रूसिया ने दबल किया था। वेकन तुक्मान बवाता ने जारशाही बच्चे का घोर विरोध किया था।

मध्य एशिया पर जारशाही का अधिकार ब्रिटेन के साथ तीव्र प्रतिद्विधा के वातावरण म हुआ जिससे मजदूर हाकर जारशाही को मध्य एशिया की जातियों के प्रति मावधानीपूर्ण नीति अपनानी पडी। यहा जारशाही ने इमलाम के मामले मे हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया। मध्य एशिया के मुसलमानों में काम करने मे ईसाई मिशनरिया को रका गया। परन्तु १९वीं सदी के अंत म जब आग्ल रूसी प्रतिद्विधा की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी, तो परिस्थिति बदली और जारशाही की नीति का दमनकारी दौर शुरू हुआ। परन्तु सदी के अंत मे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का उभार उठी हद तक मध्य एशिया म पूँजीवादी सबघा का उत्पत्ति के कारण हुआ जिससे श्रमजीवी जनगण की दग्धिता बढ गई और उनकी राष्ट्रीय चेतना जग गयी। अब आर्थिक दृष्टि मे तबाह देहकान और गरीब कारीगरों ने राजनीतिक क्रियाकलाप के क्षेत्र मे प्रवेश किया। ताशकन्द म हैजा उपद्रव और पूरे तुकिस्तान म १९१५ का बिद्रोह इसी दौर से सबध रखते है।

उन दाना आन्दोलनों को पूर औचित्य के साथ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनगण का मुक्ति-संग्राम कहा जा सकता है। हाल की सभी भाविमत ऐतिहासिक कृतिया म इन्हें इस रूप मे स्वीकार किया गया है। इस भूपाकन मे धम के प्रति विराध का कोई हाथ नहीं रहा है। सभी

सोवियत लेखकों ने ताश्कन्द में हैजा उपद्रवों को धार्मिक तत्वों के शराब होने के बावजूद जन आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया है। मार्क्सवाद ने हमेशा यह स्वीकार किया है कि किसानों पर धार्मिक अत्याचार करने से धार्मिक नारों के तहत मुक्ति सघर्ष शरू हो जा सकता है। इस संबंध में यह याद रहे कि मार्क्स ने हुस्साइट युद्धों को "धार्मिक झंडे तले चक किसानों का राष्ट्रीय युद्ध" * कहा था। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया था, जारशाही ने तुर्किस्तान में धार्मिक अत्याचार की नीति नहीं अपनाई थी। इसलिए मध्य एशिया की जातियों की राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम में धर्म ने कोई भूमिका अदा नहीं की।

१९वीं सदी के अंत में मध्य एशिया के किसानों ने जारशाही के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी राजनीतिक कारवाही शुरू की। उस क्षेत्र के ग्रामीण अर्थतंत्र में पूँजीवाद के प्रवेश के कारण देहकानों की स्थिति बिगड़ गयी थी। दरिद्र किसानों ने औपनिवेशिक शासन के तहत अपना दयनीय स्थिति के प्रतिरोध के रूप में धनी लोगों और औपनिवेशिक अधिकारियों पर छापा मारना शुरू किया। फरगाना, समरकन्द और सिर-दरिया के तीन ओब्लास्तों में, जहाँ औपनिवेशिक शोषण सबसे अधिक तीव्र था, कपास उत्पादक किसानों द्वारा ऐसे छापों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गई। १८८७ और १८९८ के बीच ६६८ ऐसे छापे मारे गये। फरगाना में, जहाँ किसानों की आर्थिक तबाही की प्रक्रिया सबसे तेज़ थी, किसान छापों की संख्या ४२९ थी। इस अवधि में समरकन्द में १८२ और सिर-दरिया क्षेत्र में ५७ छापे मारने की रिपोर्ट मिली। **

किसान आन्दोलन न पशासन के साथ मुठभेड़ का रूप भी लिया। १८८७ और १८९८ के बीच इस प्रकार की २५ मुठभेड़ों की सूचना मिली जिसमें ३४ अधिकारी उलझे हुए थे और इनके पत्र-स्वरूप २० हताहत हुए। सदी के अंत तक अधिकाधिक देहकान और खानाबदोश राज्याय स्वाधीनता तथा वग-सघर्ष में भाग लेने लगे। स्थानीय पशुपालक खानाबदोश

* व० मास्त और प्रे० एंगेल्स, पुगलेख-संग्रह १९३९ खण्ड ८ पृष्ठ ३-४। (रूसी संस्करण)

* प० ग० गलुजा "तुर्किस्तान-उपनिवेश", पृष्ठ ६०।

भी कुत्तों और कज्जाक बसनेवालों के विरुद्ध सघप के मैदान में उतर आये और उनके भवेशी पकड़ कर ले जाने लगे।

किसानों ने इस प्रकार का राष्ट्रीय सघप २० वीं सदी के प्रथम दशक में जारी रखा। किसानों के छापो को* जिनकी संख्या १९०५ तक धीरे-धीरे ही बढ़ी थी, १९०५ की नातिकारी उथल-पुथल से प्रोत्साहन मिला। १९०५ से १९०८ तक उनकी संख्या में ८३ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९०५ की नाति इस दृष्टि से मोड़-पिंडु साबित हुई। उसने देहकानों के राजनातिक सघप को सक्रिय बना दिया, जो उसके बाद खुले आम जारशाही औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। परंतु उनके आंदोलन का स्वरूप असंगठित और स्वतःस्फूर्त रहा। १९०५-१९०७ की नाति में स्थानीय सबहारा ने भी, यद्यपि उसकी संख्या कम थी, बड़ी राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की। १९०६ में जब हड़ताली रूसी मजदूरों की जगह स्थानीय जातियों के मजदूर भरती किये जाने लगे, तो वे भी स्वतःस्फूर्त ढंग से हड़ताल में शामिल हो गये। स्थानीय मजदूरों ने भी रूसी मजदूरों के साथ सभाया और प्रदर्शनों में भाग लिया। मास्को के दिसम्बर विद्रोह के असफल होने पर पूरे तुकिस्तान में घेराव की स्थिति घोषित कर दी गई और इस घोर दमन के दौरान में सामाजिक जनवादी संगठनों का बंद कर दिया गया। जन नातिकारी आंदोलन की नई लहर, जो रूस में १९१२ में शुरू हुई, तुकिस्तान के सैनिकों और मजदूरों को प्रभावित किये बिना नहीं रह सका। जुलाई १९१२ में ताशकंद में सैनिकों का शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोह हुआ। परन्तु इसे भी औपनिवेशिक प्रशासन ने कड़ाई से कुचल दिया। जारशाही के विरुद्ध मध्य एशिया की जातियों का एक जन राष्ट्रीय

* प० ग० गलुजो ने ३० जुलाई, १९२८ में 'प्राब्दा वोस्ताका' के पृष्ठ १७२ (१९६६) में प्रकाशित अपने लेख में तथा अपनी पुस्तक "तुकिस्तान-उपनिवेश" में घनी लोपा पर विमान छापो का उल्लेख किया था, मगर वह कभी भी 'रूमियो पर छापा' के बारे में नहीं बतलाने था, जसा कि अपनी मर्जी पर २० वैधानायन किया था। (R V dyanath *The Formation of the Soviet Central Asian*)

मुक्ति विद्रोह १९१६ में हुआ। इसमें मध्य एशिया की सभी जातियां न भाग लीं। साम्राज्यवादी युद्ध के फलस्वरूप मध्य एशिया का औपनिवेशिक शोषण और लूट अधिक तेज हो गई थी। जारशाही प्रशासन न पक्ष जवाब देकर और अतिरिक्त कर लगाये, जिसके कारण लोग की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। रूस से रोटी का आयात कम हो गया और इसलिए उसका दाम बढ़ गया। फसल नहीं होने से हालत और खराब हो गई और देश में अकाल फैल गया।

जारशाही के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन का अवसर २५ जन, १९१६ की आज्ञप्ति के जरिये मिल गया। यह आज्ञप्ति मोरचे के पीछे काम के लिए स्थानीय पुरुषों की लामबंदी के संबंध में थी। इससे जनगण में आक्रोश फैल गया। इसका कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा इस आज्ञप्ति पर अमल करने का ढंग था। धनी बाई लोग और समाज के अग्र समूह तत्तन रिश्तों देकर या अपने बदले किसी को रखकर सेवा से बच जाते थे। आज्ञप्ति का कड़ा धाम सारा का सारा गरीबों पर पड़ता था।

मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में देहकानों और शहर के गरीबों का विद्रोह स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरू होने लगा। नुद्ध लोगों की भीड़ ने बोलोस्त प्रशासन कार्यालयों पर धावा बोल दिया और मोरचे के पीछे सेवा के लिए भरती किये जानेवाले की सूचियां फाड़कर फेंक दी, कई अधिकारियों की हत्या भी की। आंदोलन आम तौर पर असंगठित था और उसका कोई समान नियंत्रण या आदेश-केन्द्र नहीं था। अधिकांश जिला में यह आंदोलन मनमाने जारशाही प्रशासन, औपनिवेशिक अधिकारियों और साथ ही स्थानीय बाई लोग तथा मामूली तत्त्वों के विरुद्ध था। बड़ी हद तक इसका राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष का प्रगतिशील स्वरूप था। परंतु कुछ जिला में सामन्ती और धार्मिक तत्त्व जमान और तुर्की के एजेण्टों से मिलकर इसे रंग विराधी रंग देने में सफल हुए। जिसके उद्देश्य, तंजें और गिरावट में आन्दोलन न यही रंग लिया।

१९१६ के विद्रोह का जारशाही न शस्त्र बल में बड़ी प्रतीति का साथ बुचल किया। विभिन्न साम्राज्यवादी के विरुद्ध दमन विशेष रूप से बढ़ा था। उनमें से कई तीन लाख जेलीखुज से चीन भाग गया। उनकी

जमीनें जब्त कर ली गई और रूमी बसनेवाला को दे दी गई। १९१६ के विद्रोह ने अपनी असफलता के बावजूद औपनिवेशिक क्षेत्र की जातियां के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन से सामतवाद विरोधी आन्दोलन में परिवर्तित हो गया। लामबंदी के विरुद्ध स्वतः स्फूर्त प्रदर्शनों से शुरू होकर उसने सशस्त्र संघर्ष का रूप धारण कर लिया। उसका उद्देश्य रूस से अलग होना नहीं था, बल्कि केवल राष्ट्रीय औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त करना था। आन्दोलन की शक्ति और उमकी व्यापकता मध्य एशिया में आतंकवादी परिस्थिति की परिपक्वता साबित कर रही थी। भरती हुए मजदूर और देहकान, जिन्होंने रूस में रहकर काम किया, रूसी बोल्शेविकों के प्रभाव से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गये और तुर्किस्तान में वापस आकर फरवरी और अक्टूबर आति के बीच के दौर में स्थानीय जनता के हिराबल दमने बन गये। उन्होंने मेहनतकश मुसलमानों की सोवियत सगठित करने में अग्रिम भूमिका अदा की।

१९१६ का विद्रोह विफल हुआ, मगर उसने मध्य एशिया के जनगण का आतंकवादी संघर्ष का बड़ा सबक दिया। इसने उन्हें विश्वास दिला दिया कि केवल रूसी सवहारा की सहायता से और केवल समाजवादी आति के जरिये के राष्ट्रीय और औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पूजीपति बग और पूजीवादी बुद्धिजीवियों के विश्वासघात ने, जो उस समय जारशाही साम्राज्यवाद की चाटुकारी कर रहे थे, जनता की आंखें खोल दी।

समाजवादी आति के लिए सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक पूर्वस्थितियों का परिपक्व होना

मध्य एशिया में समाजवादी आति सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक पूर्वस्थितियों की उपस्थिति के कारण फट पड़ी। कुछ लेखकों का कहना है कि मध्य एशिया में उत्पादक शक्तियां के अविकसित होने तथा वहां की जातियों के निम्न सांस्कृतिक स्तर के कारण ऐसी पूर्वस्थितियां नहीं थी।

वे यह रट लगाये जाते हैं कि स्थानीय लोगों में औद्योगिक सहारा का कोई बड़ी मय्या नहीं थी, जिसके बिना समाजवादी ताति की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सभी तर्कों का सार उनका यह दावा है कि मध्य एशिया में समाजवादी ताति की अपनी जड़ें नहीं थी और उसे रूसी बोल्शेविक रूस से लेकर आये।* रूस से समाजवादी ताति के "आयात" के संबंध में अपने ऐतिहासिक रूप से भ्रामक नतीजे पर पहुंचने में पश्चिमी लेखकों का सफारोव जैसे विगत सोवियत लेखकों से बहुत समथन मिला, जिन्हें एक समय पार्टी और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था।"

परंतु यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक वास्तविकता के विपरीत है। साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी ताति के लिए आवश्यक शर्तों का मौजदगी के सवाल पर विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के सदन में ही विचार किया जा सकता है, और सामंतविरोधी तथा राष्ट्रीय मुक्ति तातियाँ समाजवादी तातियाँ में विकास की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

तुकिस्तान के संबंध में सही दृष्टिकोण केवल इस विलगित दूरदर्शी

* A G Park *Bolshevism in Turkestan* New York 1957
R Pipes *The Formation of the Soviet Union*, Cambridge Mass 1954
W Kolarz *Communism and Colonialism*, London New York, 1964
H Seton Watson *The New Imperialism* London, 1964, Briand Krozier *Neo Colonialism* London 1964

** सफारोव के अभिनत तथा अवस्तुनिष्ठ विचारों के लिए देखिये उनकी पुस्तक "औपनिवेशिक ताति—तुकिस्तान का अनुभव", मास्को—लेनिनग्राद १९२१ (रूसी संस्करण)। इस लेखक की राय में फरवरी आति से पहले तुकिस्तान में 'तनिक भी फरा हमा तातिवार आदान' नहीं था (पृष्ठ ५३)। उनकी राय में फरवरी आति 'तार के जरिये' तुकिस्तान पहुंची (पृष्ठ ५४)। उनका दावा था कि तुकिस्तान में रूसी मजदूरों में 'आतिवारी विचारधारा कोई आतिवारी परम्परा नहीं थी' और कि उनमें और स्थानीय लोगों में कोई समानता नहीं थी। उनका कहना था कि तुकिस्तान में सभी रूसी मजदूरों और वहाँ राजकारण के अधिपत्य का 'याम औपनिवेशिक रूप' था (पृष्ठ ७१) पश्चिमी दशा में सफारोव का हवाला याम तोर पर दिया जाना है।

क्षेत्र में समाजवादी क्रांति की आवश्यक शर्तों के विश्लेषण तक ही सीमित नही रह सकता, बल्कि उसे पूरे देश के सदम में देखना होगा। जारशाही उपनिवेशवाद के विरुद्ध मध्य एशियाई जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को ध्यान में रखना होगा, जो हर साल रूस में मजदूरों के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रत्यक्ष अनुपात में और मुख्यतः उसके प्रभाव के तहत तीव्र और व्यापक हो रहा था। फिर, वस्तुनिष्ठ सामाजिक आर्थिक तत्वा के अलावा आत्मनिष्ठ तत्व की भूमिका का भी ध्यान रचना होगा।

रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन की बदौलत यह सम्भव हुआ कि समाजवादी क्रांति की सामाजिक आर्थिक पूर्वस्थितियों का विकास तेजी में हो। औपनिवेशिक काल में पूँजीवादी संघर्षों की उत्पत्ति से बग विरोध और तीव्र हुए। इसके फलस्वरूप मध्य एशिया में अंत में समाजवादी क्रांति की विजय हुई। तुर्किस्तान में क्रांति से पहले की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादक शक्तियों के विकास को ही नहीं बल्कि बग-संघर्ष की परिस्थितियों को राष्ट्रीय उत्पीड़न की तीव्रता आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। समाजवादी क्रांति के लिए यह कोई जरूरी नहीं कि किसी देश की आर्थिक और राजनीतिक परिपक्वता में प्रत्यक्ष सामुपातिक संबंध हों। जैसा कि लेनिन ने कहा है यह कहना कठिन है कि "इसकी शुरुआत कौन करेगा और अंत कौन"।* समाजवादी क्रांति के दृष्टिकोण से तुर्किस्तान के अपरिपक्व होने की सारी दलीलों का मतलब है रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के वस्तुनिष्ठ प्रगतिशील परिणामों और उस विजय के फलस्वरूप हुए राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन से इनकार करना। रूस में मिल जान के कारण तुर्किस्तान में आर्थिक विषमता बढ़ गई। उत्पादन-साधनों के प्रति विभिन्न वर्गों के संबंध बदल गये और कृषि तथा उद्योग में वर्गीय विभेदों की प्रक्रिया और गहरी हो गई। यह मानना, जैसा कि हमें याद और मुस्लिम चाकायेव कहते हैं, कि मध्य एशिया के मुसलमानों में बग भेद नहीं था और कि उन्होंने एक-दूसरे के प्रति राष्ट्र बनाय के जा बग-संघर्ष की धारणा से भी अपरिचित

थे वस्तुस्थिति के विपरीत थे। यह सही है कि तुर्किस्तान में औद्योगिक
सवहारा की संख्या बहुत कम थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि रूसी
आबादी में सवहारा तत्वा का अधिकत्व नहीं था। कृषिक सवहारा और
अर्द्ध सवहारा मिलकर आबादी का खासा बहुमत बन गये थे। यहाँ यह उल्लेख
कर दिया जाये कि लेनिन ने “शहरी सवहारा” और “ग्रामीण सवहारा”
की बात कही है और कुलको तथा किमान पूँजीपतियों के विरुद्ध उनका
एक हाने की चर्चा की है।* उन्होंने “गरीब किसानों” का अर्द्ध-सवहारा
कहा है।** अपनी “सोवियत सत्ता के संघर्ष में दस प्रस्थापनाएँ” नामक
कृति में लेनिन ने बताया कि सवहारा तथा गरीब किसानों (अर्द्ध सवहारा)
का अधिनायकत्व कायम करना सोवियत सत्ता के उद्देश्य में से एक है।***

मध्य एशिया के इतिहास का कोई गम्भीर अध्ययनकर्ता इस बात से
इन्कार नहीं कर सकता कि तुर्किस्तानी गाँवों की आबादी का अधिकांश
भाग सवहारा और अर्द्ध-सवहारा था। १९१७ की अप्रिल-रूसी कृषि
जनगणना के अनुसार कृषि में काम करनेवाले उजरती मजदूरों की संख्या
फरगाना ओब्लास्त के बस हुए हिस्सों में २२,२१७, समरकंद ओब्लास्त
में २३,०२७ और सिरदरिया ओब्लास्त में (आमू दरिया विभाग को
छोड़ कर) १५,०६७ थी।**** दूसरे प्रदेशों के संघर्ष में बाई आकड़े हासिल
नहीं किये जा सके। इन चार उपलब्ध आकड़ों से भी पता चलता है कि
ग्रामीण समाज में वर्गीय विभेदोत्पत्ति कितना बढ़ गया था। भूमिहीन किसानों
की यह विशाल सेना ही कृषिक सवहारा का आधार बन गयी। फिर गरीब
किसानों—चारिकेरो और भरदिबेरो की बड़ी संख्या थी। इनका बाड़ा
जमीन पर स्वामित्व था। वे बाई लोगों की जमीन पर बटाईदारी का
आधार और ऐसी शर्तों पर रेंती करते थे, जो उनके लिए प्रतिकूल और
बर्तन थी। तुर्किस्तान की दस्तकारी में १,०८,३२४ आदमी काम करने

* वही, पृष्ठ २८ पृष्ठ ३६२ और पृष्ठ ३३, पृष्ठ ४६५।

* वही, पृष्ठ ३१, पृष्ठ ३८५ और पृष्ठ २८, पृष्ठ ५६।

* वही, पृष्ठ २७, पृष्ठ १५३-१५४।

** *ग० त० तुगुनोव, “मध्य एशिया और कजाखस्तान में १९१६ का
विद्रोह”, ताशकंद, १९६२ पृष्ठ १००। (रुमा संस्करण)

थे।* आवादी के इस क्षेत्र की सामाजिक बनावट १६०८-१६०९ में यह थी कि उसमें ४० प्रतिशत गरीब दस्तकार, २५ प्रतिशत माध्यमिक दस्तकार और २४ प्रतिशत उजरत पर काम करनेवाले मजदूर और बाकी समस्त दस्तकार थे।** यही जनता समाजवादी क्रांति और नये जीवन का लक्ष्य थी।

रूस के साथ मध्य एशिया के विलयन के पहले दिना सं ही श्रमजीवी जनता का सम्पर्क "दो रूसों" से हुआ—एक उत्पीड़क और शोषक, रोमानोव और स्तोलीपिन का रूस, जो एशिया की जातियाँ और रूसी लोग दोनों का शोषण और उत्पीड़न करता था और दूसरा क्रांतिकारियों का रूस जो सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ता था। मध्य एशिया के लोग का जारशाही उपनिवेशवादियों, रूसी कुलकों और व्यापारियों से ही नहीं, बल्कि रूसी किसानों और औद्योगिक मजदूरों, वनानिका, शिक्षकों, लष्करी और क्रांतिकारियों से भी सम्पर्क होता था।

महान रूसी जनगण के साथ मध्य एशिया के श्रमजीवियों के इस लड़ने का प्रगतिशील चरित्र और अधिक स्पष्ट तब हुआ, जब रूस विश्व क्रांतिकारी आन्दोलन का केन्द्र बन गया और रूसी मजदूर वर्ग अपनी जमीन क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आन्दोलन का हिस्सा बन गया। रूस में क्रांति की उभरती लहर ने भी मध्य एशिया को प्रभावित किया। मध्य एशिया की प्रगतिशील शक्तियों ने रूसी स्वतंत्रता के साथ मिलकर सामंती और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया। यह समझकर कि रूस के श्रमजीवी जनगण की जनता ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि उनकी समान नियति रूसी स्वतंत्रता के साथ सम्बद्ध है।

मध्य एशिया की समाजवादी क्रांति में रूसी स्वतंत्रता न निस्संदेह अग्रिम भूमिका अदा की। उसने स्थानीय मजदूरों की वर्ग चेतना को जागृत

* वहाँ, पृष्ठ ७२।

** म० वहाँ वहाँ "उत्पन्न समाजवादी जाति का निर्माण", पृष्ठ १७३।

करने तथा देहकानो स एकता कायम करने मे एक यत्न का काम किया। ये देहकान धीरे धीरे सामतवादियो और धामिक नेताओ के प्रभाव से अपन आपका उबारने का प्रयास कर रहे थे, और १९वीं सदी के अंत स व राजनीतिक सघष के क्षेत्र मे प्रवेश करने लगे थे, यद्यपि स्वतः स्फूर्त और असंगठित ढंग से।

मध्य एशिया पर रूसी औपनिवेशिक कब्जे मे एक नया तत्व मौजूद था, जो मध्य यूरोपीय शक्तिया के औपनिवेशिक कब्जा मे नहीं था। वह था रूसी साम्राज्य की औपनिवेशिक प्रजा और साधारण रूसी जनगण मे प्रत्यक्ष सम्पर्क। रूस के उपनिवेश क्षेत्रीय दृष्टि से इससे मिले हुए थे और रूसी उनमे आकर बसते थे।

यह चीज रूसी उपनिवेशों मे समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक पूर्वस्थितियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सवहारा अनेक कारणों से, जिनमे उपनिवेशों से भौगोलिक दूरी भी एक थी, उपनिवेशों मे समाजवादी क्रांति के मामले मे पहलकदमी नहीं कर सका। ब्रिटिश सवहारा उपनिवेशों (जैसे भारत) मे वही प्रगतिशील भूमिका नहीं अदा कर सका क्योंकि वह बड़ी हद तक श्रमिक रईसशाही के प्रभाव मे था। याद रहे कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने अनेक मौकों पर भारत के लिए स्वायत्त शासन का विरोध किया था। परन्तु अगर ब्रिटिश मजदूर वगैरह श्रमिक रईसशाही के प्रभाव मे नहीं होता, तब भी भौगोलिक दूरी ऐसी चीज थी जो बाधा बनी रहता। भारत मे शायद ही कोई ब्रिटिश मजदूर रहा हो, जबकि हजारों रूसी मजदूर मध्य एशिया की रेलवे तथा अन्य औद्योगिक उद्योगों मे काम करते थे। ब्रिटिश पूँजी न अवश्य ही भारत के कच्चे सामान के साधनों का अधिक पर्याप्त शोषण करने के लिए भारत में रेलवे का निर्माण किया। इन निर्माण प्रयोजनाओं में एक भी ब्रिटिश मजदूर न काम नहीं किया। रूसी मजदूरों के अलावा मध्य एशिया में खासी बड़ी संख्या में रूसी किसान भी आकर बस गये थे। इन में से बहुतों कुत्तक नहीं थे और इनका और देहकानों का सम्बन्ध हीन था।

कुछ लेखकों ने यह निष्कर्ष का प्रयोग किया है कि मध्य एशिया में

इन रूसी बसनेवाला तथा देशी जागण के हिना मे स्यादी विरोध था, जिससे दोना य महयोग की सम्भावना नहीं थी। राफारोव का कहना कि तुकिस्तान में एक तिहाई से आधे तक रूसी आवादी "मुपतपार" थी, वस्तुस्थिति की घोर विवृति है।* वह इस "मुपनपोर वग में बिना किसी भदभाव के सभी रूसी शहरी वाशिंग्टन का शामिल करते हैं। अगर हम जनसंख्या सहमत हों, तो सभी रूसी साहित्यकार और वज्ञानिक जिन १००००० प्रशवात्सवी, १००००० सम्मोनोंव तियातशान्स्की आदि उपनिवेशवादी हों जाते हैं, और सभी मजदूर अधिकार प्राप्त श्रमिक रईसगाही के सदस्य।

तुकिस्तान की कुल रूसी आवादी ५४०,६७४ थी।** इसमें से १,८५,३०३ शहरों में रहते थे और ३,३०,४६६ गांवों में, १६६४८ शहरी वस्तिमा में और ८,२५८ रेलवे स्टेशन के निवट स्टेशनों में रहते थे। रूसी नगरनिवासियों में कोई २६,००० औद्योगिक मजदूर थे, जिनमें २०००० रेलवे मजदूर थे।*** मनजारा जैसे मजदूरों के सम्मरणों से पता चलता है कि रूसी रेलवे मजदूरों को कोई विशेष सुविधाएं नहीं प्राप्त थीं। उन्हें वही कानून मिलता था, जो उनके जैसे मजदूरों को रूस में मिलता था। निपुण रूसी मजदूरों और अनिपुण स्थानीय मजदूरों के कानून में फर्क से यह नतीजा निकालता कि मध्य एशिया में सुविधाप्राप्त रूसी श्रमिक रईसगाही थी, श्रमिक रईसगाही की धारणा के बारे में अज्ञानता प्रकट करता है। अगर मध्य एशिया के रूसी मजदूर श्रमिक रईसगाही से सबंध रखते थे, तो उनमें असंतोष किस कारण था जिससे बड़ी-बड़ी हड़तालें और प्रदर्शन होते थे? मालिक दश के पूंजीपति वग के औपनिवेशिक अतिरिक्त मुनाफे द्वारा खरीदी हुई श्रमिक रईसगाही औपनिवेशिक शोषण का एक

* ग० राफारोव, "औपनिवेशिक आति-तुकिस्तान का अनुभव", पृष्ठ ५२।

** 'सांख्यिकीय वापिकी, १९१७-१९२४', ताशान्द, १९२४, खण्ड १, भाग ३, पृष्ठ ४२-४४। (रूसी संस्करण)

*** "उजबेकिस्तान के मजदूर वग का इतिहास", खण्ड १, पृष्ठ ३१-३२।

लचीला यत्न होता। भारत की रेलवे में काम करनेवाले अंग्रेजा की हडताल और प्रदर्शन सभी सुनने में नहीं आये।

यह कहना भी सही नहीं है कि गावों में बस हुए सभी रूसी कुलक थे। जेतीसुव रूसी प्रवासी बस्तिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहां व आक्डा से पता चलता है कि रूसी प्रवासियों में भी वर्गीय विभेदाकरण की प्रक्रिया जारी थी। जेतीसुव की पुरानी रूसी बस्तियों में ११,६५६ परिवार थे जिनकी आबादी ७८,५६१ थी। इनमें १०,५३१ रूसी परिवार थे जिनमें ७२,११७ व्यक्ति थे और १,४२८ गैर रूसी परिवार जिनमें ६,४७४ व्यक्ति थे। ३,३२२ (१६.५ प्रतिशत) परिवार भूमिहीन थे (जिनमें २,२०४ यानी कोई ७० प्रतिशत रूसी थे और १,११८, यानी ३० प्रतिशत गैर रूसी)। भूमिहीन परिवार और ५ देसियातीन की छोटी भूमिारी के परिवार ओब्लास्त के कुल परिवारों का ५० प्रतिशत थे। ६८ प्रतिशत परिवार कृषि के अलावा अनुपूरक काम करते थे, २,६६० व्यक्ति खेतिहर मजदूर थे ३७७ उद्यानों में काम करते थे और २०८२ कारीगर और दस्तकार थे।* सिरदरिया ओब्लास्त के चिमकंद उयेस्व में बसे हुए हमी विसाना में वहाँ ३५ प्रतिशत परिवार खेतिहर मजदूर थे और ३४ प्रतिशत ओद्योगिक मजदूर थे।** ट्रासकास्पियन ओब्लास्त के प्रशासक न रूसी प्रवासियों की भौतिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था कि यह 'मध्यम स्तर के लोगों से घराब' है।*** वस्तुतः का कहना है कि रूसी विसाना की बड़ी सख्या भी जो वज्जाका से लगान पर जमीन लती थी, सरकार के विरोध के बावजूद चली आयी थी।****

भारत में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। १९३१ की जनगणना के अनुसार देश में ६०,६०८ यूरोपीय पुरुष थे जिनमें ५६,६६२ सना और पुलिस में काम करते थे, ३,६७२ सरकारी प्रशासन में ३,५०७ व्यापार में, ६७५८ परिवहन में, ४,०८० उद्योग में, १,४३५ रस्ते में, ३,०६६ पशुपालन

* पृ० त० तुमोव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १३०-१३१।

** वही पृष्ठ १३२।

* वही।

* * * * * य० व० बरलान्द, रचनाएँ ग्रन्थ २, भाग १ पृष्ठ ३२२।

और कृषि में और ६,०१२ बौद्धिक पेशों तथा बत्ता में* यद्यपि जनगणना की तालिकाओं में कहीं स्पष्ट नहीं कहा गया है, यह सभी जानते हैं कि उद्योग धनन और परिवहन में काम करनेवाले यूरोपीय अधिन्तर उच्च प्रशासनिक पदों पर काम करते थे और जहाँ तब पशुपालन और कृषि का सबध है वे फार्मों और बगानों के मालिक थे। अतः साधारण मजदूर बहुत कम थे। इसी प्रकार भारत में ८३१३ यूरोपीय स्त्रियाँ में, ५,०८६ बौद्धिक पेशों और बत्ता में काम करती थी।

मध्य एशिया में क्रांति कहाँ की व्याप्त पूँजीवाद पूर्व सबधों की अनूठी परिस्थिति में समाजवादी क्रांति थी। वह महान् अन्तर्वर समाजवादी क्रांति का एक अभिन्न अंग थी, उन घटनाओं का सिलसिला और विकास जो पेन्नाग्रोद और मास्को में अन्तर्वर १९१७ में शुरू हुई थी। रूस के केन्द्र में अन्तर्वर क्रांति की विजय और रूसी सबहारा द्वारा दी गई सहायता ने मध्य एशिया में क्रांति की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांति का नतत्व निश्चित ही रूसी सबहारा के हाथों में था, जिसे तुर्किस्तान की व्यापक जनता का पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त था।

मध्य एशिया में क्रांति समाजवादी रूस की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मध्य एशिया पर क्रांति रूसी मजदूरों ने ऊपर से लादी थी। मध्य एशिया के महानतवशा ने क्रांति का अभिनन्दन किया मानो यह उनका अपना मामला हो और इसका लाने और डमकी रक्षा करने में सक्रिय भाग लिया।

इतिहास हम सिखाता है कि किसी क्रांति की जड़ अगर व्यापक जनता में गहरी नहीं हो और उस ज़बरदस्ती ऊपर से लादा जाय तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। ऐसी क्रांति अगर इतिहास की आकस्मिक चोट के रूप में जीत भी जाये तो वह अदरुनी और बाहरी अनेक शक्तिशाली शक्तियों का सफल मुकाबला नहीं कर सकती थी। मध्य एशिया के लोगों ने स्वयं क्रांति का रास्ता चुना इस पूरा किया और इसकी उपलब्धियों की रक्षा की।

* J H Hutton Census of India, vol I pt II 1931, pp 420-421

२० वीं शती के प्रारम्भ से रूसी सवहारा और देशी मजदूरों और देहकानों की तेजी से विकसित होती हुई एकता के विरुद्ध जारशाही और देशी बाई लोग और मुल्लाओं में एकता स्थापित होने लगी। राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग से स्थायी जनता के बिलगाव की प्रक्रिया, जो १९०५-१९०७ के दौर में ही शुरू हो गई थी, १९१६ के विद्रोह के समय पूरा हो चुकी थी। मध्य एशिया का राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग रूसी साम्राज्यवादी पूजीपति वर्ग की सेवा कर रहा था। उसने जनता के हितों का विश्वासघात किया। फरवरी क्रांति की विजय ने औपनिवेशिक तुर्किस्तान में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये। तुर्किस्तान के श्रमजीवी जनगण को तब तक यह विश्वास हो चुका था कि वे रूसी सवहारा की सहायता से ही राष्ट्रीय और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने राजनीतिक कायकलाप संगठित करना शुरू किया। फरवरी क्रांति के बाद उनके अनेक वर्गीय संगठन कायम हुए—स्थानीय श्रमजीवी जनगण की सोवियतें, समितियाँ और मूनियन। मई १९१७ के अंत और जून के प्रारम्भ में स्थानीय मेहनतकशों की सावियत बनने लगी। सांगठनिक रूप में भी रूसी मजदूर वर्ग ने बड़ी सहायता की। देशी मजदूरों ने मोरचे के पीछे सेवा-नाथ से घर वापसी पर इन संगठनों के निर्माण में अग्रिम भाग लिया। मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतों ने शुरू ही से देशी शोषकों के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष किया। शापक तत्त्वा ने भी अपने आपको “शूरा ए इस्लामिया” और “उलमा” जस संगठना में संगठित किया। यह सही है कि शुरू में देशी जनता ने अपने सांस्कृतिक पिछड़ेपन और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण इन प्रतिश्रियावादी संगठनों में कुछ विश्वास प्रकट किया। परन्तु वर्ग विरोध तीव्र होत गये और इसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता या इन प्रतिश्रियावादी संगठनों में जो भी विश्वास था वह जाता रहा। मजदूर क्रांति के समय वर्गीय शक्तिता के विभेदीकरण की प्रक्रिया पूरा हो चुकी थी। क्रांतिकारी परिस्थिति पूरी तरह विकसित और सखट पूरा तरह परिपक्व हो चुका था। इन सब का अनिवार्य परिणाम यह था कि मध्य एशिया में समाजवादी क्रांति शुरू हो गई।

साम्राज्यवाद या भारत की सुरक्षा ?

भारत और मध्य एशिया के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कई सदी पुराना है। मध्य एशिया के ही इलाके से यात्री और व्यापारी चीन से भारत और भारत से चीन आते और जाते थे। इसी तरह पश्चिम और पूव के व्यापार का रास्ता भी यही से होकर जाता था। समुद्री रास्तों की खोज से पहले यह क्षेत्र सम्यता और व्यापार का महत्वपूर्ण चतुष्पथ था। स्ट्राबोन ने आक्सस नदी, कास्पियन सागर, ट्रांसकानेशिया और इसके आगे पश्चिम में काले सागर तट से भारतीय सामान के जाने की चर्चा की है। आधुनिक सोवियत मध्य एशियाई जनतन्त्रों के इलाके तथा चीन के सिक्किम क्षेत्र में जो पुरातन स्मारक मिले हैं, उनसे भी दोना जातियों के घनिष्ठ संबंधों का पता चलता है।

य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मध्य युग में बने रहे। खवारिज्मी विद्वान अबू रैहान अल बेरूनी तथा अब्दुरज्जाब समरकंदी की दास्ताना यात्राएँ इन सम्पर्कों के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय हैं। बाबर द्वारा स्थापित राजवंश के तीन सौ वर्षीय शासन काल में दोना जातियों का यह संबंध और विकसित हुआ।

१९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत का महत्व काफी बढ़ गया था। भारत अपने विशाल क्षेत्र, अत्यधिक भौतिक

साधनो और आवादी सहित पूरे एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता की "चौकी और वुज" बन गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने और अधिक उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए अट्टे के रूप में भारत को इस्तेमाल किया। वे सूडान, मिस्र, अबीसीनिया, अफगानिस्तान, बर्मा और चीन में आक्रमक युद्ध भारतीय सैनिकों का प्रयोग करके लड़ और इन युद्धों का खर्च भारत के सर मढ़ा। लंदन में इंडिया आफिस, अफन तथा लाल सागर की अफ बंदरगाहों में औपनिवेशिक सस्यानों, चान में कौनसलखाना और फारस में दूतावास का खर्च भारत के लोगों को देना पड़ता था।

ब्रिटिश लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास के आधुनिक युग के मिथ्या प्रदर्शन के सबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित होकर भारतीय विद्वानों को इस युग की पुनर्जागरण उससे अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से करनी चाहिए जितनी अक्सर की जाती है। नेहरू ने लिखा है

"भारत के इतिहास और खासकर जिसे ब्रिटिश युग कहते हैं, उमरे ब्रिटिश विवरण को बहुत बुरा माना जाता है सच्चाई अक्सर सबत गहरे कूप की तह में छिपी होती है, और झूठ नग्न और निलज्ज सर्वोपरि होता है।"*

ब्रिटेन की साम्राज्यवादी कारवाइया भारत के पड़ोसी देशों सिक्का अफगानिस्तान, ऊपरी बर्मा और तिब्बत तक फैली हुई थी। ब्रिटेन की औद्योगिक पैदावार के लिए मड़ी और कच्चे सामानों के स्रोत के रूप में इन देशों का महत्व नगण्य था। परन्तु विश्व के अंतिम विभाजन के साम्राज्यवादी संधि के युग में सामरिक दृष्टि से उनका महत्व बढ़ गया, क्योंकि वे चीन और मध्य एशिया के द्वार पर स्थित थे।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की वैदेशिक नीति हमेशा आक्रामक रही। उनकी युनियादी दिशा मंदप्रथम ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से निर्धारित होती थी। १९वां शताब्दी उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का केन्द्र बिंदु "पूर्वी प्रश्न" यानी पननशील तुर्की साम्राज्य की

विरासत सभालने के सधप म निहित था। निक्ट और मध्य पूव मे हस मुख्य शत्रु था। इसी तथ्य स ब्रिटिश विस्तार का विकास भारत की सीमा पर, खासकर उत्तर और पश्चिमोत्तर दिशाआ म काशगर, अफगानिस्तान और तुक्मानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रा म निर्धारित होता था। ब्रिटिश उपनिवेशवादी इन क्षेत्रा को मध्य एशिया म ह्य के विरुद्ध सधप का अड्डा मानते थे।

ब्रिटेन की सीमा-नीति की आक्रामकता म भारत के अन्तर की स्थिति म उतार-चढाव के अनुसार हेरफेर होता रहता था। सीमा-नीति के सबध म दो दष्टिकाण उत्पन्न हुए। भारत की सीमाआ पर "अग्रिम नीति" का पक्ष जो प्रतिरक्षा-व्यवस्था म उत्तर-पश्चिमी सीमाआ की दुबलता की रट लगाया करता था भारत क प्रतिरक्षा प्रबध को उसकी प्रावृत्तिक सीमाआ के बाहर सबल बनाने का आवाहन करता था। इस नीति क समर्थका का कहना था कि मध्य एशिया पर रूस का कब्जा ब्रिटिश भारत के लिए बड़ा खतरा है। दूसरा पक्ष इस खतरे से इनकार करता था और "बद सीमा-नीति" का समर्थन करता, और भारत की सीमाआ के बाहर सक्रिय रूप म आगे बढ़ने का विरोधी था। इसका उद्देश्य उपनिवेश की भीतरी स्थिति को सुदढ बनाना था। उस जमाने की ऐतिहासिक परिस्थितिया के कारण "बद सीमा-नीति" १८५७ से १८७५ तक हावी रही। १८५७ के जन विद्रोह के बाद अदरुनी पेचीदगिया के कारण सक्रिय रूप म आगे बढ़ना कठिन हो गया था। परन्तु अस्थायी रूप म "अग्रिम नीति" को त्यागने का मतलब यह नहीं था कि पडोसी इलाको म घुसपैठ की नीति को वित्कुल छोड दिया गया। कूटनीति का चतुराई से प्रयोग करके अग्रज अपने प्रभाव-क्षेत्र को बराबर बढ़ाते रहे व ऐसी परिस्थितिया तैयार करने मे सलग्न रहे, जो सक्रिय आक्रमण के अनुकूल हो सके। काशगर और अफगानिस्तान म ब्रिटिश नीति इसका स्पष्ट प्रमाण है। लारेस ने अफगानिस्तान के प्रति "निष्पक्षता" और 'हस्तक्षेप नहीं करने' की जो नीति घोषित की थी, उसका कारण भी अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता और क्षत्रीय अखण्डता का सच्चा सम्मान नहीं था। कज़वैटिक पार्टी के मन्त्री जनबान ने लारेस को लिखा "विरोधी पक्षो ने -

सतवृत्तापूर्ण खैया ही एकमात्र ब्रिटिश हितो के अनुकूल है। भारतीय साधना की आवश्यकता इस समय के विस्तार के अलावा और काम के लिए है" (जोर-दे० वी० का)।* वास्तव में नैनबोन को अफगानिस्तान से अधिक दिलचस्पी ऊपरी बमा में थी। लारेस को उस समय तक अफगान शासको से घनिष्ठ संबंध बनाने की कोई आवश्यकता या उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया था। वाइसराय ने लिखा कि "ऐसा निश्चय आ सकता है, जब ऐसा करना बुद्धिमानी होगी (जैसा वाद में लिटन ने किया), परन्तु वह दिन अभी नहीं आया है"।**

उस जमाने में काशगर में ब्रिटिश अपनी विस्तारवादी कारवाइयों पर परदा डालने के लिए व्यापार की आड़ ले रहे थे। ग० ज० ऐलडर ने स्पष्ट स्वीकार किया

"पूर्वी तुकिस्तान में ब्रिटिश नीति में उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक के बाद हमेशा ही व्यापारिक साधनों और राजनीतिक उद्देश्यों की मिलावट रही है। व्यापार एक यत्न मात्र था। उस युग के सभी वाइसराय इस बात से भली भाँति अवगत थे कि व्यापार 'राजनीतिक प्रभाव का एक बड़ा यत्न' है। लारेस और रिपन भारत की राजनीतिक जिम्मेदारियाँ का भारतीय सीमा के अंदर सीमित रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काशगर से व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं किया। और सवा न इसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे ब्रिटिश प्रभाव को फलाना चाहते थे।"***

ब्रिटिश लेखकों की यह राय सही है। परन्तु उसकी यह सफाई कि अंग्रेज काशगर में अपना प्रभाव "भारतीय सुरक्षा के लिए उमरे विशेष महत्व" के कारण फैलाना चाहते थे, सत्य से बहुत दूर है। भारत को

* द० S Gopal *British Policies in India* Cambridge, 1965 p 43 अंग्रेजों के लिए "घनिष्ठ संबंध" का एक ही मतलब था अफगानिस्तान का अधीन राष्ट्र में बदलना।

* वही, पृष्ठ ४१।

*** G J Alder *British India's Northern Frontier 1865* 95 London 1963 p 98

रूसी खतरे का हौआ अंग्रेजों ने भारत की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के परे अपने सम्भावी आक्रमण पर परदा डालने के लिए खड़ा किया था। ऐलंडर स्वयं अपना खडन करता है, जब वह उसी पुस्तक में एक और स्थान पर कहता है

“रूस द्वारा सिक्किम पर कब्जा करने की काउफमन की योजना १८८० में इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि उससे उसमें लगनेवाले समय और खर्च के मुकाबले में नगण्य लाभ होगा। इस बात के ठोस राजनीतिक तथा सैनिक कारण थे कि रूस बहुत अच्छी प्राकृतिक सीमा को छोड़ना नहीं चाहेगा और कहीं ज्यादा कष्ट देनेवाली एशियाई मुस्लिम प्रजा की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेगा। एक ब्रिटिश सैनिक रिपोर्ट ने काशगर पर रूसी हमले की सम्भावना को प्रमाणित रूप में अस्वीकार किया।”*

इससे स्पष्ट है कि काशगर की ओर से रूसी हमले से भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की चिन्ता और “कश्मीर जैसे देशी राज के साथ, जिसकी वफादारी अनिश्चित है और जो अधःगम्य है, रूस जैसे शक्तिशाली यूरोपीय राज्य के समसीमायुक्त होने” का खतरा झूठा बहाना था। दुख की बात है कि ब्रिटिश इतिहास लेखकों द्वारा दिये गये इन परम्परागत कारणों को इस विषय के कुछ प्रमुख भारतीय लेखक आख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। श्री विशेश्वर प्रसाद लिखते हैं

“फिर भी इस बात पर बल देना होगा कि इस युग में सीमावर्ती राज्यों की अखंडता और स्वतंत्रता तथा भारत की अपनी सुरक्षा का न केवल गहरा संबंध, बल्कि दोनों की अनन्यता सामने आयी। अदन, फारस की खाड़ी, बलात, अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा—सभी उसकी रक्षा के दुर्ग थे और उनको गैरों के हस्तक्षेप से बचाने में ही भारत की सुरक्षा भी थी। भारत की वैदेशिक नीति की नींव तब पड़ी और मंत्री के संबंधों और हिता की व्यवस्था विकसित हुई जिससे भारत को सुरक्षा प्राप्त हुई।”**

इसी प्रकार डी० पी० सिंगल कहते हैं

* वही, पृष्ठ ६६ ६७।

** Bisheshwar Prasad, *The Foundations of India's Foreign Policy* vol I Bombay Calcutta, Madras 1955 p 263

“भारत का हित ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था और यूरोपीय शक्तियाँ के प्रभाव के विरुद्ध भारत की सीमाओं को सबल बनाने की समस्या उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में साम्राज्यवादी नीति का एक प्रभावशाली तत्व बन गई।”*

इस तरह की धारणा भारत में अंग्रेजी राज के मूलतः साम्राज्यवादी उद्देश्यों का नजरअंदाज करती है, जिसका वे० एम० पनिकर ने सही मूल्यांकन किया है

“निस्सन्देह एक महान एशियाई शक्ति के रूप में ब्रिटेन की ताकत भारत पर आधारित थी, जिसने उसको इस योग्य बनाया कि चीन के द्वार खुलवा सके, यांग्त्से घाटी में यूरोपीय प्रभुत्व स्थापित कर सके, महान मचू मग्गाटा की शक्ति को हीन बना सके और शेप एशिया का यूरोप के अधीन बनाने में सहयोग कर सके।”**

अभी हाल में एक और भारतीय लेखक ने भी “मध्य एशिया और फारस में रुस के आगे बढ़ने के खतर” को “उत्तरी क्षेत्र में” ब्रिटेन की दिलचस्पी का कारण बताया है। परन्तु उनको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वह यह स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश नीति “मध्य एशिया पर दीर्घकालीन प्रभुत्व” स्थापित करने के उद्देश्य से “निरूपित” की गई थी। परन्तु उनका खयाल है कि रुसी खतरा न अंग्रेजों का “पुर्जाश बारबादशा” पर “आमना” कर दिया। (P N K Bamzai *Kashmir from Lake Success to Tashkent*, Delhi 1966 pp 28 33 40 46) आर० ऐच० मजुमदार के अनुसार अंग्रेजों के अधिनार में तहत भारत की बदलिता नीति का “प्रधान लक्ष्य” “शुरू से अंत तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में क्षेत्रीय विस्तार या अथवा उपायों से भारत की प्राकृतिक सीमाओं का सुरक्षा करना था (*British Paramountcy and Indian Renaissance The History and Culture of the Indian People* pt I 1963 pp 1039 1041)।

* D P Singhal, *India and Afghanistan 1876—1907* Melbourne 1963 p xi

* K M Panikkar *Asia and the Western Dominance* London 1951 p 95

एशिया में ब्रिटिश विस्तार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरित्र का स्वाभाविक नतीजा था, न कि भारत की सुरक्षा की तथाकथित चिन्ता का। ब्रिटेन के शासक वर्ग इज्जतदारी-पूर्व के पंजीवाद से साम्राज्यवाद में सन्मरण काल में अधिकतम औपनिवेशिक विस्तार चाहते थे। जैसा कि पहले कहा गया था, भारत की सुरक्षा को “रूसी खतरा” ऐसी मनगढ़त बात थी जिससे वे मध्य एशिया में अपने आक्रमण का औचित्य पेश करना चाहते थे। यह सचमुच दुःख का विषय है कि भारतीय लेखकों ने, उत्तर और पश्चिम में भारत के सीमावर्ती राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति का यह कहकर समर्थन किया कि वह भारतीय सुरक्षा के हिता द्वारा निर्धारित होती थी। इन लेखकों ने यह छानबीन करने का कष्ट नहीं किया कि यह “रूसी खतरा” रूस की सैनिक और राजनीतिक स्थिति तथा उसकी आर्थिक और यातायात सम्भावनाओं की दृष्टि से कहा तक वास्तविक था।*

मध्य एशिया से संबंध

मध्य एशिया में बड़ी भारतीय बस्तियाँ का उल्लेख १७वीं शती के स्थानीय साहित्य में मिलता है। उदाहरण के लिए, मोहम्मद यूसुफ मुशी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति में इसकी चर्चा है। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी अधिवासियों की बस्तियाँ अकतूबर आदि के समय तक कायम रही। सावित्र विद्वान ग० ल० द्मीत्रियेव ने मध्य एशिया में हिंदुस्तानी अधिवासियों की सरगमियों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। उनके मतानुसार छह से आठ हजार हिंदुस्तानी १६वीं शती के मध्य और २०वीं शती के पारम्भ में वहाँ रहते थे। वे मुख्यतया सिंध के शिकारपुर इलाके और पंजाब के पेशावर, लाहौर, मुलतान, लुधियाना और अमृतसर के रहनेवाले

* K S Menon, *The “Russian Bogey and British Aggression in India and Beyond Calcutta 1957* ब्रिटिश नीतियों के आलोचनात्मक अध्ययन का भारत में यह शायद पहला प्रयास है।

थे। उनमें कश्मीर, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई तथा अन्य नगरों के लोग भी थे।

हिंदुस्तान से आकर बसनेवालों में हिंदु, मुस्लिम, सिख—सभी प्रकार के लोग थे। वे अधिकतर अमीर-बुखारा के प्रशासन क्षेत्र में, फरगाना घाटी, समरकन्द, तुर्किस्तान के सिर-दरिया इलाके में बसे हुए थे। कुछ हिंदुस्तानी जेतीसुव और ट्रांसकास्पियन क्षेत्रों में भी आबाद थे। चीन के खान प्रशासन क्षेत्र में शायद कोई हिंदुस्तानी बस्तियां नहीं थीं, यद्यपि हिंदुस्तानी व्यापारी दो या तीन महीनों के लिए वहां जाया करते थे। मध्य एशिया में रहनेवाले अधिकांश हिंदुस्तानी व्यापारी और साहूकार थे (सिंध के भाटिये राजस्थान के मारवाड़ी, पंजाब के खत्री तथा पश्चिमी भारत के खोजा और बोहरा)। मगर उनमें कुछ किसान, दस्तकार तथा मेहनतकशा के श्रम प्रतिनिधि भी थे। ताशकंद में १८७१ में जा १९६ हिंदुस्तानी रहते थे, उनमें ३६ धनी भारतीय व्यापारियों के नौकर-चाकर और पांच भिखारी थे। उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र के पुरालेख संग्रहालय की कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ हिंदुस्तानियों के अलावा, जा खेतीपारी का काम करते थे, सोनार, जिल्दकार, बुनकर नानवाई और हलवाई भी थे।

बहुत कम हिंदुस्तानी ऐसे थे, जिन्होंने मध्य एशिया में स्थायी आवास ग्रहण कर लिया था। ज्यादातर लोग अधिक से अधिक १० या १५ वर्ष रहा करते और उससे बाद दश लौट जाते थे। बहुत कम ऐसा होना रिस्की और बच्चे उनके साथ आते हैं। भारतीय अधिवासी माधारणतया कारवान-भरावा में साथ मिलकर रहा करते थे। ताशकंद, बुखारा और समरकंद जैसे बड़े शहरों में कई-कई हिंदुस्तानी कारवान-सरायें होती थीं। नमनगान और मंगिता जैसे छोटे शहरों में ग़ाम हिंदुस्तानी मुस्लिम होते थे। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी समुदायों के अपने मुखिया होते थे, जो प्रशासन के सम्मुख उनका प्रतिनिधित्व किया करते थे तथा विवादों में सबंधी तथा श्रम क्षणों का निपटारा कराने में सहायता करते थे।

मध्य एशिया पर जारशाही रूस का कब्जा होने में पहले भारत से इन इलाकों का व्यापार काफी ज़रूरत पर था। भारत में जारशाही रूस का

सबध (जिसका स्वरूप कुछ अस्थायी और अनियमित था) मध्य एशिया के जरिये ही हुआ करता था। जब जारशाही रूसी साम्राज्य में कोकान का पान शासित क्षेत्र, बुखारा और खीवा का वह भाग मिल गया, जो तुर्किस्तान का जारशाही प्रांत बना तो बुखारा भारत से व्यापार और व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना रहा। १९वीं शती के सातवें दशक के अंत में वहां की स्थानीय आवादी को भारतीय सामान मुहैया करने में हिन्दुस्तानी व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की। वे चाय नील, मलमल, मसाले तथा अन्य प्रकार का भारतीय और अंग्रेजी तयार माल मध्य एशिया लाया करते। ५४,७५००० रुबल का भारतीय सामान जिसका वजन एक लाख पौद होता, सालाना बुखारा निर्यात किया जाता था। इसके बदले में बुखारा से २१०० पौद वजन का सामान भारत भेजा जाता था। बुखारा से भारतीय सामान रूसी तुर्किस्तान तथा रूसी साम्राज्य के अन्य व्यापार-वेन्द्रो को भेजा जाता था। भारतीय माल, खासकर चाय, के निर्यात का थोक-व्यापार पेशावर के मुस्लिम व्यापारियों के हाथों में था, परन्तु रूसी तुर्किस्तान में उसकी फुटकर बिक्री सिध और पंजाब के हिंदु व्यापारी किया करते थे। बुखारा में छह हिन्दुस्तानी कारवान-सरायें थी, जो चाय के व्यापार से संबंधित थीं। अब्दुरशीद की सराय में हर साल ३००० ऊट हिंदुस्तानी चाय लादकर आया करते थे मिर्जा गुलिया की सराय में १५०० ऊट और बद्रुद्दीन की सराय में १२०० ऊट।

जारशाही सरकार ने रूसी तुर्किस्तान में हिंदुस्तानी अंग्रेजी माल का आयात रोकने के लिए अनेक कारवाइया कीं। इन कारवाइया के फलस्वरूप पिछली शती के आठवें और नौवें दशका में भारतीय सामान का निर्यात कुछ दिना के लिए रुक गया। १८८५ में बुखारा में रूसी राजनीतिक एजेंसी स्थापित की गयी और चाय, मलमल और नील को छोड़कर बाकी आगल भारतीय सामानों के प्रवेश पर निरोध लग दिया गया। भारतीय चाय के आयात पर ५० प्रतिशत चुगी लगा दी गयी। इतने ऊंचे आयात-बरो के कारण भारतीय व्यापारी परिवहन के खर्चों में क़िफायत करने का उपाय ढूढने लगे। पहले उन्होंने मध्य एशिया में अपना सामान फारस के रास्ते लाना शुरू किया और अफगानिस्तान का खतरनाक

रास्ता छोड़ दिया। दसवीं दशाब्दी के शुरू में वे बम्बई-बतूम का समुद्री रास्ता अग्निधार बनाने लगे और वहाँ से वे ट्रांसकास्पियन रेलवे पर जाते, जो उन्हीं दिनों खुली थी। बतूम से भारतीय माल काकेशियाई रेलवे के जरिये कास्पियन तट तक लाया जाता और तब कास्पियन के रास्ते ताम्नावादस्क पहुँचाया जाता। इस रास्ते भारतीय सामान के आन से जारशाही खजाने का भी नफा था, इसलिए १८६४ में इस रास्ते सामान लाने-ले जाने की आज्ञा दे दी गयी।

मध्य एशिया से व्यापार के इस सस्ते रास्ते के खुल जाने का इस क्षेत्र से भारत के व्यापार पर लाभदायक असर पड़ा, यद्यपि चुगी बन ऊँचा था। बम्बई-बतूम रास्ता खुल जाने के साथ भारतीय व्यापारियों ने तुर्किस्तान की मंडी में, घामकर जहाँ तक चाय के व्यापार का सवाल था अपनी पुरानी हैमियत पुनः स्थापित कर ली। सोवियत इतिहासज्ञ ग० ल० दमीत्रियेव के अनुसार ताशकंद के पुरालेख-संग्रहालय में जो दस्तावेजें उपलब्ध हैं, उनसे पता नहीं चलता कि १८८१-१८९२ की अवधि में कहीं हिन्दुस्तानी व्यापारी चाय का व्यापार करता था। परन्तु १८९६ की दस्तावेज़ों में छह हिन्दुस्तानी व्यापारियों का उल्लेख है, जिनमें उम माल चाय का व्यापार किया। समुद्री रास्ते के खुल जाने से बुधारा के साथ भी भारतीय चाय का व्यापार को फायदा पहुँचा। गत शताब्दी के आठवें तथा नव दशक में बुधारा में भारतीय चाय के व्यापारियों की संख्या ८-१० थी और बीसवीं शती के प्रारम्भ में यह बढ़कर ७० के लगभग हो गयी। बुधारा के चाय के व्यापार पर भारतीय व्यापारियों ने प्रायः अपना एकाधिकार कायम रखा और धीरे-धीरे वे तुर्किस्तान की मंडी पर भी हामी हो गये। समरान्द में, जो चाय का व्यापार का एक मुख्य केन्द्र बन गया था १९१० में चाय की पैकिंग के जा १० उद्यम थे, इसमें से तीन के मालिक भारतीय व्यापारी थे।

जगा कि ऊपर उल्लेख किया गया था भारत में मध्य एशिया का नियंत्रण की जानकारी मुख्य वस्तुएँ चाय, मसबन नाल वगैरहें शाल और घग्नेही औद्योगिक जाइँ था। उन्नेन इतिहासकार श्रीमती रमलजाद का कहना है कि हर साल काद मान लागू पूड भारतीय चाय, १८ हजार

पूछ नील, मलमल की १४०० गांठ, काई ५०० कश्मीरी शाल और ३०० टुकड़े विमखाव का आयात मध्य एशिया में होता था। भारतीय व्यापारी मध्य एशिया से अफगानिस्तान, वाशगर और अक्सर हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में कच्चे रेशम, रूसी चीनी के बतन तथा अन्य औद्योगिक सामान का आयात करते थे। वे रूसी तुकिस्तान तथा मध्य एशिया के खान-प्रशासित क्षेत्रों के परस्पर व्यापार में भी भाग लिया करते थे। इस प्रकार वे कोकान से ताशकन्द कपास हाथ का बुना कपड़ा, कालीन, गाउन और रंग लात और रूसी लोहा तावा इस्पात, चीनी तथा अन्य सामान कोकान लाया करते थे। भारतीय सामानों का अलावा वे रूसी तुकिस्तान में १९१७ की अक्टूबर क्रांति तक मध्य एशियाई तथा रूसी सामानों का भी व्यापार किया करते थे और अक्सर फेरीवाला की तरह गावों गावों घूमकर फुटकर माल भी बचा करते थे।

१९वीं शती के अंत और २०वीं शती के प्रारम्भ तक कपास ऊन फर तथा छाद्यान्त की खरीद भारतीय व्यापारियों के कारोबारी कायकलाप में बड़ा स्थान ग्रहण कर चुकी थी। समय बीतने के साथ वे केन्द्रीय रूसी फर्मों से भी कारोबार करने लगे, उनसे सामान मगवाते और नीजनी नोवगोरोद के व्यापारी मेला में भाग लिया करते। कुछ हिंदुस्तानी प्रवासियों ने पजीवादी उद्योगों में पूँजी भी लगायी। १८८७ में एक बाईं बालागुलेव* को सोना तथा प्लैनिज पदार्थों का खनन करने का वनसंज्ञन मिला। बालागुलेव रूसियों के शराब के कारखानों में अगर सप्लाई किया करता था। वह भी कोई कारोबार करता था। हिंदुस्तानियों की चाय पेकिंग फैक्टरियों में अनेक स्थानीय मजदूर काम किया करते थे। उदाहरण के लिए एक पेशावरी फजल अहमदोव की फाक्टरी में १९०६ में ३० मजदूर काम किया करते थे। १८९६ में बाईं गुलाएव ने नमनगान जिले के मशहद नामक

*अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों में दज हिंदुस्तानी नामों पर स्पष्टतः उल्लेख और रूसी प्रभाव है।

गाव म रूसी अ० येपीफानोव के साझे मे कपास साफ करने की फैक्टरी स्थापित की। एक् और हिन्दुस्तानी याकूब शेख नूरखानोव न, जो पेशावर का रहनेवाला था, १६०६ म अन्दीजान मे एक् और कपास साफ करने की फैक्टरी खोली।

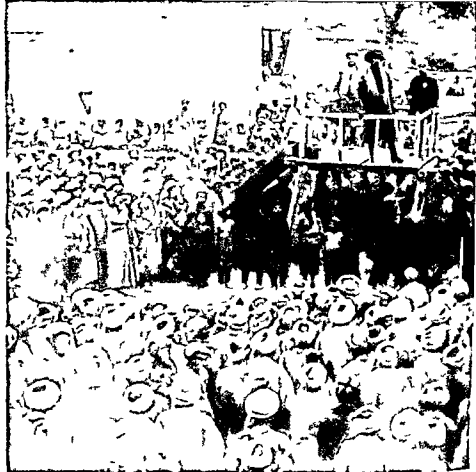
मध्य एशिया म हिन्दुस्तानी प्रवासिया की खासी बड़ी सख्या साहूकारी भी बरती थी। गत शती के आठवे दशक मे हिन्दुस्तानी साहूकारा का बारोबार रूसी तुकिस्तान मे जोरो पर चला हुआ था। उनकी शापणकारी कारवाइया की ओर प्रशासन का ध्यान १८७१ मे ही आकृष्ट हुआ था, जब जरफशान प्रदेश के सनिक गवनर ने उनके बिम्ब दडात्मक कारवाई करन की मिफारिश की थी। परन्तु १८७७ तक इनकी सरगमिया पर राक लगान के लिए कुछ नही किया गया। उस साल एक् कानन लागू करके हिन्दुस्तानिया द्वारा अचल सम्पत्ति की खरीदारी पर निषेध लगा दिया गया। इसके बाद तुकिस्तान के हिन्दुस्तानी प्रवासी धीरधीर व्यापार की ओर ध्यान देने लगे। बुधारा म बीसवी शती के शुरू तक भारतीय समुदाय म अधिकांश साहूकार थे।

यद्यपि आग्नेय रूसी औपनिवेशिक प्रतियागिता के कारण भारत तथा मध्य एशिया के परस्पर व्यापार का कुछ धक्का लगा, उनका सांस्कृतिक सम्पर्क निरन्तर बना रहा। इस दिशा मे एक् महत्वपूर्ण बंदम १८६७ मे उठाया गया, जब अशरफाबाद और ताशरन्द म तुकिस्तान सैनिक कमान के अफगरा के लिए हिन्दुस्तानी भाषा का दा वप का पाठ्यक्रम जारी किया गया। अशरफाबाद हिन्दुस्तानी पाठ्यक्रम का १६०० म ताशरन्द पाठ्यक्रम म मिला दिया गया, जो आगे बढ़कर प्राच्य विद्याभ्यास का स्कूल बन गया। अशरफाबाद म हिन्दुस्तानी पाठ्यक्रम का प्रारम्भ काल यागेत्लो न और ताशरन्द म लेफ्टिनेंट कनल विगानित्स्की न किया था। कनल यागेत्लो ने प्राच्य भाषाभ्यास के परिस स्तून म शिक्षा प्राप्त की थी और लेफ्टिनेंट-कनल विगानित्स्की न बुधारा म भारतीय लागा के साथ रहकर हिन्दुस्तानी सीखी थी। विगानित्स्का न भारत की यात्रा भी की और यहा एक् मान र] था। कनल यागेत्ला न हिन्दुस्तानी भाषा शब्दावली तयार किया था, जो १६०२ म प्रकाशित हुआ। उन्होंने मुगलान तथा

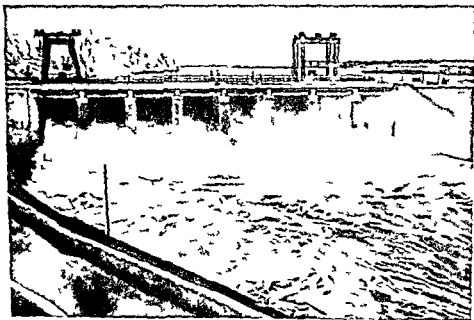
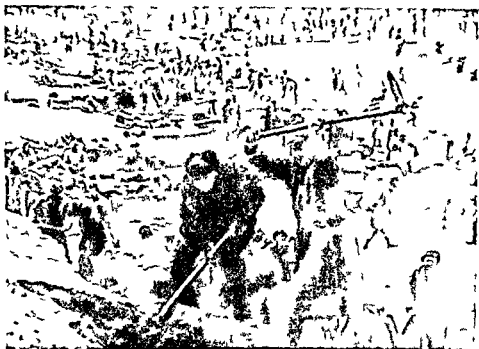


बुखारा में जन विद्रोह की विजय,
सितम्बर १९२०। विद्रोही जनता
भूमि के किले के सामने

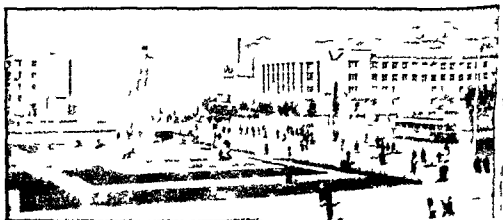
एक गरीब किसान को भूमि और
मवेशी का दानपत्र दिया
रहा है १९२५



भूमि और जन-मुधार क तानून
 की तामीन पर विचार करने क
 लिए एक मभा। प्रयत्ना है
 उम्मेद गा० म० जनता का
 राष्ट्रीय वायवार्थिता समिति क
 अध्यक्षता क अध्यक्ष
 म० अमर नारायण १९२९

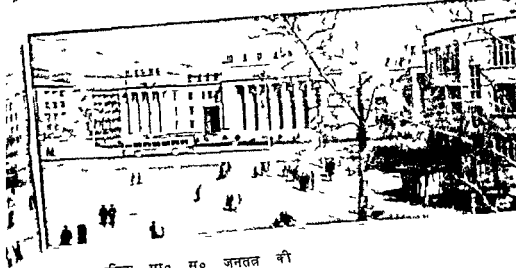
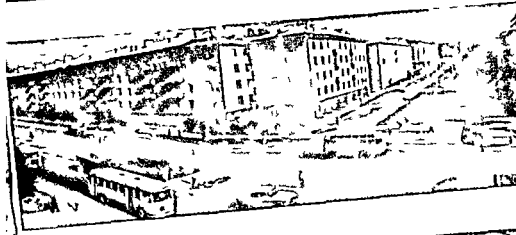
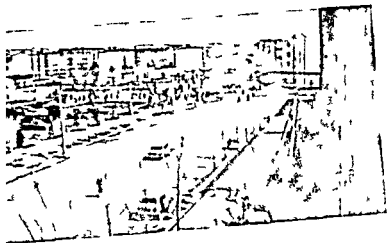


सामूहिक विमान फरहाद पनविजलीघर का बाध,
पनविजलीघर व निर्माण से

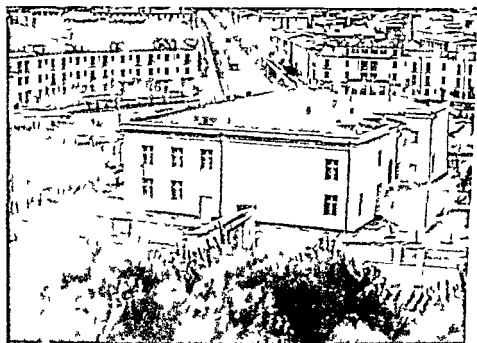
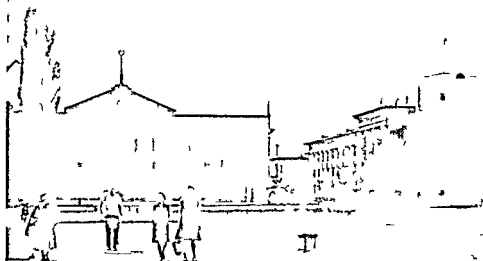


उपरोक्त मा० म० जनता की
राजधानी सागराद का चित्रान
सार मुद्रा

वज्राय मा० म० जनता की
राजधानी धमाधमा का धारा
प्रणयन

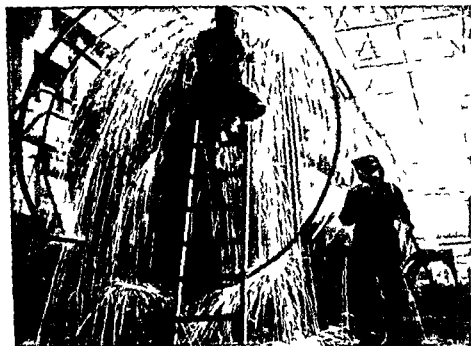
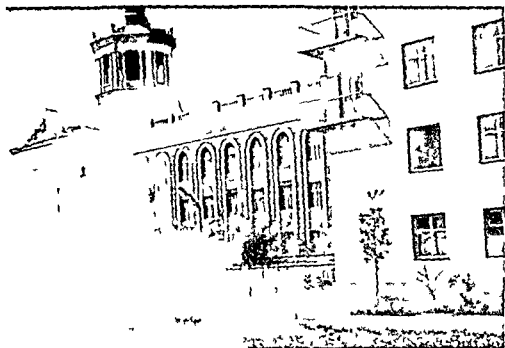


ताजिक सा० स० जनतंत्र की
राजधानी दुशान्बे का लेनिन

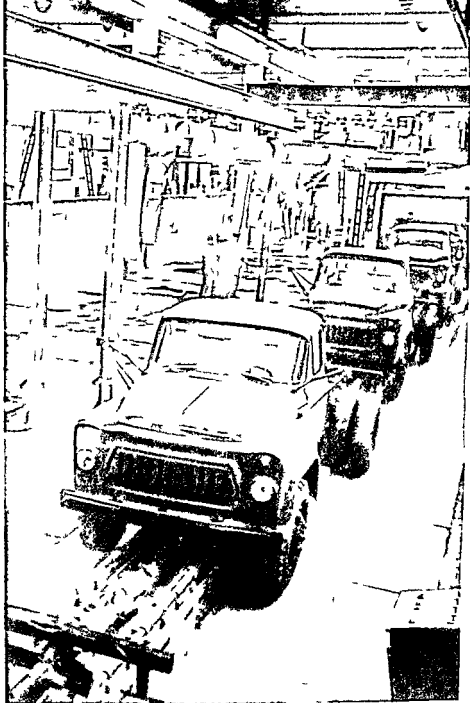


पुरमाग मा० म० जनवर रा
सकधाना धनारारा

विभिन्न मा० म० जनवर रा
सकधानी प्रज रा सारगारा
भगा



चिरचिक् उज्जेक् सा० म०
जनतन्त्र, मे रासायनिक उद्योग
के लिए यन्त्रो का निमाण



फरद रिगिद सा० म० जतात
 म एर माटर वाग्यात

चित्राल की बोलियों का व्याकरण तैयार करने में भी सहायता की। अप्रैल १९०१ में प्राच्य विद्याओं की रूसी संस्था की एक शाखा अ० ग० सेरे-ब्रेनिकोव, अ० ई० स्नमारेव, म० व० ग्रुलेव तथा अन्य प्रसिद्ध प्राच्य विदा की पहलकदमी पर ताशकन्द में स्थापित की गयी। ताशकन्द ने दो महत्वपूर्ण अखबारों—रूसी में “तुकिस्तानस्कीये वेदामास्ती” तथा उज्बेक में “तुकिस्तान विलायतिनिग गजेती” ने हिंदुस्तानी मामला में काफी दिलचस्पी ली। इस दूसरे अखबार ने उज्बेक कवि फुक्त तथा यात्री सैयद अली खाजा की भारत यात्रा के सबंध में मूल्यवान सूचनाएँ प्रकाशित की। रूसी प्राच्यविदों के साथ उज्बेक विद्वानों ने भी भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी ली। इस सबंध में सैयद रसूल खोजा, सैयद अजीज़ खोजायेव, ताहिरखेव कियाशवेकोव और खलीलुद्दीन अहमद के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ उज्बेक विशेषज्ञ भारतीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने भारत भेजे गये।

बहुतेरे हिंदुस्तानिया न मध्य एशिया में अपने लम्बे निवासकाल में वहाँ की स्थानीय भाषाएँ सीखीं। कुछ ने रूसी भी सीखी। कुछ हिंदुस्तानिया को उज्बेक और ताजिक भाषायाँ का अच्छा ज्ञान हो गया था जिसका दस्तावेजी सबूत ताशकन्द के पुरालेख-संग्रहालय के कागजात में मौजूद है। बबीरशाह मुस्ताफीन, जो कश्मीर से आये थे और ताशकन्द जिले के बेकाबाद गाँव में अपने परिवार सहित पिछली सदी के दसवें दशक में रहते थे, ताशकन्द के रहनेवाले किर्गामल और सुयमल, जो मिर्घ के शिकारपुर से आये थे, तथा अन्य हिंदुस्तानी जैसे साधुमल खिमनमलीयेव, खासा खुदायेव, गुलाममल खिमनमलीयेव और मुश्कीमल खिमनमलीयेव उज्बेक भाषा से भली भाँति परिचित थे। ज़ारशाही रूस में मध्य एशिया के विलयन के बाद हिंदुस्तानियों को रूसी व्यापारियों, कारोबारियों तथा प्रशासकों से काम पड़ने लगा। कुछ दिनों में अनेक हिंदुस्तानिया न रूसी बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। १९वीं शती के आठवें दशक में सरकारी कागजों में एक भारतीय नुका बूता का उल्लेख है जिसके बारे में कहा गया है कि वह रूसी का अच्छा ज्ञान रखनेवाला विदेशी था। हमें १९०४ में ताशकन्द में कम से कम एक हिंदुस्तानी का पता मिलता

है, जिसका काम अपन स्वदेशियों के लिए रूसी में अनुवाद करना था। उसका नाम था पीरदास शबीलदासोव। अधिकांश हिंदुस्तानी नामा के अंत में "ओव" प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसमें रूसी प्रभाव प्रकट होता है। सरकारी दस्तावेजों में यह सूचना भी है कि समरकंद में रहनेवाले एक ३२ वर्षीय हिंदुस्तानी तथा एक १६ साल के लड़के ने रूसी भाषा सीखने के लिए रूसी स्कूल में नाम लिखावाये थे। १८२६ की जनगणना में मध्य एशिया के क्षेत्र में रहनेवाले ३७ हिंदुस्तानिया का उल्लेख है। ये सब मावियत सघ के नागरिक बन गये थे। उनमें से पांच न रूसी को और एक ने उज्बेक को अपनी मुख्य भाषा लिखवाया था।

मध्य एशिया के जारशाही साम्राज्य में विलयन के बाद उस इलाके में अनेक हिंदुस्तानियों की उपस्थिति से कई रूसी प्राच्यविदा में दिलचस्पी पैदा हुई। १८६७ में ही ५० ई० पचीसों ने "कश्मीरिया की जवानी कश्मीर की कहानी" प्रकाशित की। रूसी में यह उस राज्य का पहला वर्णन है, जो ताशकन्द में रहनेवाले कश्मीरियों के माध्य लेखक के समालाप पर आधारित है। कुछ भारतीयों ने, जस रामचंद्र बालाजी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध १८५७ के विद्रोह के महान नेता नाना साहब का भतीजा थे, मध्य एशिया के अध्ययन के लिए रूसी वैज्ञानिक यात्रा-यात्रा में भाग लिया। १८८७ की गमिया में रामचंद्र ने समरकंद वैज्ञानिक यात्रा-यात्रा के सदस्य की हैमियत से मध्य एशिया का विस्तारपूर्वक दौरा किया और ग्रामूरिया की एक शाखा की प्राचीन धारा के अध्ययन में योगदान दिया। मध्य एशिया में हिंदुस्तानी प्रवासियों ने अनावादी और ताशकन्द में रूसी अफगानों के लिए हिंदुस्तानी के पाठ्यक्रम संगठित करना भी गण्यता की। विमानिकी तथा मिलफेदिंग जग रूसी अफगानों का हिंदुस्तानी बान्धन का व्यावहारिक अभ्यास मुगल में हिंदुस्तानी प्रवासियों के बीच में हुआ था। भारतीय व्यापारों अनेक गांध वही सघात में लीपाप्राप्त में छपा पुस्तक मध्य एशिया लाये थे। १८९३ में यात्रा के एक ताजिक व्यापारों ने रूसी, बम्बई, लग्नऊ, ताहोर, कापूर तथा अन्य हिंदुस्तानी रहस्य में प्रकाशित २००० पुस्तक छापा

की थी। उस व्यापारी ने बाद में बम्बई में अपना निजी छापाखाना भी वायम किया।

मध्य एशिया पर रूसी कब्जे का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर भी पड़ा। एंगेल्स ने लिखा था " जब एक प्रथम श्रेणी की यूरोपीय मजदूर शक्ति तुर्किस्तान में अपने कदम जमाती है, वल प्रयोग तथा चापनूमी दोनों से काम लेकर फारस और अफगानिस्तान को अपना अधीन बनाने का प्रयास करती है, और धीरे-धीरे मगर दृढ़तापूर्वक हिंदूकुश तथा सुलैमान पर्वतमाला की ओर बढ़ती है - तो वहाँ एक सवथा भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंग्रेजी प्रशासन कोई अनिवार्य नियति नहीं रह जाता, और स्थानीय लोगों के सामने एक नयी सम्भावना उत्पन्न होती है। शक्ति द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, शक्ति ही उसे छिन्न भिन्न भी कर सकती है " *

मध्य एशिया पर रूसी कब्जे से ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के वृत्त से भगोडो ने १८५७ के विद्रोह की असफलता के बाद बुधारा और कोवान में शरण लिया था। मध्य एशिया में रूसी आगमन से भारतीय जनगण का आशा बढी कि वे अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक अत्याचार का जूआ उतार फेंकेगे। अवश्य ही यह आशा प्रारम्भ में केवल कुछ देशी रजवाडों के शासकों तक ही सीमित थी जिनकी जनप्रिय आकांक्षाएँ उही थी और जो केवल दो औपनिवेशिक शक्तियों के अतविरोध से फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे।

सोवियत इतिहासकार नि० अ० खालकिन, ग० ल० द्मोन्त्रियेव और प० व० रसूलज़ादे ने विभिन्न दूत मंडलियों का उल्लेख किया है, जिन्हें भारतीय राजा महाराजों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता मागने के लिए तुर्किस्तान में रूसी अधिकारियों के पास भेजा था। कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह ने चार व्यक्तियों का मंडल भेजा था। इनमें से मंडल के नेता सहित दो व्यक्ति रास्ते में मार डाले गये और महाराजा का पत्र

* व० माक्स, फ्रे० एंगेल्स, रचनाएँ, खंड २२, पृष्ठ ४५। (रूसी संस्करण)

भी उनके साथ खो गया। बाकी दो—अब्दुर्रहमान खान और सरफराज खान—नवम्बर १८६५ में ताशकन्द पहुँचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनसे भेंट की, जिसके समक्ष उन्होंने मंत्री की घोषणा की और पूछा कि रूसिया से क्या आशा की जा सकती है। इस दूत-मंडल को कोई सफ़लता नहीं मिली। ज़ारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय को प्रोत्साहित करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी केवल अपने औपनिवेशिक विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिक साधनों के अभाव के कारण उस समय उसकी अभिरुचि नहीं थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से किसी प्रकार झगड़े में पड़े।

१८६६ में इंदौर के शासक ने भी इसी तरह के उद्देश्य से एक दूत मंडल ताशकन्द भेजा। दूत ने अपने को इंदौर के मुख्य मंत्री का सुपुत्र बताया। उन्होंने अनेक रजवाड़े, जैसे हैदराबाद, त्रिवानेर, जोधपुर और जयपुर के नाम पर सहायता की याचना की। लेकिन सम्भव है कि उन दूत ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के विचार से ही इतने सारे नाम ले दिए हों, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन हिंदुस्तानी राज्यों ने अग्रजों का निवाला भगाने के लिए कभी कोई एका किया हो। इस दूत मंडल का भी कोई परिणाम नहीं निवाला।

कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह का एक दूसरा दूत मंडल जून १८७० में ताशकन्द पहुँचा। इसका नेता थे बालिया नाम प्रताप। परंतु इस बार भी ज़ारशाही रूस ने कोई सैन्य या सैन्य सहायता नहीं दी। हिंदुस्तानी साम्राज्य और जागण के लिए ज़रा कहीं से हा सार समर्थन पाने का प्रयास करता स्वाभाविक ही था। मगर यह बात गंभीरता है कि उपनिवेशवादी ज़ारशाही रूस का सहायता अगर मिल भी जाती, तो इस देश का ज़रा हा सारता था। ज़ारशाही रूस “यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का जनक” और जातियों का कारागार” था, और उतना यह ज़रा ही का ज़रा सहायता करे।

भारत के सामंती राजाओं द्वारा भेजे गये इन दूत-मंडलों में क्या क्या महत्वपूर्ण गुरु परण सिंह का दूत-मंडल था, जो १८७८ में ताशकन्द पहुँचा। इस दूत-मंडल का जातिव दूत-मंडल क्या था बताया है।

इसका भारत के सामंती राजाओं से कोई संबंध नहीं था। इसे पंजाब के नामधारी सिखा ने भेजा था, जो उस प्रांत का अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना चाहते थे। गुरु चरण सिंह ने जब यह कठिन यात्रा की, तो उनकी आयु ७० वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्होंने रूसी अधिकारियों को यह समझाने की चेष्टा की कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में भारतवासियों की सहायता करना क्या आवश्यक है। यह अपने माय बालिया राम सिंह का पत्र ले गये थे जिसमें गुरु गोविंद सिंह की भविष्यवाणियों के आधार पर बताया गया था कि भारत का रूसिया के आन पर अंग्रेजी जूए से मुक्ति मिलेगी। गुरु चरण सिंह के संबंध में लिखते हुए जरफ़शान प्रांत के गवर्नर न० अ० इवानोव ने इस बात पर बल दिया कि "यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी के एक भाग ने वैदेशिक जूए से मुक्ति दिलाने के लिए हमसे सहायता मांगी है"। उन्होंने यह भी नोट किया कि "गुरु चरण सिंह से बातें करने से हमें रूस की शक्ति में ऐसे विश्वास का, ब्रिटेन के धृष्ट शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने की हमारी नियति में ऐसी आस्था का पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव में सन्देह करना असंभव हो जाता है"।* लेकिन ज़ारशाही सरकार ने हिन्दुस्तानी देशभक्तियों की प्रार्थना को फिर सुना अनसुना कर दिया। तुर्किस्तान के ज़ारशाही गवर्नर-जनरल काउफ़मन ने किसी प्रकार वचनबद्ध हुए बिना दास्ताना उत्तर दे दिया।

ग्वालियर और जयपुर के महाराजाओं ने भी १८७६ और १८८० में तुर्किस्तान में रूसी अधिकारियों के पास दूत भेज दिए थे। ग्वालियर के शासक के ब्राह्मण दूत हीरालाल से जरफ़शान के गवर्नर न० अ० इवानोव ने समरकंद में भेंट की। इवानोव ने शाहजादे इब्राहीम शाह से भी भेंट की, जो जयपुर के महाराजा का पत्र लाये थे। सोवियत

*उत्सवेक सो० स० जनतंत्र का राखीय अभिलेखागार, फाइल १। मिशन के बारे में पढ़िये पी० सी० राय द्वारा लेख, 'प्राब्लेमी वोस्तोकोवेदेनिया', १९४६, अंक ४, पृष्ठ ७७-८१। (रूसी संस्करण)

भी उनके साथ खो गया। बाकी दो—अब्दुरहमान खान और सरफराज खान—नवम्बर १८६५ में ताशकन्द पहुँचे। जनरल चेरन्यायेव ने उनसे भेंट की, जिसके समक्ष उन्होंने मैत्री की घोषणा की और पूछा कि रूसिया से क्या आशा की जा सकती है। इस दूत मंडल को कोई सफलता नहीं मिली। जारशाही सरकार को भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के ध्येय का प्रोत्साहित करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको दिलचस्पी केवल अपने औपनिवेशिक विस्तार से थी, यद्यपि पर्याप्त भौतिक साधना के अभाव के कारण उस समय उसकी अभिरुचि नहीं थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से किसी प्रकार झगड़े में पड़े।

१८६६ में इंदौर के शासकान भी इसी तरह के उद्देश्य से एक दूत मंडल ताशकन्द भेजा। दूत ने अपने को इंदौर के मुख्य मंत्री का सुपुत्र बताया। उन्होंने अनेक रजवाड़ों, जैसे हैदराबाद, बिजानेर, जोधपुर और जयपुर के नाम पर सहायता की याचना की। लेकिन सम्भव है कि उक्त दूत ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के विचार से ही इतने सारे नाम ले दिये हों, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन हिन्दुस्तानी राज्यों ने अंग्रेजों को निकाल भगाने के लिए कभी कोई एका किया हो। इस दूत मंडल का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह का एक दूसरा दूत मंडल जून १८७० में ताशकन्द पहुँचा। इसके नेता ये बालिया ग्राम प्रकाश। परंतु इस बार भी जारशाही रूस ने कोई राजनीतिक या सैनिक सहायता नहीं की। हिन्दुस्तानी राजाओं और जनगण के लिए जहाँ वहाँ से हो सके समर्थन पाने का प्रयास करना स्वाभाविक ही था। मगर यह बात सन्देहजनक है कि उपनिवेशवादी जारशाही रूस की सहायता अगर मिल भी जाती, तो इससे देश आजाद हो सकती था। जारशाही रूस 'यूरोपीय प्रतिक्रिया का जनडाम' और "जातिया का बारागार" था, और उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि निस्स्वार्थ सहायता करे।

भारत के सामंती राजाओं द्वारा भेजे गये इन दूत मंडलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु चरण सिंह का दूत-मंडल था, जो १८७६ में ताशकन्द पहुँचा। इस दूत मंडल को जनप्रिय दूत मंडल कहा जा सकता है।

इसका भारत के सामंती राजाओं से कोई सबध नहीं था। इसे पंजाब के नामधारी सिखों ने भेजा था, जो उस प्रांत का अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना चाहते थे। गुरु चरण सिंह ने जब यह कठिन यात्रा की, तो उनकी आयु ७० वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्होंने रूसी अधिवारियों को यह समझाने की चेष्टा की कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के सपना में भारतवासियों की सहायता करना क्यों आवश्यक है। वह अपने साथ बालिया राम सिंह का पत्र ले गये थे जिसमें गुरु गोविंद सिंह की भविष्यवाणियों के आधार पर बताया गया था कि भारत की रूसियों के आने पर अंग्रेजी जूए से मुक्ति मिलेगी। गुरु चरण सिंह के सबध में लिखते हुए ज़रफ़शान प्रांत के गवर्नर न० अ० इवानोव ने इस बात पर बल दिया कि "यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी के एक भाग ने वैदेशिक जूए से मुक्ति दिलाने के लिए हमसे सहायता मांगी है"। उन्होंने यह भी नोट किया कि "गुरु चरण सिंह से बातें करने से हमें रूस की शक्ति में ऐसे विश्वास का, ब्रिटेन के धृणित शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने की हमारी नियति में ऐसी आस्था का पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया की आवादी पर हमारे महान नैतिक प्रभाव में मदेह करना असम्भव हो जाता है"।* लेकिन ज़ारशाही सरकार ने हिंदुस्तानी देशभक्तियों की प्रार्थना को फिर सुना अनसुना कर दिया। तुर्किस्तान के ज़ारशाही गवर्नर-जनरल काउफ़मन ने किसी प्रकार वचनबद्ध हुए बिना दोस्ताना उत्तर दे दिया।

खालियर और जयपुर के महाराजाओं ने भी १८७६ और १८८० में तुर्किस्तान में रूसी अधिवारियों के पास दूत मंडल भेजे थे। खालियर के शासक के ब्राह्मण दूत हीरासाल से ज़रफ़शान के गवर्नर न० अ० ट्रा नोव ने समरकंद में भेंट की। इवानोव ने शाहज़ादे इब्राहीम शाह से भी भेंट की, जो जयपुर के महाराजा का पत्र लाय थे। सोवियत

*उल्लेख सो० स० जनतंत्र का राजकीय अभिलेखागार, फाइल १। मिशा के बारे में पढ़िये पी० सी० राय द्वारा लेख, 'प्राग्नेमी वोस्तोकोवेदेनिया', १९५६, भाग ४ पृष्ठ ७७-८१। (रूसी संस्करण)

इतिहासकार इ० अ० रुस्तामोव ने १८६१ में हुआ के शासक के दूत मडल की यात्रा का उल्लेख किया है। १६०३ में बम्बई में रूसी कौन्सल व० ओ० क्लेम ने रूसी विदेश मन्त्रालय को सूचना दी कि उनके पास गुमनाम चिट्ठियाँ आ रही हैं जिनमें अंग्रेज़ों के प्रति घणा तथा यह आशा व्यक्त की जाती है कि रूस शीघ्र ही भारत की धरती पर प्रकट होगा।

अंग्रेज़ों को इन सम्पत्तियों का पता चल गया था। इसलिए उन्होंने रूसी अधिकारियों से मिलने मध्य एशिया जानवाले भारतीय प्रतिनिधियों का पीछा करने का पक्का प्रबंध किया। इस काम में उन्हें गुलाब खान नामक एक हिन्दुस्तानी से सहायता मिली। उसने भारत तक गुरु चरण सिंह का पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। गुलाब खान अपनी पत्नी सहित कत्ता कुर्गन में बस गया था, जहाँ उसने दवा की दुकान खोल ली थी। उसे ब्रिटिश इंडियन सेना के एक भगाड़े सैयन् खान से, जो जरफशान के रूसी गवर्नर का सहायक बन गया था, और दो यहूदिया रिउवेन तथा इसहाक से, जो नमश पुलिस अधिकारी और जरफशान के गवर्नर का दुभाषिया थे, सूचना मिली थी। गुलाब खान ने अपने एजेंटों ताजिक मुल्ला इनाम और गुलाम मुहिउद्दीन के जरिये भारत में अंग्रेज अधिकारियों को सवाद भेजा। ये दोनों कत्ता-कुर्गन के रहनेवाले थे। गुलाब खान की भेजी हुई सूचना भारत के राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय में मौजूद है और उससे कश्मीर के महाराजा तथा नामधारी सिखों के भावी सम्पर्कों पर दिलचस्प प्रकाश पड़ता है। इन सम्पर्कों के बारे में उल्लिखित रूसी स्रोतों से कुछ पता नहीं चलता। राष्ट्रीय पुरालेख-संग्रहालय में गुलाब खान के जा पत्र हैं, उनसे हमें ज्ञात होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के गुप्तचर विभाग के प्रधान अफसर सिंह ने १८७० में कम प्रकाश के दूत मडल के तुरंत बाद एक और व्यक्ति गंगा रास ठागरा का महाराजा का सन्देश देकर भेजा। गुलाब खान की सूचना के अनुसार गंगा रास समरकन्द में चार साल तक रहा और रूसी स्कूल में पढ़कर अच्छी रूसी सीख ली। जम्मू लौटने के बाद उस तहसीलदार बना दिया गया। गुलाब खान ने एक और कश्मीरी अधिकारी शेर सिंह का भी उल्लेख किया है जिसे कश्मीर के शासक ने १८७२ में तुर्किस्तान भेजा था।

ब्रिटिश एजेंट की सूचना के अनुसार वह ताशकन्द में जनरल काउफमन से मिला। गुलाब खान ने लिखा है कि रूसियों ने १८८० में युसूफज़ई के एक व्यक्ति अब्दुल को कश्मीर भेजा, जो एक और कश्मीरी प्रणिधि जीवन मान डोगरा को साथ लेकर ताशकन्द लौटा। अब नामधारी प्रणिधिया में गुलाब खान ने पटियाला के एक ब्राह्मण जस राम और इलाही वस्त्राभीरासी का उल्लेख किया है, जिन्होंने समरकन्द के रूसी गवर्नर के समक्ष अपने आप को पेश किया। कहा जाता है कि उसने उन्हें अपने सहायक सैयद खान के पास भेज दिया, जिसने उनके बाग़ पकड़कर उन्हें निवाल दिया। गुलाब खान ने गुरु चरण सिंह के बारे में भी लिखा है (जा उस समय बंद थे) कि उन्होंने शिकारपुर के निवासी शम्भू के जरिये बुखारा से रूसी गवर्नर के नाम एक पत्र जनवरी १८८२ में डाक में डनवाया। इस पत्र के मिलने पर गवर्नर अब्रामोव ने जस राम को दूढ़ने का आदेश दिया। वह बुखारा में मिला और वहां से लाया गया। गुलाब खान की सूचना के अनुसार जनवरी १८८२ में जस राम का गुलाम रसूल के साथ, जिसे वह रूसी एजेंट कहता है, भेंट-उपहार देकर जम्मू में भेजा गया। उनको जा पत्र दिया गया था, वह एक कश्मीरी बचक मसूख की सहायता से डोरी में लिखवाया गया था। मन्मूख कत्ता-कुर्गान में रहना और रूसी पढ़ रहा था।

रूसी अधिकारियों के पास इन दूत-मंडलों के भेजन से भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को कोई लाभ नहीं हुआ। परन्तु इनसे इतना अवश्य प्रकट हुआ कि भारतीय जनगण को अंग्रेज़ा के विरुद्ध अपने सघर्ष में रूसी सहायता की बड़ी आशा थी। १८७६ में बम्बई में रूसी मुद्र-पोता के आने के समाचार पाकर लोग शहर की ओर यह देखने को दौड़ पड़े कि वे सचमुच वहां आये हैं। रूसी सहायता के सवध में भारतीय देशभक्तों की आशाओं का एक उल्लेखनीय पन्चिय इस बात से मिलता है कि तिलक न बम्बई स्थित रूसी कौनमला चेकिन तथा कनेम से वार्तालाप किया था। उनसे उन्होंने रूसी फर्मों से परिचय कराने का अनुरोध किया ताकि भारत में फैक्टरिया की स्थापना के लिए मशीनरी खरीदी जाय, और सैनिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय नवयुवकों को रूस भेजन में सहायता

मागी। ज़ारशाही रूसी सरकार हिंदुस्तानी जनगण को सहायता देने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। इस तथ्य से “भारत की रूसी खतरे” के मिथ्या प्रचार का भाड़ा फट जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह खतरा अंग्रेज़ा की मनगढ़त था, जिससे वे मध्य एशिया में अपने निदिष्ट आक्रमण पर परदा डालना चाहते थे।

१९१७ की महान् अक्टूबर समाजवादी क्रांति द्वारा मध्य एशिया के आज़ाद होने के बाद यह इलाका भारतीय स्वाधीनता के अनेक सेनानियों के लिए आकषण का केन्द्र बन गया, जिन्होंने ताशकन्द को अपनी क्रांतिकारी सरगमियों का एक मरकज बनाया। पश्चिम में लंदन, पेरिस, बर्लिन, स्टॉकहोम, ‘यूयाक’, सान फ्रांसिस्को और बैलीफोनिया में तथा पूर्व में टोकियो में भारतीय क्रांतिकारियों के कायकलाप से लोग भली भाँति परिचित हैं, परंतु महान् अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद के दौर में सोवियत एशिया में उनकी सरगमियों का ज्ञान कम लोगों को है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अनेक राष्ट्रीय क्रांतिकारी ब्रिटेन की विरोधी वैदेशिक शक्तियों से सहायता मागने के लिए भारत से विदेश चले गये थे। चूँकि ज़ारशाही रूस ब्रिटेन का मित्र था, इसलिए उससे सहायता मिलन का कोई सवाल ही नहीं था। १९१५ में बर्लिन स्थित भारतीय क्रांतिकारी समिति ने हेटिंग मिशन में राजा महेन्द्र प्रताप और बक्तुल्लाह को शामिल कराया। यह मिशन ब्रिटेन के विरुद्ध अमीरों को अपने साथ मिलाने के लिए साम्राज्यवादी जर्मनी द्वारा अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा था। काबुल में राजा महेन्द्र प्रताप ने “भारत की अस्थायी सरकार” की स्थापना की, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष बन, और बक्तुल्लाह का प्रधान मंत्री तथा ज़वेदुल्लाह सिद्दी को गृह मंत्री बनाया। अपने जर्मन सलाहकार हेटिंग की सलाह के बावजूद राजा महेन्द्र प्रताप ने ज़ारशाही हम से भी सहायता मागन का प्रयत्न किया। उन्हें इस क्षेत्र में आग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता के कारण कुछ आशा थी। मगर तीव्र ही उन्हें निराश होना पड़ा। ताशकन्द में ज़ारशाही रूस के अधिकारियों ने ज़ार के नाम—उनके ‘स्वर्ण घात पत्र’ का कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी बार उन्होंने जिन दो दूतों को

ताशकन्द भजा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ईरान में अग्रेजों के हवाले कर दिया गया। अग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी।

परन्तु जारशाही रूस ने भारतीय जातिवारियों द्वारा सम्पन्न स्थापित करने के सभी प्रयासों को अंगर अस्वीकार कर दिया, ता सोवियत सरकार ने उन लोगों का स्वागत किया, जा भारत की स्वाधीनता के लिए काम करना चाहते थे। उसने खुल्लमखुल्ला पूव की सभी दलित जातियों के लक्ष्य का समर्थन किया। भारतीय सवैधानिक सुधारों के सबध में माटेगु-वैल्सफोर्ड रिपोर्ट (१९१८) ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि रूस की आति से "भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रेरणा मिली है"। मध्य एशिया के विभिन्न नगरों में कई हजार हिंदुस्तानी बसे हुए थे, जा भारत के एक निकटवर्ती इलाके से ब्रिटिश विरोधी कायकलाप के लिए अच्छे आधार का काम द रहे थे। दूसरे, सुनसान पहाड़ी दर्रा में होकर इस इलाके में भाग आना समुद्र के रास्ते यूरोप जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित था। इसलिए अक्तूबर समाजवादी आति के पीछे पीछे सोवियत एशिया में भारतीय देशभक्तों का स्थायी धारा-सी बहने लगी।

१९१८ में १९२० तक हिंदुस्तानियों के कई दल भारत की स्वाधीनता के लिए सोवियत सहायता की आशा में मध्य एशिया पहुंचे। फरवरी १९१८ में महेन्द्र प्रताप तुकिस्तान सोवियत अधिकांशियों ने निमंत्रण पर ताशकन्द आये और वहां से पेत्रोग्राद के लिए रवाना हुए जहां उच्च सरकारी नेताओं ने उनसे भेंट की। पेत्रोग्राद से महेन्द्र प्रताप बलिन गये। उनके बाद "भारत की अस्थायी सरकार" के कई प्रतिनिधि कावन से सोवियत सघ आये। ताशकन्द और बुखारा के मध्य एशियाई नगरों के अलावा वे मास्को और कज़ान में भी रहते और काम करते थे और अफगानिस्तान से सम्पन्न स्थापित करने में उन्होंने नवजात सोवियत राज्य की विशेष सहायता की।

अमानुल्लाह खान के अमीर बनने के बाद मार्च १९१९ में दक्खिनाह ताशकन्द के रास्ते मास्को पहुंचे। नये अमीर ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि सोवियत रूस से स्थायी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर। ७ मई, १९१९ का वे लेनिन से मिले। महेन्द्र प्रताप उस समय जमनी में

थे। ब्रिटेन और अफगानिस्तान की लड़ाई का समाचार पाते ही उन्होंने मास्का होते हुए अफगानिस्तान लौटने का निश्चय किया। सावियत इतिहासकार म० अ० पेसित्स के अनुसार महेन्द्र प्रताप जुलाई १९१९ में मास्का लौटे। उनके साथ अब्दुरव और प्रतिवादी आचाय भी थे। वहाँ उनसे बकतुल्लाह मिले। महेन्द्र प्रताप के आने के शीघ्र ही बाद उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें बकतुल्लाह, अब्दुरव प्रतिवादी आचाय, दलीप सिंह गिल और पंजाब का एक किसान इब्राहीम भी था, लेनिन से भेंट की। सोवियत वैदेशिक कमिसारियत से अपने वार्तानाप में महेन्द्र प्रताप ने माग की कि सोवियत सरकार काबुल स्थित उनका "भारत की अस्थायी सरकार" को भारत की आतंककारी शक्तियों के एकमात्र केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए सोवियत अफगान सैनिक कारवाई की भी योजना पेश की।

काबुल स्थित "भारत की अस्थायी सरकार" का एक विशेष मंडल, जिसमें मोहम्मद अली और शफीक अहमद थे, ३१ मार्च, १९२० को ताशकन्द पहुँचा। बाद में इब्राहीम और अब्दुल मजीद भी उनमें आ मिले। इन लोगों ने बकतुल्लाह से मिलकर "अस्थायी सरकार" का दल स्थापित किया। इस दल ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए वैदेशिक सैनिक अभियान पर जोर दिया, यद्यपि वह राष्ट्रीय सेना संगठित करने की बात भी करता था। बकतुल्लाह ने तुर्की युद्ध-वैदिकता में तथा वोल्गा क्षेत्र और मध्य एशिया के मुसलमानों में सोवियत सत्ता के समर्थन में प्रचार किया और अनेक पुस्तिकाएँ लिखी, जिनमें बाल्योविस्म का इस्लाम का मित्र साबित किया गया था और दोनों के सामाजिक आदर्शों और मित्रता की समानता को पेश किया गया था। बकतुल्लाह दल के विचारशील लोग का विकास वामपंथी तथा समाजवादी विचारों की दिशा में हुआ और उसके कई सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय पंचार की सोवियत के लिए सक्रिय रूप में काम करने लगे, जिसकी स्थापना वैश्वीय कामवाग्विपी समिति के तुर्की आयोग द्वारा दिसम्बर १९१९ में ताशकन्द में हुई थी। इस संगठन का काम सोवियत तुर्किस्तान में काम करनेवाले अनेक आतंककारी

संगठना को पड़ोसी देशों में काम करनेवाले संगठनों से एकताबद्ध करना था। "सोवियन्तप्रोप" (अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की सोवियत) के भारतीय विभाग ने कुछ हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश इंडियन सेना व सिपाहियों में काम करने बाबू और ईरान भेजा और सीमावर्ती कबोला में काम करने पामीर भेजा। इसमें अनेक पैफलेट और पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित कीं। इससे साप्ताहिक पत्र "जमीदार" का एक अंक ताशकन्द से प्रकाशित हुआ।

संगठित भारतीय राष्ट्रीय आतिशारिया का एक नया और बड़ा दल २ जुलाई १९२० का काबुल में ताशकन्द पहुँचा। इससे नेता अब्दुरख के और इससे सदस्यों की संख्या २८ थी। उन्होंने काबुल में ही भारतीय आतिशारी सस्था के रूप में अपने को संगठित कर लिया था। सस्था ने काबुल से लेनिन के नाम पर अभिनन्दन सवाद भेजा था, जिसका उन्होंने बड़ा उत्साहवर्धक उत्तर भेजा था। ताशकन्द में इन लोगों का सम्मान में एक सार्वजनिक सभा की गयी, जिसमें व० व० यूइविशेव तथा म० व० फूजे जैसे प्रमुख सोवियत नेता भी उपस्थित थे। भारतीय आतिशारी सस्था के सदस्यों में १०-१२ ब्रिटिश सेना के भागे हुए लोग भी थे। अब्दुरख के साथ जो लोग ताशकन्द आये उनमें दो नसीर खान भाई भी थे जो स्वतंत्र चलूच कबोला के नेता थे जिन्होंने १९१७-१९१८ में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रतिवादी आचार्य भी इन दल के साथ थे। भारतीय आतिशारी सस्था के सात सदस्य उन १४ भारतीय प्रतिनिधियों में थे, जिन्होंने सितम्बर १९२० में पूब की जातियों की बाबू कांग्रेस में भाग लिया था। सस्था के सदस्यों की धारणा थी कि स्वतंत्र कजाखली सीमावर्ती लोगों के समर्थन से भारत को सोवियत रूस द्वारा स्वाधीन कराया जाय। अवश्य ही सोवियत पक्ष इस प्रकार के दुस्साहसिकतावादी सैनिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता था। फिर भारतीय आतिशारी सस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की सोवियत के भारतीय विभाग में तीव्र अनद्वंद्व पदा हो गया और इसमें भी ताशकन्द में भारत की स्वाधीनता के आतिशारी काम की प्रगति में बाधा हुई।

सितम्बर अक्टूबर १९२० में हिन्दुस्तानी मुहाजिरीन का एक दल कठिन यात्रा के बाद ताशकन्द पहुँचा। ये लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता

आन्दोलन के मुस्लिम अंग के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलन के दौरान खिलाफत की बहाली की खातिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश को त्याग किया था। अफगान सरकार ने सोवियत मध्य एशिया से होकर उनके तुर्की जाने का विरोध किया। उस विरोध को दूर करने के बाद हिंदुस्तानी मुहाजिरीन दो जत्था में तेरमीज की ओर रवाना हुए। हर जत्थे में ८० आदमी थे। पहले जत्थे के नेता थे मोहम्मद अकबर खान। इसमें अनेक शिक्षित नौजवान मुसलमान थे। इसको तुक्मान आतिविरोधिया ने पकड़ लिया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। लाल सेना ने उन्हें उनके हाथ मारे जाने से बचा लिया। बाद में इस जत्थे के कुछ लोगो ने किरकी किले पर आतिविरोधियों के हमले का परास्त करने में सोवियत सेना की सशस्त्र सहायता भी की। अतः इन मुस्लिम नौजवानों के दिल में तुर्की जाने का इरादा छोड़ दिया और ताशकंद जाने पर राजी हो गया। जो बहुतेरे तुर्की गये, वापस ताशकंद लौट आये, क्योंकि कमालपाशा का तुर्की अब उंह लेना नहीं चाहता था। वे जिस खिलाफत की रक्षा करने निकले थे, उसे तुर्की में मिटा दिया था। नवम्बर १९२० तक ताशकंद में अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ कोई १०० हिंदुस्तानी सेनानी जमा हो गये थे। दिसम्बर १९२० तक उनकी सख्या लगभग २०० हो गयी। कोमिटन के तुक-ब्यूरो ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को अधिकाधिक खिलाफती मुहाजिरा के आने की सूचना दी। बुखारा में १९२० के अन्त तथा १९२१ के प्रारम्भ में अनेक हिंदुस्तानी मुहाजिर आये जिनमें कोई २० बंगाली भी थे।

एम० एन० राय और अबनि मुखर्जी अक्टूबर १९२० में ताशकंद पहुँचे। वे खिलाफती मुहाजिरीन के बड़ी सख्या में आने की खबर सुनकर मध्य एशिया पहुँचे थे। उन्होंने सोचा कि यह स्वाधीनता सेना का केन्द्रीय दस्ता बनाने का अच्छा अवसर है। इस सेना का संगठन अफगानिस्तान में भारत के सीमावर्ती कवायलिया का लेकर करना था, जिनमें ब्रिटिश विरोधी भावना तगड़ी थी। ताशकंद आने से पहले राय मास्को में ही अखिल भारतीय अस्थायी केन्द्रीय आतिकारी समिति की स्थापना कर चुके थे, जिसमें कोमिटन की दूसरी कांग्रेस में भाग लेनेवाले हिंदुस्तानी शामिल थे। यद्यपि

राय साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का मयुक्त मोरचा बनाने की लेनिनवादी ढाइन को, जिसे दूसरी कांग्रेस में स्वीकार किया गया था, मानने का दावा करते थे, परन्तु उन्हीं ने न केवल राष्ट्रीय पजीपति का से, बरिच राष्ट्रीय क्रान्तिकारी संगठना से भी सहयोग के प्रति अपना नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं त्यागा था। उनकी क्रान्तिकारी समिति का सुरत ही भारतीय क्रान्तिकारी सम्या से, जिसके नेता अन्दुरख और आचाय थे, बगडा हो गया। दिसम्बर के शुरू में अन्दुरख को, जिह क्रान्तिकारी समिति का सदस्य बना लिया गया था, मगठन से निवाल दिया गया। राय और अन्दुरख के मतभेद इतने तेज हो गये कि तुर्किमान की कम्युनिस्ट पार्टी के तुव-व्यूरो १ ३१ दिसम्बर, १९२० का एक समुन्न बैठन में उसके समाधान के लिए उह मास्को जान की मलाह दी।

ताशकन्द में अपने सक्षिप्त निवासकाल में राय को पूव में कम्युनिस्ट आन्दोलन संगठित करने की व्यावहारिक कठिनाय्या का सामना करना पडा। उस समय तब उहे इन समस्याओ का कोई परिचय नहीं था। वे समझते थे कि ब्रिटिश शासा से मुक्ति पाने के राष्ट्रीय संग्राम पर सवहारा का अधिनायकत्व स्थापित करना यायाधिक काम है। परन्तु वह खिलाफनी मुहाजिरीन की बडी सख्या को तालकन्द में राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रशिक्षण पाने पर राजी नहीं कर सके। इससे उह एक सवक मिला। सैनिक प्रशिक्षण के आकषण से भी उहे अपने अनुयायी बनाने में सफलता नहीं हुई। तालकन्द के सैनिक स्कूल में १९२० के अत तक केवल २५ हिंदुस्तानी मुहाजिरीन शामिल हुए और उनकी अधिक से अधिक सख्या माच १९२१ में ३६ तक पहुची और उसके बाद घटने लगी। मई १९२१ में यह स्कूल ाद कर दिया गया और उसमें प्रशिक्षण पानेवाले भारतीयों को पूव के अमजीवियों के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए मास्को भेज दिया गया। बाद में भारत लौटने पर अंग्रेजों ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया। उनपर पेशावर साजिश मुकदमा चलाया गया और विभिन्न अवधि के लिए सजाए दी गयी। तालकन्द में भारतीय मुक्ति सेना संगठित करने की योजना को धक्का इस बात से भी लगा कि अफगान सरकार ने इसे अपने इलाके से होकर भारत जाने

की आज्ञा देने से इनकार कर दिया। वैसे भी भारत में मुख्यतया बाहरी सैनिक अभियान के जरिये सामाजिक राजनीतिक क्रांति करने की योजना अत्यंत अव्यावहारिक थी। इससे निम्न पूँजीवादी क्रांतिवाद की व आती थी। इसमें सन्देह नहीं कि गहपुद्ध में लाल सेना की शानदार विजय के कारण बहुतेरे भारतीय देशभक्तों के मन में क्रांतिकारी सघर्ष के सैनिक उपायों की श्रेष्ठता का सिक्का जम गया था। परन्तु वे यह भतने लगे थे कि लाल सेना को क्रांतिकारी जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस जनता को बोल्शेविकों ने संगठनात्मक तथा विचारधारात्मक रूप से अच्छी तरह तैयार किया था।

सिवयाग में अंग्रेजों की साजिशें

काशगर को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अंग्रेजों का प्रयास १९वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में ही शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अस्तित्व का अधीक्षक विलियम मरनाफ्ट १८२१ में लेह गया जहाँ उसने लद्दाख से होकर चीनी और उज्बेक तुर्क व्यापारियों के आने जाने के बारे में एक समझौता किया। उसने चीनी अधिकारियों से काशगर जाने की आज्ञा भी मागी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। मरनाफ्ट ने काशगर के रास्ते रूसी हमले का हौआ उस समय खड़ा किया, जबकि रूस ने अभी वज्राख स्टेपी पर भी कब्जा नहीं किया था। आगा मेहदी नामक एक रूसी एजेंट के लद्दाख के शासक तथा रणजीत सिंह से भट करन आने के संबंध में जो अपवाहें फैली हुई थी, मरनाफ्ट को उनपर विश्वास था। लद्दाख में उसने रणजीत सिंह के विरुद्ध पड़यत्न में भाग लिया।*

मरनाफ्ट के बाद अन्य यूरोपीय "खोज-यात्री", जैसे गेराड बिरादरान, हेडरसन, फालक्नर और विगने लद्दाख, कश्मीर और

बलूचिस्तान में सक्रिय रहे।* अंग्रेजों की सहमति से ही गुलाब सिंह ने, जो रणजीत सिंह का जागीरदार था, १८३४ में लद्दाख पर अधिकार कर लिया। सिंध की पराजय के बाद अंग्रेजों ने गुलाब सिंह का कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का महाराजा बना दिया। उसे आदेश था कि सीमा में कोई हेरफेर करने से पहले अंग्रेजों की अनुमति ले और पड़ोसिया से सारे थगड़े निवटाने के लिए अंग्रेजों के पास ले जाये। १८४६ में रहा-सहा सिंध राज्य भी समाप्त हो गया और ब्रिटिश भारत की सीमाएँ गुलाब सिंह के इलाके से और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सिक्खों से आ मिली।

सिक्खों में अब अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जून १८६१ में सिक्खों से व्यापार के बारे में एक छपी हुई प्रश्नावली पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा पंजाब के अधिकारियों के पास भेजी गई। इस प्रश्नावली के आधार पर पंजाब की सरकार के सचिव २० ह० डेवीस ने एक विस्तारित रिपोर्ट तैयार की। डेवीस इस नतीजे पर पहुँचा था कि मध्य एशिया की मंडिया में भारतीय व्यापार रूसी व्यापार का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है।**

पंजाब के उत्साही अधिकारियों के लिए भारत और सिक्खों के बीच बारबानी रास्ते की भौतिक कठिनाइयाँ व्यापार में उतनी बाधक नहीं थी जितना हुआ कबायलिया के हमले, राजनीतिक अव्यवस्था और चीनी अधिकारियों की उदासीनता। उन्होंने कश्मीरी अधिकारियों की अनुरोधक व्यापार-नीति का भी कुछ दोष ठहराया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर राबर्ट माटगोमरी ने हिमालय पार के व्यापार के विकास में बनी दिलचस्पी ली। १८६४ में कश्मीर के महाराजा को आपात और परिवर्तन कर में कमी करने पर राजी कर लिया गया।

* इन खोज-यात्राओं के सवध में द० S A Hedin, *Southern Tibet*, Chapter VII—*History of Exploration in the Kara Koran Mountains*, Stockholm 1922 ईश्वरी प्रसाद झा "खोज-यात्रियाँ" को "साम्राज्यवाद के माग शोधक" कहते हैं (*History of Modern India* 1951, p 167)।

** National Archives F D S P, Aug 1874, Nos 205 07

सिक्खों की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई, जब १८६६ में बोकान के याकूब बेग न सत्ता समाली। याकूब बेग ने व्यापारिक सबंध कायम करने के लिए पंजाबी अधिकारियों के उत्साह का प्रतिदान किया और अपने शासन के प्रथम वर्ष में एक व्यापार मंडल कश्मीर भेजा।* उसने रिंगिज और हज्जा लुटेरों का चाय के कारवान लटने से रोकना और लेह के व्यापार के रास्तों की रक्षा करने का वायदा किया। सिक्खों से चीनियों के निकाले जाने से भारतीयों को सुनहरा अवसर मिला गया। बागडा के चाय के नये बागानों को, जो कुरू के रास्तों पर थे, इसमें बहुत लाभ होने की आशा थी।

डा० कली न, जो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर थे, काशगर के रास्ते को बेहतर बनाने के बड़े प्रयत्न किये और यारकंद के व्यापारियों का भारत से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। चांग चेमो मांग की खोज करने का श्रेय उही को दिया जाता है। शो और हवड ने बाद में यही रास्ता लिया। डा० केली ने याकूब बेग से मंत्री-सहि कराने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल काशगर भेजने का प्रस्ताव रखा। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।** लेह में व्यापारियों के जरिये जो सूचनाएं मिल रही थी, उससे डा० केली ने यह अनुमान लगाया कि अमीर अंग्रेजों से दोस्ती रखना चाहता है। इसकी पुष्टि शो की रिपोर्ट से भी हुई, जो १८६८ में व्यक्तिगत रूप से यारकंद गया था। याकूब बेग के राज में मैत्रीपूर्ण सबंधों की शुरुआत उस समय हुई, जब १८६८ की गमिया के प्रारम्भ में उसके प्रतिनिधि माहम्मद नजीर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भेंट की। शा ने इस प्रतिनिधि से अपनी काशगर जान की इच्छा प्रकट की और प्रतिनिधि ने इस विचार का स्वागत किया। दिसम्बर १८६८ में शो काशगर रवाना हुआ जहां उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट हवड का भी देश में आने की आशा दी गई। शा ने अमीर से 'तुर्की के सुलतान मुसलमानों के खलीफा के प्रति

* *Letters from India and Madras* vol I, p 845

** National Archives F D S P Aug 1871 Nos 205 07

इंग्लैंड की दोस्ती" की चर्चा की।* उसने यारकंद के रास्ते के सबध में "स्मृति पत्र" लिखा, जिसमें उसने मध्य एशिया के इलाकों तक अबाध व्यापारिक रास्ते के लिए कश्मीर से वातचीत का सुझाव दिया। उसने कराकुरम के बदले चांग-चेमो के रास्ते को ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इसमें दरें और नदिया कम पार करनी होती थी और घास, इधन, सामान आदि आसानी से मिल जाता था। लद्दाख के लिए वह कागडा, कश्मीर के रास्ते के मुकाबले में कुछ लाहल रास्ते को ज्यादा पसंद करता था।** अगले दस वर्ष तक दोनों व्यापारिक रास्ता पर वाद-विवाद जारी रहा। १८७४ में लेह के ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर कप्तान इ० मोलोय ने बुलू रास्ते के मुकाबले में कश्मीर रास्ते का ज्यादा पसंद किया, 'क्योंकि वह ३५ मील कम था और कम से कम साल के नौ महीने चाल रह सकता था, जबकि बुलू का रास्ता छह महीने बन्द रहता था।' मोलोय ने थोड़ा के बजाय ऊँटा के इस्तेमाल की सिफारिश की, क्योंकि हसी भी यही कर रहे हैं और यातायात के खर्च में कमी कर रहे हैं। उसने यह भी शिकायत की कि अंग्रेजी सामान तुर्कों की पसंद का नहीं होता, जबकि हसी सामान "अपनी चमक-दमक और भड़कीले रंगों और बहुत मजबूत होने की वजह से" पसंद किये जाते हैं।*** मोलोय काशगर के लिए कुगियार के रास्ते को तरजीह देता था, जबकि जलधर डिवीजन के कमिश्नर फोरसाइथ की राय में चांग-चेमो का रास्ता ज्यादा अच्छा था। शो ने भारत और सिक्किम के बीच व्यापार की बड़ी रंगीन तस्वीर खींची है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यारकंद ट्रेडिंग कम्पनी की स्थापना की गई।

* National Archives Pol A, July 1870, Nos 73 76
D C Boulger, *The Life of Yakoob Beg* London, 1878, pp 214—215

** National Archives Memorandum by Shaw Foreign Department, Sec, July 1876 No 30

*** National Archives, Pol A May 1874, Nos 37 39,
E Molloy to the Secretary, Punjab Government

सिक्याग से व्यापार के लिए उत्साह की यह लहर अनेक "पयवेभणो" का नतीजा थी, जिसका प्रारम्भ १८५५ में हुआ था। छह वर्षों के दौरान भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के सर्वेक्षक ने अपना काम लदाख और कश्मीर तक फैला दिया था। १८६८ तक इस इलाके के नये नक्शे तैयार कर लिए गये। काशगर में लारेस द्वारा अपनाया गई "अहस्तक्षेप" की सावधानीपूर्ण नीति के बारे में बहुत बात का बताई बनाया गया है। इस सबध में यह उल्लेखनीय है कि कराकुरम के उत्तर की भूमि के बारे में अंग्रेज़ों का ज्ञान उस समय तक अस्पष्ट था। एकमात्र यूरोपीय जिसके बारे में मालूम था कि उसने कराकुरम को पार किया है, अलेक्सांद्र गाडनर था। उसने इस पहाड़ के रास्ते लदाख में प्रवेश किया था। तीन श्लागिटवैट बिरादर नं १८५४ और १८५८ के बीच कम्पनी की ओर से इस इलाके की छानबीन की। यारकन्द में अब्दुल्फ श्लागिटवैट की हत्या से इस क्षेत्र में प्रवेश करने का यूरोपीय उत्साह कुछ ठंडा पड़ा गया। मगर काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ और देशी एजेंटों के हवाले कर दिया गया। देशी एजेंटों का प्रयोग कोई नया नहीं था। मरनापट ने अपने कमचारी मीर इब्जतुल्लाह को १८९२ में काशगर भेजा था।* १८५२ में अहमद शाह नक्शबन्दी और १८५८ में मोहम्मद अमीन को वहां भेजा गया था। जब कप्तान माटगोमरी कश्मीर का सर्वेक्षण कर रहा था, तो उसने इस इलाके के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए देशी कमचारियों को प्रशिक्षित किया था। ऐलंडर लिखता है

'१८६३ से असाधारण व्यक्तियों का ताता लगा हुआ था, जो मिथ्या या सक्षिप्त नाम रखकर, बेस बदलकर और खोखले प्राथना चक्र या दशम की जपमाला लेकर ताकि चरणा की गिनती आसानी से की जा सके, पूरे उत्तर पश्चिम सीमा-क्षेत्र में फैल गये थे।' **

* *Calcutta Quarterly Oriental Magazine and Register*, III and IV (1825)

** ग० ज० ऐलंडर उपराक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१। देशी "सर्वेक्षकों" के बारे में द० K Mason *Abode of Snow* London 1955

एक आदमी से सरकार"। और अतः मे उसने लिखा "और यह बहुत जरूरी कील कुएन लुएन पवतमाला के उस पार आसानी से मिल सकती है।"*

फोरसाइथ, शो और हेवड ने काशगर से रूसी आक्रमण का हौआ खड़ा किया। फोरसाइथ को जब यह अंदाजा हुआ कि पहाड़ी रेगिस्तानी भूमि पर कुछ सी घोड़सवारों को भी रखना कितना कठिन है, तो उसने अपना विचार बदल दिया। मगर शो और हेवड यह चूठा डर फलाते रहे।

लाड मेयो काशगर को ब्रिटेन के उचित प्रभाव क्षेत्र का भाग मानता था। वह ब्रिटेन के राजनीतिक प्रभुत्व में एक "दरमियानी" राज्य का निर्माण करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था। उसने व्यापार के विकास को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। मेयो ने कश्मीर के प्रति दबदबा रख अपनाया। एक विशेष प्रतिनिधि कप्तान ग्रे को महाराजा से समझौते की बातचीत करने वहाँ भेजा गया। फोरसाइथ ने बाद में (१८७० में) ग्रे की खींची हुई सीमा रेखाओं के अनुसार एक संधि सपन्न की। संधि में तमाम रास्ता का सर्वेक्षण करने की बात थी जिसके बाद उनमें से एक को सभी यात्रियों और व्यापारियों के लिए 'हमेशा के लिए खुला मार्ग' घोषित कर दिया जायेगा। इस मार्ग की देखभाल करने और झगड़े चुकाने के लिए दो जॉइंट कमिश्नर होंगे, हर पक्ष से एक। महाराजा ने यह मान लिया कि कश्मीर होकर जानेवाले सामान पर वह कोई परिवहन कर नहीं लगायेगा। डा० केली को लेह में पहला ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर नियुक्त किया गया।

शो की प्रथम गैरसरकारी काशगर यात्रा के फलस्वरूप याकूब बेग ने १८६६-१८७० के जाड़ों में अपने प्रतिनिधि मिर्जा शादी को भारत भेजा। फोरसाइथ और दल इसी प्रतिनिधि के साथ काशगर गया।** मेयो ने इस दल में किसी सैनिक को शामिल नहीं किया और इस बात से इनकार

* National Archives Foreign Department, Nov 1868 Pol A, Nos 1-3

** National Archives Sec July 1876 No 30

किया कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है। परन्तु फोरसाइथ को पड़ोसी देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया गया। उसे यह भी कहा गया कि अमीर को अपनी उत्तरी सीमाओं पर आक्रामक कारवाइयाँ करने से मना करे। ब्रिटिश जानते थे कि ऐसा किया गया, तो रूसी काशगर की इट से इट बजा देंगे और इसी के साथ उसपर एक दिन अपना प्रभुत्व कायम करने का अंग्रेजों का स्वप्न भी चूर चूर हो जायेगा। फोरसाइथ की पहली यात्रा असफल रही और उसे अतालीक याने याकूब बेग से मिले बिना ही लौट आना पड़ा। दो सौ जानवर, जो उसके दत्त के साथ थे, रास्ते में मर गये।*

१८७० की फोरसाइथ की यात्रा ने रूसियों को चौकन्ना कर दिया और उन्होंने मुज आत दर्रे पर दखल कर लिया। यह देखकर कि याकूब बेग ईली घाटी पर अधिकार करना चाहता है, रूसिया ने १८७१ में उसपर कब्जा कर लिया, ताकि वह अंग्रेजों का अधीन राज्य न बनने पाय।

१८७१-१८७२ के जाड़ों में काशगर का एक और प्रतिनिधि अहरार खान नियुरा भारत आया। वह केवल बाइसराय ही नहीं, महारानी विक्टोरिया के नाम भी पत्र लाया था। १८७२ में रूसी राजनयज्ञ वाउलवास काशगर पहुँचा और उसने बहुत ही लाभदायक व्यापारिक संधि कर ली। १८७३ में सैयद याकूब खान कुस्तुनतुनिया जाते हुए भारत आया। इस बीच लाड मेयो की हत्या हो चुकी थी और उसके स्थान पर लाड नाथब्रुक आ गया था। उसने इसका प्रबंध किया कि सैयद याकूब खान के तुर्की से लौटने पर एक ब्रिटिश मंडन उसके साथ जायेगा। कुस्तुनतुनिया में काशगर के प्रतिनिधि ने काशगारिया के नये राजतन्त्र को खलीफा के अधिराजत्व में दे दिया। अंग्रेजों ने सब इस्लामवाद और सब तुर्कवाद का प्रयोग अपने रूसी प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध बड़ी चतुराई से किया। उन्होंने अमीर याकूब बेग को तुर्की के सुल्तान से गहरा संबंध स्थापित करने पर प्रोत्साहित किया। बाद में लाड लिटन के समय, जब निक्ट पूव में ब्रिटेन और रूस में टक्कर होने की सम्भावना थी, ब्रिटिश कूटनीति

* National Archives Foreign Department, July 1875, No 30

ने मध्य एशिया में रूस के विरुद्ध इस "मुस्लिम सच" का प्रयोग करने की तत्परता दिखाई। परन्तु १८७५ में जब काशगर के प्रतिनिधि न फोरसाइथ और ब्रिटिश विदेश मंत्री से मेट के दौरान अफगानिस्तान से मत्रीपूर्ण सवध स्थापित का सवाल उठाया, तो उसे चेताया गया कि ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि इससे रूस नाराज हो जायेगा।* परन्तु दरअसल अंग्रेजों का इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय मोरचे के नतीजा का डर था, क्योंकि उनके अपने साम्राज्य में मुसलमान प्रजा की बड़ी सख्या थी।

फोरसाइथ के नेतृत्व में एक मडल १८७३ में काशगर भेजा गया और उसे १८७२ की रूसी सधि, के समरूप व्यापार सधि करने का आदेश दिया गया। सदा की तरह इस दूसरे फोरसाइथ मडल का प्रत्यक्ष उद्देश्य व्यापार था, मगर असल में वह इससे व्यापक था। याकूब बेग के रात को ब्रिटिश नीति की परिधि में ले आना था और उसे रूस और चान के विरुद्ध ब्रिटिश आक्रमण का अड्डा बनाना था। अंग्रेजों को कोकान की अव्यवस्था का ज्ञान था और वे इस बात से कि याकूब बेग कोकान का रहनवाला था, फायदा उठाना और उसको कठपुतली बनाकर उस इलाक में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मडल में जिस तरह के लोग रखे गये, उनका उसके घोषित उद्देश्य—व्यापारिक सवधों को प्रोत्साहित करने से कोई लगाव नहीं था। इसमें गुप्तचर अधिकारी और स्थलरूपरेखीय विभाग के छिपे एजेंट थे। इस मडल के सदस्यों में सेना के कप्तान बिडडुल्फ, कप्तान चैपमैन, कप्तान ट्राटर और लेफ्टिनेंट कनल गाडन थे। एक वैज्ञानिक डा० स्टोलिच्का और एक चिकित्सक डा० वेलो और इनके अलावा अनेक दली अधिकारी और चाकर थे। सब मिलाकर ३०० व्यक्ति और ४०० जानवर थे। यह छोटी-सी सेना लगती थी। ब्रिटिश मडल के सदस्यों का काशगर के अमीर ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया और तीन महीने से अधिक उनका अतिथि सत्कार किया। २ फरवरी, १८७४ को अमीर के साथ एक सधि सम्पन्न की गई, जो अंग्रेजों के लिए उतनी ही लाभदायक थी जितनी १८७२ की सधि रूस के लिए थी। इसके अनुसार

ब्रिटिश प्रजा को अपरदेशीय अधिकार मिल गये और अंग्रेजों को अमीर के दरबार में एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। इस मंडल ने सिन्धुतट तथा पड़ोसी देशों की स्थिति, साधन, इतिहास, भूगोल और व्यापार के संबंध में बहुत बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा की। लेफ्टिनेंट-कमल गाडन ने तियान शान पठार की यात्रा की, कप्तान टाटर और डा० स्टालिच्का ने तबले रेवात दर्रे के रास्ते का और रूसी इलाके में गदुर-कल धील का सर्वेक्षण किया। काउफमन ने रूसी युद्ध मंत्री मित्यूतिन को फोरसाइथ मंडल के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में लिखा। ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे पता चलता है कि १८७३ में कोकान पर रूसी कब्जे का कारण काशगर आधारित ब्रिटिश षडयंत्र का भय था। कोकान पर रूसियों का कब्जा हो जाने से सैनिक दृष्टि से काशगर रूस का आश्रित हो गया।

फोरसाइथ का दल जो सूचना लाया, उससे सिन्धुतट का व्यापारिक महत्त्व सन्देहजनक हो गया। मंडल ने पामीर के पार और सुगम दरों के रास्ते हुआ, यासिन और चित्तल तक रूस के बढ़ आने के खतरे की ओर संकेत किया। पामीर के बारे में गाडन की रिपोर्ट ने काशगर को एक नई सामरिक रौशनी में पेश किया कि वह “और अधिक पश्चिमी बढ़ाव के बाज में समृद्ध सप्लाई-केन्द्र है”।

फोरसाइथ को भारत से “काशगर राज की राजनीतिक सीमाएं निश्चित करने” का आदेश दिया गया था, मगर उसने पाया कि “यह कोई आसान काम नहीं है”, क्योंकि स्वयं अमीर को भी इन सीमाओं का पता नहीं था। फोरसाइथ ने अपनी रिपोर्ट में उनका निर्धारण इस तरह किया

“दक्षिण-पूर्वी कोने से शुरू होने पर इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि कुएन लुएन पर्वतमाला यारकन्द का इलाका है और हमेशा रहा है, और चकि निचली कराकाश घाटी में नेफ्राइट की खान में चीनी गत १५० वर्षों से काम करते आये हैं, इसलिए मान लिया जा सकता है कि घाटी ही सीमा है जहां तक मैं स्वयं यारकन्दियों से पता लगा सका, कराकाश नदी के दक्षिण में किसी इलाके पर दावा नहीं किया जाता, और यारकन्द

नदी पर वे कूफीलोग से आगे नहीं जाते। परन्तु सुविधा के लिए मैं सामा को आक-तांग पर निर्धारित करूंगा। और अपना सामान ले जाने में मन व्यवहार में उसी को अपना अंतिम बिंदु बनाया। तो रेखा कुएनलैन के पूर्वी कोने (भोगाश ८१) से नीचे, कराकाश नदी तक (भोगाश लगभग ७८ ५, अक्षांश ३५ ५६) जायेगी, वहां से यारखंद नदी के रास्ते कुजुत तक। कुजुत यारखंद के इलाके से बाहर है।”*

१८७६ में लाड नाथब्रुक की जगह लाड लिटन को वाइसराय नियुक्त किया गया। नाथब्रुक के शासन काल में “काशगर में ब्रिटिश प्रभाव उच्चतम शिखर” पर पहुंच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ की संधि है। परन्तु लिटन इससे सतुष्ट नहीं था। सितम्बर १८७६ में उसने अपनी नई काशगर नीति रेखांकित की। जब मैयद याकूब खान दूसरी बार भारत आया, तो लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह से मधोपुर में एक समझौते के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके अनुसार उसे अपने इलाके को यासिन तक विस्तारित करना और गिलगित में एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति का अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिन्हें फोरसाइथ मंडल के सदस्यों ने “सुगम” बताया था, ब्रिटिश नियंत्रण विस्तारित करने की अपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान बिड्डुल्फ ने इन दरों के सुगम होने के बारे में अपनी पहली राय बदल दी थी। जब लिटन को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमें से एक तथाकथित सुगम दर्रा बंद हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निराशा” हुई। ऐलंडर ने कहा “आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है, अगर उन दर्रा तक कश्मीर के और इसलिए ब्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षात्मक था”** १८७७ के प्रारम्भ में लिटन ने निजी रूप से सुझाव दिया कि रूस से कहा जाये कि “वह पलूचिस्तान और

* National Archives Confidential Report Yarkand Mission Aug 1875 Sec, No 68

** ग० ज० ऐलंडर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ६१।

काशगर और अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप या हम से प्रतियोगिता नहीं करे"।

ब्रिटिश प्रतिनिधि भेजने के फैसले को औपचारिक अनुमति अप्रैल १८७७ तक नहीं मिली। इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से शो चुना गया जा जुलाई में भारत जाने की तैयारी कर रहा था। इस निश्चय को अनुमति देने में हिचकिचाहट का कारण किसी हद तक यह था कि शो १८७४ की संधि का अनुसमर्थन प्राप्त करने में असफल रहा था। याकूब गे १८७४ की संधि की धारा ६ को, जिसका सबंध स्थायी प्रतिनिधि से था उस समय तक अमली रूप नहीं देना चाहता था जब तक तुर्की के सुलतान की अनुमति न मिल जाये। वह रूस को नाराज करना नहीं चाहता था और डरता था कि वह भी अपने लिए ऐसी मांग करेगा। जब जुलाई १८७५ में शो को वापस लौटने का आदेश मिला, तो वह अपने साथ एक पत्र लाया जिसपर अमीर की मोहर थी। मगर शो जिस कागज को अनुसमर्थन की दस्तावेज समझ रहा था, वह वाइसराय के नाम केवल धमकी का पत्र निश्चय।

अंग्रेजों को विश्वास था कि काशगर में याकूब बेग का शासन स्थायी रहगा। उन्हें विश्वास था कि चीनियों की यह स्थिति नहीं कि सिक्किम पर पुन अधिकार कर सकें। केवल १८७६ में ही पेकिंग स्थित ब्रिटिश मंत्री को विश्वास हुआ कि चीनी वास्तव में सिक्किम को अपने अधिकार में लाने की बात गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। लेट पीट्सबर्ग में ब्रिटिश राजदूत लाड आगस्टस लाफ्टस की राय थी कि अंग्रेज और रूसी मिलकर मध्यस्थता का प्रयास करें। परन्तु पेकिंग में टामस वेड ने इसका विरोध किया। उसने अकेले यह पहलकदमी की। अंग्रेज मचू सन्नाटो को ऋण देने के बावजूद याकूब बेग की सत्ता को बचाये रखना चाहते थे, जो उनके प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उस और मच सरकार में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया।

१८७६ में फोरसाइथ पेकिंग गया और काशगर और चीन में मध्यस्थता कराने में भाग लिया। टामस वेड पहले ही से पेकिंग में चीनियों के साथ यह सवाल उठा रहा था। उसके प्रयत्न से ली-हुंग चांग और फोरसाइथ

नदी पर वे कफीलोग से आगे नहीं जाते। परन्तु सुविधा के लिए मैं सीमा को आक-ताम पर निर्धारित करूंगा। और अपना सामान ले जाने में मन व्यवहार में उसी को अपना अंतिम बिन्दु बनाया। तो रेखा कुएन-लुएन के पूर्वी कोने (भोगाश ८१) से नीचे, कराकाश नदी तक (भोगाश लगभग ७८ ५, अक्षांश ३५ ५६) जायेगी, वहाँ से यारकंद नदी के रास्ते कुजत तक। कुजत यारकंद के इलाके से बाहर है।”*

१८७६ में लाड नाथब्रुक की जगह लाड लिटन को वाइसराय नियुक्त किया गया। नाथब्रुक के शासन काल में “काशगर में ब्रिटिश प्रभाव उच्चतम शिखर” पर पहुँच गया था, जिसका प्रमाण १८७४ की संधि है। परन्तु लिटन इससे सतुष्ट नहीं था। सितम्बर १८७६ में उसने अपनी नई काशगर नीति रेखांकित की। जब सैयद याकूब खान दूसरी बार भारत आया, तो लिटन कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह से मधोपुर में एक समझौते के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके अनुसार उसे अपने इलाके को यासिन तक विस्तारित करना और गिलगित में एक ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति की अनुमति देनी थी। लिटन ने उन तीन दरों तक, जिन्हें फोरसाइथ मन्त्र के सदस्यों ने “सुगम” बताया था, ब्रिटिश नियंत्रण विस्तारित करने की अपनी योजना जारी रखी, यद्यपि कप्तान विड्डुल्फ ने इन दरों के सुगम होने के बारे में अपनी पहली राय बदल दी थी। जब लिटन को यह सूचना मिली कि ग्लेशियर के कारण उनमें से एक तथाकथित सुगम दरों बढ़ हो गया है, तो उसने स्वीकार किया कि उसे “निराशा” हुई। ऐलंडर ने कहा “आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है, अगर उन दरों तक कश्मीर के और इसलिए ब्रिटिश प्रभाव के भी विस्तार का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षात्मक था”** १८७७ के प्रारम्भ में लिटन ने निजी रूप से सुझाव दिया कि रूस से कहा जाये कि ‘वह बलूचिस्तान और

* National Archives Confidential Report, Yarkand Mission, Aug 1875, Sec No 68

** ग० ज० ऐलंडर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ६१।

अंग्रेजों को विश्वास था कि काशगर में याकूब बेग का शासन स्थायी रहेगा। उन्हें विश्वास था कि चीनिया की यह स्थिति नहीं कि सिक्किम पर उन अधिकार कर सक। केवल १८७६ में ही पेकिंग स्थित ब्रिटिश मंत्री ने विश्वास हुआ कि चीनी वास्तव में सिक्किम को अपने अधिकार में ले की बात गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। सट पीटसबग में ब्रिटिश राजदूत ड आगस्टस लाफटस की राय थी कि अंग्रेज और रूसी मिलकर स्थिता का प्रयास करे। परन्तु पेकिंग में टामस वेड ने इसका विरोध था। उन्होंने अकेले यह पहलकदमी की। अंग्रेज मजू सभाओं को श्रृण्व के वावजूद याकूब बेग की सत्ता को बचाये रखना चाहते थे जो उनके अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उस और मजू सरकार में स्थिता कराने का प्रयास किया। १८७६ में फोरसाइथ पेकिंग गया।

यह मवाल उठा रहा था। उसके प्रयत्न से लीडिंग चांग और फारसाइय

तथा मेयस का सम्मेलन आयोजित किया गया। ली-हुग चांग ने यात्रा बैग द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण और चीनियों की अधीनता स्वीकार करने पर जोर दिया। यह पूछे जाने पर कि काशगर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि का स्वागत पेकिंग में किस प्रकार किया जायेगा, ली-हुग चांग ने उत्तर दिया कि काशगर के मामलों का सारा प्रबंध जनरल त्सो-त्सुंग तांग के जिम्मे कर दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे भारत के सारे मामले वाइसराय के जिम्मे हैं, और याकूब बेग को जनरल त्सो से बात करना चाहिए।*

परंतु याकूब बेग और चीनियों में सफलतापूर्वक निवटारे का आशा फिर जाग उठी जब पेकिंग में ब्रिटिश अस्थायी कायदूत ने सर्वोच्च समिति में काशगरिया के विरुद्ध सैनिक कारवाइयों पर विचारविमर्श में मनमर्श की रिपोर्ट भेजी।** १८७७ के पूरे साल पेकिंग में ब्रिटिश अस्थायी कायदूत काशगर के मुकाबले में चीनिया के कदम पीछे हटाने की बात लिखता रहा। कैनटन के वाइसराय से सर ब्रूक राबटसन की बातचीत के स्मृतिपत्र से पता चलता था कि ली-हुग चांग ने फोरसाइथ से अपनी बातों में याकूब बेग द्वारा अधीनता स्वीकार करने की जा मांग की थी, उसे अब बर्तन दिया गया है। नया प्रस्ताव यह था कि काशगर का चीन से संबंध बढ़ी होना चाहिए, जो नेपाल और बर्मा का है।*** यह सुनने पर वाइसराय लार्ड लिटन ने भारत के लिए सेनेटरी आफ स्टेट लार्ड सोल्सबेरी को १६ जुलाई, १८७७ को लिखा

“अगर कैनटन के गवर्नर द्वारा काशगरिया के बारे में सर बी० राबटसन से प्रकट किये गये विचार किसी प्रकार भी चीनी सरकार के विचारों का प्रतिबिम्बित करते हैं, तो हमारी राय है कि वे पूर्व में ब्रिटिश हितों के अनुबूल हैं और हमें विश्वास है कि इंग्लैंड में यारकंद के प्रतिनिधि

* National Archives Foreign Department Sec, Jan 1877
No 120

** वही, अक्टूबर १८७७ अथ १९३।

*** वही, अथ १९५ १९७।

- की उपस्थिति से हर मजिस्टी की सरकार को उस समझौते को प्रोत्साहित करने का मौका मिल सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप में चीनी सरकार द्वारा लड़ाई से करना चाहती है।**

लाड सोल्सबेरी ने सैयद याकूब खान से भेंट की, जो उन दिनों लंदन में था। अब कारवाई का क्षेत्र पेकिंग से लंदन आ गया और लाड डरवी, लाड सोल्सबेरी और टामस वेड ने चीनी राजदूत की सेवाय सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया। वे इसमें सफल हुए और जुलाई १८७७ को टामस वेड के घर पर चीनी राजदूत और अमीर के विशेष प्रतिनिधि में भेंट का प्रबंध किया गया। मगर उसी दिन काशगर के अमीर याकूब बेग के मरण का समाचार आया और काशगर और चीन में समझौता कराने के एन प्रयत्न का कोई नतीजा नहीं निकला।** चीनियों ने दिसम्बर १८७७ में काशगर पर कब्जा कर लिया।

यकूब बेग की मृत्यु के बाद काशगर में जो गड़बड़ मची रही उससे मजबूर होकर भारत सरकार को शो की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इस बीच नये शासक बेग कुली बेग ने ब्रिटिश प्रतिनिधि के आगमन की इच्छा प्रकट की। लेह में ब्रिटिश जाइंट कमिशनर ने इलियास ने मुझाव दिया के ब्रिटिश प्रतिनिधि काशगर भेजा जाये ताकि चीनिया से सम्मानपूर्ण समझौता करने में नये शासक को ब्रिटिश नैतिक समर्थन प्राप्त हो।

लाड लिटन ने इस मुझाव को स्वीकार करने का समर्थन किया। स्थायी प्रतिनिधि के लिए लंदन की अनुमति प्राप्त करने से पहले उसने इलियास को काशगर जाने की आज्ञा दे दी। इलियास काशगर के लिए रवाना हुआ, मगर वह वहाँ पहुँचा नहीं क्योंकि बेग कुली बेग राज छोड़कर भाग चुका था। चीनिया के लौट आने के बाद कुछ दिनों तक शक्ति-संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में रहा। ईली घाटी को वापस लेने का सवाल उठ गया था जिसपर

*वही अंक १९७।

**वही, अंक २१६-२२५।

रूसिया ने १८७१ में इस शर्त पर कब्जा किया था कि उस इलाक में स्थिति सामान्य हो जाने के बाद उसे लौटा दिया जायेगा। आठ महीने की कड़ी सौदेबाजी के बाद लिवादिया में जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए, उसे चीनी वैदेशिक कार्यालय ने अस्वीकार कर दिया और चीनी रूसी सबंध, जिनमें पहले ही तनाव पैदा हो चुका था, बहुत खराब हो गये। लगता था कि युद्ध होनेवाला है, मगर फरवरी १८८१ में सेंट पीटर्सबर्ग की संधि की बदौलत वह टल गया और सेंट का अंत हो गया।

१८७८-१८८१ की अवधि में, जब चीनी रूसी सबंध खराब हो गये, अंग्रेजों ने इससे फायदा उठाकर सिकियांग में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। सिकियांग से उनका व्यापार १८७६-१८८० में बराबर बहाल होता गया और १८८१ में वह १८७६ के उच्च स्तर पर पहुंच गया था।* भारतीय चाय पर चीनियों का प्रतिवध कारगर नहीं था। एक अंग्रेज व्यापारी एंड्रयू डालगीश ने काफी मुनाफा कमाया। इसके विपरीत चीनी रूसी व्यापार का दोनों शक्तियों के तनाव से बड़ा धक्का पहुंचा। इलियास जिस १८८० में यारकंद में वापस भेज दिया गया था, यारकंद के गवर्नर से मिला और ऐसी "व्यवस्था" पर जोर दिया जिसमें "ब्रिटिश और चानिया के बीच रूसिया के कायबत्ताप के बारे में गुप्त सूचना का आदान प्रदान किया जा सके"।** पेकिंग में चीनी वैदेशिक कार्यालय ने काशगर में अंग्रेजी उपद्रुतावास खोलने तथा व्यापार का नियंत्रण करने के लिए करारनामे क ब्रिटिश अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। परन्तु उसने ब्रिटिश एजेंटों को सिकियांग में यात्रा करने की आज्ञा दे दी। यात्रा की इन सुविधाओं से फायदा उठाकर डालगीश सिकियांग के अपने व्यापक क्षेत्र पर खाना हुआ। परन्तु स्थानीय चीनी अधिकारियों की ओर से उसे बहुतरी बाधाओं का सामना करना पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग की संधि से भारतीय व्यापार को, जो कुछ दिना से बढ़ गया था, १८८१

* ग० ज० ऐलडर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ७७।

** वही।

मे, जो १८८४ मे तैयार की गई थी, यह प्रबध था कि मध्य एशिया के खान प्रशासित प्रदेशों और तुर्कमानिस्तान में गडबड कराने के लिए आतंकों भेजे जायें। यह बात दिलचस्प है कि इस योजना में "चीन से तुल्य पुनर्मात्री" करने पर जोर दिया गया था।* रिपन को आन्तमक वार्षिक नीति के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करना वास्तविक तथ्यों पर परदा डालना है। अफगानिस्तान में उसने जो समझौता कराया, वह इस माना में "रूढ़िवादी समझौता" था कि वह गडामक संधि के "बहुत निकट" था। यह भी रिपन ही के शासन काल की बात थी कि अफगान सरकार ने अंग्रेजों के दबाव से १८८३ में रूशान और शुगनान पर कब्जा कर लिया और यह बात अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के सबध में ब्रिटिश और रूस के १८७३ के समझौते के विपरीत थी।

लाड डफरिन (१८८४-१८८८) ने एक व्यापारिक करारनामा और सिन्धुवाग में उपद्रुतावास खुलवाने का निश्चय किया। उसने काश्गार में एक मंडल भेजने का निणय किया। चीनी वैदेशिक कार्यालय ने इलियास से बातचीत करने अपना प्रतिनिधि भेजने से यह कहकर इनकार कर दिया कि ब्रिटिश भारत व्यापार कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि इसके लिए विशेष व्यापार करारनामा किया जाय। चीनिया ने इलियास से अनमनीपूर्ण व्यवहार किया और उसने इस असफलता के लिए पेकिंग में ब्रिटिश अत्यापी कायदत आकोनोर पर दोष मढ़ा। भारत से एक व्यापार उपसंधि का मसवदा आकोनोर के पास भेजा गया था। परंतु पेकिंग में चीनी अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और चीन के साथ सबधों में अनेक उलझन पैदा होते रहे जैसे तिब्बत का व्यापार, बर्मा का झगडा, सिक्किम का वार्तालाप, आदि। ओरानार ने सिन्धुवाग के शहरों में टियेंटसिन की संधि की सबसे अनुगृहीत राष्ट्र की

* मन्त्रालय, "भारत की सुरक्षा", भाग १- 'एशिया विषयक भौगोलिक, स्थलरूपपरखीय तथा सांख्यिकीय सामग्रियों का संग्रह', अर् ४३, सेंट पीटर्सबर्ग, १८८९, पृष्ठ २०७, खालकिन, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३६७।

धारा के आधार पर अंग्रेजों के लिए उपद्रुतावासीय अधिकारों की मांग की। परन्तु चीनियों को इससे पहले काशगर में रूसी उपद्रुत का बहुत कटु अनुभव हो चुका था (रूसी उपद्रुत पेत्रोव्स्की ने उससे अधिक राजनीतिक प्रभाव कायम कर लिया था जितना चीनी देना चाहते थे)। अतः अब वे कोई और उपद्रुत नहीं चाहते थे। उपद्रुतीय प्रतिनिधि की अंग्रेजों की मांग को बदलकर राजनीतिक एजेंसी की मांग कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश भारत व्यापार बहुत कम हो गया था। ब्रिटिश भारत सरकार पेकिंग में वालशम को कुरेदनी रही कि वह इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय पर दबाव डाले, परन्तु चीनियों के हठ के कारण इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

१८६१ में ब्रिटिश भारत सरकार ने मकादनी को सिक्काम में अनिश्चित काल तक रखने का निश्चय किया, अगरचे चीनियों द्वारा उसे कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसने अंग्रेजों की अच्छी सेवा की। चीनियों से वह उनका "सम्पर्क" कायम रखनेवाला व्यक्ति भी था और रूसिया पर निगाह रखनेवाला उनका गुप्तचर एजेंट भी। १८६१ में हुआ पर अंग्रेजों के कब्जे से चीनी नाराज हो गये। उनका दावा था कि उसके शासक उह नजराना दिया करते थे और इसलिए उसपर उनका कभी का अस्पष्ट अधिराजत्व का अधिकार था।

१८६३-१८६५ की अवधि में लद्दाख चीनियों की मंत्री बनाये रखना चाहता था ताकि पामीर के विरुद्ध आक्रामक कारवाइया कर सके। भारत को रूस के "खतरे" का पुराना बहाना बनाकर अंग्रेज इस इलाके सैन्य घुसपैठ की नीति पर अमल कर रहे थे। इसलिए अब वे काशगर उपद्रुतावास की मांग पर जोर देना नहीं चाहते थे। अधिक व्यापक साम्राज्यवादी नीति के हित में अंग्रेजों ने १८६३ में चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनायी। इसका उद्देश्य यह था कि वे चीनी सागर तट पर तथा प्रधान भूमि के कुछ इलाका में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे जिन्हें उन्होंने चीन के मजबूत शासकों के साथ अममान संधियां करके अर्द्ध-औपनिवेशिक पराधीनता की स्थिति में पहुंचा दिया था। जनवरी १८६३ में भारत सरकार ने इंग्लैंड में अपनी सरकार को सूचना दी कि चीनी

अधिकारियों ने कराकुरम दर्रे पर सीमा चिह्न लगा दिए हैं।* पेकिंग में आ'कोनोर ने इस मामले में चीनी रवैये पर किसी आपत्ति का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उसका समयन किया। विदेश मंत्री लाड किम्बरलैंड ने सुझाव दिया

“पेकिंग में चीनी सरकार को उन रिपोर्टों के सारतत्व की सूचना दे देनी चाहिए, जो हर मैजिस्ट्री की सरकार को प्राप्त हुई है और वह बता देना चाहिए कि कश्मीर राज्य की ओर से भारतीय अधिकांश काशगरिया में चीनी अधिकारियों के साथ तोह से काशगर तक की सड़क पर सीमा निर्धारण करने में सहप सहयोग करेंगे। परंतु इस सड़क पर काशगरी अधिकारियों द्वारा लदाख राज्य के सीमा निर्धारण का कोई प्रयास हर मैजिस्ट्री की सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया, तो वह एना नहीं करने देगी।”**

आ'कोनोर को पता लगा कि पेकिंग के सरकारी क्षेत्रों में “पानीर में रूस की आन्नामक नीति” के कारण लागू “खीजे” हुए हैं और इसलिए उसने कराकुरम में चीनियों द्वारा चिह्न लगाने का विरोध नहीं करने का सलाह दी।

यद्यपि वर्तमान पेकिंग शासक भारत को दोष देते नहीं थकते कि उनका ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा एकपक्षीय तौर पर स्थापित सीमाएं विरासत में मिली हैं, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि अंग्रेजों ने हमेशा ऐसा रख नहीं अपनाया, जो भारत के हिता के अनुकूल हो। इसकी एक मिसाल अन्नामक चीन के मामले में अंग्रेजों की गड़बड़ है। काशगर में ब्रिटिश प्रतिनिधि मजादनी ने दिसम्बर १८६५ में चीनी प्रांतीय गवर्नर को कुछ पुस्तकें और गणितीय यंत्र भेंट किए। गवर्नर ने काशगर के ताम्रो-साई से आपत्ति किया कि वह उसकी ओर से इन चीजों के लिए धन्यवाद दे दे। इन पुस्तकों

* National Archives Foreign Department, K W Sec F, April 1888 Nos 282—283

** National Archives Foreign Department, Enclosures to 1894, Aug., Sec F Nos 26—33

सोवियत सत्ता की स्थापना

प्रारम्भिक सोवियत आजाप्तियां

सोवियत सघ ने अपनी प्राथमिक आजाप्तियों में से एक—“शांति व बारे में आजाप्ति” में अपनी वैदेशिक नीति के एक मौलिक सिद्धान्त के रूप में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की। आगे चलकर इस सिद्धान्त की अभिव्यक्ति रूसी सघ तथा अन्य सोवियत जनतन्त्रों की आय अनेक आजाप्तियां (‘रूस की जनताओं के अधिकारों का घोषणापत्र’, “मेहनतकश और शोषित जनता के अधिकारों का घोषणापत्र”, “रूस और पूर्व के मेहनतकश मुसलमानों के नाम जन कमिसार परिषद की अपील”, अनेक राजनयिक नोट, वक्तव्य आदि) में हुई।

“शांति के बारे में आजाप्ति”, जो लेनिन द्वारा लिखी गई थी, महान अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक असाधारण दस्तावेज़ है। इसने समस्त जातियों और राष्ट्रों के अधिकारों की समानता के आधार पर “यावोचित और जनवादी शांति की स्थापना की मांग की। इसने वैदेशिक भूमि पर सभी कब्जों की निंदा की। आजाप्ति ने न केवल राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का निरूपण किया बल्कि इस बात की विस्तारपूर्वक व्याख्या भी की कि कब्जा करना क्या होता है। आजाप्ति में कहा गया “जब भी कोई छोटा या कमजोर राष्ट्र उस राष्ट्र की सुस्पष्ट शब्दों में, साफ-साफ तथा स्वेच्छापूर्वक व्यक्त की गयी अनुमति या इच्छा के बिना किसी बड़े

या शक्तिशाली राज्य में शामिल कर लिया जाता है, ता इस बात का कोई लिहाज किए बिना कि इस प्रकार बलात कब्जा किस समय किया गया या इस बात का कोई लिहाज किये बिना कि वह राष्ट्र, जिसे किमा दूसरे राज्य में बलात शामिल कर लिया गया है या जिसे जबरदस्ती किमा दूसरे राज्य की सीमाओं के भीतर रखा जा रहा है, कितना उन्नत या पिछड़ा हुआ है और अतः इस बात का कोई लिहाज किये बिना कि वह राष्ट्र, जिस पर अधिकार किया गया है, यूरोप में है या समुद्र-पार का कोई सुदूर देश है, यह सरकार उसे आम तौर से पूरे जनवाद और छास तौर से मेहनतकश जनता की 'यायभावा' के अनुरूप सजाजन या कब्जा समझती है। '•

आज्ञप्ति के इस भाग में आत्मनिर्णय के सिद्धांत के सार, अतः और काय-क्षेत्र की व्याख्या की गई है। आज्ञप्ति ने घोषणा की कि यह सिद्धांत न केवल श्रमजीवी जनगण के 'याय-बोध' के, बल्कि "आम तौर पर जनवादिया के 'याय-बाध' के अनुकूल है। वास्तव में आत्मनिर्णय का नारा पूजीवादी-जनवादी कायन्त्रम का अंग था। आज्ञप्ति से यह भी नतीजा निकलता था कि किसी राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना बनाकर उसे अपने मामलों का प्रबंध करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज्ञप्ति ने उपनिवेशवादियों के इन दावा पर निर्णायक प्रहार किया कि उन्होंने अथ राष्ट्रों का अपनी गुलामी में इसलिए लिया है कि उनमें अपना प्रशासन स्थापित करने की क्षमता नहीं थी।

"शांति के द्वारे में आज्ञप्ति" न जहाँ राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की घोषणा मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में की गई थी, बल्कि "मेहनतकश और शोषित जनता के अधिकारों का घोषणापत्र" में सोवियत राज्य के राष्ट्रीय विकास के सिद्धांत के रूप में किया गया। "इस का जनताओं के अधिकारों के घोषणापत्र" में कहा गया था कि सोवियत

1 वाग्रेस से सम्बोधन किया, "उलेमा" की वाग्रेस थी जिसे मुसलमान मेहनतकशा के नाम पर बालन का कोई अधिनार नहीं।* रहीमजायेव ने घोषणा की कि मुसलमान मजदूर रूसी मजदूरों का साथ दोगे। कई दिना की लम्बी बहस के बाद सोवियतों की तीसरी वाग्रेस न पूजीपतिया और दक्षिण-पश्चिमी समाजवादी प्रातिकारियों के प्रस्ताव को लिए भगविका और सोवियत सत्ता की विजय का एगान किया और अस्वीकार कर दिया। बोलशेविका और "पराकाष्ठावादियों" द्वारा प्रस्तावित घापणापत्र ने तुकिस्तान में सोवियत सत्ता की विजय का एगान किया और वतमान केन्द्रीय सत्ता और उससे सगठन के रूपों को स्वीकार किया। उसने स्पष्टतः "मुसलमानों" (यानी पूजीवादी राष्ट्रवाणियों और प्रतिक्रियावादी धर्मावलम्बियों) और समन्वितवादी रूसियों के साथ सत्ता में शरीक होने से इनकार कर दिया जो अस्थायी सरकार का समर्थन करते, प्राति के विरुद्ध लड़ते तथा प्रातिकारी जनवाद से विश्वासघात करते थे।**

इस प्रकार सोवियतों की तीसरी क्षेत्रीय वाग्रेस ने तुकिस्तान में सत्ता के सगठन के महत्वपूर्ण सवाल को प्रातिकारी ढंग से हल किया। इसकी अवसर यह आलोचना की गई है कि उसने स्वायत्त शासन की समस्या को नजरअन्दाज किया और सत्ता की उच्चतर सत्साम्राज्य में मुसलमानों की शिरकत के बारे में नकारात्मक खयाल अपनाया। परन्तु वाग्रेस की कारवाई की अगर पूरी छानबीन की जाये, तो इस आलोचना का कोई आधार नहीं रह जाता।

जब १५-२२ नवम्बर, १९१७ की वाग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस समय तुकिस्तान के क्षेत्र का केवल एक छोटा भाग सोवियत नियन्त्रण में था। ताशकन्द के अलावा यह फरगाना और समरकन्द इलाकों के केवल बड़े शहरों तक सीमित था। जेतीसुव और अधिकांश ट्रांसकास्पियन इलाका

* 'नाशा गजेता'

तुकिस्तानस्कीये बन्धोमोस्ती' अक्टूबर १३३, २३ नवम्बर, १९१७ और

** नाशा गजता, अक्टूबर २१ नवम्बर, १९१७।

अभी तक अस्थायी सरकार की सस्थाओं तथा पूजीवादी राष्ट्रवादी समितियों के हाथों में था। ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः समाजवादी आति ठप्पा सत्ता के आतिकारी संगठन के सवाल को कांग्रेस की कार्य-सूची में स्वागत शासन के सवाल के मुकाबले में प्राथमिकता प्राप्त थी।

तीसरी कांग्रेस में बोल्शेविकों और "पराकाष्ठावादियों" के घोषणापत्र की तीव्र आलोचना इसलिए भी की गई है कि उसने मुसलमानों को आतिकारी सत्ता की उच्चतम सस्थाओं से अलग रखा। मुसलमानों को अलग रखने तथा सोवियत सत्ता के प्रति उनके रवैये की अनिश्चितता का उल्लेख किसी हद तक भ्रामक है। इतना तो मानना ही पड़गा कि घोषणापत्र के इस भाग की शब्दावली ठीक नहीं है और इसमें आलेखन की अनेक गलतियाँ हैं। परन्तु अगर घोषणापत्र को उसकी पूर्णता में लिया जाये और उसे पूजीवादी राष्ट्रवादियों की इस मांग के प्रसंग में पढ़ा जाय कि मजदूर महान कुर्बानियों के बाद हासिल की हुई सत्ता का छाड़ दें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि "मुसलमान" शब्द वर्गीय अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। घोषणापत्र ने सत्ता की सस्थाओं से मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि रूसी समूह के उन प्रतिनिधियों को भी अलग रखा, जो आति के विरुद्ध लड़े थे। अगर घोषणापत्र को पूरा पढ़ा जाये, तो उसमें लेखकों का आशय साफ हो जाता है। उसमें जोर दिया गया था कि "सक्रिय सार्वजनिक काम में हिस्सा लेने से व्यापक जनता को अलग नहा रखना है और स्थानीय प्रतिनिधियों को लेकर जिससे मुसलमान अलग नहा किये जायेंगे, सोवियतों की कांग्रेस" आयोजित की जायेंगी, ताकि अग्रतन्त्र और राजकीय ढांचे के सवाल पर विचार किया जाये।* इस अंतिम शब्द ये थे

"इस प्रकार न तो स्थानीय आन्दोलन और न स्थानीय बुद्धिजातियों का इस क्षेत्र के जीवन में सुधार के लिए सक्रिय काम करने के अवसर से वंचित किया जाता है। इसके विपरीत इस काम के लिए उनका बल स्वागत किया जाता है।" **

* पूरा या पूरा घोषणापत्र 'गंगा गजेंद्र' में २३ नवम्बर, १९१७ का प्रकाशित किया गया था।

** वही।

सोवियतों की तीसरी कांग्रेस ने तुर्किस्तान की सरकार की उच्च सत्ता के रूप में १८ सदस्यों की जन-वमिसार परिषद स्थापित की। सोवियत कृतियाँ में भी इस बात की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि कांग्रेस ने जन-वमिसार परिषद में तीन स्थान मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित कर दिये थे। 'नाशा गजेता' के २३ नवम्बर, १९१७ के अंक में जन-वमिसार परिषद में मुसलमान मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का स्पष्ट उल्लेख है।* इसकी पुष्टि हमें पुनः २५ जनवरी, १९१८ को सोवियतों की चौथी क्षेत्रीय कांग्रेस में बोल्शेविक दल के नेता तोलोत्किन के भाषण में मिलती है।** तातोलीन ने कहा था कि जन-वमिसार परिषद में १८ सदस्य होंगे। १५ सदस्यों का निर्वाचन सोवियतों की तीसरी कांग्रेस कर चुकी है और तीन स्थान मुसलमान मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए खाली छोड़ दिये गये हैं। सोवियतों की चौथी क्षेत्रीय कांग्रेस ने बोल्शेविकों के आग्रह पर इस सुझाव का समर्थन किया।

जन-वमिसार परिषद के निर्देशन के लिए सोवियतों की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत आदेश से कोई सदेह नहीं रह जाता कि सोवियत सत्ता की उच्च सत्ताओं में मुसलमानों की शिरकात के खिलाफ कहीं कोई भावना नहीं थी। आदेश की धारा ३ में मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जन-वमिसार परिषद की रचना में मुस्लिम सहयोग और श्रमजीवी जनगण के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा और उन्हें " (सामुदायिक रूप से) उचित स्थान दिये जायेंगे"।*

* 'स्वोबोदनी समरकन्द' (रूसी संस्करण) जैसे गैर-बोल्शेविक अखबार ने भी (अंक १२७, २६ नवम्बर, १९१७) इसकी पुष्टि की थी।

** 'नाशा गजेता', अंक २२, २७ जनवरी, १९१८।

*** 'नाशा गजेता', अंक १३३, २३ नवम्बर, १९१७। "सामुदायिक" शब्द आदेश के मूलपाठ से किसी तरह निकल गया था, जब वह "तुर्किस्तान में महान् अवतुवर समाजवादी क्रांति की विजय, दस्तावेज संग्रह" में (ताशकन्द, १९४७, पृष्ठ ६३-६५, रूसी संस्करण) प्रकाशित किया गया था और कुछ समय बाद "उज़्बेकिस्तान में अवतुवर क्रांति की विजय" नामक दस्तावेज-संग्रह में (ताशकन्द, १९६३, पृष्ठ ५७२-५७३, रूसी संस्करण) प्रकाशित हुआ।

आदेश की धारा ४ ने जन कमिसार परिषद का केवल तुकिस्तान के मजदूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के सामने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम गवहारा तथा मेहनतकश जनसंगठनों के सामने भी जवाबदेह बनाया।

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि तुकिस्तान के प्रारम्भिक बोशविकों का मुस्लिम जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासन में भाग लेने से अलग करने का कोई इरादा नहीं था। घोषणापत्र में अवश्य आलेखन का कुछ गलतियाँ थीं। परन्तु इसी कारण इसके लेखकों पर स्थानीय मुसलमानों के प्रति शत्रुता की भावना का दोष नहीं मढ़ा जा सकता। निम्न पूँजीवादी अखबार तुकिस्तान के बोशविकों का मजाक उड़ाया करते थे कि वे सभाओं की विज्ञप्तियाँ आदि भी ठीक से नहीं लिख पाते। 'स्वाबोल्नी समरबन्द' अखबार ने तिरस्कारपूर्वक इस बात का उल्लेख किया है कि तुकिस्तान का जन कमिसार परिषद में बलक, कम्पाज़ीटर तथा चिकनाई करनेवाले मजदूर हैं। उसने वित्त-कमिसार द्वारा लिखी हुई एक नोटिस की नकल भी यह दिखाने के लिए छपी कि साक्षरता का स्तर कितना नीचा है।*

सोवियतों की तीसरी कांग्रेस ने स्थानीय सत्ता-संगठन पर भी एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। स्थानीय क्षेत्रों में सारी सत्ता मजदूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथ में होगी। स्थानीय सोवियतों से आग्रह किया गया था कि जहाँ कहीं मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतें नहीं हैं, वहाँ वे उनका संगठन करें। जहाँ ऐसी सोवियतें हैं, वहाँ उन्हें आत्मशासित रहने दिया जाय।**

नवम्बर १९१७ के अंत में पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने सोवियत सत्ता का घुलेग्राम विरोध किया। तीसरी कांग्रेस द्वारा सत्ता उनके हवाले करने के साफ़ इनकार के फनस्वरूप २७ नवम्बर को काकास में तथाकथित क्षेत्रीय मुस्लिम कांग्रेस बुलाई गयी थी। कोकान कांग्रेस में उर्वेक, कजाख,

* 'स्वाबोल्नी समरबन्द', अंक १२७, २६ नवम्बर, १९१७।

** 'तुकिस्तान में महान अन्तूर समाजवादी आति की विजय',

ताजिक और किर्गिज पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने भाग लिया, जो "शूरा-ए-इस्लामिया", उलेमा" और "आलश आरदा" जैसी राजनीतिक पार्टियाँ में संगठित थे। मुस्लिम मेहनतकशों के कम ही प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने दो सवाल पर विचार किया, एक था तुर्किस्तान के "दक्षिण पूर्व संध" में जिसका प्रधान प्रतिनातिकारी नेता दूतोव था, शामिल होने का सवाल और तुर्किस्तान की स्वायत्तता का सवाल। पहला सवाल उसने तुर्किस्तान की भावी सरकार के लिए छोड़ दिया और तुर्किस्तान की क्षेत्रीय स्वायत्तता की घोषणा कर दी। उसने तुर्किस्तान की अस्थायी परिषद का निर्वाचन किया, जिसके ५४ सदस्य थे जिनमें से एक तिहाई रूसी पूँजीपतियों के प्रतिनिधि थे। कोकान की तयारबद्ध स्वायत्त सरकार का प्रधान पहले बजाव सब-नुकवादी मोहम्मदजन तिनिशवायेव था, जिसका स्थान जल्दी ही "शूरा-ए-इस्लामिया" के मुस्तफा चोवायेव ने ले लिया। स्वायत्तवादियों का घनिष्ठ संबंध दूतोव से काशगर में ब्रिटिश कौंसल से तथा मरगेविक और समाजवादी नातिकारी संगठनों से था। उन्होंने स्वायत्तता का नारा केवल अपने प्रतिनातिकारी उद्देश्यों पर परदा डालने के लिए दिया था।

कोकान स्वायत्तता रूसिया के विरुद्ध मुसलमानों का कोई राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं था, जैसा कि कुछ लेखकों का कहना है। वास्तव में यह वग-संध था, जिसमें एक और मुस्लिम सम्पत्तिवान वग थे जो रूसी पूँजीपति वग और वैदशिक साम्राज्यवादियों से मिले हुए थे, और दूसरी ओर रूसी सवहारा था, जिस मुस्लिम मेहनतकश जनता का समर्थन प्राप्त था। वास्तव में यह तुर्किस्तान में प्रतिनातिकारी तथा नातिकारी शक्तियों का संध था। अ० लटिमोर ने खुलासा करते हुए सही कहा है कि "नाति ज्यों ज्यों गहरी होकर राजनीतिक संध से वग-संध का रूप धारण करती गई, विभाजन की रेखाओं ने अधिकाधिक सम्पत्तिवान रूसिया और गैर रूसिया को एक ओर कर दिया, जो इसलिए लड़ रहे थे कि पुरानी व्यवस्था में से जो कुछ हो सके उसे बचायें, और सम्पत्तिहीन

रूसियों और गैर-रूसियों को दूसरी ओर, जो नई व्यवस्था को पूर्ण अपन हाथों में लेना चाहते थे।”*

कुछ लेखकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि बाल्शेविक स्वयत्तता के बट्टर विरोधी थे और पूँजीवादी राष्ट्रवादी इसके पक्के समर्थक। यह कहना वस्तुस्थिति के विपरीत है। पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्त्व, जो सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद स्वायत्तता के ध्येय के समर्थन में गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे, अस्थायी सरकार तथा उसकी तुर्किस्तान समिति के प्रति अपनी अटूट वफादारी जतलाने में एक दूसरे पर बाजी लड़ने का प्रयत्न करते थे, हालाँकि उन सबको मालूम था कि वह स्वायत्तता की धारणा का विरोधी है। अस्थायी सरकार चाहती थी कि तुर्किस्तान को ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के नमूने पर स्वशासन की निशा में विकसित करे और वह स्वायत्तता की समयक नहीं थी।

जातीय संघर्ष के संघर्ष में पूँजीवादी राष्ट्रवादियों का कोई सुसंगत कार्यक्रम नहीं था। उनकी स्वायत्तता की धारणा बेहद उलझी हुई, अतर्विरोधी और बड़ी हद तक धर्म से प्रभावित थी। कुछ लेखकों ने उन्हें “राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता” की वैज्ञानिक धारणा का ध्येय देने का प्रयत्न किया है।** पर यह भ्रामक है। पूँजीवादी राष्ट्रवादियों में कई प्रकार की राय थी। एक तो सब इस्लामवादी थे, जिनके विचारों से रूस के सभी मुसलमान एक कौम थे और उन्हें उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए था। वे मुगलमानों में कोई वर्ग भेद नहीं देखते थे और सबों के हितों का एक और समान मानते थे। सब-तुर्कवादी तातारों, आज़रबैजानियों, उज़्बेकों, बख़ावों, तुर्कमानों और किर्गिज़ों का मिलाकर कृत्रिम रूप से एक तुर्की कौम का निर्माण करना चाहते थे। वे तातार पूँजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनका इच्छा थी कि वे तुर्की भाषा-बोलनेवाले मनुष्यों से संघर्ष करनेवाले रूस के सभी मुसलमानों पर अपना वर्गीय नेतृत्व कायम करें।

* O Lattimore *Pivot of Asia* Boston 1950 p 204

S A Zenkovsky *Pan Turism and Islam in Russia* Cambridge Mass 1960 pp 147—149

- मध्य एशिया के जदीदो भिन गिरोहा का पचमल थे, वे अभी तक-
 इसलामवाण्या की ओर झुकते और सभी सब-तुक्वादिया की ओर और
 सभी स्वयं अपने पूजावादी राष्ट्रीयतावाद की ओर। तथाकथित अखिल-
 रूसी मुस्लिम कांग्रेस में पूजावादी राष्ट्रवादिया की यह उलचन और
 सिद्धांतहीनता पूरी तरह चलवती है। पहली अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस
 मास्को में मई १९१७ में हुई। इसने "एक सघीय आधार पर संगठित
 जनवादी जनतंत्र" के भीतर "राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता" का प्रस्ताव
 स्वीकार किया।* परन्तु दूसरी अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस की वायसूची
 में जो वजान में जुलाई १९१७ में हुई, "राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता"
 का सवाल निहित था।** दूसरी अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस के साथ-साथ
 वजान में मुस्लिम मुल्लाओ और सनिका की कांग्रेस भी हुई। तीनों कांग्रेसों
 के एक संयुक्त अधिवेशन में रूस की सभी तुक्-तातार बीमा की
 सांस्कृतिक स्वायत्तता का" कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया।***
 पूजावादी राष्ट्रवादिया के इस अंतर्विरोधी मत की रोशनी में प्रथम
 अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस के प्रस्ताव में उल्लिखित "राष्ट्रीय क्षेत्रीय
 स्वायत्तता" को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। इससे यह नतीजा
 निकालना कि पूजावादी राष्ट्रवादिया का वायजम में राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता
 की स्पष्ट मांग थी, बात का बतगड बनाना है। इस प्रसंग में यह कहा
 जा सकता है कि प्रथम अखिल रूसी मुस्लिम कांग्रेस ने भूमि-मुद्दारा पर
 प्रतिनातिकारी प्रस्ताव स्वीकार किया था। उसने मांग की थी कि
 सभी प्रकार की ज़मीनें "समस्त जनगण की सम्पत्ति" घोषित कर दी
 जायें और "भूमि के हर प्रकार के निजी स्वामित्व को बिल्कुल मिटा दिया
 जाये"। किसानों को बिना उजरती के श्रम का प्रयोग किये भूमि को इस्तेमाल
 करने का अधिकार प्रदान करना था। मुस्लिम कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव
 ने सविधान सभा द्वारा समस्या के समाधान की प्रतीक्षा किये बिना तुरत
- * 'उलुग तुकिस्तान', अंक ५, १३ मई, १९१७ और 'नाशा गज़ेता',
 अंक १८, १६ मई, १९१७।
 ** 'उलुग तुकिस्तान', अंक २०, ४ अगस्त, १९१७।
 *** वही, अंक १८, २७ जुलाई, १९१७।

भूमि-सुधार की मांग की थी।* यह देखा जा सकता है कि प्रथम क्रिस्ती मुस्लिम कांग्रेस का भूमि कायनम भूमि के संवर्धन में बाल्शेविक वायन की प्रतिध्वनि माल था। यहां तक कि उसने भूमि के राष्ट्रीयकरण के लेनिनवादी आज्ञाप्ति का भी प्रस्तुत कर लिया था। परन्तु इसके आधार पर कोई यह कह सकता है कि पूंजीवादी राष्ट्रवादी वायन में भूमि की समस्या का क्रान्तिकारी समाधान चाहते थे? जाहिर है कि बहुत सी बातें जनता को भ्रमान के लिए कही गई थी। वे जानते थे कि बाल्शेविकों द्वारा प्रचारित राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण का विचार मुस्लिम श्रमजीवी जनता में बहुत जनप्रिय हो रहा था। इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों से अपनी अनुमति जल्दी ही प्रकट की।

यह सही है कि कभी-कभी पूंजीवादी राष्ट्रवादियों ने धर्म के प्रभाव से निवर्तन तथा अपनी अलहदा राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। परन्तु वे अपने आप को उसके प्रभाव से पूर्ण तरह मुक्त नहीं कर सके। उनके लिए इस्लाम और राष्ट्र मूलतः एक ही चीज थी। सितम्बर १९१७ में हुई दूसरी असाधारण क्षेत्रीय मुस्लिम कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि स्वायत्त तुर्किस्तान जनतंत्र का संसद द्विसदनी होना चाहिए, जिसकी उच्च सभा धर्मावलम्बियों की सिनेट हो। उसका वायन यह देखना होगा कि संसद द्वारा स्वीकृत सभी कानून शरीअत के अनुसरण हों। धर्मावलम्बियों की इस सिनेट को सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करना था।** इन सब बातों से यही स्पष्ट होता है कि स्वायत्तता का उनकी धारणा ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक थी, राष्ट्रीय क्षेत्रीय नहीं। जेनाइया ने (यह बात जेनाइया भी स्वीकार करता है) मध्य एशिया की स्वायत्तता को वायरूप देने के लिए कोई यत्न नहीं उठाया।*** व "उलेमा" की प्रतिष्ठा से बहुत डर हुए थे जिनके आगे उन्होंने धार-धार घुटन टेक दिए। "उलेमा" का न स्वायत्तता से कोई दिलचस्पी थी और

* 'नाशा गजेता', अंक २०, १७ मई, १९१७।

* तुर्किस्तान स्त्री कुयूर, अंक २६३, ११ नवम्बर, १९१७। (रूसी मस्वरण)

*** ग० जेनाइया, उपरान्त पुस्तक, पृष्ठ २२५-२२६।

न स्वतंत्रता से। वह केवल मध्य एशिया के मुसलमानों पर धर्माविलम्बिया का प्रभाव कायम रखना चाहती थी।

अन्य पश्चिमी लेखकों ने तुर्किस्तान के पहले बाल्शेविका का स्वायत्तता के कट्टर शत्रु के रूप में वर्णन किया।* कुछ सोवियत लेखकों ने भी उन्हें अप्रैल १९१८ में सावियता की पांचवीं क्षेत्रीय कांग्रेस से पहले तक स्वायत्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का दावा ठहराया है। परन्तु इस विचार से सहमत होना बठिन है। स्थानीय बाल्शेविका पर तुर्किस्तान की स्वायत्तता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का आरोप लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।

ताशकन्द के पुराने शहर में १३ दिसम्बर, १९१७ को स्वायत्तता की माग के पक्ष में प्रदर्शन की तयारी के संबंध में एक सभा हुई, जिसमें ताशकन्द नगर सावियत का एक प्रतिनिधि उपस्थित था।** इस प्रदर्शन में जन-वमिसार परिषद के अध्यक्ष बालेसोव तथा अन्य वमिसार उपस्थित थे। कोलेसोव ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष भाषण दिया और तुर्किस्तान की स्वायत्तता का समर्थन किया।*** प्रतिक्रियावादी रूसियों ने उसको टोकना चाहा, मगर मुस्लिम प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे उसकी बातें सुनते रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो जाता, अगर कुछ प्रतिक्रियावादी रूसिया ने मुसलमानों को हिंसा पर न उकसाया होता और दोरेर जिस प्रति आतिशयियों को जेल से छोड़ा न लिया होता। अतः कुछ प्रतिआतिशयकारी रूसियों के उकसाव का नतीजा था कि प्रदर्शन पर गोली चलाई गई और कुछ निरपराध लोग मारे गए।

‘नाशा गजेता’ ने, जो ताशकन्द सोवियत का मुखपत्र था, १३ दिसम्बर के सम्पादकीय में लिखा कि बाल्शेविक “स्वायत्तता के सिद्धांत” विरोधी नहीं हैं, मगर वे अवश्य “एक छोटे समूह द्वारा स्वायत्तता के नाम पर पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता का शोषण करने और उसको गुलाम

* R Pipes *The Formation of the Soviet Union* p 179, A G Park, *Bolshevism in Turkestan*, pp 14—21

** ‘नाशा गजेता’, अंक १४६, ६ दिसम्बर, १९१७।

*** वही, अंक १५२, १५ दिसम्बर, १९१७।

बनाने के प्रयत्नो" के विरोधी है। ऐसी झूठी स्वायत्तता के विरोध सच्ची वास्तविक स्वायत्तता के पक्षपाती थे जिसकी घोषणा सावधान रूप से निवाचित संविधान सभा (अर्थात् सावियतो की कांग्रेस) द्वारा की जाय।

सोवियतो की चौथी कांग्रेस न, जो ताश्कन्द में १९ से २६ जनवरी १९१८ तक हुई, तात्ति के बाद के पहले कुछ महीना में सोवियत म के निर्माण तथा सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे में तात्तिकारी परिवर्तन में हुई प्रगति पर जोर दिया। स्वायत्तता के सवाल पर भी विचार किया गया। इस अवधि में वास्तविक नेता तोबोलिन का भाषण, जिसपर अफ़ग़ानिस्तान की स्वायत्तता का विरोध करने का आरोप लगाया जाता है इस के योग्य है कि उसका लम्बा उद्धरण दिया जाये। तोबोलिन ने चौथी कांग्रेस में घोषणा की

"इस देश के असली मालिक, जिसकी स्वायत्तता की हम बात कह रहे हैं, हमारे अनुसार इस देश के जनगण हैं। हम आत्मनिर्णय की केवल बात नहीं करते, बल्कि इस विचार को हर तरह कार्यान्वित भी करते हैं। हम हथियार लेकर प्रतितात्ति के विरुद्ध लड़ते हैं चाहे उसका स्रोत भी हो, देशी पजीपति या इसी। इसी के साथ हम न केवल इस देश के लोगों का स्वायत्तता का अधिकार स्वीकार करते, बल्कि उनके अधिकार की भी रक्षा करते हैं कि अगर वे चाहें तो अलग होकर अलग जायें। हम कहते हैं कि तुर्किस्तान के इलाके पर बलपूर्वक बसाया गया था और बलपूर्वक रखा गया था और अगर आम मतानुसार व्यक्त जनमत इस से अलग होना चाहे तो हम अलग होने के इस अधिकार की रक्षा करेंगे।"

परंतु तोबोलिन का विचार था कि यथायक और तुरत स्वायत्तता को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि तात्ति की उपलब्धियाँ प्रतितात्ति से खतरा था और देश में युद्ध की स्थिति थी। मगर तोबोलिन की राय में स्वायत्तता या आत्मनिर्णय के लिए भी तयारी का काम चलाना पड़ा था। उन्होंने विश्वास दिलाया

“हम अपनी मांग ठीक ठीक निरूपित करेंगे और मुसलमानों के बीच मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियत सगठित करके हम सत्ता के उस स्तर का निर्माण कर रहे हैं जो तुर्किस्तान के भावी स्वतंत्र देश के लिए जरूरी होगा।”

तोवोलिन के भाषण के विपरीत मशेविक अंतर्राष्ट्रीयतावादी पावलुचेवो का भाषण था जिसने बोल्शेविकों द्वारा देशी लोगों को देश का “मालिक” कहने पर आपत्ति की। उसने कहा

“हम अपने आपको श्रमिकों के अगुआ दस्ते के रूप में देखते हैं और अपना कर्तव्य यह समझते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व मुस्लिम श्रमजीवी जनगण को सही रास्ते पर ले चल। हम मुसलमानों को सही रास्ते पर ले चलने के सिवा और कुछ नहीं देने जा रहे।”

मशेविकों का सुझाव था कि स्वायत्तता स्थापित करने के लिए, जिसकी घोषणा संविधान सभा द्वारा की जानवाली थी, तयारी के रूप में शहरी और स्थानीय स्वशासन स्थापित किया जाये।

बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने चौथी कांग्रेस के सामने अपने प्रस्ताव में, जो भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ, घोषणा की कि स्वायत्तता का प्रश्न तब तक नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय सवाल से जुड़ा हुआ है जिसे रूसी श्रमिकों ने इस तौर से प्रस्तुत किया था और जिसपर केवल श्रमिकों की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी घोषणा की गई कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत को समाजवाद के ध्येय के अधीन करना चाहिए और उस केवल श्रमजीवी जनगण का आत्मनिर्णय समझना चाहिए। बोल्शेविक प्रस्ताव के अनुसार सारी सत्ता सोवियतों के हाथ में होनी चाहिए। उसने केवल मजदूरों, सैनिकों, किसानों तथा मुस्लिम मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की सत्ता को स्वीकार किया और सत्ता में सारे सुझावों को ठुकरा दिया। अतः प्रस्ताव ने मुठ्ठी भर रूसी और मुसलमान प्रतिनिधियों द्वारा पूंजीवादी स्वायत्तता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष का आवाहन किया

* वही।

** वही।

ग्रीर कहा कि सामाजिक जनवादियों को पार्टी उन क्षेत्र के लिए सवहारा स्वायत्तता स्थापित करने का प्रयास करेगी।*

ऊपर उद्धृत प्रस्ताव से स्पष्ट है कि बोल्शेविक स्वायत्तता के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि केवल पूंजीवादी स्वायत्तता के विरोधी थे। उन्होंने मने ही पूंजीवादी स्वायत्तता के मुकाबले में सवहारा स्वायत्तता को पेश किया। यह आगोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि उनमें स्थानीय ममनमान जनता के प्रति शत्रुता की भावना थी। उन्होंने सोवियत प्रशासन में धर्मजात मुसलमान जनता की शिक्षण का स्वागत किया और सोवनारकाम (जो कमिसार परिषद) में उनके लिए तीन स्थान रिक्त रखे।

परंतु इस सबके बावजूद पहले बोल्शेविक ऐसी जातीय स्वायत्तता का निर्माण करने में असफल रहे। जहां उनकी पूंजीवादी स्वायत्तता का विपरीत सवहारा स्वायत्तता की मांग बिल्कुल सही थी, वहां शुरू में अपने सवहारा स्वायत्तता का जातीय रूप देने में उनकी असफलता के कई दर परिणाम हुए। पूंजीवादी राष्ट्रवादियों ने इस स्थिति से पूरा पायदा उठाया, जिन्होंने जातीय स्वायत्तता के रूप में अपनी पूंजीवादी स्वायत्तता का विचार को जनता में चालू करना चाहा। परंतु सोवियत की तीसरी और चौथी कांग्रेसों के समय सोवनारकोम में मुसलमान प्रतिनिधियों का नहीं हान की जिम्मेदारी बोल्शेविकों की केवल आशिक है, क्योंकि उसमें १५ स्थान में उन्हें केवल ५ स्थान प्राप्त थे ("पराकाष्ठावादियों" को २ तथा सामान्य समाजवादी आतिथारियों को ८)।

जनवरी १९१८ के अंत में सोवियत मत्ता न जाइत्मव और बज्जा की प्रतिनिधित्वारी शक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने उससे बगावत कर दी थी, सैनिक दारवाई शुरू की। कोकान स्वायत्ततावादी और इतोंव न जाइत्मव से मिले हुए थे। ताशकन्त के लाल गाड ने जाइत्मव के १८ परवरी १९१८ का ममरान्द के निकट पराम्त्त कर लिया। समरकन्त नोट सफन्त वदज्जाना का शिवम्त दन के बाद बोल्शेविकों ने वारत स्वायत्ततावादीयों के विरुद्ध अपना गावजनिव प्रचार आशालन और त कर लिया।

जनवरी ही में शहरा और ग्रामों के गरीबों की गणायें संगठित की गई थीं, जिनमें सावियत सत्ता के समयन में प्रस्ताव पास किये गये। इन सभाओं में बोलशेविकों का वारान स्वायत्ततावादियों के वास्तविक द्वारा का बेनकाब किया। ताशकन्द के पुराने भाग में एक बड़ी सावजनिक सभा में स्थानीय श्रमजीवी जनता ने कोमान के मिथ्या स्वायत्ततावादियों के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया। फरगाना और समरकन्द प्रदेशों के श्रमजीवी जनगण ने अनन्त सभाएँ की और तुकिम्तान की जन-समितार परिषद का अभिनन्दन किया। अन्दीजान उपेन्द (जिले) के श्रमजीवी जनगण ने ५ जनवरी, १९१८ को एक सभा में जिनमें १५ हजार मजदूर उपस्थित थे, एक प्रस्ताव स्वीकार करके सावियत सरकार में अपना विश्वास प्रकट किया।*

३०-३१ जनवरी की रात, १९१८ को वारान स्वायत्ततावादियों ने सावियत सत्ता की नगर-संस्था के विरुद्ध सनिक कारवाई शुरू की। उन्होंने कोमान जिले को घेर लिया। हमने मजदूरों को सावियत सरकार को उनके विरुद्ध खारदार सनिक बंदम उठाना पड़ा। समरकन्द के निकट सफेद बन्जाराओं की शिवस्त के बाद लाल गाड़ वाले कोमान की तरफ बढ़ गये। फरगाना और अन्दीजान के लाल गाड़ वाले भी वारान की ओर बढ़े। उनकी पकिया में बहुत से देशी लोग भी थे। सनिक कारवाई १६ फरवरी, १९१८ को शुरू हुई और २२ फरवरी, १९१८ तक जारी रही। कोमान के पूजीवादी स्वायत्ततावादियों के विरुद्ध सड़कों में स्थानीय देहशानों और गरीबों ने प्रमुख भाग लिया। कोमान सरकार द्वारा लामबन्दी का आदेश मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। २२ फरवरी, १९१८ का कोमान सरकार नष्ट कर दी गई। प्रतिभातिकारी स्वायत्ततावादियों का एक हिस्सा भाग कर दुखारा चला गया, जहाँ वे अमीरों से मिलकर सोवियत सत्ता के विरुद्ध पड़पन्न करते रहे। कोमान सरकार के विघटन के बाद पूजीवादी राष्ट्रवादी फरगाना घाटी में बासमची** गिरोह संगठित करने लगे।

* "उजबेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास", ताशकन्द, १९५७, खण्ड २, पृष्ठ ६१। (इसी संस्करण)

** सोवियत सत्ता के प्रथम वर्षों में मध्य एशिया में आतिविरोधी कारवाइया करनेवाले सशस्त्र दलों के सदस्यों को बासमची कहते थे। - अनु०।

मार्च १९१८ को सोवियत सरकार का असाधारण कमिन्तर त्वा
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति का प्रतिनिधि बोरोस
ताशकन्द पहुंचा। उसे सोवियत सत्ता को सबल बनाने और तुकिस्तान
स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना करने में पार्टी को
सोवियत सत्ता की स्थानीय संस्थाओं की व्यावहारिक सहायता करने के
लिए भेजा गया था। अप्रैल १९१८ में तुकिस्तान के मजदूरों, किसानों,
सैनिकों तथा मुस्लिम बेहकानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की पांचवीं
क्षेत्रीय कांग्रेस हुई। पांचवीं कांग्रेस के प्रतिनिधियों में काफी बड़ा हिस्सा
देशी आवादी के प्रतिनिधियों का था। प्रतिनिधियों के भाषणा का अनुवाद
उत्सव भाषा में किया जाता था। २२ अप्रैल को कांग्रेस के नाम लेनिन
और स्तालिन का तार आया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि
सोवियतकोम सोवियत के आधार पर क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करेगा।
३० अप्रैल, १९१८ को पांचवीं कांग्रेस ने "रूसी संघ के तुकिस्तान सोवियत
जनतन्त्र की संविधि" का अनुमोदन किया। संविधि की धारा १ और २
में जनतन्त्र के राजकीय ढांचे, इसकी क्षेत्रीय सीमाओं तथा रूसी सोवियत
संघात्मक समाजवादी जनतन्त्र से पारस्परिक वैधानिक संबंधों की व्याख्या
की गई थी। तुकिस्तान सोवियत संघात्मक जनतन्त्र को स्वायत्ततापूर्ण
स्वशासित घोषित किया गया। परन्तु उसने केन्द्रीय सत्ता को स्वीकार किया
और उसके साथ संबंध स्थापित किया। कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक आया
केन्द्र के साथ पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने का स्वागत भेजा गया।

पांचवीं कांग्रेस द्वारा स्वायत्तता की घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी का
लेनिनवादी जातीय नीति के मौलिक सिद्धांतों की विजय का परिचायक था।
इसका तुकिस्तान में सोवियत सत्ता के सुदृढीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ
पनपी। कांग्रेस ने तुकिस्तान सोवियत जनतन्त्र की उच्च मन्त्रिमंडल-स्तरीय
(केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति) और सोवियतकोम (जन-अभिसार परिषद)
का निर्माण किया। स्थानीय स्तरों के प्रतिनिधि राज्य की सर्वोच्च मन्त्रिमंडल
में चुने गये। नयी जन-अभिसार परिषद में नयी आवाजी के तार प्रतिनिधि
थे। पांचवां कांग्रेस ने तुकिस्तान इलाके की स्वायत्तता की घोषणा कर
एक बड़ा ऐतिहासिक काम पूरा किया। तुकिस्तान की सोवियत स्वायत्तता

सोवियत सत्ता की स्थापना १८५

- मध्य एशिया में राष्ट्रीय सोवियत जनतन्त्रों के निर्माण की दिशा में
- महत्वपूर्ण कदम था।

१९१८ में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जून में तुकिस्तान के बोल्शेविक सगठनों की, जिन्होंने संयुक्त होकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के अभिन्न अंग के रूप में तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, पहली कांग्रेस हुई। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में राज्य के प्रशासन में स्थानीय श्रमजीवी जनगण की व्यापक शिरकत, पार्टी प्रसारण को सबल बनाने, सभी ओब्लास्तों, उपेखों और स्थानीय सोवियतों में राष्ट्रीय मामलों की कमिसारियत स्थापित करने, दली भाषाओं में कांग्रेस की दस्तावेजों प्रकाशित करने, आदि की जरूरत पर ज़ार दिया गया।* तुकिस्तान में सभी जातियों के श्रमजीवी जनगण सोवियत निर्माणकार्यों में व्यापक पैमाने पर शरीक होने लगे। तुर्क केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के ११ जुलाई, १९१८ के निर्णय के अनुसार मध्य एशिया की जातियाँ की भाषाओं को रूसी के साथ समान स्तर पर राजकीय भाषाएँ घोषित किया गया।**

ताशकन्द में २१ अप्रैल, १९१८ को तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।*** जुलाई १९१८ में उज़बेक भाषा में "इस्तराकिज़्न" (कम्युनिस्ट) अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ।

अक्टूबर १९१८ में सोवियतों की छठी कांग्रेस ने तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के प्रथम संविधान का अनुमोदन किया। तुकिस्तान के लिए सोवियत स्वायत्तता की घोषणा और संविधान की स्वीकृति के साथ पार्टी की लेनिनवादी नीति को कार्यान्वित करने के संघर्ष की पहली मजिल पूरी हो गई। स्वायत्त तुकिस्तान एक बहुजातीय जनतन्त्र था, जिसके भीतर सभी जातियों के समान अधिकारों की रक्षा की गई थी। राजनीतिक अधिकारों की समानता के सुरक्षित होने के बाद अब

* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव और निर्णय", ताशकन्द, १९५८। (रूसी संस्करण)

** नाशा गज़ेता

अंक १४४, १७ जुलाई, १९१८।

*** नाशा गज़ेता, २३ अप्रैल, १९१८।

समाजवादी विकास तथा समाजवादी जनतन्त्रों के निर्माण की तयारी का काम रह गया था।

तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना के सम्पूर्ण सहयोग के वातावरण में हुई। किसी भी अवस्था में केंद्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों में उनके अपने-अपने अधिकारों के सवाल पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ पश्चिमी लेखकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों में इस सवाल पर फूट थी। उनके लिखने का आशय यह होता है मानो तुकिस्तानी प्राधिकारी ज्यादा अधिकार चाहते थे और केंद्र उन्हें देना नहीं चाहता था। इसके सवाल में वे कहते हैं कि तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र के निर्माण की आज्ञाप्ति जारी करने में केंद्र ने "असाधारण" तौर पर बड़ी देर की। यह आज्ञाप्ति, उनका कहना है, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ११ अप्रैल, १९२१ में जारी की गई। उनका कहना है कि यह तभी किया गया, जब तागो "अवकाशी" नहीं रहा और सितम्बर १९२० में सोवियतों की क्षत्रप कांग्रेस में नया संविधान स्वीकार करके, जो "अभरत मास्को में स्वायत्तता की धारणा के अनुकूल था" पर्याप्त मात्रा में मास्को में आनाकारी बन गया।*

परन्तु इस विचार में तथ्य भी सत्य नहीं है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि अस्तूवर १९१८ तक मास्को और ताशकेंड परस्पर संघर्ष का सवाल तय हो चुका था और केंद्र ने तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र का पूर्ण स्वीकार कर लिया था। अगर इस संघर्ष में कोई आज्ञाप्ति जारी नहीं की गई तो इसका कारण यह था कि तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र के संविधान का अनुमोदन करने में कुछ दिनों की आज्ञाप्ति की ज़रूरत नहीं थी। नया सोवियत संघ, रु० सो० स० म० जनतन्त्र का स्वच्छापूर्ण संघ था जिसका निर्माण कमाल शमिन हानन स्वायत्त जनतन्त्र के वार्ताचार्य के जरिये हुआ था। जुलाई १९१८ में मास्को में आया अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वा० सो० स० म०

जनतन्त्र के संविधान में इसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि इसमें शामिल होने वाले स्वायत्त जनतन्त्रों के संविधान का अनुमोदन केंद्र द्वारा किया जाये, न ही संविधान ने इसका अधिकार केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को दिया था।*

हम यह भी जानते हैं कि तुकिस्तान केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का प्रतिनिधि मंडल जिम्म त्राईत्सकी, युसूपोव, तेओदोरोविच तथा दो और व्यक्ति थे, पारस्परिक संबंधों पर वार्तालाप करने मांस्का गया था। प्रतिनिधि मंडल लेनिन और स्वेदलोव से मिला और इसके सदस्यों ने तुकिस्तान स्वा० सा० स० जनतन्त्र के प्रतिनिधियों की हैसियत से सोवियतता की पाचवीं अखिल रूसी कांग्रेस में भाग लिया। पारस्परिक संबंधों के सवाल पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति स्वेदलोव ने एक आयोग नियुक्त किया जिसमें रोजेनगोल्स, यनुकीद्जे, खेलनीत्स्की तथा दो और थे। कई बैठकों के दौरान में, जो जुलाई १९१८ में केंद्रीय आयोग और तुकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई, बड़ी प्रगति हासिल की गयी थी और तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र की सीमाओं, इसकी सत्ता-संस्थाओं तथा प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों आदि के संबंध में कुछ सवालों पर स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण के सवालों को सतोपजनक रूप में हल कर लिया गया। केंद्र और तुकिस्तान के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक की बारंबारी की जो रिपोर्ट ४ अक्टूबर, १९१८ के "नाशा गजेता" में छपी, उससे यह लग सकता है कि बातचीत सरल ढंग से नहीं चल रही थी। उसमें संकेत है कि तुकिस्तान की कार्यकारिणी संस्था के लिए सोवन्तारवोम का नाम संवसम्मति से नहीं स्वीकार किया गया और कार्यकारिणी समिति संगठित करने का सवाल अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के हवाले कर दिया गया। यह भी खबर थी कि तुकिस्तान की "असाधारण घटनाओं" के कारण चौथी बैठक स्थगित कर दी गई और आयोग का काम वहां सामान्य स्थिति लौट आने तक के लिए रोक दिया गया। यह भी कहा गया कि तुकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल वापस लौट रहा है।

* "सोवियतता की कांग्रेसों की दस्तावेजें १९१७-१९२६", मांस्को, १९५६, खण्ड १, पृष्ठ ७७-७८। (रूसी संस्करण)

परन्तु प्रतिनिधि मंडल तुकिस्तान वापस नहीं गया। यह भी "नागा गजेता" के उम्मी अक् से मालूम हो जाता है। अक्टूबर में वह अफा मारा में ही था और २ अक्टूबर, १९१८ को तोईत्स्की और युसूपोव ने २४ और तुकिस्तान के परस्पर संबंधों को तय करने के सवाल पर हई प्रती के बारे में एक सदेश केन्द्र से भेजा था। उन्होंने इस सदेश पर तुकिस्तान के पूर्णाधिकारी दूतों की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे। ऐसा लगता है कि शुरू की बैठको में, जो जुलाई १९१८ में हुई थी, मतभेद कुछ तकरावा बातों पर हुआ था। जनवरी १९१८ में स्वीकृत रु० सा० स० जनतंत्र के संविधान में स्वायत्त जनतंत्रों के निर्माण की बात नहीं साची गई थी। इसमें केवल "स्वायत्त ओब्लास्त सभा" की गुजाइश रखी गई थी। परन्तु जीवन में तुकिस्तान के स्वायत्त जनतंत्र को जन्म दिया था और लेनिन तथा स्वेदलोव ने इसकी उत्पत्ति का स्वागत किया। तुकिस्तान के प्रतिनिधियों ने सकेत किया है कि उन्होंने लेनिन, स्वेदलोव तथा जन कमिसार परिषद के अन्य सदस्यों की ओर से तुकिस्तान जनतंत्र में पूर्ण विश्वास पाया। उन्होंने आशा प्रकट की कि जब आयोग अपना काम शुरू करेगा, तो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा सोवनास्त्रों के अधिकारों तथा संगठन के संबंध में सब कुछ तय हो जायेगा। उन्होंने यह भी लिखा था कि "लेनिन से निजी बातचीत के अनुसार तुकिस्तान कार्यकारिणी समिति को अधिस्तार था कि आपत्ति में कुछ बातों को बदल दे, जो उस क्षेत्र के लोगों की जीवन स्थितियों के विलकुल अनुरूप थी।" "

अतः हमें कोई सन्देह नहीं कि अक्टूबर १९१८ में सावित्रता का एक क्षेत्रीय कांग्रेस में स्वीकृत तुकिस्तान रु० सा० स० जनतंत्र के संविधान का चर्चा की पूरी मजबूरी प्राप्त थी और उम्मी कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। तत्पश्चात् में इस संविधान ने और सितम्बर १९२० में सावित्रता का सभी क्षेत्रीय कांग्रेस में स्वीकृत संविधान द्वारा एक वैश्वीय संरक्ष, प्रतिष्ठा,

'सावित्रता की कांग्रेस की व्याख्या', पृष्ठ ७३।

'नागा गजेता' अंक २०६, ४ अक्टूबर १९१८।

- वित्त रेलवे डाक-तार संपीय सरकार व हवाय पर दिया था।* परन्तु १९१८ के संविधान में इन विषयों पर कुछ अधिकारक्षेत्रीय प्रतिबंध थे। जिनको १९२० के संविधान में हटा दिया गया। इन प्रतिबंधों की जरूरत तुर्किस्तान में १९१८ की असाधारण स्थिति व कारण थी, जब वहाँ स कोई स्थायी सम्भव नहीं था। परन्तु १९२० में यह स्थिति बदल चुकी थी। तुर्किस्तान जनतन्त्र १९१८ में अपने जन्म के समय ही समाजवादी राज्य बन गया। १९१८ से १९२४ तक लगभग हर जगह ग्रामीण सोवियत और जन 'यायालय' स्थापित किए गये, जिनमें देशी भाषाभाषी, रीति रिवाज और परम्पराओं का गान रखनेवाले स्थानीय जातियाँ के लोग थे। अब प्रशासकीय संस्थाओं में बहुमत स्थानीय भाषावादी व प्रतिनिधियों का था। सोवियत सत्ता इस प्रकार सचमुच जनगण की अपनी सत्ता बन गई। सरकार ने स्थानीय विरासतों का ध्यान रखा और कुछ हालतों में पुराने रिवाजों को रहन दिया। मिसाल के लिए सोवियत 'यायालयों' के साथ साथ जहाँ नये कानूनों व अनुसार 'याय' किया जाता था, पुरानी शाय जहाँ नये कानूनों व अनुसार 'याय' किया जाता था, पुरानी स्लिम अदालत भी थी जिनका लोग आदी थे और जिनमें कानूनी लोग रोकत (धार्मिक कानूनों) व अनुसार 'याय' करते थे। अगर किसी व्यक्ति को कानूनी के फसले से सतोष नहीं होता, तो वह सोवियत 'यायालय' में जा सकता था। लोग थोड़े ही दिना में अपने अनुभव से सोवियत कानूनों की श्रेष्ठता के कायल हो गये, जो शासितों की सुरक्षा करते थे और कानूनी की अदालतों का काम धीरे धीरे पच फँसला करना हो गया और फिर वे बिल्कुल लुप्त हो गई।

खीवा और बुजारा में सोवियत जनतन्त्रों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खीवा के लोगों की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। रुस से खाद्यान्न के आयात में बाधों से भी ज्यादा की

*"सोवियतों की काग्रेस की दस्तावेज़ें", पृष्ठ २७६, ४५०।

कमी हो गई तथा अन्य निमित्त सामानों के आयात में भी कमी हुई। इससे लोगों की कठिनाइयां बहुत बढ़ गईं। खाद्य पदार्थों का बड़ा अभाव हो गया। किसान करा के भारी बोझ में लाहि लाहि कर रहे थे, जो १९१८ और १९२० के बीच और बढ़ गया। उन दिनों खीवा पर खान का प्रभुत्व था। खान के अधिकारी और डाकू दाना जनता का लूटते। खान शासित प्रदेश में अनेक जातियों के लोग थे, जस उस्त, तुक्मान, कराकल्पाक और कजाख। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि उनमें आपस में शांति बनी रहती हो। अक्टूबर आति से पहले के दश में राष्ट्रीय सवाल बहुत तीव्र हो उठा था। उज्बेक अभिजात वर्ग के साथ उज्बेक श्रमजीवियों का शोषण तो करते ही थे, वे तुक्माना और कराकल्पाक का भी दमन करते थे।

पूजीवादी अस्थायी सरकार ने जिसे फरवरी आति के फलस्वरूप सत्ता मिली थी, उज्बेक, तुक्माना, कराकल्पाक देहकानों तथा शहरी ग्रामीणों के विद्रोहों के विरुद्ध अपनी सेनाओं के जरिये खान के निरकुश राज का समर्थन किया। खान राज में रहनेवाले किसान और बारीगर स्वतंत्र ढंग से ही खान के अधिकारियों के निरकुश शासन और सामंती बाई तांग और मुत्ताआ के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया करते। वे बाई और बक लागा की संपत्ति जला देते और उनके मकानों और छायादान लूट ल जाते। २० मई, १९१७ को खान राज की राजधानी खीवा के दरिद्र लोगों ने आटा और चानल लूट लिया। खीवा स्थित कज़ाख पलटन ने "अपने के बचक" को बड़ाई से कुचन दिया।

मई-जून १९१७ में देहकानों ने बुनिया उरगेच इलाके में सफल विद्रोह शुरू किया। आदालत इतना प्रबल हो उठा कि खान की अस्थायी सरकार की सहायता सनी पड़ी। उसने जाइल्मेव की कमान में कज़ाख टुकड़ा भेजा। उसने ज़ुनेत खान की ताकत में कुत्तक और बाई फोजी टुकड़ा संगठित करना में भी सहायता की। २० मितम्बर, १९१७ का आदालत और जुनेत खान की बीच एक गमगीला हुआ कि वह ग्यारहमं की गमनिरात में आतिकारी आन्दोलन के विरुद्ध मिन्नतें सपथ करण।

अब और तुर्किस्तान में अगस्त के आति की विजय खीवा के खान के

विरुद्ध जनता के श्रातिकारी सघप व भावी विरास व लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। खान शासित प्रदेश अथ उपनिवेश नहीं रहा और जनगण का अथ खान व निरकुश राज स भुक्ति प्राप्त करने व काम म नय प्रशासन की पूरी सहानुभूति और समथा का विश्वास था। जुनैद खान व सैनिका और क़ज़ाका क़ आतक के बावजूद शहरो और क़िस्ताको (गावा) व थमजीवी जनगण निरकुश शासन और दमन व विरुद्ध उठ खड़े हुए। जन-सघप की इन स्थितियो म खोवा की कम्युनिस्ट पार्टी का जम हुआ, जिसने जनगण को खान प्रशासन की निरकुशता के विरुद्ध संगठित करना शुरू किया।

सोवियत सरकार ने प्रारम्भ म ही घोषित कर दिया कि वह खोवा की स्वाधीनता और प्रभुसत्ता का स्वीकार करती है। इसी सो० स० स० जनतंत्र तथा बुकिस्तान स्वा० सो० स० स० जनतंत्र न अपनी और स खोवा स अच्छे पड़ोसिया जसे सबध विकसित करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु खोवा व प्रतिश्रियावादी शासक हल्के सावियत सत्ता स अपनी अंगी घणा तथा खोवा के लोग पर उसके बहुत प्रभाव के डर व कारण, साम्राज्यवादी खेमे म जा मिल।

शुरू ही स खोवा मध्य एशिया म सावियत विरोधी प्रतिश्रानिगारी बढ़ बन गया, जहा सफ़ेद गाड वाले, मशेविक, समाजवादी श्रातिकारी, पुत्रीशानी राष्ट्रवादी तथा अन्य प्रतिश्रातिकारी तत्व चारा धार स गया व ग्राम लग। यहा ब्रिटिश साम्राज्यवाद व एजट उनस आ मित और उनस महयाग स सोवियत मध्य एशिया पर हमले की तयारी करन लग। उनस मावियन-विरोधी योजनाओं म जाइत्सेव को महत्वपूर्ण भूमिका गौपी गई। जाइत्सेव कोकान स्वायत्ततावादियो तथा आन्क़ा क़ज़ाक़ नता दूताव से भेंट करने के बाद सावियत सत्ता व विरुद्ध प्रन्नाकिन आक्रमण म जुनैद खान का साथ देने पर राजी हो गया। उनकी यात्रना यह थी कि चरख पर क़ज़ा किया जाय और तब राज ठान व तिनार काज़ान क़द और जिज़्ज़ाक़ पर क़ज़ा करन क़ बात न ताइन्द क़द कोकान स्वायत्ततावादिया की सनाए उनस आ मितगी। वतन क़ स्वायत्त सो० स० स० जनतंत्र व आन्क़ा क़ज़ा के इनाक़े म क़द

तख्ता उलटने का काम भी जुनैद खान के सुपुद किया गया। खात्र प्रतिनातिकारियों का स्थायी सम्पक ताशकद के गुप्त सोवियत विराज सगठन से था, जिसे तुकिस्तान सैनिक सगठन कहा जाता था और बिना स्थापना अमरीकी कौसल, फासीसी एजेंट कस्ताये और अग्रज बन वेली की सक्रिय शिरकत से हुई थी। जुनैद खान की सेनाया ने अज्ञाता में प्रतिनातिकारी उलट फेर सगठित करने में सक्रिय भाग लिया।* २६ नवम्बर, १९१८ को जुनैद खान आमू दरिया क्षेत्र में सोवियत इलाक में घुस गया और लूटमार करने लगा। उसने किपचाक और बिम्बाई पर कब्जा कर लिया और तुतकुल (उस समय पेत्रो अलेक्साद्रोव्स्क) को पर लिया। तुतकुल के वीर रक्षकों ने जुनैद खान को भारी क्षति पहुंचाई और उसे विवश होकर अपना ११ दिन का असफल घेरा उठा लेना पड़ा। जनवरी १९१९ में जुनैद खान ने फिर सोवियत क्षेत्र पर आक्रमण किया, मगर फिर उसे शिकस्त खानी पड़ी। अप्रैल १९१९ में उसने सोवियत सरकार से शांति का आग्रह किया। रु० सो० स० स० जनतंत्र तथा खात्र के प्रतिनिधियों के बीच ६ अप्रैल, १९१९ का तखता किले में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसका अनुमोदन तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और खान सैयद अब्दुल्लाह ने मई १९१९ में किया। इस समझौते के अनुसार जुनैद खान को रु० सो० स० स० जनतंत्र के विरुद्ध कोई सशस्त्र कारवाई नहीं करना था। समझौते में स्वयं और जल मार्गों से व्यापार की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा राजनयिक प्रतिनिधिमंडल की अदला-बदली का भी प्रबंध था।**

परन्तु चीवा ने इस समझौते का पालन कभी नहीं किया। साविक सरकार ने एक व्यापार संधि करने का कई बार आग्रह किया, मगर खात्र ने उग अस्वीकार कर दिया। जुनैद खान ने सावियत विरोधी हरकतें बना रही छाड़ी। जून १९१९ में उसने कई सामवांती का आदेश दिया और माताक से संपक स्थापित किया। उसी महीने चीवा और दुंगारा के बीच

* उर्वरेण मायिया समाजवादी जनतंत्र का इतिहास", पृष्ठ १८१।

*यही, पृष्ठ १८३-१८४।

प्रतिनिधि मंडल का आदान प्रदान हुआ। अगस्त में उराल के कज़ाखों ने सोवियत सरकार व विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया और बाई लोग और कुलकों की सहायता से चिम्बाई और नुकूस पर कब्ज़ा कर लिया। आमू-दरिया की सरकार की स्थापना की गई जिसका प्रधान एक कुलक फेलिचेव था। जुनैद खान ने इसे तुरंत मायता दे दी। द्रासवास्पिन इलाक में सफ़द गाड़ का १९१९ के अंत में सफाया हो गया तो सभी समाजवादी नातिकारी और मशेविक अशकावाद से भागकर चीवा पहुँचे, जहाँ वे जुनैद खान के सलाहकार बन गये।

जब जुनैद खान इस प्रकार सोवियत सरकार व विरुद्ध पड़्यत कर रहा था, तो चीवा में देहकानों का नातिकारी आंदोलन बढ़ता जा रहा था। देहकानों और भूमिहीन किसानों के विद्रोही दस्ता ने तुतकुल को अपना केन्द्र बनाया। फूजे और कूइविशेव के नेतृत्व में तुक आयोग ने चीवा के कम्युनिस्टों रहमान प्रिमचतोव, अहमेजान इब्राहीमोव, कुर्वान बकनियोजोव, अब्दुल्लायेव, न० सलापाव आदि की सहायता की कि वे चीवा के नातिकारी आंदोलन को संगठित करें। उन्होंने चीवा नौजवान संगठन के दक्षिणपथियों का परदा फाश किया जो जुनैद खान की मदद करने लगे थे। वामपंथी नौजवान चीवाई जैसे पहलवान नियोज युसूपोव, नज़ीर शालिकारोव, इत्यादि स्थानीय बुद्धिजीवियों तथा पूँजीपतियों व मध्यम तबके के साथ-साथ सामंती उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। किसान और कारीगर नौजवान चीवाई इस आंदोलन से अलग होकर चीवा की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये।

चीवा व कम्युनिस्ट सशस्त्र नातिकारी स्वयंसेवकों का संगठित करने में सक्षम हो गये। उनके निदेशन में नवम्बर १९१९ में कूनगिरात, क्वाज़ेली ईनअलिस्व और दुनिया उरगच की ज़मींदारियों में सशस्त्र विद्रोह हुआ। सोवियत सरकार ने चीवा व लोगो के आग्रह पर सफ़ेद गाड़ के विरुद्ध संघर्ष में सहायता करने का फैसला किया। २२ दिसम्बर, १९१९ को सोवियत सेना ने चीवा में प्रवेश किया। २ फरवरी १९२० को चीवा में नाति विजयी हुई। जुनैद खान की कठपुतली सैयद अब्दुल्लाह खान के प्रशासन का अंत कर दिया गया। २ फरवरी, १९२० को चीवा की

कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल सावजनिक सभा न खान के अत्याचार के अत तथा जन-सत्ता की स्थापना का अभिनन्दन किया। सभा ने खीवा के जनगण को खान और ब्रिटिश साम्राज्यवाद्या का अन्त मुक्ति दिलाने में लाल सेना द्वारा दी गई सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकटी की। अस्थायी प्रांतिकारी सरकार ने कुरुलताई (जन प्रतिनिधियों के कांग्रेस) आयोजित करने की तैयारी की।

जन प्रतिनिधियों की प्रथम अखिल-भारत कुरुलताई का आयोजन अप्रैल १९२० में हुआ और उसने भूतपूर्व खीवा खान प्रशासन को द्वारा सोवियत जनवादी जनतंत्र घोषित किया। कांग्रेस न केन्द्रीय कार्यकारी समिति का निर्वाचन किया और सरकार बनायी, जिसे ग्रामी नायबों की परिषद कहते थे। जन प्रतिनिधियों की पहली कुरुलताई ने द्वारा सोवियत जनवादी जनतंत्र के प्रथम संविधान का अनुमोदन किया, जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय क्षेत्रों में सारी सत्ता मेहनतकशों की सोवियत संघ में सुपुर्द कर दी। कुरुलताई सत्ता की सर्वोच्च संस्था थी। संविधान खीवा के जनगण के लिए भाषण, अखबार और सभा इत्यादि की स्वतंत्रता की गारंटी दी। खान और उसके उच्चाधिकारियों की सम्पत्ति, जो प्राति के समय जब्त कर ली गई थी, सावजनिक सम्पत्ति घोषित कर दी गई। १८ वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों का वोट का अधिकार दिया गया। इससे वंचित थे प्रांतिकारी, खान और उसके स्थानीय भूतपूर्व खान प्रशासन के उच्चाधिकारी और बड़े जमींदार। अखिल सोवियत जनवादी जनतंत्र के संविधान न सभी जातियों के समान अधिकारों का प्रावधान था।

खीवा की प्राति की अपनी खास विशेषताएँ थी। औद्योगिक सहायता की संख्या बहुत कम थी और अधिकांश लोग देहात थे। इसलिए पहला अवस्था में प्राति समाजवादी नहीं, बल्कि जनवादी प्राति था। जनवादी जनता का प्रांतिकारी जनवादी अधिनायकत्व स्थापित किया। पहली अवस्था की प्राति को दूररी समाजवादी अवस्था में सन्नत बनाने का प्रयत्न किया था। पूँजीवादी-जनवादी प्राति का कार्यक्रम पूँजीवादी वर्ग को नहीं बल्कि जनता के प्रांतिकारी अधिनायकत्व का प्रसार करना था।

यह किसान जनता ने अपनी सोवियत सत्ता की सस्थाओं के जरिये किया।

क्रांति के बाद खीवा में युसूपोव के नेतृत्व में जो प्रथम सरकार बनी, उसपर भूतपूर्व नौजवान खीवाई तत्वों का कुछ रंग चढ़ा हुआ था, जो सोवियत सरकार के कायमारों के विरोधी थे। उसमें अनेक पूजीवादी राष्ट्रवादी थे, जो ख्वारज़म को सोवियत रूस से अलग रखना और उसे अग्नेज़ा का उपनिवेश बना देना चाहते थे। उन्होंने भूमि-सुधार में बाधाएं डालीं। पान की जल की हुई ज़मीनें बाई लोग और साहकारों के हवाले कर दी गईं। वक्फ की ज़मीनें ज्यों की त्यों रहने दी गईं और देहकानों ने जब उनपर कब्ज़ा करना चाहा, तो उन्हें सज़ा दी गई। नई सरकार ने उज्वेका और तुक्माना में जातीय शगडा भी उठा दिया।

अतः खीवा की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने एक गम्भीर कायभार था। और वह था भूमि और पानी की समस्या तथा जातीय सबंधों की समस्या का आतिकारी समाधान ढूँढने का कायभार। वह बैरी लोगो को निकाले बिना इस कायभार को पूरा नहीं कर सकती थी। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के तुक् ब्यूरो तथा तुक् आयोग की सहायता से इसका प्रयास शुरू हुआ। पार्टी में अधिकाधिक गरीब लोगो को शामिल किया गया और पूजीवादी राष्ट्रवातियों के विरुद्ध सघष छेड़ दिया गया। ६ मार्च, १९२१ को खीवा में मेहनतकश लोगो की आम सभा की गई, जिसने बैरी लोगो को सरकार से निकालने की मांग की। दूसरी क्रुहलताई के अधिवेशन से पहले एक नई अस्थायी आतिवारी सरकार बनायी गई।

मई १९२१ में दूसरी क्रुहलताई का अधिवेशन हुआ। कुल ३४० प्रतिनिधियों में बड़ा बहुमत गरीब और मध्यम देहकानों का था। उसने वक्फ की ज़मीन को राज्य से अलग किया और भूमि के स्वामित्व की हदबन्दी उठाने पर कर दी जितने पर स्वयं एक व्यक्ति काम कर सकता था। चौदह हजार तनाब भूमि देहकानों में वितरित की गई। दूसरी क्रुहलताई ने बड़े उत्साह के साथ रु० सो० स० स० जनतंत्र के साथ सैनिक और राजनीतिक समझौते का अनुमोदन किया। रु० सो० स० स० जनतंत्र ने खीवा के श्रमजीवी जनगण के आर्थिक, राजनीतिक और

सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने में उनकी बड़ी सहायता की। रूस स० स० जनतंत्र ने खीवा जनतंत्र की स्वाधीनता और प्रभुसत्ता को स्वीकार किया और भूतपूर्व खान ग्रासिन प्रदेश में पहले की रूसी सरकार की औपनिवेशिक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त थीं, उन सब का त्याग का घोषणा की। फिर उसने खीवा में अपनी सारी सम्पत्ति, कारखाने, जंगल और जहाज आदि जनतंत्र की नई सरकार के हवाले कर दिया। सोवियत सरकार ने जनगण का आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊँचा करने में खीवा सोवियत जनवादी जनतंत्र की बड़ी सहायता की। उसे सावियत सरकार ने ५० करोड़ रूबल की सहायता एकमुश्त मिली। रूस से बड़ी संख्या में प्रशिक्षक, इंजीनियर, डाक्टर और शिक्षक आदि भी वहाँ भेजे गए थे।

खीवा की तरह बुखारा में भी सामंती निरकुश राज था जो वह जारशाही रूस का संरक्षित राज्य था। फ़रगाना के बाद जारशाही रूस के लिए वह कपास का दूसरा बड़ा स्रोत था। रूस को इन कुल निर्यात में ४० प्रतिशत कपास था। अपनी कपास का ६० प्रतिशत वह रूस को भेज दिया करता था। बुखारा में पूँजीवादी ढंग का कोई बड़ा निमाण-उद्योग नहीं था। जो ५२ फैक्ट्रियाँ थीं, उनमें २६ स्त्रीश्रम का काम करती थीं। आवादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसान था दिनकी हाना दिनादिन बिगड़ती जा रही थी। बुखारा में मुस्लिम धार्मिक नेताओं का बड़ा प्रभाव था। मकतबा और मदरसा में वहाँ २० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे।

प्रथम रूसी प्राप्ति के विचारों के प्रभाव में बुखारा में जदीदियत का नाम से एक प्रगतिवादी पूँजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन का विकास हुआ। परन्तु जदीदियो का काम सामंती तथा शैक्षणिक क्षेत्रों तक ही सीमित था। उन्होंने विद्यमान व्यवस्था के पिछाप लट्ठन का बीड़ा नहीं उठाया। उन्हें अमीर तथा उमरे धर्मभीरु बजिरा की शायबूद्धि और विवेक का बड़ा भरोसा था। रूस की परवरी प्राप्ति के बाद ही जदीदियाँ न, ज

नौजवान तुर्कों की देखा दखी अपन को नौजवान बुखारो कहने लगे थे, आशिव सुधारा की माग की। उनकी माग थी कि कर ठीक-ठीक तय कर दिय जायें और भजलिस (संसद) का आयोजन किया जाये। अमीर ने ७ अप्रैल, १९१७ को कुछ सुधारा का वादा करत हुए जा घायणापत्र जारी किया, उसे कभी पूरा नहीं किया। जदीदो प्राति का नहीं, सुधारा का समर्थन करत थे।

अक्टूबर प्राति की विजय न बुखारा के लोगो को रूसी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिला दी। नवम्बर १९१७ में बुखारा की सभी रूसी वस्तियाँ—नया बुखारा, चारजूए, केरकी और तेरमीज—में सत्ता सावियतो के हाथ में आ गई। बुखारा की धरती पर सोवियतता का जाल सा बिछ गया, जो बुखारा में प्रातिकारी आंदोलन के भावी विकास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

शुरू ही में सोवियत सत्ता ने प्रति अमीर का रख शत्रुतापूर्ण था। नवम्बर १९१७ और मार्च १९१८ के बीच उसने तीन बार सेना के लिए तामबन्दी का आदेश दिया। उसने ओरेनबुर्ग कज़ाक के नेता दूताव से तथा कोकान के पजीवादी राष्ट्रवादी स्वायत्ततावादियों से भी सम्पर्क स्थापित किया। उधर ईरान में अंग्रेजी सेना के कमांडर मैलेसन से भी उसका सवध था। अमीर की सेना में कोई २,००० अफगान भाड़े के सिपाही अंग्रेज अफगानों की कमान में काम करते थे। १९१८ के प्रारम्भ में अमीर ने रेलवे लाइन के किनारे किनारे ३० हजार की सेना तैयार कर ली, जो तुकिस्तान में सोवियत सत्ता के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी। सावियत सरकार ने अमीर से सामान्य सवध स्थापित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया और इस उद्देश्य से दिसम्बर १९१७ में एक राजनयिक मंडल बुखारा भेजा। लेकिन अमीर ने उससे भेंट नहीं की।

६ दिसम्बर १९१७ को नौजवान बुखारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ताराबन्द पहुँचा और उसने सोवियत अधिकारियों का बुखारा में प्राति की तैयारियाँ की सूचना दी, जिसमें बाई ३० हजार सशस्त्र आदमियों के भाग लेने की आशा थी। बुखारा की जनता द्वारा प्रातिकारी कारवाही तयारी की रूढ़ अतिशयोक्तिपूर्ण सूचनाओं से गुमराह होकर ७

जन-कमिसार परिषद ने बुखारा के जनगण को असामयिक सहायता दान का गलत फैसला किया। २८ फरवरी, १९१८ को तुकिस्तान का जन कमिसार परिषद के अध्यक्ष कोलेसोव ५००-६०० लाल गांव दाना लेकर बुखारा की ओर बढ़े। उन्होंने रूसी वस्तुधरो में सोवियत सत्ता का मान्यता देने तथा नौजवान बुखारिया के प्रतिनिधियों को लेकर एक कायकारिणी समिति का निर्माण करने और इस तरह प्रशासन के जनवादीकरण की मांग की। अमीर ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद २ मार्च, १९१८ को कोलेसोव ने अपनी सैनिक कारवाई शुरू कर दी। उनकी बर्मान में कुल २,००० आदमी थे। प्रभात १ समय लेने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव किया और इस बात पर की तैयारी की। उसने समरकंद से रेलवे लाइन काट दी और बास्मच के विरुद्ध "जैहाद" छेड़ दिया। कोलेसोव की समरकंद की तरफ पला हटना पड़ा और तुकिस्तान से ताजी कुमक पहुंचने की वगैरह सबनाश में बच गये। अमीर को किजिल-तेपे में २५ मार्च, १९१८ का समझौता पर हस्ताक्षर करने पड़े। वह सेना की सामवादी का बद करने, तमान रूसी प्रतिआतिकारियों का बुखारा के इलाके से निवालने, विनष्ट रेल लाइन की मरम्मत करने और बुखारा में एक सोवियत कमिसार रखने पर राजी हो गया। इस प्रकार अमीर के शासन का तख्ता उलटने का प्रथम प्रयास विफल हुआ। जनता ने नौजवान बुखारिया का साथ नहीं दिया। अभी वह बड़ी हद तक मुल्लाया के प्रभाव में थी। लेकिन २ मार्च १९१८ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवीं कांग्रेस में इसका चयन का और पिछड़े हुए इलाका में आतिकारी परिवर्तन लागू करने में मायघाता में काम लेने पर जोर दिया।*

किजिल-तेपे के समझौते से तुकिस्तान को आवश्यक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अमीर मार्च की घटनाओं के बाद अंग्रेज साम्राज्यवादी का और निरुद्ध हो गया। अप्रैल और मई १९१८ में कई सौ ऊट्टा पर तमर अंग्रेजी शम्शा अफगानिस्तान के राज्य दुबारा पट्टाचय गये। अमीर

म अमीर को २० हजार राइफले मिली और मई में आठ हजार और।* १९१६ के वसंत तक अमीर की सेना में अंग्रेज प्रशिक्षकों की संख्या ६०० तक पहुंच गई थी।** १९१६ की गमियों में अमीर ने ट्रांसकास्पियन के सफेद गाड़ वालों से मिलकर और अंग्रेजों की प्रत्यक्ष शिरकत से केरवी पर सशस्त्र घावा किया।

इस असफल अभियान का नेतृत्व तुकिस्ता का भूतपूर्व बोल्शेविक युद्ध मंत्री ओसिपोव और अंग्रेज वरनल लोमवाट कर रहे थे। अंततः १९१६ में वरनल बेली ताशकन्द से बुखारा पहुंचा और सोवियत तुकिस्ता का विद्रोह कारवाई की योजना तैयार करने लगा। स्वयं अमीर ने लीग ऑफ नेशन्स के नाम एक स्मृतिपत्र में स्वीकार किया कि वह अफगानिस्ता, खैवा और अंग्रेजों से मिला हुआ है।***

अमीर के आक्रामक इरादों के विपरीत तुकिस्ता के बोल्शेविक उसी प्रति शान्तिपूर्ण नीति पर अमल कर रहे थे। सोवियत सरकार ने हमेशा यही कोशिश की कि अमीर के बुखारा के साथ अच्छे पड़ानियाँ जैसे संबंध स्थापित हों। तुकिस्तान की सोवियतता की पांचवीं गाप्रेस ने बुखारा की स्वतंत्रता की घोषणा की और आगे चलकर बुखारा को काफी भौतिक सहायता भी दी गई। सोवियत सरकार ने अपनी अत्यंत गठिआई के दिनों में भी १९१८ की पतझड़ में बुखारा का डेढ़ करोड़ रूबल वज्र देकर वित्तीय तबाही से बचा लिया।**** परन्तु अमीर ने सोवियत सरकार के प्रति अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। उसने ऊंची दर पर जारशाही मुद्रा खरीदी और उसे भारत की मंडी में इस्तेमाल किया। इसी कारण सोवियत मुद्रा का भाव गिर गया और इससे बुखारा और सोवियत तुकिस्तान के वित्तीय

* "उत्तरे सोवियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास" पृष्ठ २

** व० इ० इसकदारोव, "सोवियत तुकिस्ता में हस्तक्षेप करने के लिए ब्रिटेन द्वारा बुखारा अड्डे की तैयारी", सोवियत विज्ञान परामर्शी के ब्रायज़ान, १९५१, पृष्ठ ४३। (अंती संस्करण)

*** वही, पृष्ठ ४१, ४३।

**** वही, पृष्ठ ५०।

सबधो मे उलझन पैदा हुई। अमीर के शत्रुतापूर्ण रवैये की वजह से बख़ा और सोवियत तुकिस्तान के बीच व्यापार बन्द हो गया। सोवियत सरकार ने बुखारा के कपास के बदले में कपास का तेल और चावल देने का प्रस्ताव किया, परन्तु बुखारा के शासक हल्की ने इसे अस्वीकार कर दिया ब्रिटेन तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियाँ सोवियत देश की आर्थिक नाकाम कर रही थी। इसमें उनकी सहायता करने के लिए अमीर ने सोवियत तुकिस्तान से व्यापार करने से इनकार कर दिया और अपना माल, मुख्यतः कपास और ऊन ब्रिटेन और अफगानिस्तान के हाथ हथियारों के बंधे बेचा। अमीर के अधिकारियों ने बुखारा में सोवियत प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यकलाप में बाधाएं डाली। उन्होंने ट्रांसफास्पियन इलाके के सरगांड वालों को सभी आवश्यक रसद पहुँचाई और उनके विरुद्ध सार्वजनिक कारवाइयों में बाधा डालने के लिए रेलवे लाइनें और तारों के खम्भे उखाड़ फेंके और देहकानों को मना कर दिया कि वे सोवियत सैनिकों को घातक बेलने के लिए रेलवे लाइन के निकट नहीं आया कर।

युवा आयोग ने ताशकंद पहुँचकर बुखारा के मामलों की ओर ध्यान दिया। ७ जनवरी १९२० को आयोग के सदस्य बुखारा गये और अमीर सैयद अलीम खान से मिले। उन्होंने उसे सोवियत रुम से प्रतिस्पर्धा के समय काम करने की आवश्यकता समझाने की कोशिश की, जो एंग्लो-बुखारा की पूर्ण स्वतंत्रता तथा आर्थिक और सामाजिक विकास की सामान्य स्थितियों की जमानत दे सकता था। फिर १४ मार्च, १९२० को फ़ूज दुआ आयोग के अन्य सदस्यों के संग बुखारा आय और अमीर से मिले। परन्तु अमीर ए-बुखारा का सही रास्ते पर लाने के ये सार प्रयास निरर्थक हुए और सोवियत सरकार के सभी शान्तिपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गये। मुस्लिम मान्यता का वांछितता के विरुद्ध धर्मांधता का भावना उभारने की खुली हट दे दी गई। अमीर ने मशहद में अग्नेयता से अग्नि गमक व्यापित किया और अफगानिस्तान से सैनिक संधि का। अगस्त १९२० में उगान १० हजार की मना तयार की और वापस आने के विरुद्ध जहाज का फतवा जारी दिया।

ऐसा स्थिति में बुखारा की घाम जाता के मामला यह बात स्पष्ट हो

बहुत बढ़ गई। पार्टी की दूसरी कांग्रेस ताशकन्द में २६-२७ जून, १९१६ को हुई। इसने पार्टी का आह्वान किया कि जनता में अपने प्रचार आन्दोलन को और सबल बनाने और उसके दायरे में जनता के विभिन्न हिस्सों को खींच लाने के लिए ज्यादा मुस्तैदी से कदम उठाये जायें। न० हुसनोंवाली की केन्द्रीय समिति के नये अध्यक्ष चुने गये। तीसरी पार्टी कांग्रेस के तब तक, जो ताशकन्द में २६-३१ दिसम्बर, १९१६ को हुई, पार्टी की ३३ शाखाएँ काम कर रही थी, उनमें २४ देहकानो और कारीगरों में १३ सेना में।* तीसरी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी प्रचार और आन्दोलन का तेज करने पर जोर दिया और इस उद्देश्य से "ताग" (सवेग) और "कुतुलूश" (आजादी) नामक की प्रकाशित ताशकन्द और नये बजारों से प्रकाशित की गई। १९२० की गमियो तक बुखारा में आन्दोलन मजबूत हो चुका था। बुखारा के मजदूर, विमान और कारीगर आन्दोलन के घृणित तथा अत्याचारी शासन का तख्ता उलटने का तयार थे। उन समय तक ४३ पार्टी इकाइयाँ काम कर रही थी और पार्टी सम्मेलन की संख्या ५,००० तक पहुँच गई थी। पार्टी हमदर्दों की संख्या २०,००० थी। स्वयं पुराने बुखारा में २१ इकाइयाँ थी जिनमें १,५०० सदस्य थे।** बजारों के कम्युनिस्ट अमीरों की सेना में भी सक्रिय थे। इरगाश मुसाबायेव ने बड़ी गुयोग्यता से सेना में पार्टी प्रचार किया। अमीरों की सेना के भगोड़ों का लेकर समरखन्द में एक सैन्यदल संगठित किया गया। पार्टी की चौथी कांग्रेस चारजूएँ में १६ से १६ अगस्त, १९२० का हुई। उसने अमीरों का नाम के विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन की आगवाही करने का फैसला किया।

अभी तक नोजवान बुखारिया के साथ बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध की यादत कुछ नहीं कहा गया है। मार्च १९१८ की अगस्त में बाद नोजवान बुखारिया की पार्टी का मतारत कुछ दिना के लिए टूट गया। परन्तु जनवरी १९२० में वह नुकिम्बान की भूमि पर फिर उभरा। इस में अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिणत न ६ फ़रवरी, १९२० को उत्त

* "उत्तरेक साविगत गमाजवादी जनतंत्र का इतिहास", पृष्ठ १७०।

** वही, पृष्ठ १७२।

कायकलाप को मजूर किया और तुकिस्तान आयोग ने इस मजूरी का अनु-
मोदन किया। पूव में अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद की २५ मार्च, १९२०

की बैठक में बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान बुखारियों के संबंध
के सवाल पर भी विचार किया गया था। परिपद ने बुखारा के कम्युनिस्टों

के लिए यह आवश्यक कर दिया था कि वे अमीर के खिलाफ सघष को
नौजवान बुखारियों की सहमति से चलाए। परन्तु बुखारा की कम्युनिस्ट
पार्टी इस फैसले से खुश नहीं थी। उसकी राय में नौजवान बुखारी पार्टी

पूँजीवादा राष्ट्रवादियों की पार्टी थी और उसका दृष्टिकोण सोवियत विरोधी
और सब इसलामवादी था। पूव में अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद और तुर्क

आयोग के विदेशी मामला के विभाग का संयुक्त अधिवेशन १९ जून,
१९२० को आयोजित हुआ। उसने नौजवान बुखारी पार्टी के बारे में

बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी के इस मूल्यांकन से सहमति प्रकट की। उसने
इस बात का समर्थन किया कि नौजवान बुखारी पार्टी में शामिल हो जायें।

और उनके अधिक प्रगतिशील सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जायें। उसने
उसने नौजवान बुखारियों को वित्तीय सहायता केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की

परिपद के नियंत्रण में प्रचारकाय के लिए देने की स्वीकृति दी। तुर्क
आयोग की ३० जून, १९२० की बैठक में अमीर के अत्याचारी राज का

तख्ता उलटने का फैसला किया गया। उसने नौजवान बुखारियों से संबंध

निर्यात करने का नारा दिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद को आदेश
दिया कि वह केवल बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करे। आयोग

न कहा कि नौजवान बुखारी परिवर्तन की पार्टी हैं और बुखारा के
कम्युनिस्ट अंतर्वर्तन की पार्टी हैं।*

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की परिपद सभी प्रगतिशील और जायादी
शक्तियाँ के व्यापक मोर्चे का समर्थन करने के पक्ष में थी। उसकी
राय में नौजवान बुखारियों की पूरी पार्टी में हाथ मिला बुखारा की

प्राति के लिए हानिकारक था। नौजवान बुखारी पार्टी के मंत्रीय वर्ग में
संनिध के नाम भी एक पत्र निम्नलिखित था जिसका था

*वही, पृष्ठ १७/१।

अनुरोध किया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) का सागठनिक ब्यूरो नतीजे पर पहुँचा कि नौजवान बुखारिया को उनके वर्तमान कार्यक्रम के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल करना सम्भव नहीं है, मगर अमीर की सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी सघर्ष में उनसे सहयोग करने का सिफारिश की।

इस सिफारिश की राशनी में तुकिस्तान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रवा की परिषद नौजवान बुखारियो तथा बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधिया की संयुक्त बैठक में दोनों पार्टियों के विलयन के मुद्दे पर विचार किया गया। नौजवान बुखारी पार्टी के प्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी पार्टी के कार्यक्रम का मतलब केवल कार्यक्रमीतिक था, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों का भी, जो कम्युनिस्ट कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, अमीर के निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी सघर्ष में साथ रहना था। उनका कहना था कि बुखारा में क्रांति की विजय के बाद नौजवान बुखारी पार्टी वाला कम्युनिस्ट पार्टी का नाम और कार्यक्रम अपना लगे। इसी आधार पर तुक आयोग ने नौजवान बुखारियों के समर्थन का निष्कर्ष दिया। उनसे कहा गया कि बुखारा के कम्युनिस्टों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाएँ, उनके विरुद्ध सघर्ष करें और भविष्य में दोनों पार्टियों के विलयन की हर तरह तयारी करें। उनसे इन बातों की लिखित रूप में घोषणा करा जा रहा गया, जो उद्देश्य ६ अगस्त, १९२० का बना।* इसपर बुखारा के कम्युनिस्टों का चौथी पार्टी कांग्रेस ने भी नौजवान बुखारी पार्टी वाला स अस्थायी एका के सम्भावना का स्वीकार किया। परंतु यहां यह कह देना चाहिए कि नौजवान बुखारी पार्टी वाला के मध्य में बुखारा के कम्युनिस्टों में जो सद्भाव था, वह पूरी तरह बर्ही दूर नहीं हुआ।

१ अगस्त १९२० का प्रूजे ने लनिन का एक तार भेजकर बुखारा के गठन पर आग्रह मांगा। प्रूजे के सामने दो ही रास्ते थे अगस्त

* इसका मासिक सम्पादन जारी रखा जा रहा था, पृष्ठ १०६-१०७।

प्रातिकारी प्रक्रिया के विकास की आशा करना और इसकी प्रतीक्षा करना, या बाहरी सहायता से प्राति सगठित करना। उनकी राय में पहले को बढ़ावा देना व लिए हर उपाय करत हुए दूसरे पर अमल करना चाहिए। पोलिट-ब्यूरो न इस तार पर विचार किया और निम्नलिखित कायपद्धति अपनाते

“बुखारा में और बुखारा की सीमा पर रूसी लोगों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कारवाई करना, बुखारा के इलाके और बुखारा की सभ्य शक्तियों पर हमला करने में अभी पहल नहीं करना, अंग्रेज एजेंटों तथा रूसी प्रतिप्रातिकारियों की मिलीभगत से बुखारा द्वारा की जा रही प्रतिप्रातिकारी हरकतों व विरुद्ध मुसलमानों में व्यापक प्रचार-आंदोलन करना, इस आन्दोलन के दौरान में एक देशी सेना तैयार करना जिसमें बुखारा के कम्युनिस्ट भी शामिल हों, और इन प्रतिरक्षात्मक कारवाइयों को आनामक रूप तथा देना, जब जनप्रिय प्रातिकारी केन्द्र बुखारा में बन जाये और सहायता का अनुरोध करे।”

यह बता देना उचित होगा कि सोवियत सरकार और पार्टियों में जिम्मेदार लोग खोवा या बुखारा में प्राति का निर्यात करने के सदा विरोधी थे। परन्तु इसका समयन नौजवान खोवाई और नौजवान बुखारी किया करते थे जिनके बारे में सोवियत अखबारों ने एक बार कहा था कि वे “मध्य एशिया के दिसम्बरवादी हैं, जो इतिहास से कोई सबक नहीं सीखना चाहते।” उनके लिए जनता का प्रातिकारी बनाने का माग बहुत लम्बा था। इसलिए खोवा और बुखारा के उत्पीड़ित लोगों को बाहर से तुकिस्तान की सैन्यीय सहायता की सगीना के बने पर “मुक्ति” दिलानी चाहिए। मावियन अखबारों ने इन “एशियाई दिसम्बरवातियों” की आलाचना करते हुए निर्यात कि वे यह नहीं समझते कि “शापित जनता अपनी अज्ञानता में ‘मुक्ति’ तिलानेवालों को वही वदेशिक हमलावर न समझ बैठे।”

वहा, पृष्ठ १७८-१७९।

• इरगितिया तुर्क लोका’, ५ अगस्त, १९१९। (रूसी संस्करण)

यह याद दिला दिया जाय कि तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी चौथी कांग्रेस ने भी, खीवा और बुखारा के लोगो पर बाहर से शोषण की धारणा का विरोध किया था। वर्तमान परिस्थिति के तत्त्व में प्रस्ताव में कहा गया था कि "हमें उस स्वाभाविक क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब खीवा और बुखारा के लोगो के भीतर स्वयं प्रेरणा उथल पुथल आये, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि तुर्किस्तान सोवियत जनतन्त्र के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य शक्ति द्वारा कार्रवाई का अह्दा बन जायें।"*

बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १९२० को चारजून के मुक्त करके बुखारा में क्रांति शुरू की। उसकी अपील पर फ्रूजे के नेतृत्व में सोवियत सेनाएं जन मुक्ति संग्राम में सहायता करने आया। भारी लड़ाई के बाद सोवियत सेना ने ६ सितम्बर, १९२० को निरबुश राज के तत्त्व बुखारा पर अधिकार कर लिया। ५ अक्टूबर, १९२० को पहली कूहता बुखारा में आयोजित हुई। उसने बुखारा का सोवियत जनवादी जनतन्त्र घोषित किया।** ३ नवम्बर १९२० को रूसी सो० स० म० जनतन्त्र तत्त्व

* 'तुर्किस्तानस्वी कम्युनिस्ट', २० सितम्बर, १९१९। (रुसा म)

** अफगान अमीर ने खीवा और बुखारा को मायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था जिसपर भारत के लिए राज्य मंत्री और भारत के वाइसराय में कुछ पत्र व्यवहार हुआ। भारत के लिए राज्य मंत्री ने २८ अप्रैल १९२४, दिनांकित ६ मई, १९२२ के तार में मायता नहीं प्रदान करता था पत्र किया। "जब तक बहा स्वायत्ती अदस्ता सरकार नहीं हो जाय जिज मैजस्टी की सरकार किसी तरह भी खीवा और बुखारा का स्वाधीनता का मायता नहीं प्रदान कर सकती और फिर उस समय तक भी नहीं जब तक रूस के मुताबक में उनकी स्वतन्त्र हैसियत निर्दिष्ट हो जाय। तत्त्व में तत्त्व की जिजी से प्राप्त जा १६ तार रूसी सरकार के पत्र में जमा था उसका मुताबक अमीर ए-बुखारा ने जाना। उस तार का अफगान पत्रों हुई था कि अमीर भारत भारत रहता था है। कुछ जोड़कर बुखारा एजेंट अमीर की परकी वर १९२३ में भारत में था। मगर उस समय तक बहा मायता गता स्थिर हो चुकी थी तत्त्व प्रदान हो रहा हो करता उचित नहीं समझा।

सोवियत सत्ता की स्थापना २०७

बुखारा जनतन्त्र के बीच एक सैनिक और राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर
 हो गये। बुखारा के सोवियत जनवादी जनतन्त्र ने रु० सो० स० स० जनतन्त्र
 के साथ एक आर्थिक संधि भी की जिसके अनुसार दोनों राज्या न अपनी
 आर्थिक नीतियाँ और योजनाएँ को समन्वित करने का फैसला किया।
 रु० सो० स० स० जनतन्त्र ने बुखारा के जनतन्त्र को पाँच अरब रूबल
 अशासनीय ऋण दिया। रु० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ सहयोग की
 बदौलत बुखारा का तेज़ी से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सम्भव हुआ।

यह याद दिला दिया जाय कि तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की वाग़्दम न भी चीवा और बुखारा के लोग पर बाहर से शक्ति इन की धारणा का विरोध किया था। वर्तमान परिस्थिति के संबंध प्रस्ताव में कहा गया था कि "हम उस स्वाभाविक क्षण की प्रतीक्षा नहीं चाहिए जब चीवा और बुखारा के लोग के भीतर स्वयं शक्तिकारी ल-मुयल आय, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वे अमान सावियत जनतंत्र के विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य शक्ति द्वारा कारवाई अट्टा बन जायें।"*

बुखारा की कम्युनिस्ट पार्टी ने २८ अगस्त, १९२० को चारजूए का न करने बुखारा में शक्ति शुरू की। उसकी अपील पर फ्रूजे के नेतृत्व मानियत मनाए जब मुक्ति संग्राम में सहायता करने आयी। भारी लड़ाई बाद सावियत मना न ६ सितम्बर, १९२० को निरबुश राज के बिल गग पर अधिकार कर लिया। ५ अक्टूबर, १९२० को पहली क़ुहलताई गग में आयोजित हुई। उसने बुखारा को सोवियत जनवादी जनतंत्र बना दिया।** २ नवम्बर १९२० को रूसी सो० म० जनतंत्र तथा

* 'तुकिस्तानम्बकी कम्युनिस्ट २० सितम्बर, १९१६। (रूसी म)
अफ़ग़ान अमीर ने चीवा और बुखारा का मायता प्रदान कर का तार रखा था जिसपर भारत के लिए राज्य मंत्री और भारत के मंत्रालय में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। भारत के लिए राज्य मंत्री ने अफ़ग़ान १० १७८८, तारान्त ६ मई, १९२२ के तार में मायता नहीं प्रदान का पत्र दिया। "जब तब कहा म्यामी अरफ़ी सरकार नहीं हा र हिंदू मजेन्दी की सरकार किसी तरह भी चीवा और बुखारा की चीवाना का मायता नहीं प्रदान कर सकती और फिर उम समय तब तब, जब तब मग के मुतासल में उनकी मन्तव हैमियत निश्चिन हा र'। तब म करगून की विन्नी म प्राप्त जा १६ तार म्या बम्बई म म म म था, उता मुम्मा अमीर म बुखारा न जान दिया। तब बनी अफ़ग़ान पत्री हुई था कि अमीर भारत आकर रहना चाहत मुम्मा गोजवान बुखारी एजेंट अमीर की परवी मग १९२३ में भारत आय मगर उम समय तब कहा मानियत मता स्थिर था चुकी थी, मगिण था न हम्माप करत उचित नहीं ममता।

बुखारा जनतन्त्र के बीच एक सैनिक और राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। बुखारा के सोवियत जनवादी जनतन्त्र ने रू० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ एक आर्थिक संधि भी की जिसके अनुसार दाना राज्या ने अपनी आर्थिक नीतियाँ और योजनाएँ को समन्वित करने का फैसला किया। रू० सो० स० स० जनतन्त्र ने बुखारा के जनतन्त्र को पाँच अरब रूबल अशाघनीय ऋण दिया। रू० सो० स० स० जनतन्त्र के साथ सहयोग की बदौलत बुखारा का तेजी से आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सम्भव हुआ।

प्रतिप्राप्ति तथा वदेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष

१९१८ की गमिया में तुर्किस्तान में गृहयुद्ध और वैश्विक सशस्त्र हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। कानून "म्यायत्त" सरकार के विघटन व तुरन्त बाद ही परगाना में बासमची आन्दोलन आरम्भ हुआ और तुर्किस्तान की हानत घिर हुए तिल की हो गई जिगरे चारा और मारचा की मात्रा भी बन गई थी। खीवा का गान शामिल क्षेत्र और बुधारा का घमार शांति धात्र साक्षियन तुर्किस्तान पर हमला करत के अट्टे बन गये। द्वागनाम्बिया इनारे में मफेन गाड़ों व ममाजनाती प्रातिसागिया तथा मशेरिया में पन्थर करके साक्षियन मत्ता ता उनटन की कारनाई मगटि की। प्रतिप्राप्तिकारी अम्बायी द्वागनाम्बिया सरकार की स्थापना का गई। न्ग कारनाई व ह्वा ही प्रिटिग सशस्त्र हस्तक्षेप ह्मा। मफेन जारन ह्मान व आरानुग पर त्वा कर लिया और तुर्किस्तान का मध्य ह्म व मध्य भाग में रिच्छा हा गया। जेीमुन द्वागना में प्रतिप्राप्तिकारी कुनर और मफेन करजाना व साक्षिया मत्ता व रिच्छा गान उठा लिया। ताशकन्त में एन प्रतिप्राप्तिकारी एम्बी तुर्किस्तान भरित मगटन व ताग में द्वागनाती ताशकन्त व ताशकन्त म स्थापित का गई। न्गा घण्टा में एन ममणीत लिया, रिच्छा हस्तिगत और घा ता ता बाग लिया। न्गा बागमची प्रधान द्वागना घमार मज्जगाग और मीया व जुन गान में मफेन स्थापित लिया।

सावियत तुकिस्तान के लोगो १ इग बठिन म्यिति वा मुवाबला बडे साहस के साथ किया और सोवियत सत्ता की प्रतिरक्षा म और अन्तर्नी तथा बाहरी सभी शत्रुओं के विरुद्ध बीरतापूर्वक सघर्ष किया। ५ अक्तूबर, १९१८ का तुकिस्तान की केन्द्रीय वायकारिणी समिति और सोवनारकोम तथा रनवे मजदूरों की वायकारिणी समिति ने एक संयुक्त बैठन म असाधारण छानबीन आयाग नियुक्त करने का निश्चय किया जिसका काम राजनीतिक स्थिति पर नज़र रखना और प्रतिश्रांतकारिया के विरुद्ध सघर्ष करना था। इसी आयाग न तुकिस्तान सैनिक संगठन के अस्तित्व का पता चलाया और अग्रजा से उसके सवध का परदाफाश किया। इन संगठन के एक भाग का कुचल दिया गया, परंतु शेष वामपक्षी समाजवादी-श्रांतिकारिया की सहायता से जो सत्ता म बाल्गेविका के माझेदार थे, और युद्ध कमिसार आसिपोव जैसे गद्दारा की सहायता से बच गये। १८-१९ जनवरी १९१९ की रात आसिपोव ने सावियत सत्ता के खिलाफ प्रतिश्रांतिकारी बगावत की। सरकार के सभी महत्वपूर्ण बोल्गेविक सदस्य तथा तुकिस्तान कम्यनिस्ट पार्टी के सभी नेता गिरफ्तार किये गये और मार दिये गये। परंतु ताशकन्द के मजदूर और सैनिक सावियत सत्ता के समर्थन म डटे रहे। उद्देक स्वयसेवका न भी आसिपोव के विरुद्ध सशस्त्र सघर्ष म भाग लिया। आसिपोव भागकर बासमचियो से जा मिला। जनगण ने सत्ता पर अधिकार करने के उसके प्रयासों को मिट्टी म मिला दिया।

साम्राज्यवादिया ने फरगाना म बासमची आन्दोलन से बड़ी उम्मीदें बांध रखी थीं। यह जनविरोधी आन्दोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान म मुल्ताया सामंतवादियों तथा पजीवादी राष्ट्रवादी तथा का शामन स्थापित करना था। चूंकि श्रमजीवी जनता में उसका कोई व्यापक आधार नहीं था, इसलिए उसे अधिकतर वैदेशिक साम्राज्यवादिया के समर्थन पर निर्भर करना पड़ता था। इसके अनुयायी मुख्यतः ज़ारशाही प्रशासन के भूतपूर्व पदाधिकारी थे, जैसे आकसकाल, मोरख तथा बोलास्त प्रशासक तथा मुल्ताया में से थे। बासमचियो की पक्तियों में अगर स्पष्ट रूप से किसी की अनुपरिधि दिखाई देती थी, तो वे गरीब किसान और कारीगर

प्रतिप्राति तथा यदनिष हस्तभय के विन्दु सधाय

१९१८ का गणित म तुर्किस्तान म गणपद घोष बर्तित मनि
हमनाम की तुर्किस्तान दुः। काका 'म्यायन' मगरा र विपत्ति म सुरा
या ही पम्पना म धाममची धामना धामना धा घोष तुर्किस्तान का
हालत धिरे हुए मिन की हो गई जिता चारा धार मोरना का
माना सी धा गई थी। मीवा म गात गाति धेन धार बुनागा का धमार
शासित धेन सावित्र तुर्किस्तान पर हमना करा र धुटे का गद।
द्रामवाग्मिया इलाके म मफे गाती र मगाजवाही धातितारिया तथा
मशेविका मे पम्पन करन सावित्र मत्ता म उरटा री सरसाई मगटिन
की। प्रतिधातिवारी अध्यायी द्रामवाग्मिया सरसार की स्थापना की
गई। मग वाग्वादी मे हा ही ध्रिटिध सनिह एगाधेप हृमा। मफे नारन
हताय न धारनयुग पर रब्बा कर निपा धीर तुर्किस्तान का मयध हन म
मध्य भाग से विच्छेद हा गया। जेतीमुप इलाके म प्रतिधातिवारी बुत्त
और साफे वज्जवा म सावित्र मत्ता र विद्ध मग उठा निपा।
ताशाद म एन प्रतिधातिवारी एजेमी तुर्किस्तान सनिह सगटन र नाम
से जारगाही जारगा के तत्तावधान म स्थापित री गई। मगा अधेजा स
एक समझोता किया, जिहा हथियार और धन नैन म धाग किया।
इसी धासमची प्रधान इरगाश अधीर ए बुधारा और मीवा के जुन धान
से सम्पध स्थापित किया।

सोवियत तुकिस्तान के लोगो ने इस कठिन स्थिति का मुकाबला बड़े साहस के साथ किया और सोवियत मत्ता की प्रतिरक्षा में और अदस्ती तथा बाहरी सभी शत्रुओं के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। ५ अक्टूबर, १९९८ को तुकिस्तान की नैट्रीय कायकारिणी समिति और सोवनारफोम तथा रेलवे मजदूरों की कायकारिणी समिति ने एक संयुक्त बैठक में असाधारण छानबीन आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया जिसका काम राजनीतिक स्थिति पर नज़र रखना और प्रतिप्रार्तिवारिया के विरुद्ध संघर्ष करना था। इसी आयाग ने तुकिस्तान सनिक संगठन के अस्तित्व का पता चलाया और अग्रजों से उसके संघ का परदाफाज किया। इस संगठन के एक भाग का कुचल दिया गया, परन्तु शेष वामपक्षी समाजवादी आतिकारिया की सहायता में जो सत्ता में बोल्शेविकों का सायेंदार थे, और युद्ध कमिस्सार् ओसिपोव जैसे गद्दारों की सहायता से बच गये। १८-१९ जनवरी, १९९९ की रात ओसिपोव ने सोवियत सत्ता के खिलाफ प्रतिप्रार्तिवारियों कागवत की। सरकार के सभी महत्वपूर्ण बोल्शेविक सदस्य तथा तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता गिरफ्तार किये गये और मार दिये गये। परन्तु ताशकन्द के मजदूर और सैनिक सोवियत सत्ता के समर्थन में डटे रहे। उन्हे स्वयंसेवकों ने भी ओसिपोव के विरुद्ध संशस्त्र संघर्ष में भाग लिया। आसिपोव भागकर बासमचियो से जा मिला। जनगण ने सत्ता पर अधिहार करने के उसके प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया।

साम्राज्यवादियों ने फरगाना में बासमचों आन्दोलन से बड़ी उम्मीद बाध रखी थी। यह जन विरोधी आन्दोलन था जिसका उद्देश्य तुकिस्तान में मुलामो, सामतवादियों तथा पंजीवादी राष्ट्रवादी तत्वा का शासन स्थापित करना था। चूंकि श्रमजीवी जनता में उसका कोई व्यापक आधार नहीं था, इसलिए उसे अधिक्तर वैदेशिक साम्राज्यवादियों के समर्थन पर निर्भर करना पड़ता था। इसके अनुयायी मुख्यतः जारशाही प्रशासन के भूतपूर्व पदाधिकारी थे, जैसे आक्सकाल, मोरख तथा बोस्तोस्त प्रशासक तथा मुलामो में से थे। बासमचियों की पकियामें अगर स्पष्ट रूप से किमी की अनुपस्थिति दिखाई देती थी, तो वे गरीब किसान और कारीगर

ये, सिवा चंद लोगो के, जो या तो अपने अत्यंत पिछड़ेपन के कारण या भय से कुछ दिनों के लिए उनके साथ हो गये थे। ऐसे अपराधी, जो बाई लोगो और धनी व्यक्तियों के संरक्षण में रहते थे और उनके इशारे पर हर तरह का पाप करते थे बड़े शौक से इस आंदोलन में शामिल हो गये जिसमें उनके लिए बड़ा मौका था। बासमचियों के अधिकार में जो इलाके थे, वहां स्थिति पुराने खान प्रशासन के दिनों से कुछ अधिक भिन्न नहीं थी।

बासमचियों ने सोवियत सरकार के विरुद्ध जेहाद का एलान कर दिया। प्रारम्भ में उन्हें कुछ सफलता मिली, क्योंकि फरगाना में किसानों का बहुमत शुरू में बासमचियों के विरुद्ध सघर्ष में तटस्थ था। फरगाना के किसानों की इस तटस्थता का कारण उनकी आर्थिक स्थिति का स्पष्टतः खराब होना था। यह खराबी प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों से शुरू हुई, जब निमित्त सामान और खाद्यान्न का दाम बहुत बढ़ गया था, जबकि फरगाना की मुख्य पैदावार—कपास का दाम कमोबेश स्थिर था।

यह स्थिति ओरेनबुर्ग की नाकाबंदी के कारण और बिगड़ गई। फिर यह बात भी थी कि तुकिस्तान आयोग के पहुंचने से पहले देहकानों में पार्टी ने बहुत कम प्रचारकाय किया था और उनके कुछ बुनियादी हितों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाया गया था। बाजार बिल्कुल बन्द थे तथा खाद्यान्न की वसूली के मामले में भेदात्मक वगैरह दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। कुछ स्थानीय बोलशेविकों द्वारा पार्टी की जातीय नीति की विकृति भी बासमचियों और पंजीवादी राष्ट्रवादियों के काम आयी, जिन्होंने फरगाना में फैले हुए आर्थिक असंतोष से पूरा लाभ उठाया।

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि १९१८ से १९२० तक फरगाना में बासमची आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। परन्तु वह कभी भी जन आंदोलन नहीं बन सका और स्थानीय किसानों में सावियत सत्ता के प्रति शत्रुता की भावना जगाने में सफल नहीं हो सका। फरगाना की २० लाख की आबादी में १० हजार बासमची नगण्य अल्पमत थे। बासमची की प्रारम्भिक सफलताएँ किसी व्यापक जन-समर्थन की वजह से नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध सघर्ष के बड़ी हद तक असंगठित होने की

वज्र से थी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ज्यो ज्यो किसानों को सोवियत सत्ता की धारणाओं और उद्देश्यों का ज्ञान होता गया, वे बासमचियों के विरुद्ध संघर्ष में अधिक सक्रिय होते गये।

राकान सरकार के पतन के बाद उसका सेनापति इरगाश बासमचियों का प्रधान बन गया। उगने बाकीर की अपना बैट्र बनाया और वहाँ से शहर और गाँव पर हमले किये। शीघ्र ही एक और बासमची दल मदामिन बेक के नेतृत्व में गायम हुआ जिसे पूजोवानी राष्ट्रवादिया ने मंगिलान शहर की मिलिशिया का प्रधान नियुक्त किया था। रूसी कुलक और आप्रवासी भी, जिनके हित सोवियत सत्ता से टकराते थे, बासमचियों के साथ हो गये। रूसी कुलक मानस्त्राव के नेतृत्व में तथाकथित किसान मेना ने ओश पर बल्ला कर लिया और बासमचियों से जा मिली। मदामिन बेक ने इन सब भाति भाति के गिरोहों को एकत्रित किया और फरगाना की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। इस सरकार में ज़ारशाही जनरल, रूसी कुलकों और कपास फर्मों के प्रतिनिधि, स्थानीय बाई और मुल्ला लोग थे। मार्च-अप्रैल १९१८ से १९१९ की पतझड़ तक बासमचियों ने फरगाना घाटी में बड़ा उत्पात मचाया। वे लूट मार करते, फैक्टरियों और खानों को नष्ट करते और जिस किसी पर सोवियत सत्ता के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह होता, उसपर पाश्विक अत्याचार करते।

यह स्थिति तब तक जारी रही जब तक कोल्चाक की पराजय के बाद फ्रूजे की कमान में तुकिस्तान मोरचा नहीं बन गया। लेनिन की पहलकदमी पर फ्रूजे, बूइविशेव तथा अन्य लोगों को लेकर तुकिस्तान आयोग कायम किया गया और उसे तुकिस्तान के श्रमजीवी जनगण द्वारा उनकी प्रातिकारी सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता करने के लिए ताशकन्द भेजा गया। उस आयोग ने पार्टी और सोवियत सत्ताओं के नवीनीकरण का काम शुरू करने के अलावा फरगाना घाटी में बासमचियों के विरुद्ध और ट्रांसकास्पियन इलाके और जैतीसुव में सफेद गण और सफेद बल्लाओं के विरुद्ध जनता का संघर्ष संगठित करने में सक्रिय भाग लिया। उसके निर्देशन में लाल सेना का पुनर्गठन किया गया। उसे बगव्युत दुसाहसी तथा सदेह

जनक तत्वों से बिल्कुल साफ किया गया। तुकिस्तान आयोग ने स्वेच्छा पूर्वक भरती के आधार पर स्थानीय जातियों के जनगण को लेकर ३० हजार की सेना सफलतापूर्वक संगठित की। केवल फरगाना घाटी में दस हजार स्थानीय लोग लाल सेना में शामिल हुए। फरवरी माच १९२० तक बासमचियों के विरुद्ध अभियान में काफी सफलता प्राप्त हो चुकी थी और गमियों तक फरगाना में उनके दल नष्ट कर दिये गये थे। परन्तु कुछ दल १९२३ तक लूट मार करते रहे, क्योंकि जब अनवर पाशा ने उनका नेतृत्व सभाला, तो उनमें नई जान आ गई थी। मगर १९२० के बाद बासमची सोवियत सत्ता के लिए कोई गम्भीर खतरा नहीं रहे।

इसी तरह १९२० तक ट्रांसकास्पियन इलाके और जेतीसुव में भी प्रतिआतिकारी मसूवों पर पानी फिर गया जब सफेद गाड़ और सफेद कज़ाखों को शिकस्त हुई और ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों को पीछे हटना पड़ा। परन्तु तुकिस्तान के लोगों को, जो बहुत दिना तक केन्द्र से कटे और चारों ओर मारचों से घिरे रहे थे, अधिकतर स्वयं अपने बल-बूते पर लड़ना पड़ा। उन्हें बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उनके पास खाद्यान्न तथा हथियारों और गोले-बारूद का अभाव था। फिर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़े। गृहयुद्ध में वे विजयी हुए, क्योंकि यह मुक्ति का 'यायपूर्ण युद्ध था जिसे जनगण औपनिवेशिक गुलामी और सामंती अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता और सम्पन्न जीवन के महान उद्देश्य की खातिर लड़ रहे थे। गृहयुद्ध में जनगण ने जिन महान उद्देश्यों के लिए प्राणा की बाजी लगायी, उमने उनमें सावियत देशभक्ति की प्रबल भावना को जन्म दिया।

गृहयुद्ध में सोवियत सत्ता की विजय के महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह था कि लेनिनवादी जातीय नीति पर ईमानदारी से अमल किया गया जिसकी बदौलत तुकिस्तान की सोवियत स्वायत्तता का निर्माण किया गया था, सत्ता की सभी संस्थाओं में स्थानीय श्रमजीवियों की व्यापक शिरकत सुनिश्चित की गई तथा औपनिवेशिक और सामंती अतीत के सभी अवशेषों को मिटाने के लिए सघट किया गया। सबहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा जातियों की मैत्री भी गृहयुद्ध के दौरान प्रबल हुई। स्थानीय जातियों के

श्रमजीवी जनगण के अलावा, जिन्होंने अपनी समाजवादी मातृभूमि की रक्षा में देशभक्ति की उच्च भावना का परिचय दिया, अनेक यूरोपीय देशों के किसानों और मजदूरों ने भी, जो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध बंदी होकर तुर्किस्तान आये थे और साथ ही पड़ोसी एशियाई देशों के जनगण के क्रांतिकारी प्रतिनिधियों ने भी, जिनमें कुछ भारत के भी थे, सोवियत सत्ता की विजय में योगदान किया।

आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन

गृहयुद्ध का समय तुर्किस्तान के जनगण के जीवन में आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए भी उल्लेखनीय है। वावजूद इसके कि सोवियत सत्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसने गृहयुद्ध के दिनों में ही एक नये समाजवादी आर्थिक ढांचे की बुनियाद डाली और जनगण के सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन किये।

उद्योगों के समाजवादी रूपांतरण की दिशा में प्रारम्भिक कदम अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद ही उठाये गये थे। १९१७ के अंत से १९१८ के मध्य तक सभी उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और बैंकों, परिवहन तथा बैदेशिक व्यापार आदि का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। भूमि के राष्ट्रीयकरण की भी घोषणा कर दी गई थी। खाद्यान्न में राजकीय ढंजारा स्थापित किया गया और भूमि सुधार लागू करने के लिए गांवों में गरीबों की समितियाँ बनाई गईं। उद्योगों पर मजदूरों के नियंत्रण की स्थापना तथा मुख्य उद्योगों और रेलवे के राष्ट्रीयकरण से सवहारा के अधिनायकत्व का आर्थिक आधार तैयार हो गया। मजदूरों के नियंत्रण की पद्धति की स्थापना १९१७ के अंत में किसी हद तक स्वतः स्फूर्त ढंग से हुई और सोवियत सत्ता ने इसे पूँजीपतियों द्वारा तोड़फोड़ के विरुद्ध बग सघर्ष के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि पूँजीपति उत्पादन को कम करना और उद्योगों को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। सोवियत सत्ता ने मजदूरों के नियंत्रण की प्रथा को बग-सघर्ष के रूप में तथा औद्योगिक प्रवर्धन में उनके

प्रशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन की दिशा में वह महत्वपूर्ण मजिल सिद्ध हुई।

मार्च १९१८ में बैंक कमचारियों की तीसरी असाधारण कांग्रेस ताशकंद में हुई। कांग्रेस ने बका के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार किया और अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार की सहायता करने की तत्परता व्यक्त की। मई १९१८ तक बका का राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अब सोवियत राज्य के हाथों में सकेन्द्रित हो चुकी थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सोवियत सत्ता ने पजीपति वर्ग को उसके आर्थिक प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र से वंचित कर दिया।

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १ मार्च, १९१८ को जेतीसुव रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ३१ मार्च को फरगाना रेलवे और अप्रैल १९१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।

मार्च अप्रैल १९१८ में अलग अलग उद्यमों का ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों की पूरी की पूरी शाखाओं का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ५ मार्च, १९१८ को समस्त रूई उद्योग और साबुन, तेल आदि जैसे सहायक उद्योगों का भी सोवियतकोम की एक आज्ञाप्ति द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। रूई की निजी खरीद बित्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और रूई के बड़े जखीरे जल कर लिए गये। कोयला और तेल उद्योगों का भी उसी महीने राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च के अंत तथा अप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकड़ने का उद्योग, छापेखाने, आटा, शकर तथा चावल उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

जून १९१८ में पूरे क्षेत्र में उन औद्योगिक इकाइयों की संख्या गिनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, २०४, जुलाई में २४५ और सितम्बर में २८३ तक पहुंच चुकी थी।* साल के उत्तरार्द्ध में कई छोटे और मध्यम

* य० नेपामनिन, "उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, १९१७-१९३७", पृष्ठ ६६।

उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। मगर यह गलती थी जिसका कारण अत्यधिक विचारधारात्मक उत्साह था। शुरू में राष्ट्रीयकरण के सार की उचित समझ बहुत कम थी और राष्ट्रीयकृत उद्यमों का प्रबंध मजदूरों की फँकटगी या कारखाना समिति द्वारा किया जाता, जो समाजवादी आतिकारियों के विचारों के प्रभाव में अक्सर इस अपनी सामूहिक सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादन में कुछ दुब्यवस्था उत्पन्न हुई। परन्तु मार्च १९१८ में इसका सुधार हो गया, जब सोवियतकॉम ने जन-अथयंत्र की क्षेत्रीय परिषद (सोवनारखोस) स्थापित करने का फैसला किया। अप्रैल १९१८ में उत्पादन की एक क्षेत्रीय परिषद गठित की गई और उसे उत्पादन संगठित करने और क्षेत्र के आर्थिक जीवन को नियमित करने के लिए मानदंड और योजनाएँ तैयार करने का काम सौंपा गया। आगे चलकर इस सस्था का पुनर्गठन जनअथयंत्र की उच्च परिषद के रूप में किया गया जिसके कार्य वही थे। प्रत्येक ओब्लास्त में औद्योगिक उद्यमों का निरीक्षण करने के लिए जनअथयंत्र की परिषद की स्थापना की गई। अगस्त सितम्बर १९१९ में जनअथयंत्र की परिषदों की प्रथम कांग्रेस के समय १८ ऐसी परिषदें (सोवनारखोस) थीं। १९१९ के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई थी। परन्तु बाद में कुछ की भग और दूसरा का विलयन कर दिया गया जिससे उनकी संख्या घट गई। जुलाई १९२० में सोवनारखोसों की दूसरी कांग्रेस ने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सोवनारखोस के वायकनाप के परिणामों पर विचार विमर्श किया। १९२० तक उनकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १९२१ में फक्टरी-प्लांट किस्म के कोई ८६६ उद्यम थे जिनमें ३२,५३३ मजदूर काम करते थे। इन ८६६ में से ४०५ गृहयुद्ध के दौरान पदा हुई आर्थिक दुब्यवस्था के कारण चालू नहीं थे।*

१९१८ की गमियों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमें श्रम-अनुशासन के सवाल पर विचार किया गया और इस संबंध में कई सिफारिशें की गईं। तुकिस्तान केन्द्रीय वायकारिणी समिति ने कारखाने और फँकटरी में

पशिक्षण के लिए बहुत महत्त्व दिया। योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन की दिशा में वह महत्वपूर्ण मजिल सिद्ध हुई।

माच १९१८ में बक कमचारियों की तीमरी असाधारण वाग्रस ताशकद में हुई। कांग्रेस ने बैंको के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर विचार किया और अपने समस्त अनुभव और ज्ञान सहित सोवियत सरकार की सहायता करने की तत्परता व्यक्त की। मई १९१८ तक बैंको का राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका था और ऋण की सारी व्यवस्था अब सोवियत राज्य के हाथों में सकेन्द्रित हो चुकी थी। बैंको का राष्ट्रीयकरण करके सोवियत सत्ता ने पजीपति वर्ग को उसके आर्थिक प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र से वंचित कर दिया।

परिवहन के राष्ट्रीयकरण ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १ माच, १९१८ को जेतीसुव रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ३१ माच को फरगाना रेलवे और अप्रैल १९१८ में बुखारा रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।

माच अप्रैल १९१८ में अलग अलग उद्यमों का ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों की पूरी की पूरी शाखाओं का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ५ माच, १९१८ को समस्त रूई उद्योग और साबुन, तेल आदि जैसे सहायक उद्योगों का भी सोवन्तारकोम की एक आनप्ति द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। रूई की निजी खरीद बिनी पर प्रतिबध लगा दिया गया और रूई के बड़े जखीरे जम्त कर लिए गये। कोयला और तेल उद्योगों का भी उसी महीने राष्ट्रीयकरण किया गया। माच के अत तथा अप्रैल के शुरू तक अराल मछली पकड़ने का उन्गार, छापेखाने, आटा, शकर तथा चावल उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

जून १९१८ में पूरे क्षेत्र में उन औद्यागिक इकाइयाँ की सख्या जिनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था २०५, जुलाई में २८५ और सितम्बर में २८३ तक पहुच चुकी थी।* साल के उत्तरार्द्ध में कई छोटे और मध्यम

* व० नपामनिन, उज्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव, १९१७-१९३७, पृष्ठ ९९।

उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। मगर यह गलती थी जिसका कारण अत्यधिक विचारधारात्मक उत्साह था। शुरु में राष्ट्रीयकरण के सार की उचित समझ बहुत कम थी और राष्ट्रीयकृत उद्यमों का प्रबंध मजदूरों की फँटरी या कारखाना समिति द्वारा किया जाता जो समाजवादी आतिकारियों के विचारों के प्रभाव में अवसर इसे अपनी सामूहिक सम्पत्ति मानती थी। इससे उत्पादन में कुछ दुर्ब्यवस्था उत्पन्न हुई। परन्तु मार्च १९१८ में इसका मुद्धार हो गया, जब सोवियतकोम ने जन अथतः की क्षेत्रीय परिषद (सोवियतखोज) स्थापित करने का फैसला किया। अप्रैल १९१८ में उत्पादन की एक क्षेत्रीय परिषद गठित की गई और उस उत्पादन संगठित करने और क्षेत्र के आर्थिक जीवन को नियमित करने के लिए मानदंड और योजनाएँ तैयार करने का काम सौंपा गया। आगे चलकर इस संस्था का पुनर्गठन जन अथतः की उच्च परिषद के रूप में किया गया जिसके कार्य वही थे। प्रत्येक ओब्लास्त में औद्योगिक उद्यमों का निदेशन करने के लिए जन अथतः की परिषद की स्थापना की गई। अगस्त मितम्बर १९१९ में जन अथतः की परिषदों की प्रथम कांग्रेस के समय १८ ऐसी परिषदें (सोवियतखोज) थीं। १९१९ के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई थी। परन्तु बाद में कुछ का भग और दूसरों का विलयन कर दिया गया जिससे उनकी संख्या घट गई। जुलाई १९२० में सोवियतखोजों की दूसरी कांग्रेस ने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सोवियतखोजों के कार्यक्रमों के परिणामों पर विचार विमर्श किया। १९२० तक उनकी संख्या ४० से घटाकर १७ कर दी गई। १९२१ में फँटरी-प्लान विस्म के कोई ८६६ उद्यम थे जिनमें ३२५३३ मजदूर काम करते थे। इन ८६६ में से ४०५ गृहयुद्ध के दौरान पैदा हुई आर्थिक दुर्ब्यवस्था के कारण चालू नहीं थे।*

१९१८ की गमियों में ट्रेड-यूनियन कांग्रेस हुई, जिसमें श्रम-अनुशासन के सवाल पर विचार किया गया और इस संबंध में कई सिफारिशें की गईं। तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने कारखानों और फँटरी में

*वही, पृष्ठ १०१-१०२।

देने की इजाजत केवल अपवाद के रूप में स्थानीय भूमि समिति की आज्ञा से और वह भी एक साल में अधिक के लिए नहीं दी जाती थी और इसके लिए भी स्थानीय सोवियत की अनुमति जरूरी थी। भूमि समितियों के संगठन के संबंध में अस्थायी सरकार का अधिनियम बदल दिया गया।* दिसम्बर १९१७ में सोव्नारकोम ने आप्रवासी प्रशासन द्वारा आप्रवासियों का जमीन देने से रोक दिया।** बाद में कई बड़ी जमींदारियां का राष्ट्रीयकरण किया गया। १३ मार्च, १९१८ को जारी की गई सोव्नारकोम की आज्ञा के जरिये सभी सिचाई नहरों और नालों भूमि कमिसारियत के जिम्मे कर दिये गये। तुकिस्तान में सोवियत सत्ता की भूमि नीति के इन बुनियादी सिद्धांतों का अनुमोदन १७ नवम्बर, १९२० को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति तथा सोव्नारकोम द्वारा स्वीकृत अधिनियम के जरिये कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रारम्भिक धाराओं में घोषणा की गई कि तुकिस्तान जनतंत्र के भीतर सारी भूमि और जल जनगण की राजकीय सम्पत्ति है।

परन्तु भूमि-सुधार को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। जमींदारी और सामंती भूमि व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया बहुत धीरे चल रही थी और १९२५-१९२८ तक जाकर पूरी हुई। इस विलम्ब का कारण तुकिस्तान की विशेष स्थितियां, वहां के सामाजिक आर्थिक संबंधों का अधिक पिछड़ापन, रूस के मध्यवर्ती इलाकों की तुलना में यहां के देहकानों की चेतना और उनके संगठन का अपेक्षाकृत धीरे विकास, पितृसत्तात्मक कबायली स्थिति के अतगत किसानों पर सामंतवादियों और मुल्लाओं का असर तथा बासमन्तियों के विरुद्ध तम्बा सघर्ष था।

परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद इस अवधि में कृषि के समाजवादी पुनर्गठन की दिशा में कुछ प्रारम्भिक कदम उठाये गये। १९१८-१९१९

* 'तुकिस्तानस्कीये वेदोमोस्ती', अंक १६०, ६ दिसम्बर, १९१७।

** "तुकिस्तान में महान् अवतूबर समाजवादी क्रांति की तैयारी और तामील, दस्तावेजों का संग्रह", ताशकंद, १९६७, पृष्ठ २४१। (रूसी संस्करण)

मे ही तुकिस्तान मे ४०० कृषि कम्पून और आर्तेल उत्पन्न हुए। चालीस हजार किसान उनमे शरीक हुए और उनके पास ३५ हजार देसियातीना जमीन थी। मगर ये प्रारम्भिक कम्पून बस जीवन निर्वाह कर लेते थे। उनका कोई ठोस आर्थिक और तकनीकी आधार नहीं था। उनका उद्देश्य यह था कि युद्ध के प्रारम्भिक कठिन दिना में गावों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गरीबों की बड़ी संख्या को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया जाये। ये कम्पून बिल्कुल स्वेच्छाकृत थे और अलग देहकानों के अथवा तंत्र को मिटाया नहीं गया। केन्द्र से खाद्यान्न की सप्लाई की बदौलत इन कम्पूनों की कोई जरूरत नहीं रह गई और उन्हें तोड़ दिया गया। परन्तु इनसे कुलको और बाई लोगों के प्रचार का खोखलापन जाहिर हो गया कि सामूहिक कृषि अवास्तविक चीज है। इन कम्पूनों के अलावा तुकिस्तान में १७ सोवखोज (राजकीय फार्म) भी संगठित किये गये जिनके पास कुल २८,५०० देसियातीना जमीन थी। इन फार्मों को भी शुरू में बड़ी कठिनाइयां हुईं। मवेशी की बड़ी कमी थी और इसलिए जमीन किसानों का बटाई पर देनी पड़ी, मगर बटवारा अधिक न्यायपूर्ण, यानी फसल के ४/५ से ७/८ तक के आधार पर किया जाता था।

सोवियत सत्ता ने जेतीसुव में भूमि सुधार के काम पर तत्काल ध्यान दिया। वहाँ रूसी आप्रवासियों के आकर बसने से देशी किगिज़ लोगों को बहुत हानि पहुंची थी। किगिज़ खानाबदोशों को उनकी सबसे अच्छी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इन रूसी अधिवासियों द्वारा भूमि पर अधिकार उस समय बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, जब इसे १९१६ के विद्रोह में किगिज़ों के भाग लेने के कारण उनके खिलाफ दंड के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तुकिस्तान में सोवियत शासन के प्रथम दो वर्षों में जेतीसुव में भूमि-सुधार की समस्या को कई कारणों से हाथ नहीं लगाया जा सका था। फिर, जेतीसुव के सोवियत और पार्टी संगठन पर भी कुछ कुलक रंग चढ़ा हुआ था और इससे भी वहाँ भूमि-सुधार पर अमल करने में बाधा पड़ी।

परन्तु तुकिस्तान आयोग ने जेतीसुव में भूमि-सुधार की समस्या के समाधान के लिए मुस्तैदी से और दृढ़तापूर्वक कदम उठाया। इन्होंने पहले ता

पार्टी और सोवियतों से पैरी वर्गों के लोगों को निकाला। जो किगिज़ भागकर चीन चले गये थे, उन्हें वापस वुतान का प्रबंध किया गया। ४ मार्च, १९२० का जब्ती ज़मीनें स्थानीय श्रमजीवी किसानों का वापस देने के मस्ये में आज्ञाप्ति जारी की गई। अप्रैल १९२० में तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अस्थायी भूमि-वादपत्ती की। चीन से वापस आनेवाले किगिज़ के पुन आवास पर ४ करोड़ ४५ लाख रुबल की रकम खर्च की गई। सोवियतों की नवी क्षेत्रीय कांग्रेस ने भी आज्ञा दिया कि रूसी अधिवासियों ने १९१६-१९१८ की अवधि में देशी किसानों और खानाबदोशों की जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है उन्हें वापस किया जाये। इसने तुकिस्तान में बाहर से सभी प्रकार के लोगों के आकर बसने और देशी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया।* इस तरह भूमि-मुधार की सबसे पहली कारवाई उन इलाकों में की गई, जहाँ रूसी कुलक आवासन के कारण समस्या ने जातीय रूप धारण कर लिया था। यह वित्कुल स्वाभाविक भी था, क्योंकि देशी बाई और भानप लोग स्थिति में लाभ उठाकर अपने वर्गीय हित में जातीय भावनाओं का उत्तेजित कर रहे थे।

सोवियत सरकार ने गृहयुद्ध के दौरान कृषि अथनत्र को पुन युद्धपूर्व के स्तर पर पहुँचाने के लिए काफ़ी काम किया। लेनिन ने १७ मई, १९२० का एक आज्ञाप्ति पर हस्ताक्षर करके तुकिस्तान में सिचाई प्रयोजना के निर्माण के लिए पाच करोड़ रुबल की रकम मंजूर की। २ नवम्बर, १९२० का उन्होंने तुकिस्तान और आज़रबैजान में कपास की खेती को बहाली के लिए २० सो० स० स० जनतंत्र के सावनारखोज के फ़मने पर हस्ताक्षर किया। अप्रैल १९१८ में सोवनारखोज ने तुकिस्तान में कपास की खेती और रूई उद्योग के नवीनीकरण के लिए ५० करोड़ २० लाख रुबल पूँजी निवेश किया।** इसके तुर्त बाद दो सूती मिला को

* "सोवियतों की कांग्रेसों की दस्तावेज़ें", पृष्ठ ४३५।

** स० मुरावेइन्की, "मध्य एशिया में नातिकारी आंदोलन के इतिहास संबंधी तथ्य", ताशकन्ट, १९२६, पृष्ठ २२। (रूसी संस्करण)

तुकिस्तान भेजने का फैसला किया गया। इन प्रारम्भिक प्रयासों के फलस्वरूप कपास की खेती के क्षेत्र में १९१८ की तुलना में तीन लाख हेक्टेयर जमीन की वृद्धि हुई। सोवियत संघ ने मक्का और अजोरा से देशवासियों की सहायता की। कपास उपजानेवाले किसानों का काफी रकम वेशगी दी गई और उन्हें बीज और खाद भी मुहैया की गई। इन भौतिक प्रोत्साहनों के कारण कपास की खेती के क्षेत्र में केवल १९२० में ही पिछले वर्ष की तुलना में २१,००० हेक्टेयर जमीन की वृद्धि हुई। मगर इन सब प्रयासों के बावजूद तुकिस्तान में १९२० में कुल बोवाई का क्षेत्र १९१८ का ३५ प्रतिशत ही था।*

गह्युद्ध के दिनों में खाद्यान्न की समस्या बहुत तीव्र हो गई। तुकिस्तान में बहुत दिनों में खाद्यान्न चला आ रहा था और वह मध्य रूस से खाद्यान्न की आपूर्ति पर निर्भर करता था। वहाँ से हर साल सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ मूँद अनाज का आयात होता था। अक्टूबर क्रांति से पहले लगातार तीन वर्ष फसल भारी गई। इससे समस्या और तीव्र हो उठी। १९१८-१९१९ में तुकिस्तान सोवियतसंघ ने दो करोड़ रुबल की रकम अनाज खरीदने के लिए अलग की। परन्तु खुली मंडी में दाम गेज बढ़ रहा था, इसलिए कोई भी निश्चित दाम पर राज्य के हाथ अनाज बेचने को तैयार नहीं था। तब सरकार को किसानों पर जिस रूपी कर लगाना पड़ा — फसल का ४ प्रतिशत। परन्तु इस तरह केवल ४५ लाख मूँद अनाज मिला, जबकि लक्ष्य दो करोड़ मूँद था। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को मजबूर होकर खाद्यान्न के राजकीय इजारे के संवर्ध में एक आशक्ति जारी करनी पड़ी। शहरों में राशनिंग करनी पड़ी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का १/४ से एक पाउंड तक रोटी मिलती थी। इसकी मात्रा उस व्यक्ति की सामाजिक उत्पादितता पर निर्भर करती थी।** कुल मिलाकर सोवियत प्रशासन ने अपनी खाद्य नीति पर सफलतापूर्वक अमल किया, उसमें कोई विकृति नहीं हान दी, यद्यपि कुछ अधिकारियों द्वारा

* म० वहाँवोव उपराक्त पुस्तक पृष्ठ २६३।

** वही, पृष्ठ २६५-२६६।

तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खुल गये थे, जिनमें १,६५,१२२ बच्चों में से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियों के थे।* शिक्षा पर बजट का खच १९१७ के २३ लाख ५० हजार रूबल से बढ़कर १९२० में ६५ लाख रूबल हो गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम अवधि के पाठ्यक्रम जारी किये गये। १९२० तक १,०४६ व्यक्ति इस तरह के ११ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संगठित किये गये जिनमें १,०६२ व्यक्तियों ने भाग लिया। वयस्कों के निरक्षरता उन्मूलन अभियान में सभी शहरों में सध्या स्कूल खोले गये। १९२० में ३१ पेशावर और तबनीवी स्कूल थे जिनमें ५,५०० व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।

२१ अप्रैल, १९१८ को ताशकन्द में तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। तब से पहले तुकिस्तान में उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय में पांच विभाग थे जिनमें १९१८-१९१९ में १२०० विद्यार्थी थे। १९१९-१९२० में यह संख्या बढ़कर १,४७० हो गई। ७ सितम्बर, १९२० को लेनिन के हस्ताक्षर से एक आज्ञापत्र जारी करके तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन तुकिस्तान राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। मास्को और पेत्रोग्राद में मध्य एशिया के इस पिछड़े हुए इलाके की सांस्कृतिक प्रगति के लिए अपने सवश्रेष्ठ प्रोफेसर भेजे। १९२० के अंत तक ताशकन्द के विश्वविद्यालय में २,६४१ छात्र थे।

मह्युद्ध की अवधि में ही तुकिस्तान में सावियत बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ। हमजा और जोकी, जो उदार विचारों के जनवादी थे, बोल्शेविकों के सक्रिय समर्थक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूँजीवादी-राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका संघर्ष मध्य एशिया में सोवियत बुद्धिजीवियों के विकास में एक नये युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। फरगाना में उज्जेक सावियत थियेटर का जन्म सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष की आग में हुआ। हमजा इसने संस्थापक थे। उसी साल ताशकन्द संगीत विद्यालय कायम हुआ

जहाँ उसके और ताजिक संगीत का नियमित अध्ययन किया जाने लगा।
 १९१८-१९२० के दौरान में उसके भाषा में ११ अक्षर प्रकाशन शुरू हुआ।
 थे और उनके अलावा बजाख और ताजिक भाषा के अक्षर भी थे।
 इसी दौर में उसके लिपि में सुधार करने के प्रारम्भिक प्रयास हुए। कई
 अक्षर, जिनकी उसके भाषा में जरूरत नहीं थी, निकाले गये और
 कई नये अक्षर जोड़ गये ताकि लिपि उच्चारण के अधिक अनुकूल हो
 जाये।

इस प्रकार गहयुद्ध का काल केवल बर्बादी और विनाश का ही काल
 नहीं था। वह तुकिस्तान के जनगण के जीवन के आर्थिक और सांस्कृतिक
 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का भी दौर था। गहयुद्ध के दिनों में जन
 राजनीतिक वायवलाप में भी वृद्धि हुई जिसका केन्द्र बिन्दु सोवियत सत्ता
 थी। सभी प्रयासों का उद्देश्य सशस्त्र प्रतिक्रांति को परास्त करना था
 जिसे वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप की सहायता मिल रही थी।

अधराष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवाद के विरुद्ध पार्टों का संघर्ष

मध्य एशिया में सोवियत सत्ता की सफलता का कारण बड़ी हद तक
 जातीय संघर्ष के क्षेत्र में उसकी सही नीति है। अधराष्ट्रवादी तथा राष्ट्रवादी
 भटकावों के विरुद्ध तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टों का संघर्ष वैदेशिक तथा
 सोवियत दोनों ही ऐतिहासिक साहित्यों में बहुत वाद विवाद तथा भ्रम
 का विषय रहा है। सोवियत लेखकों की कुछ प्रारम्भिक कृतियों में
 अधराष्ट्रवादी भटकाव पर जरूरत से ज्यादा जोर देने और उन्हें बड़ा चढ़ाकर
 पेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अतः हम उनमें से कुछ को इसी
 की रट लगाते पाते हैं कि स्थानीय बोलशेविकों ने ज़ारशाही की "औपनि-
 वैशिक विरासत" पायी थी। प्रारम्भिक स्थानीय रूसी बोलशेविकों में से
 अधिकांश को "श्रमिक अभिजात समुदाय" कह दिया गया, जो सवहारा
 के अधिनायकत्व के परदे में अपनी अधिकारप्राप्त स्थिति को ज्यों का त्यों
 बनाये रखना चाहते थे। उनकी राय में "यूरोपीय सवहारा" और "देशी

तुकिस्तान में २,०२२ प्राथमिक स्कूल खुल गये थे, जिनमें १,६५,१२२ बच्चों में से ६७,००० बच्चे स्थानीय जातियों के थे।* शिक्षा पर बजट का खर्च १९१७ के २३ लाख ५० हजार रूबल से बढ़कर १९२० में ६५ लाख रूबल हो गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम अवधि के पाठ्यक्रम जारी किये गये। १९२० तक १,०४६ व्यक्ति इस तरह के ११ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। उसी साल ११ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संगठित किये गये जिनमें १,०६२ व्यक्तियों ने भाग लिया। वयस्कों के निरक्षरता उन्मूलन अभियान में सभी शहरों में सघ्ना स्कूल खोले गये। १९२० में ३१ पेशावर और तकनीकी स्कूल थे जिनमें ५,५०० व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।

२१ अप्रैल, १९१८ का ताशकन्द में तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। नाति से पहले तुकिस्तान में उच्च शिक्षा की कोई संस्था नहीं थी। विश्वविद्यालय में पांच विभाग थे जिनमें १९१८-१९१९ में १२०० विद्यार्थी थे। १९१९-१९२० में यह संख्या बढ़कर १,४७० हो गई। ७ सितम्बर, १९२० को लेनिन के हस्ताक्षर से एक आज्ञा जारी करके तुकिस्तान जन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन तुकिस्तान राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। मास्को और पेत्रोग्राद में मध्य एशिया के इस पिछड़े हुए इलाके की सांस्कृतिक प्रगति के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर भेजे। १९२० के अंत तक ताशकन्द के विश्वविद्यालय में २,६४१ छात्र थे।

गृहयुद्ध की अवधि में ही तुकिस्तान में सोवियत बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ। हमजा और जीकी, जो उदार विचारों के जनवादी थे, बोल्शेविकों के सक्रिय समर्थक बन गये। उनकी यह तब्दीली तथा पूँजीवादी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका संघर्ष मध्य एशिया में सोवियत बुद्धिजीवियों के विकास में एक नया युग के प्रारम्भ का प्रतीक था। फरगाना में उज्बेक सोवियत थियेटर का जन्म सोवियत सत्ता के लिए संघर्ष की आग में हुआ। हमजा इसके संस्थापक थे। उसी साल ताशकन्द संगीत विद्यालय कायम हुआ।

जहाँ उर्बेक और ताजिक संगीत का नियमित अध्ययन किया जाने लगा।
उन्हीं दिनों सोवियत जातीय अखबार और पुस्तक प्रकाशन शुरू हुआ।
१९१८-१९२० के दौरान में उर्बेक भाषा में ११ अक्षर प्रकाशित होते
थे और इनके अलावा क़ज़ाख़ और ताजिक भाषा के अखबार भी थे।
इसी दौर में उर्बेक लिपि में सुधार करने के प्रारम्भिक प्रयास हुए। कई
अक्षर, जिनकी उर्बेक भाषा में ज़रूरत नहीं थी, निकाले गये और
कई नये अक्षर जोड़े गये ताकि लिपि उच्चारण के अधिक अनुकूल हो
जाये।

इस प्रकार गहयुद्ध का काल केवल बर्बादी और विनाश का ही काल
नहीं था। वह तुर्किस्तान के जनगण के जीवन के आर्थिक और सांस्कृतिक
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी दौर था। गहयुद्ध के दिनों में जन
राजनीतिक क्रायकलाप में भी वृद्धि हुई जिसका केन्द्र बिन्दु सोवियत सत्ता
थी। सभी प्रयासों का उद्देश्य सशस्त्र प्रतिशक्ति को परास्त करना था
जिसे वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप की सहायता मिल रही थी।

अधराष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवाद के विरुद्ध पार्टों का संघर्ष

मध्य एशिया में सोवियत सत्ता की सफलता का कारण बड़ी हद तक
जातीय संघर्षों के क्षेत्र में उसकी सही नीति है। अधराष्ट्रवादी तथा राष्ट्रवादी
भटकावों के विरुद्ध तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष वैदेशिक तथा
सोवियत दोनों ही ऐतिहासिक साहित्य में बहुत बड़ा विवाद तथा भ्रम
का विषय रहा है। सोवियत लेखकों की कुछ प्रारम्भिक वृत्तियाँ में
अधराष्ट्रवादी भटकाव पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने और उन्हें बड़ा चढ़ाकर
पेश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अतः हम उनमें से कुछ को इसी
की रट लगाते पाते हैं कि स्थानीय बोलशेविकों ने ज़ारशाही की "श्रौपनि-
वैशिक विरासत" पायी थी। प्रारम्भिक स्थानीय रूसी बोलशेविकों में स
अधिकार के "श्रमिक श्रमिजात समुदाय" कह दिया गया, जो सवहारा
के अधिनायकत्व के परदे में अपनी अधिकारप्राप्त स्थिति को ज्यों का त्यों
बनाये रखना चाहते थे। उनकी राय में "यूरोपीय सवहारा" और "देशी

एशियाई जनगण" का राष्ट्रीय अंतर्विरोध इन दोनों समूहों के भीतर के वर्गीय अंतर्विरोध से ज्यादा गहरा था। पश्चिम के अधिकांश लेखकों ने भी कमोवेश यही मत अपनाया है और उन सोवियत लेखकों से व्यापक उद्धरण दिये हैं जो तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पक्षधरता में अधराष्ट्रवादी प्रवृत्तियों पर जोर देते थे।

लेकिन इस धारणा को इतिहास के तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी की पक्षधरता में कुछ अधराष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति मौजूद थे, मगर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनकी संख्या किसी भी समय इतनी अधिक थी कि उन्होंने जातीय समस्या के बारे में पार्टी की आम स्वस्थ नीति को विकृत कर दिया। पार्टी में हमेशा ठोस मार्क्सवादी-लेनिनवादी तत्वों का सशक्त दल मौजूद रहा है जिसने पार्टी नीति से अधराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी हर तरह के भटकाव के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष किया है।

कभी-कभी केन्द्र को बहुत श्रेय दिया जाता है कि उसने स्थानीय गुमराह बोलशेविकों की गलतियों का सुधार किया, और ऐसी धारणा पदावरण का प्रयत्न किया जाता है मानो सितम्बर १९१९ में केन्द्र से तुर्किस्तान का संबंध बहाल होने से पहले पार्टी और सोवियतों के ढाँचे पर रूसी अधराष्ट्रवादी छाये हुए थे, जो स्थानीय लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और सरकार में उनके उचित स्थान से उन्हें वंचित रखते थे, और माना पूरी परिस्थिति में परिवर्तन केवल उस समय हुआ जब केन्द्र के प्रतिनिधि आये और आयागा आदि की नियुक्ति हुई। परन्तु अधराष्ट्रवादी के विरुद्ध संघर्ष रूसी तथा देशी कम्युनिस्टों के बीच का संघर्ष नहीं था, इसमें देशी कम्युनिस्टों को केन्द्र के ऐसे प्रतिनिधियों का समर्थन मिलता था, जैसे विशेष कमिस्सर कावोजेव और फ़जे, बूडविशेव तथा तुर्किस्तान आयोग तथा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के तुर्किस्तान ब्यूरो के दूसरे सदस्य।

पार्टी नीति से भटकावों के विरुद्ध संघर्ष का अमल में पार्टी के भीतर जातीय समूहों से कोई संबंध नहीं था। अतः अनेक स्थानीय रूसी कम्युनिस्टों ने अधराष्ट्रवादी विचारों के रूसी कम्युनिस्टों के विरुद्ध समान संघर्ष में अपने

मुस्लिम साथियों का साथ दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह मुस्लिम साथियों ने पूंजीवादी राष्ट्रवादियों का परदाफाश करने में रूसी कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। इसमें संदेह नहीं कि केंद्र के प्रतिनिधियों ने पार्टी को अधराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने जातीय संघर्ष पर पार्टी नीति की शुद्धता के लिए संघर्ष अपने आप और अकेले किया। इस संघर्ष में उह पार्टी की पक्तियों और आम जनगण से व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश, कुछ सोवियत कृतियों में, जो व्यक्ति पूजा के प्रभाव में लिखी गई थी, विभिन्न आयोगों और व्यूरा की भूमिका को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है पर अधराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष के जन स्वरूप की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

निस्संदेह, तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्टूबर क्रांति के बाद के प्रारम्भिक दिनों में स्थानीय जातियों के लोगों के प्रति कुल मिलाकर बड़ी हद तक सही नीति अपनायी। जातीय संघर्ष हमेशा तुकिस्तान के बोल्शेविकों के ध्यान का केंद्र बना रहा। १९०५-१९०६ में ही बोल्शेविकों ने ताशकंद और समरकंद से जो गैरकानूनी पत्र प्रकाशित किये, उनमें जातीय संघर्ष पर काफी ध्यान दिया था।* तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की करने के महत्त्व पर जोर दिया था। उन्होंने देशी लोगों में काम पहली कांग्रेस (१७-२६ जन, १९१८) ने मुस्लिम जनगण में पार्टी काय पर अपने प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया था कि व्यापक मुसलमान जनता को नये जीवन के निर्माण काय में खींच लेना जरूरी है। उसने स्थानीय जातियों की भाषाओं को रूसी के साथ-साथ राज्य भाषाओं के रूप में स्वीकार किया। उसने मांग की कि सभी ओब्लास्तों, उयेरदों आदि में जातीय मामलों की कमिमारियत नियुक्त की जाए जिनका नाम मुसलमानों को सोवियत निकाया में लाने के लिए प्रचार करना हो। उसने

* मजारा, "१९०५-१९२० में मध्य एशिया में क्रांतिकारी आंदोलन (स्मृतियां)", ताशकंद, १९३४ पृष्ठ १९। (रूसी संस्करण)

मुस्लिम मेहनतकशों में पूरा विश्वास प्रकट किया और मुस्लिम सवहारा में से लाल सेना के दस्ते संगठित करने का आह्वान किया।*

दिसम्बर १९१८ में तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस के समय ही पार्टी सदस्यों की कुल संख्या का लगभग आधा भाग देशी कम्युनिस्ट थे और मुस्लिम श्रमजीवी जनता के प्रतिनिधि अप्रैल १९१८ में तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम जैसे सोवियत सत्ता के उच्च निकायों में नियुक्त किये जाने लगे थे। यह ध्यान रहे कि पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने मुस्लिम जनता में शैक्षणिक और प्रचार कार्य पर असतोष प्रकट किया था और यह मांग की थी कि सोवियतों और अन्य सामाजिक संगठनों में स्थानीय जातियों के श्रमजीवी जनगण को ज्यादा व्यापक पैमाने पर खींचा किया जाये जिसके लिए उन्हें प्रशासकीय तथा अन्य पदों पर नियुक्त किया जाये।** इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि नाति के तुरंत बाद के जमाने में जातीय सवाल पर पार्टी की नीति सही थी।

अक्सर तो बोलीन के नेतृत्व में “पुराने कम्युनिस्टों” के समूह पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे स्थानीय कम्युनिस्टों के प्रति अधराष्ट्रवादी रव्य अपनाते थे।*** परंतु इसके लिए ठोस सबूत देना अभी बाकी है। यह सही है कि इस गिरोह ने पार्टी के भीतर अपना एक गुट संगठित करने का अनुचित कदम उठाया था जिसका एकमात्र आत्मनिष्ठ दावा यह था कि ताशकंद नगर पार्टी संगठन में अनेक व्यक्तियों को इस गिरोह के लाग पसंद नहीं करते थे और उन्होंने पार्टी अनुशासन मानने से इनकार कर दिया था जिसके लिए दूसरी कांग्रेस ने इनकी निंदा की। परंतु इसके अलावा ताबोलिन पर अधराष्ट्रवाद का कोई ठोस आरोप नहीं लगाया जा सकता। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने “पुराने कम्युनिस्टों”

* “तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेसों के प्रस्ताव और निणय, १९१८-१९२४”, ताशकंद, १९५८ पृष्ठ ११-१२। (रूसी संस्करण)

** “तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस की दस्तावेजें”, मास्को-ताशकंद, १९६४, पृष्ठ ६२। (रूसी संस्करण)

*** “उजबेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास”, खण्ड २, पृष्ठ ९१।

के समूह और ताशकन्द नगर पार्टी इवाई में कोई विचारधारात्मक विभेद नहीं पाया। इस इकाई के नेता भी रूसी कम्युनिस्ट थे। उनके बीच अधराष्ट्रवादी भटकाव का कोई सवाल नहीं था।

इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि जनवरी १९१६ से पहले जातीय सवाल पर पार्टी नीति को महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद की ओर स कोई खतरा था। उस महीने आसिपाव के प्रतिनातिकारी विद्रोह से तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को बड़ा धक्का लगा। आसिपाव की घोखेबाजी के फलस्वरूप अनेक अनुभवी और विश्वसनीय स्थानीय नेताओं की हत्या कर दी गई। पहले ही जुलाई १९१८ में कई महत्वपूर्ण बोल्शेविक नेता अशकाबाद और किज़िल अरवात में प्रतिनातिकारी पडयत्नकारिया द्वारा मारे जा चुके थे। इन भारी नुकसानों के कारण जो कि पार्टी को १९१८-१९१९ में उठाने पड़े पार्टी में सुयोग्य नेतृत्व का अभाव हो गया और इसलिए अधराष्ट्रवादी भटकाव को सिर उठाने का मौका मिल गया। तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बज़ाकाव वामपक्षी समाजवादी नातिकारी उत्पन्नी के साथ अनचाहे ही उस नीति की धारा में बह गये। परन्तु इस भटकाव की जिम्मेदारी बोल्शेविकों से अधिक वामपक्षी समाजवादी नातिकारियों पर थी और फिर भी संपूर्ण भटकाव कभी नहीं होने पाया। वह सोवनारकोम तथा पार्टी की क्राइकोम (क्षेत्रीय समिति) में अलग अलग नेताओं द्वारा कुछ डक्की-डुक्की घटनाओं तक ही सीमित रहा।

१९१६ के प्रारम्भ से पार्टी तथा सावियत कार्यक्षेत्र में महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध तीव्र सघर्ष शुरू हुआ। यह पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पूँजीवादी राष्ट्रवादी देशों महानतकशों में रूसी मजदूर वर्ग के विरुद्ध असंतोष का बीज बाने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे। परन्तु अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध सघर्ष कोई मध्य एशिया की ही परिघटना नहीं थी। बल्कि जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की आठवाँ कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को शामिल करने का रोध कर रहे थे।

तुकिस्तान की सोवियतों की सातवीं कांग्रेस (मार्च १९१८) और तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन में अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध सघर्ष छेड़ा गया। पार्टी के ठोस मार्क्सवादी तत्व कोवोजेव के गिद जमा हो गये, जो मार्च १९१९ में केन्द्र के विशेष प्रतिनिधि के रूप में ताशकन्त आये थे। सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में कोवोजेव के मतत्व में जातीय विभाग की स्थापना हुई, जिसने खाद्यान्न के मोरचे पर कज़ाक-उस्पेस्की गिरोह के सरकारी तथा पार्टी नेताओं की गलतियों की आलोचना की। कांग्रेस में रिस्कूलोव ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें खाद्यान्न निदेशालय की नीति की आलोचना थी। कांग्रेस ने कहा कि इस नीति के कारण सबहारा के दो भाग—रूसी और देशी—एक दूसरे के विरुद्ध बना लिये गये थे।

सोवियतों की सातवीं कांग्रेस के जातीय विभाग ने मांग की कि सरकार मुस्लिम सबहारा की प्रतिनाति के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियारों से लैस करे। उसने आतिकारी सघर्ष में मुस्लिम मेहनतकशों की भूमिका को कम करके आकने के लिए सरकार के कुछ सदस्यों की आलोचना की। उसने नारा दिया कि लाल गाड़ में से सभी सदेहजनक तत्व निकाले जायें और क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस का शीघ्र आयोजन किया जाये। उसने इस बात पर असंतोष प्रकट किया कि नई सरकार में देशी आगदी के प्रतिनिधियों को केवल सात स्थान दिये गये थे।

कज़ाकोव, उस्पेस्की और सोलकिन ने सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में जातीय विभाग कायम करने का विरोध किया और जातीय मामलों की कमिसारियत को भंग करने का प्रस्ताव पेश किया। परन्तु कांग्रेस ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कज़ाकोव-उस्पेस्की गिरोह ने यह भी दावा किया कि २० सा० स० स० जनतंत्र की सरकार द्वारा स्वीकृत हर कानून का तुकिस्तान में लागू होने के लिए यहाँ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह की क्षेत्रीय मांगों के ज़रिये अधराष्ट्रवादी गिराह अपने मत को तुकिस्तान की प्रभुता के अधिनारा के लिए तथा केन्द्र से इसकी तथाकथित स्वतंत्रता के लिए सघर्ष का रूप देना चाहता था।

अगर सोवियतों की सातवी कांग्रेस में कोबोजेव दल को विजय हुई, तो पार्टी के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन ने पलड़ा किसी हद तक कच्चाकोव के पक्ष में झुका दिया। पार्टी सम्मेलन ने सोवियतों की सातवी कांग्रेस में रिस्कूलोव द्वारा तुकिस्तान पार्टी की पूरी केन्द्रीय समिति की व्यापक आलोचना को अनुचित ठहराया। उसने कहा कि गलतियाँ पूरी पार्टी नीति की नहीं, व्यक्तिगत पार्टी नेताओं की थी। उसने पार्टी की फ्राइकोम (क्षेत्रीय समिति) में विश्वास प्रकट किया और सावियता की सातवी कांग्रेस के जातीय विभाग द्वारा प्रतिरोध को निराधार कहकर अस्वीकार किया। सम्मेलन ने मुस्लिम जनता में प्रचारकाय करने के लिए पार्टी में एक मुस्लिम ब्यूरो कायम करने का निश्चय किया। मुस्लिम ब्यूरो को पार्टी का सहायक निकाय होना था। और उसकी निगरानी और नियंत्रण में काम करना था। पार्टी के दूसरे सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा कोबोजेव को वापस बुलाने की माग की। उन्हें पदच्युत कर दिया गया और उनकी हरकतों की जांच करने का आदेश दिया गया।* कोबोजेव की कारवाइयाँ से खोज आकर फ्राइकोम के कुछ सदस्यों ने शकीरोव को पार्टी की केन्द्रीय समिति के सामने कोबोजेव के खिलाफ शिकायत करने के लिए मास्को भेजा।

तुकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस (११५ जून, १९१६) में अधराष्ट्रवाद के विरुद्ध सघन रूप लिया। सोलकिन का कहना था कि पर सिद्धांतवादी बहस का रूप लिया। चूँकि मुसलमानों में अभी सामंती सबंध छाये हुए हैं और खानाबदोशी के सबंध अवशेष भी मौजूद हैं, इसलिए कोई मुस्लिम सबहारा नहीं है। उनका समयन वास्तानतिनोपोल्स्की ने किया। इनका कहना था कि तुकिस्तान में केवल अर्द्ध-सबहारा वर्ग है और कोई सबहारा नहीं, जो ऐतिहासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाये। कोन्स्तानतिनोपोल्स्की ने भय प्रकट किया कि देशी सबहारा के अभाव में तुकिस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन कहीं

* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस की दस्तावेज़," ताशक़न्द, १९१६, पृष्ठ १३४-१३५।

सब-इसलामवाद के हाथ में न पड़ जाये। परन्तु कोवोजेव इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बताया कि अभी ही पार्टी के आगे से अधिक सदस्य देशी कम्युनिस्ट हैं जिससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम जनता पार्टी के कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुई है।* पार्टी की फ्राइकोम के कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए तीसरी पार्टी कांग्रेस ने सोवियतों की सातवीं कांग्रेस में जातीय विभाग का संगठन करने की कार्यनीति को गलत ठहराया। फ्राइकोम की रिपोर्ट पर अपने प्रस्ताव में तीसरी पार्टी कांग्रेस ने यह विचार प्रकट किया कि पिछली पार्टी कांग्रेसों द्वारा जो काम उसके सिपुद किये गये थे, उन सबों को फ्राइकोम ने पूरा नहीं किया है। प्रस्ताव ने खासकर जिन बातों की चर्चा की, उनमें स्थानीय क्षेत्रों, विशेषकर मुसलमानों में सही आतिकारी काम का अभाव तथा पार्टी पकितियों में अनुशासन की कमी थी। कांग्रेस ने पार्टी के सामने अनुशासन को सुदृढ़ करने और मुस्लिम ब्यूरो के जरिये स्थानीय आवादी में पार्टी कार्य को तेज करने का कार्यभार रखा।

तीसरी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी समितियों के भीतर काम करनेवाले मुस्लिम विभागों को वही हैसियत दी, जो पार्टी इकाइयों की थी, और उन्हें मुस्लिम ब्यूरो के नियंत्रण में रखा जिसे हर सम्भव सहायता देनी थी। तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की फ्राइकोम में कोवोजेव, रिस्कूलोव, आफन्दीयेव, खोजायेव और अलीयेव के निर्वाचन से बजाकोव का अधराष्ट्रवादी गिराह कुछ कमजोर हुआ। परन्तु यह गिराह अभी भग नहीं हुआ था। बजाकोव अभी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। थोड़े ही दिनों में इस गिराह के खिलाफ लम्बा संघर्ष शुरू हुआ।

इस संघर्ष के पुनः छिड़ने का कारण १२ जुलाई, १९१६ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रीय समिति का यह संदेश था कि क्षेत्रीय प्रशासन में स्थानीय आवादी का सानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान पार्टी और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि "तुकिस्तान की स्थानीय आवादी की राजकाय

* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस की दस्तावेजों", पृष्ठ ५०।

कायकलापो में सानुपातिक शिरकत होनी चाहिए, जिसके लिए पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर मुस्लिम मजदूरों के संगठन उनकी उम्मीदवारी का अनुमोदन कर दें, तो यह काफी है।" * कजाकोव उस्पेस्की गिरोह के अधराष्ट्रवादी विचार के लोगो ने देखा कि अगर इस आदेश पर अमल किया गया, तो उनकी स्थिति खतर में पड़ जायेगी। उन्होंने यह तक पेश किया कि पार्टी की केन्द्रीय समिति तुकिस्तान की स्थिति को ठीक तरह नहीं समझती है और कि स्थानीय मजदूर और किसान अभी परिपक्वता के उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, जो राजकीय कायकलाप में शिरकत के लिए जरूरी है। उन्होंने अखबारों में विज्ञप्ति के प्रकाशन में बाधा डाली। २० जून, १९२० को उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति के पास एक तार भेजा, जिसमें इस आदेश पर अमल करना असम्भव बताया।

इस प्रकार सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय समिति के आदेश के संबंध में तीव्र सघर्ष छिड़ गया। इसपर ताशकंद, समरकंद और फरगाना जैसे विभिन्न स्थानों में पार्टी और जन-सभाओं में बहस हुई। १६ जुलाई, १९१९ को ताशकंद के पुराने शहर में एक सावजनिक सभा में, जिसमें पार्टी की क्षेत्रीय समिति तथा मुस्लिम ब्यूरो के कई सदस्य उपस्थित थे, एक प्रस्ताव स्वीकार करके इसकी फौरी तामील की, खासकर सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन की मांग की गई। कजाकोव उस्पेस्की गिरोह ने कोवोजेव को बदनाम करना शुरू किया और उनपर देशी लोगो को रूसी मजदूरों के विरुद्ध उभारने का आरोप लगाया। उसने मांग की कि केन्द्र कोवोजेव को वापस बुला ले, क्योंकि वह व्यक्तिगत सत्ता की खातिर मुस्लिम वगच्युत तत्वा, भूतपूर्व व्यापारियों और काराबारियों आदि के साथ साजबाज कर रहे हैं। केन्द्र के आदेश का व्यापक पैमाने पर समर्थन किया गया। समरकंद तथा अन्य शहरों में पार्टी इकाइयां ने अपनी पूरी सहमति प्रकट की।

* 'तुकिस्तानस्की काम्युनिस्त', अंक ६२, १६ जुलाई, १९१९।

तुकिस्तान की सोवियतों की आठवी काग्रेस तथा तुकिस्तान का कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी काग्रेस, जो सितम्बर १९१९ में आयोजित हुई, एक बार फिर पार्टी और सरकार में अधराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघर्ष का अखाड़ा बन गई। सोवियतों की आठवी काग्रेस में कज़ाकोव-उस्पेस्की गुट ने एक प्रस्ताव पेश करके मांग की कि जातीय मामला की जन कमिसारियत को तोड़ दिया जाये। कज़ाकोव-उस्पेस्की गुट की अधराष्ट्रवादी प्रवृत्ति के जवाब में पार्टी में राष्ट्रवादी भटकाव उत्पन्न हुआ जिसके अगुआ रिस्कूलोव थे। इसका पहला इजहार सोवनारकोम का भग बनाने का प्रस्ताव था, जो रिस्कूलोव के पेश करने पर सोवियतों की आठवी काग्रेस में स्वीकृत हो गया। सोवनारकोम को भग कर दिया गया और इसका स्थान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के भीतर की तीन परिषदों ने लिया। इससे सरकार के कार्यकारी निकायों के निपुण काम पर बुरा असर पड़ा।

चौथी क्षेत्रीय पार्टी काग्रेस ने एक प्रस्ताव के जरिये सानुपातिक प्रतिनिधित्व के संवध में केन्द्र के आदेश के बुनियादी सिद्धांतों को मंजूर किया। उसने तुकिस्तान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी तामील के व्यावहारिक उपाय निकाले। चौथी काग्रेस ने निश्चय किया कि हर अलग अलग सूरत में सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर अमल तभी किया जायगा जब सोवियतों की क्षेत्रीय या स्थानीय काग्रेस वाक्यांश इसकी मांग करेगी। इसपर अमल सोवियत विधान की धाराओं के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की क्षेत्रीय और स्थानीय समितियां तथा मुस्लिम ब्यूरो के आम निर्देशन में किया जायेगा।* यह याद रखना चाहिए कि तुकिस्तान में मुस्लिम जनता अभी अच्छी तरह संगठित नहीं हो पायी थी और इसलिए स्वयं अपनी जाति के शोषकों के बहकावे में आने का वास्तविक खतरा था।

सितम्बर १९१९ में तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी काग्रेस में अधराष्ट्रवादी गुट को पार्टी के स्वस्थ तत्वों के हाथों मुह की खानी पड़ी। मुसलमान ही नहीं, कई रूसी प्रतिनिधियों ने भी सानुपातिक प्रतिनिधित्व

* 'तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की काग्रेसों के प्रस्ताव और निर्णय', पृष्ठ ४६-४९।

के सबध में केन्द्र के तार का समर्थन किया। बुनाचे श्वात्स ने कहा कि किसी जाति की सध्या को ध्यान में नहीं लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि "जहाँ तक प्रशासन में लोगा के भाग लेने का सवाल है किसी जाति का सांस्कृतिक स्तर कोई भूमिका अदा नहीं करता, क्योंकि राजकीय कायकनाप के दौरान में ही जानि इसका सबूत देती है कि वह उन कामों को पूरा कर सकती है या नहीं, जो उसके सिपुद किये गये हैं।" कोबोजेव ने कहा कि केन्द्रीय समिति का तार तुकिस्तान की जातियों के आत्मनिर्णय की दिशा में एक नया कदम है।"

अधराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघष जारी ही था, जब तुक आयोग नवम्बर १९१६ में ताशकन्द पहुँचा। आयोग ने पार्टी और सोवियत संगठना से उन लोगा को निकालना शुरू किया जो उसकी राय में अधराष्ट्रवादी भटकाव के अपराधी थे। उसने कजाकान्ड उस्पेन्स्की, सोरोकिन और कई और व्यक्तियों को तुकिस्तान से चले जाना का आदेश दिया। कई जारशाही अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कारवाइया शुरू की गई। आयोग ने मुर्स्तौदी से कदम उठाकर जेतीसुव में पार्टी की उपेक्ष और ओब्लास्त समितियों को अधराष्ट्रवादी तत्वों से मुक्त किया। जेतीसुव के प्रलावा करगाना और सिरदरिया ओब्लास्तों में भी इसी तरह के कदम उठाये गये।

ऐसी सही जातीय नीति के लिए, जो भटकावा से मुक्त हो, सघष को तेज करने में तुकिस्तान के कम्युनिस्टों के नाम लेनिन के पत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। लेनिन ने इसी कम्युनिस्टों को सलाह दी कि तुकिस्तान के लोगा से व्यवहार करने में अत्यंत सहिष्णुता और भरासे से काम ले और इस बात पर जोर दिया कि इसी साम्राज्यवाद के सभी चिह्न मिटा दिये जायें। अपने पत्र में लेनिन ने कहा कि तुकिस्तान के जनगण से सही सबध कायम करने का "जवरदस्त, युगांतरकारी"

* 'तुकिस्तान में इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) का मुस्लिम व्यूरो', पृष्ठ ५२। (रूसी संस्करण)
** वही, पृष्ठ ६३।

महत्त्व है।* लेनिन के पत्र पर तुर्किस्तान भर में पार्टी तथा सावजनिक सभाओं में विचार किया गया और बहुत सताप प्रकट किया गया।

जब तुर्क आयोग के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी सारी शक्ति और धन पार्टी से अधराष्ट्रवादी भटकाव का उन्मूलन करने में लगा दिया तो पूंजीवादा राष्ट्रवाद के विरुद्ध संघर्ष की किसी हद तक उपेक्षा की गई। नतीजा यह हुआ कि शीघ्र ही राष्ट्रवादी भटकाव उभरकर सामने आ गया और तुर्किस्तान की पिछड़ेपन की स्थिति में सोवियत काम के निगमभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

राष्ट्रवादी भटकाव जनवरी १९२० में सामने आया। इसने पांच क्षेत्रीय पार्टी सम्मेलन में तथा मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में मर उठाया। मुस्लिम ब्यूरो ने कुछ दिनों तक मुस्लिम जनता में अच्छा काम किया, उनमें सोवियत तथा पार्टी आदर्शों का प्रचार किया, उस सोवियत सत्ता के नज़दीक लाया। परंतु थोड़े ही दिनों में वह पार्टी समानान्तर स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करना लगा और रिस्कूला आदि के राष्ट्रवादी विचारों के असर में प्रतिश्रियावादी राष्ट्रवाद का अनुसरण करने लगा।

पार्टी के पांचवें क्षेत्रीय सम्मेलन ने निश्चय किया कि पार्टी के तीनों अग्रिम निकायों, यानी तुर्किस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आइकोम, क्षेत्रीय मुस्लिम ब्यूरो तथा वैदेशिक कम्युनिस्टों की क्षेत्रीय समिति के तुर्किस्तान की एक ही संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी में मिला दिया जाय यह सही फैसला था जिससे पार्टी की एकजुटता और अधिक बनी थी। परंतु सम्मेलन ने रिस्कूलोव के कहने पर एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारी गलती की जिसमें पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। रिस्कूलोव की राय में मुस्लिम जनता में आइकोम का मानना छोड़ दिया था और इससे फनस्वरूप तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी अब उसपर अपना विचारधारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती थी इसलिए उन्होंने पार्टी के नाम में परिवर्तन करने का मुझाव दिया।

* अना० इ० लेनिन, संपादित रचनाएँ (चार भागों में), प्रकाशित मास्को, १९६६, भाग ३, पृष्ठ २५६-२६०। (हिंदी संस्करण)

पार्टी के पाचवे क्षेत्रीय सम्मेलन व साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिस्टों का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन भी हो रहा था। उमम रिस्कूलाव ने स्वायत्तता और तुकिस्तान के संविधान पर अपनी रिपोर्ट में अपना राष्ट्रवादी भटकाव थोपने का प्रयास किया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुकिस्तान जनतंत्र का नाम बदलकर तुर्की जनतंत्र कर दिया जाये। उनकी दलील यह थी कि कजाख, किर्गिज, तुर्कमान, ताजिक और उज्बेक अलग अलग जातियाँ नहीं, बल्कि एक ही जाति, यानी तुर्क है। मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन ने रिस्कूलाव का यह सुझाव मान लिया। उसने तुकिस्तान के अधिकारों में वृद्धि करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता उठायी। अगर सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव से प्रातिकारी शाहवाली की अलग कर दिया जाये, जिसका उद्देश्य उसके समर्थकों के असल इरादा को परदा डालना था, तो वास्तव में वह रूस से अलग होने की मांग थी। वह सव-सुखवाद की और दरअसल घोर प्रतिरियावादी मांग थी।

पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की पार्टी रखने का रिस्कूलोव का सुझाव पाचवें पार्टी सम्मेलन द्वारा स्वीकार हो गया। इसका कारण यह था कि तुकिस्तान आयोग के सदस्यों में इस सवाल पर एक मत नहीं था। आयोग के अध्यक्ष एलिआवा ने रिस्कूलोव के सुझाव का समर्थन किया और कूडबिसेव और गोलोश्चोकिन द्विधा में थे। केवल रुदज़ताक ने रिस्कूलोव के सुझाव का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। फ्रूजे ने आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह तुकिस्तान से बाहर थे। ताशकन्द पहुँचने पर उन्होंने आयोग को इस पर राजी कर लिया कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की क्षेत्रीय समिति का आदेश आने तक पार्टी का नाम बदलकर तुर्की जाति की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रखा जाय।*

मार्च १९२० में तुकिस्तान आयोग ने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन तथा पार्टी के पाचवें क्षेत्रीय सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की क्षेत्रीय समिति के पास उसकी

* "तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संक्षेप में लेख" कद, १९६४, खण्ड ३, पृष्ठ १२६। (रूसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतन्त्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धान्त के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाले नहीं थे। उन्होंने रिस्कूलोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मांगें रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने मांग की कि सार अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निमाण किया जाये। उन्होंने यह भी मांग की कि डाक-तार, वैदेशिक मामला और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतन्त्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में हों। व उज्बेक, कजाखो तुकमानो, और किर्गिजों को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्कों जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिस उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इस्लामवाद और सब-तुक्वाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में खतम हो चुका था।*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मांगा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को प्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किए गये मसविदे का देखा और उमम कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

* "उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के सवध में सच", पृष्ठ ७७।

भटकाववादिया की माग को लेनिन ने अस्वीकार कर दिया और मुझाव दिया कि "मुल्ताआ, सब इसलामवादी और पूजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन से सघप के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।" रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० का तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी कायभारा पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केंद्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मतविदे के साथ उसमें लेनिन के मुझावा और विचारों का भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव में जनतंत्र के अधिक जीवन में सामंती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटाने तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतता का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, जो महानतकश जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान के श्रमजीवी जनगण और रुस की जातियां व बीच अंतरजातीय मंत्री को सबल बनाने और विकसित करने के लिए अथक सघप का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबप्रथम रुसी सवहारा की विरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातियां स्वतंत्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के माग पर विकास कर सकती हैं। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग का रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और ८० सो० स० स० जनतंत्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कायम रखना जरूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादिया की इस माग को कि तुर्की जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाये दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका नतीजा यह होता कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरुमी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। उसने तीनों स्थायी क्षेत्रीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमोदन किया। राष्ट्रवादियों के गिरौह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आइकोम से तथा तुकिस्तान की

* लेनिनी सग्रह, खण्ड ३४ पृष्ठ ३२६। (रुसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतंत्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धान्त के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाला नहीं थे। उन्होंने रिस्कलोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मार्ग रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने माग की कि सारे अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवनारकोम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण किया जाये। उन्होंने यह भी माग की कि डाक तार, वदेशिक मामलों और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतंत्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में हों। वे उज्बेकों, कज़ाखों तुकमानों, और किर्गिज़ों को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्कों जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इसलामवाद और सब-तुक्वाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में घनम हा चुका था।*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मागा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को प्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे को देखा और उसमें कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

* "उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संघर्ष में लेख", पृष्ठ ७७।

भटकाववादिया की माग को लेनिन ने अस्वीकार कर दिया और मुझाव दिया कि "मुल्लाभा, सब इसलामवादी और पूजीवादी-राष्ट्रवादी आंदोलन से सघप के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।" *
 इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० को तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी व बुनियादी कायभारा पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केन्द्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मतविदे के साथ उसमें लेनिन के मुझावो और विचारा को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव में जनतंत्र के आर्थिक जीवन में सामंती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटाने तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतता का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर ज़र दिया गया था जो महन्तकश जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान के श्रमजीवी जनगण और इस की जातिया व बीच अंतरजातीय मैत्री का सबल बनाने और विकसित करने के लिए अथक सघप का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबसेप्रथम इसी सहारा की विरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातिया स्वतंत्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के माग पर विकास कर सकती है। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग को इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और रू० सो० स० स० जनतंत्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कायम रखना जरूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादियों की इस माग को कि तुर्की जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाये दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका नतीजा यह होता कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरूसी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। उसने तीना स्थायीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमान किया। राष्ट्रवादियों के गिरोह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की फ्राइकोम से तथा तुकिस्तान की

* लेनिनी संग्रह खण्ड ३४, पृष्ठ ३२६। (रूसी संस्करण)

राय के लिए भेजा। केन्द्रीय समिति ने तुकिस्तान जनतंत्र और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलने की माग को अस्वीकार कर लिया क्योंकि यह मार्क्सवादी लेनिनवादी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा पार्टी संगठन के सिद्धान्त के विपरीत थी। उसने अखिल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को पूर्ण अधिकारप्राप्त संगठन माना।

परन्तु राष्ट्रवादी भटकाववादी इतनी आसानी से हार माननेवाला नहीं था। उन्होंने रिस्कूलाव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अपने प्रयोजन का समर्थन करने के लिए मास्को भेजा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के समक्ष अपने स्मृतिपत्र में उन्होंने राष्ट्रवादी मांगें रखी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जातीय नीति के विपरीत थी। उन्होंने मांग की कि सारे अधिकार तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और सोवियत-कॉम के हवाले कर दिये जायें, तुकिस्तान आयोग भंग कर दिया जाये, तुकिस्तान की लाल सेना से रूसी हटा दिये जायें और शुद्ध मुस्लिम सेना का निर्माण किया जाये। उन्होंने यह भी मांग की कि डाक-तार, वैदेशिक मामला और वित्त के साथ-साथ रेलवे को भी जनतंत्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाये, जो तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की देख रेख में होगा। वे उज्बेको, कजाख तुर्कमाना, और किर्गिजा को अलग अलग जातियाँ नहीं मानते थे और तुर्की जाति में उन्हें मिलाना चाहते थे। वे उस राष्ट्रवादी प्रस्थापना को पुनः सामने लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिस्टों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में पेश किया था, कि सब इस्लामवादी और सब-तुर्कवाद का आधार सोवियत तुकिस्तान की परिस्थिति में खतम हो चुका था।*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रीय समिति ने ध्यानपूर्वक उनकी मांगा पर विचार किया और इस काम के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया। १३ जून, १९२० को व्ला० इ० लेनिन ने आयोग द्वारा तैयार किए गये मसविदे का देखा और उनमें कई बातें जाड़ी। राष्ट्रवादी

* "उज्बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के संवध में लेख", पृष्ठ ७७।

भटकाववादियों की मागों को लेनिन न अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि "मुल्लाखा, सब इसनामवादी और पूजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन से सघष के उपाय विशेष रूप से तैयार किये जायें।"*

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) के पोलिटब्यूरो ने १६ जून, १९२० को तुकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी व बुनियादी कार्यभारा पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। केन्द्रीय समिति के आयोग द्वारा तैयार किये गये मसविदे के साथ उसमें लेनिन के सुझावों और विचारों को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी के पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव में जनतन्त्र के आर्थिक जीवन में सामंती और पितृसत्तात्मक अवशेषों को मिटान तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, जो महानतकश जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के गिद जमा कर सकती थी। उसने तुकिस्तान में धर्मजीवी जनगण और रूस की जातियाँ के बीच अन्तरजातीय मैत्री को सबल बनाने और विवसित करने के लिए अथक सघष का नारा दिया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि सबप्रथम रूसी सबहारा की विरादराना सहायता से तुकिस्तान की सभी जातियाँ स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर आजादी के साथ समाजवाद के मार्ग पर विकास कर सकती हैं। पोलिटब्यूरो की राय में तुकिस्तान आयोग को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) और रू० सो० स० म० जनतन्त्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में त्रायम रखना जरूरी था। पोलिटब्यूरो ने राष्ट्रवादी भटकाववादियों की इस माग को कि तुर्की जाति की विशेष कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाय दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका नतीजा यह होना कि स्थानीय कम्युनिस्ट संगठन और अखिलरूसी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग हो जाती। उसने ताना स्थानीय क्षेत्रीय समितियों को तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में मिला देने की जरूरत का अनुमोदन किया।

राष्ट्रवादियों के गिरोह ने पोलिटब्यूरो के प्रस्ताव से असहमति प्रकट की और तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की फाइकोम से तथा तुकिस्तान की

* लेनिनी मग्नह, खण्ड ३४, पृष्ठ ३२६। (रूसी संस्करण)

केन्द्रीय कायकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया। इससे १६ जुलाई, १९२० को तुर्क आयोग द्वारा काइकोम को भग करना और तुर्किस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की नयी अस्थायी केन्द्रीय समिति का निर्माण करना जरूरी हो गया। यह भी निश्चित किया गया कि केन्द्रीय कायकारिणी समिति को भग किया जाय और उसको नये ढंग से पुनर्गठित किया जाये। तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की नई अस्थायी केन्द्रीय समिति के प्रधान तियुराक्लोव और नई केन्द्रीय कायकारिणी समिति के प्रधान रहीमबायेव थे। तुर्किस्तान आयोग की पहलकदमी पर काइकोम और केन्द्रीय कायकारिणी समिति के भग किये जान का विभिन्न स्तरों पर पार्टी संगठनों ने व्यापक रूप में स्वागत किया। रिस्कूलोव के नेतृत्व में पूंजीवादी राष्ट्रवादियों ने भूमि और सिचाई सुधारों को लागू करने में बाधा डालने का प्रयत्न किया। इसी कुत्तको तथा आप्रवासियों के विरुद्ध तुर्किस्तान आयोग के अभियान का उन्होंने समर्थन किया था, मगर जब मुस्लिम ब्राई और मानप लोगों के विरुद्ध आक्रमण की योजना बनी, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। वे दशै पूजा के विरुद्ध संघर्ष को अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखना चाहते थे। उनकी राय में फौरी कायभार वगैरे चेतना को नहीं, बल्कि जातीय चेतना को जाग्रत करना था। इस प्रकार पूंजीवादी राष्ट्रवादियों ने अपने आपको तुर्किस्तान की आम जनता की नजरों में बिल्कुल बेमकाब कर दिया। तियुराक्लोव और रहीमबायेव जैसे ईमानदार और सच्चे मुस्लिम कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों के हानिकारक विचारों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया।

तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी केन्द्रीय समिति ने पाचवी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के आयोजन की तैयारियां शुरू कीं। कांग्रेस का अधिवेशन ताशकन्त में १२ से १८ सितम्बर तक, १९२० को बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ क्योंकि लाल सेना ने प्रतिनाति और वैदेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष में महान सफलताएं प्राप्त की थीं। उसने सबसे अधिक से तुर्किस्तान आयोग के फैसले के जरिये काइकोम को भग किया जान का अनुमोदन किया और राष्ट्रवादी भट्टवाववादियों के आचरण और नीतियों की बड़ी आलोचना की। राष्ट्रवादियों ने बाबू में पूँव की जातियों की

काग्रेस के समक्ष जो निगाधार आराप लगाये थे, उनका काग्रेस ने खंडन किया। काग्रेस की रिपोर्टों और भाषणा में इस बात पर जोर दिया गया था कि पार्टी के सामने बुनियादी बायभार सोवियत रूस के मजदूरों और किसानों के साथ तुर्किस्तान के मेहनतजशा की एकजुटता को सुदृढ़ करना और व्यापक बनाना, जातीय असमानता के समस्त अवशेषों को मिटाना तुर्किस्तान के गरीब जनगण का कुलकोष बाई और मानव लोगों के शापण से मुक्त करना तथा श्रमजीवी खानाबदोशों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों का जमीन देना है। काग्रेस ने स्वीकार किया कि गावा में गरीब तथा मसोल किसानों के हिता का मुनिश्चित करने के लिए कोइची-गरीब किसानों के सघ-मगठित करने की आवश्यकता है।

तुर्किस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पाचवी काग्रेस ने नियुराकूतोव के नतृत्व में नई केन्द्रीय समिति का गठन किया। उस काग्रेस ने तुर्किस्तान में पार्टी के सघटनात्मक और विचारधारात्मक दृढीकरण में बड़ी भूमिका अदा की। वह इस बात का सबूत थी कि महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवादी और पूँजीवादी राष्ट्रवादी भटकावों दोनों से मुक्ति पाने के लिए पार्टी का सघष सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

तुर्किस्तान की सोवियत की नवी काग्रेस ने, जो सितम्बर १९२० में आयोजित हुई, तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र के लिए नया संविधान मजूर किया। उसने तुर्किस्तान को उस क्षेत्र में रहनेवाली मुख्य जातियाँ, यानी तुर्कमाना, उर्बेका, किगिज़ो आदि का स्वायत्त जनतंत्र घोषित किया। संविधान में वैदेशिक मामलों, पतिरक्षा, वित्त, डाक-तार और संचार को स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के एकमात्र अधिकार में रहने दिया। याद रहे कि १९१८ के संविधान में भी इन कार्यों को संघीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में धारित किया था, परन्तु उसने तुर्किस्तान के पदाधिकारियों का यह अधिकार दिया था कि वे स्थानीय स्थितियों के अनुकूल सघ की आज्ञानिया और आदशा में फेरबदल कर सकते हैं। तुर्किस्तान स्वायत्त जनतंत्र अठ्ठ भी इकट्ठा कर सकता था तथा पड़ोसी देश से सीमित वैदेशिक सबध भी स्थापित कर सकता था। वह सघ के उन अधिकारियों को वापस बुलाने की माग भी कर सकता

था, जो उसे स्वीकार नहीं थे। वैदेशिक सवधो, रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक तार तथा वित्त जैसे मामलो में सघ के एकमात्र अधिकार-क्षेत्र पर वे पावदिया बड़ी हद तक गृहयुद्ध और वैदेशिक हस्तक्षेप के कारण ज़रूरी हो गई थी। १९१८ में तुकिस्तान का केन्द्र से कोई स्थायी सम्पर्क नहीं था। परन्तु १९२० में स्थिति बदल चुकी थी। केन्द्र से अब तुकिस्तान का लगातार सीधा सम्पर्क ल कायम था। फिर गत तीन वर्षों के अनुभव ने बता दिया था कि इन कायभारों का तुकिस्तान जनतंत्र द्वारा समवर्ती अधिकारों की पावदियों के बिना मघीय सरकार के एकमात्र अधिकार-क्षेत्र में रहना ज्यादा अच्छा है। इसके लिए १९१८ के संविधान में हेर फेर करने का ज़रूरत थी जिसे तुकिस्तान की सोवियतों की नवी कांग्रेस ने किया। पूँजीवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि १९१८ में जो स्थिति थी, उस स्थाया बना दे और उसे और अधिक बढ़ायें तथा कानून के जरिये उसकी पुष्टि कर। अवश्य ही यह तुकिस्तान के श्रमजीवी जनगण के वास्तविक हिता के विपरीत था जिसका तकाज़ा था कि अत्य सावियत जातिया से घनिष्ठ एकता कायम हो।

तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की पाचवी कांग्रेस और तुकिस्तान की सोवियतों की नवी कांग्रेस के समय तक अधराष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी भटकावा के विरुद्ध तीव्र सघर्ष का दौर समाप्त हो चुका था। मगर ये प्रवृत्तियाँ, घासकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ १९२५ में पुन १८ के गुट के रूप में उत्पन्न हुई। पार्टी के कुछ सदस्या पर पूँजीवादी राष्ट्रवादी प्रभाव के जमे रहने का मुख्य कारण नयी आर्थिक नीति के दौर में व्यापारी पूँजीपतियाँ, कुत्सों तथा अत्य शोषक तत्वा का अस्तित्व था, जो हर सम्भव उपाय से राष्ट्रवादी अवशेषों से लाभ उठाना चाहते थे। प्रशामन का देशी बनाने व कायभार से भी समझौता पैदा हो और पूँजीवादी राष्ट्रवादी तथा अधराष्ट्रवादी भटकाव उत्पन्न हुए। अधराष्ट्रवादी प्रवृत्ति के लाग दशों लोगों की सजनामा योग्यता में विश्वास नहीं करते थे, जबकि पूँजीवादी राष्ट्रवाद का बल राष्ट्रीय आधार पर दशोन्नरण की माग करते थे जिना यह गाँवे हुए कि हमारे लिए वास्तविक तयारियाँ कहा तक हुई हैं और समस्या का मामाजिन और राजनीतिन स्वरूप क्या है। जातीय ममान पर पार्टी

लाइन में इन दोनों में से किसी भी भटकाव के पुन उत्पन्न होने के विरुद्ध पार्टी अत्यंत चौकसी से काम लेती रही। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वो०) की दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं कांग्रेस ने भी दोनों भटकाव के विरुद्ध, सवप्रथम अधिराष्ट्रवादी भटकाव के विरुद्ध सघन का नारा दिया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बारसवी कांग्रेस ने भी पार्टी के नये कार्यक्रम में अधिराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के अवशेषों के विरुद्ध सघन के कार्य-भार को नहीं भुलाया।

नौक मोवियन जननत्र मे

मोवियत नमाजवादी जननत्र मे

मंक्रमण

बुधारा और खीवा मे

जननानि का स्वरूप

बुधारा और खीवा मे १९२० मे जा जानि हुई उन किमाना का मावियतो के रूप मे अमजीवी जनगण की नत्ता म्यापिन की। वहा का नानि गुरीव किमाना और कारीगरा की शक्तिया द्वारा लाल मेना का मनिय सहायता मे की गई थी। कुछ इतिहासकारो का मत है कि बुधारा और खीवा की जानि का स्वरूप पूजीवादी-जनवादी था और इन जननत्रा का सामाजिक ढांचा भी पूजीवादी-जनवादी था। वास्तव मे, खीवा और बुधारा की जानि न सवप्रथम पूजीवादी-जनवादी आति का कायभार पूरा

न प्रयास किया कि किसानों की सोवियतता का अपने वर्गीय शासन के निकाया के रूप में इस्तेमाल करे और पजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम करके श्रांति को चरम कर दे। परन्तु इन जनतन्त्रों के जनसाधारण ने अकतूबर श्रांति के शक्तिशाली प्रभाव में पूँजीपति वर्ग की इन आकांक्षाओं का विरोध किया। शुरु ही से उनका प्रयत्न था कि श्रांति का और आगे विकास हो और किसानों की सोवियतता को रूपांतरित करके लोक सोवियत व्यवस्था का आधार बना दिया जाये।

बुखारा और खीवा में श्रांति लोक सोवियत जनतन्त्रों की घोषणा के साथ समाप्त नहीं हुई। समाज का श्रांतिकारी पुनर्गठन और आगे जारी रहा यहाँ तक कि ये जनतन्त्र समाजवादी जनतन्त्रों में परिवर्तित हो गये। दिसम्बर १९२० में सोवियतों की आठवीं अखिलरूसी कांग्रेस में अपने भाषण में बुखारा, आज़रबैजान और आर्मीनिया में सोवियत जनतन्त्रों की स्थापना और सुदृढीकरण का अभिनन्दन करते हुए लेनिन ने कहा

“य जनतन्त्र इस बात के सबूत हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सत्ता के विचार और उसूल केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही नहीं, केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ सबहारा वर्ग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध और फौरन काम में लाये जाने योग्य है, जहाँ आधार किसान-समुदाय है। किसान सोवियतता का विचार विजयी हो चुका है। किसानों के हाथ में सत्ता सुरक्षित है उनके हाथ में ज़मीन है, उत्पादन के साधन हैं। हमारी नीति के व्यावहारिक नतीजा द्वारा किसान सोवियत जनतन्त्रों और रूसी समाजवादी जनतन्त्र के दोस्ताना सम्बन्ध पक्के हो चुके हैं।”*

आर्मीनिया और आज़रबैजान में किसान जनसाधारण ने अपनी सोवियतों के जरिये मजदूरों से अपनी वर्गीय एकरता स्थापित की और अपने जनतन्त्रों को तुरत समाजवादी जनतन्त्रों में बदल दिया। खीवा और बुखारा में इसी प्रक्रिया में तीन चार साल लग गये।

* व्ला० इ० लेनिन, सकलित रचनाएँ, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९६७, खण्ड ३, भाग २, पृष्ठ ६३-६४। (हिन्दी संस्करण)

आठवा अध्याय बुखारा और ख्वारज़्म --- लोक सोवियत जनतंत्र से सोवियत समाजवादी जनतंत्र में संक्रमण

बुखारा और खीवा में जन-क्रांति का स्वरूप

बुखारा और खीवा में १९२० में जो क्रांति हुई, उसने किसानों की सोवियतों के रूप में श्रमजीवी जनगण की सत्ता स्थापित की। वहाँ की क्रांति गरीब किसानों और कारीगरों की शक्तियों द्वारा लाल सेना की सशस्त्र सहायता से की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बुखारा और खीवा की क्रांति का स्वरूप पूँजीवादी जनवादी था और इन जनतंत्रों का सामाजिक ढाँचा भी पूँजीवादी जनवादी था। वास्तव में, खीवा और बुखारा की क्रांति ने सर्वप्रथम पूँजीवादी जनवादी क्रांति का वास्तविक पुरा किया। इसके सिवा और कुछ हा भी नहीं सकता था, क्योंकि जिन देशों में अभी सामंती व्यवस्था कायम थी, वहाँ समाजवादी क्रांति के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं हो सकती थीं, और किसी भी क्रांति का पहला और सबसे बड़ा काम मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का मिटाना था। इसलिए स्वाभाविक था कि यहाँ की क्रांति का स्वरूप पूँजीवादी जनवादी हो।

परन्तु बुखारा और खीवा में फिर ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियाँ न क्रांति हुई, उनका प्रभाव भी उसका स्वरूप पर पड़ा। महान् अन्तर्गतर क्रांति का प्रिय और स्वयं में मावियत गत्ता की स्थापना न बड़ी हूँ तब बुखारा और खीवा की क्रांति के स्वरूप का निर्धारित किया। वहाँ के पूँजीपति वग

ने प्रयास किया कि किसानों की सोवियतता को अपने वर्गीय शासन के निकाया के रूप में उल्लेख करने और पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था कायम करके अति के चरम पर ले जाने। परन्तु इन जनतन्त्रों के जनसाधारण ने अतृप्त अति के शक्तिशाली प्रभाव में पूँजीपति वर्ग की इन आकांक्षाओं का विरोध किया। शुरू ही से उनका प्रयत्न था कि अति का और आगे विकास हो और किसानों की सोवियतता को रूपांतरित करके लोक सावित्य व्यवस्था का आधार बना दिया जाये।

बुखारा और खीवा में अति लोक सावित्य जनतन्त्रों की घोषणा के साथ समाप्त नहीं हुई। समाज का अतिकारी पुनर्गठन और आगे जारी रहा यह तब कि ये जनतन्त्र समाजवादी जनतन्त्रों में परिवर्तित हो गये। दिसम्बर १९२० में सोवियतों की आठवीं अखिल रूसी कांग्रेस में अपने भाषण में बुखारा, आज़रबैजान और आर्मीनिया में सोवियत जनतन्त्रों की स्थापना और सुदृढीकरण का अभिनन्दन करते हुए लेनिन ने कहा

“ये जनतन्त्र इस बात के सबूत हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सत्ता के विचार और उसूल केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही नहीं, केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ सबहारा वर्ग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध और फौरन काम में लाये जाने योग्य है, जहाँ आधार किसान-समुदाय है। किसान सावित्य का विचार विजयी हो चुका है। किसानों के हाथ में सत्ता सुरक्षित है, उनके हाथ में ज़मीन है, उत्पादन के साधन हैं। हमारी नीति के व्यावहारिक नतीजों द्वारा किसान सावित्य जनतन्त्रों और रूसी समाजवादी जनतन्त्र के दोस्ताना सम्बन्ध पक्के हो चुके हैं।”*

आर्मीनिया और आज़रबैजान में किसान जन-साधारण ने अपनी सोवियतों के जरिये मजदूरों से अपनी वर्गीय एकता स्थापित की और अपने जनतन्त्रों का तुरन्त समाजवादी जनतन्त्रों में बदल दिया। खीवा और बुखारा में इसी प्रक्रिया में तीन चार साल लग गये।

* व्ला० इ० लेनिन, सकलित रचनाएँ, प्रगति प्रकाशन, मास्को १९६७, खण्ड ३, भाग २, पृष्ठ ६३-६४। (हिन्दी मस्करण)

बुखारा और खीवा में जनता ने तमाम बड़े सामंती जमींदारों और मुल्ताओं की सत्ता का उन्मूलन कर दिया। अब सत्ता किसानों की सोवियतता के हाथ में सौंपी गयी। बुखारा में अमीर और उसके सभ सवधियों की कोई ७,५०० तनाव ज़मीन जप्त कर ली गई। सत्ता ऊपर से लेकर नीचे तक जनता के हाथों में थी, जो सोवियतता के जरिये उस काम ले रही थी। जनता के सभी हिस्सों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, उससे वंचित केवल अमीर और खान और उच्च पदाधिकारी थे।

राज्य का सर्वोच्च निकाय जनप्रतिनिधियों की अखिल-बुखारा और अखिल-स्वारज्म कुल्लुताई (कांग्रेस) थी। यही कांग्रेस जनतंत्र की बेद्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती थी, जो कुल्लुताई के अधिवेशनों के बीच की अवधि में सर्वोच्च निकाय के सारे काम पूरे करती थी। कुल्लुताई ही लोक नाज़िरो की परिपद चुनती थी, जो राज्य प्रशासन का एक उच्च निकाय थी।

स्थानीय प्रशासन के निकाय विभिन्न स्तरों की, जैसे ओब्लास्त, रायोन, और घोलोस्त की सोवियतें थी जिनकी अपनी अपनी कार्यकारिणी समितियाँ होती थी। सत्ता का निम्नतम निकाय गाँव या शहर के मोहल्ले के लोगों की ग्राम सभा होती थी।

गाँव की ग्राम सभाओं में आरुस्तफ़ल और स्तारशीना चुने जाते थे। चुनाव में जातंत्र के सभी नागरिक धर्म पुरुष-स्त्री, नस्ल या जाति के भेदभाव के बिना भाग लेते थे। उस राजकीय व्यवस्था की पुष्टि इन जनतंत्रों के सविधानों के जरिये कर दी गई थी। इन जनतंत्रों के राजस्व और सामाजिक ढाँचे की विशेषता व्यापक जनवाद और उनका लोकप्रिय स्वरूप था जिससे वे अवश्य ही साधारण पंजीवादी गणराज्यों से अलग थे। कुछ दिनों के लिए निजी स्वामित्व बुद्ध्याग और हाररज्म के लोग सोवियत जनतंत्रों के आधिकारिक आधार के रूप में कार्यम रहा। उन नागरिकों का अपनी निजी तौर पर अजित या विरागत में पायी हुई वन और अचल सम्पत्ति रखने का असीमित अधिकार था। इसी विशेषता के कारण वे समाजवादी जनता से भिन्न थे।

समाजवादी जनतंत्रों में सश्रम

चरि इन शाना जनतंत्रा के अधिनाश लाग गरीब विमान और वारीगर थे, इनलिए सरकार का सबसेप्रथम काम उनकी स्थिति का सुधारना था। इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिए करो, व्यापार तथा दम्तवागी के क्षत्र में के महत्वपूर्ण तत्त्वों का की गई। बुधारा में विमानों पशुपालन और दम्तवागी पर टैक्स काफ़ी कम कर दिये गये। १९१३ में एक विमान का विभिन्न करा के रूप में औसतन १२,५ रुपय देना पड़ता था। परन्तु अब १९२३-१९४ में उन्हें कुल मिलाकर ८ रुपय यानी ७ प्रतिशत कम देना पड़ा था।* छावा में भी विमानों पर करा का प्रायः २५ प्रतिशत कम किया गया।

थे।* उनके अलावा एक दस्तकारी और चार संगीत के स्कूल खोले गए। १९२२ में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर ५,४०६ हो गई।** यह याद रहे कि प्राति से पहले बुधारा में धर्म निरापेक्ष शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं था। स्वराज्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की गई। १९२३ में २६ स्कूल तथा कई दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं काम कर रही थी, जिनमें १,३६२ व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।***

बुधारा और स्वराज्य के जनतंत्र में समाजवादी उद्योग की स्थापना और उनके अपने मजदूर वर्ग के निर्माण में कई दशक लग जाते, अगर उन्हें हमी मजदूर वर्ग और उसके राज्य की सहायता नहीं मिली होती। १९२३ में बुधारा में ३२ में से केवल ६ कारखाने चालू थे। खीवा में काई भी औद्योगिक संस्थान काम की हालत में नहीं था। इन जनतंत्रों के शहर मुख्यतः दस्तकारी के केंद्र थे, जहां व्यापारी पूजा का बालबाला था। तीस बड़ी व्यापारी फर्मों की पत्नी ही सभी राष्ट्रीयकृत कारखानों की पूजा में अधिक थी।

मगर इन कठिन स्थितियों में भी समाजवादी जनतंत्रों में सश्रमण का परिस्थितियां बहुत तेजी से परिपक्व हुई। इसका कारण आर्थिक रूप में वर्ग की राजनीतिक स्थिति थी। नौजवान बुधारी और नौजवान खीवा जनतंत्रों में कम्युनिस्ट पार्टियों की पत्नियां में इतने बड़े पैमाने पर घुस आए थे कि बुधारा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या १९२२ में १६००० हो गई थी।

के नाज़िरो की परिपद मे एक भी देहकान नही था और उमके सारे पदो पर समाज के शापक तत्वो का नियुक्त किया गया था। यही हाल स्वायत्त का था।

इसका असर सरकार की नीतियो की तामील पर पडे मिना नही रह सकता था। स्तालिन ने सम्मेलन मे बताया कि बुधारा के राजकीय बैंक द्वारा दिये गये कर्जों का ७५ प्रतिशत निजी व्यापारियो को दिया गया था और केवल २ प्रतिशत किसान सहकारी समितियो को मिला था। बुधारा और खीवा के राष्ट्रवादी उज्बेको और तुक्मानो के बीच जातीय पगडे की आग भडकाते थे। बुधारा जनतंत्र के सत्ता निकायो मे उज्बेक पूजीवादी राष्ट्रवादी तुक्मानो और ताजिको के विरुद्ध जातीय भेदभाव की नीति पर अमल करते थे। खीवा मे, जहा उज्बेक और तुक्मान उच्च श्रेणियां न काफी शत्रुता थी प्रतिक्रियावादी तुक्मान बढायली सरकार इस स्थिति स लाभ उठाने का प्रयास करते थे। स्वायत्त जनतंत्र की सरकार जिममे अधिकतर नौजवान खीवादी थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी नीतियां पर अमल करती रही। इसने जनता न आक्रांश की भावना पैदा हुई और ६ मार्च १९२१ को जनता न सरकार को हटा दिया और कई नाज़िरो का गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कुकूलताई के आयोजन की तैयारी करने के लिए एव आतिवारी समिति नियुक्त का गई।

बुधारा जनतंत्र मे भी सरकार के पूजीवादी राष्ट्रवादी सदस्य जनगण के विरुद्ध पडपत्र रचो लगे। उनमे से कई बासमचियो से मिने हुए थे। १९२१ के अंत मे बुधारा जनतंत्र का अध्यक्ष, उस्मान खोजा स्वयं एक नया बासमची दल संगठित करने लगा। बासमचियो का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रवादिया न तुर्की सब इसलामवादी अनवर पाशा को आमन्त्रित किया जिमके नेतृत्व मे मध्य एशिया के सभी बासमची दल एकताबद्ध हो गये। अगर इन घटनाओ से एक आर समाजवादी व्यवस्था की दिशा मे बुधारा और खीवा के लोक सोवियत जनतंत्र के विकास मे निश्चन्देह बटिनाइया पदा हुई तो दूसरी ओर पूजीवादी राष्ट्रवादिया की जन विराघी नीति के कारण उनके विरुद्ध जन आक्रांश बढा। इसकी वजह से धमजीवी जनगण के राजनीतिक कार्यक्रम मे वृद्धि हुई। बासमची के विरुद्ध सघप

थे।* इनके अलावा एक दस्तकारी और चार संगीत के स्कूल खोल गये। १९२२ में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर ५,४०६ हो गई।** यह याद रहे कि त्रांति से पहले बुधारा में घमनिरूप शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं था। स्वराज्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएँ हासिल की गईं। १९२३ में २६ स्कूल तथा कई दूसरी शैक्षणिक संस्थाएँ काम कर रही थी, जिनमें १,३६२ व्यक्ति शिक्षा पा रहे थे।***

बुधारा और स्वराज्य के जनतंत्रों में समाजवादी उद्योग की स्थापना और उनके अपने मजदूर वर्ग के निर्माण में कई दशक लग जाते अगर उन्हें समी मजदूर वर्ग और उसके राज्य की सहायता नहीं मिली होता। १९२३ में बुधारा में ३२ में से केवल ६ कारखाने चालू थे। खीवा में बाद भी औद्योगिक संस्थान काम की हालत में नहीं था। इन जनतंत्रों के शहर मुख्यतः दस्तकारी के क्षेत्र थे, जहाँ व्यापारी पूजा का बालवाला था। ताम बड़ी व्यापारी फर्मों की पूजा ही सभी राष्ट्रीयकृत कारखानों की पूजा से अधिक थी।

मगर इन बठिन स्थितियों में भी समाजवादी जनतंत्रों में सत्रमण का परिस्थितियाँ बहुत तेजी से परिपक्व हुई। इसका कारण आशिक रूप में वहाँ की राजनीतिक स्थिति थी। नौजवान बुधारी और नौजवान खीवाँ इन जनतंत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी की पंक्तियों में इतने बड़े पमाने पर घम आय थे कि बुधारा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या १९२२ में १६००० हो गई थी। पूजावादी राष्ट्रवादी बाई और व्यापारी भी उन राजकीय निराशा में घुस गये थे। जमा कि स्तानिन न जानीय जनतंत्रों के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के माय समी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) का केंद्रीय समिति के चौथे सम्मेलन में बनाया बुधारा लान सावियत जनतंत्र

* "उत्तरेण सावियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास", पृष्ठ २ पृष्ठ २१६।

** म० बहाराण, उपरान्त पुनः, पृष्ठ ३०४।

* उत्तरेण सावियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास, पृष्ठ २, पृष्ठ २१८।

के नाज़िरो की परिपद में एक भी देहकान नहीं था और उसके सारे पदों पर समाज के शोषक तत्वों को नियुक्त किया गया था। यही हाल ख्वारज़म का था।

इसका असर सरकार की नीतियों की तामील पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। स्टालिन ने सम्मेलन में बताया कि बुखारा के राजकीय बैंक द्वारा दिये गये वज़ों का ७५ प्रतिशत निजी व्यापारियाँ को दिया गया था और केवल २ प्रतिशत किसान सहकारी समितियों को मिला था। बुखारा और खीवा के राष्ट्रवादी उज्ज्वेको और तुक्मानो के बीच जातीय बगड़े की आग भड़काते थे। बुखारा जनतंत्र के सत्ता निवाधों में उज्ज्वेक पूँजीवादी राष्ट्रवादी तुक्मानो और ताजिकों के विरुद्ध जातीय भेदभाव की नीति पर अमल करते थे। खीवा में, जहाँ उज्ज्वेक और तुक्मान उच्च श्रेणियों में काफी शत्रुता थी, प्रतिक्रियावादी तुक्मान कबायली सरदार इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करते थे। ख्वारज़म जनतंत्र की सरकार जिसमें अधिकतर नौजवान खीवाई थे, ऐसी ही प्रतिक्रियावादी नीतियों पर अमल करती रही। इससे जनता में आक्रोश की भावना पैदा हुई और ६ मार्च, १९२९ को जनता ने सरकार का हटा दिया और कई नाज़िरो को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कुहलताई के आयोजन की तैयारी करने के लिए एक आतंककारी समिति नियुक्त की गई।

बुखारा जनतंत्र में भी सरकार के पूँजीवादी राष्ट्रवादी सदस्य जनगण के विरुद्ध घड़यत्न रचने लगे। उनमें से कई बासमचियों से मिले हुए थे। १९२९ के अंत में बुखारा जनतंत्र का अध्यक्ष, उस्मान खोजा स्वयं एक नया बासमची दल संगठित करने लगा। बासमचियों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रवाधियों ने तुर्की सब इस्लामवादी अनवर पाशा को आमंत्रित किया जिसके नेतृत्व में मध्य एशिया के सभी बासमची दल एकताबद्ध हो गये। अगर इन घटनाओं से एक और समाजवादी व्यवस्था की दिशा में बुखारा और खीवा के लोक साक्षर जनतंत्र के विकास में निस्सन्देह कठिनाई पैदा हुई, तो दूसरी ओर पूँजीवादी राष्ट्रवादियों की जनविरोधी नीति के कारण उनके विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा। इसकी वजह से श्रमजीवी जनगण के राजनीतिक कार्यक्रम में वृद्धि हुई। बासमची के विरुद्ध संघर्ष

म श्रमजीवी किसान और कारीगर लाल सेना के नज़दीक आ गये। बासमचियो के कारण लोगो मे इतनी तवाही फैली कि १९१३ की तुलना म १९२३ मे बुखारा मे खेती करनेवालो की सख्या घटकर २८७ प्रतिशत रह गई थी और खानाबदोशो की सख्या ७५१ प्रतिशत हो गई थी।* यही वजह थी कि गरीब किसान बासमचियो के विरुद्ध लड़ते, उत्साहपूर्वक लाल सेना मे भरती होते, जबकि बहुत से पूँजीवादी राष्ट्रवाणे मंत्री बासमचियो से जा मिले, जैसे उदाहरण के लिए युद्ध मंत्री आरिफाब।

सोवियत सघ की सरकार तथा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने इन कठिन दिनो मे बुखारा और खीवा के श्रमजीवी जनगण की बड़ी सहायता की। बासमचियो के विरुद्ध लड़ाई म उनका मदद करने के लिए कई अनुभवी पार्टी नेता और सेना कमांडर भेज गये। इसके अलावा खाद्यान्न की रसद तथा औद्योगिक सामाना के रूप म उन्हें और भी भौतिक सहायता दी गई। ओर्जोनीकीदजे पार्टी तथा सोवियत काय का सुधारने मे हाथ बटाने के लिए रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति के प्रतिनिधि की हैसियत से बुखारा आये। उन्होंने पार्टी और सोवियत सस्थाआ से दैरी वग के लोगा और राष्ट्रवादिया को निवालने के काम मे अपन सुयाम्य निदेशन क जरिये मदद की।

बुखारा और रवारज्म लाक सोवियत जनतंत्र सोवियत सघ की भौतिक सहायता और तनगीकी निदेशन के बिना अपनी आर्थिक म्यिति का सुधार नही सकते थे। १९२३ म १७ लाख रुबल का सामान २० सो० स० म० जनतंत्र और तुर्किस्तान से बुखारा भेजा गया। सोवियत सघ न बुखारा जनतंत्र स व्यापार समझौता किया, जा बुखारा के लिए बहत लाभदायक था। बुखारा की कपास का मय नाम १/२ रुबल प्रति मूँड निर्धारित किया गया, जबकि लागत १० रुबल थी। अक्टूबर-नवम्बर १९२४ म २७६५१२ रुबल का माधारण म्मनमाल का सामान और कृषि

* '१९२३-१९२४ की राजकाय आधिकार याज्ञा म बुखारा का स्या', बुखारा १९२३, पृष्ठ ५४-५५। (रुगी मस्करण)

औजार खीवा जनतंत्र भेजा गया। उसी महीन में खीवा जनतंत्र को २५ हजार पूड चीनी, १,००० पूड चमड़ा, २५ हजार जोड़े जूते और ४ हजार पूड चाय भेजी गई। सोवियत सघ ने खीवा जनतंत्र का नगम माफ करनेवाली और तल की मिला के पुनर्निर्माण के लिए ५७५ हजार रयल का कज दिया।*

बुधारा के राष्ट्रवादी तत्वा ने सोवियत रम से बुधारा के सघबद्ध होने के विरोध में एही चाटी का जार लगा लिया और रम प्रवार बुधारा जनतंत्र की सोवियतो की प्रथम काप्रेम के निदज का पूरा नहीं किया। इससे लोग म आत्रोश की लहर फैल गई। जनगण की बढ़ती हृर्द शत्रुता के कारण बुधारा लोक सोवियत जनतंत्र की कायकारिणी ममिति का मन्त्रिमंडल (नाखिरो की परिपद) से कई मन्त्रिया का जम पिनरत नजरुलाह खोजा, अमीनाव आदि का, जिनसे जनगण घृणा करते थे, निकालने का फैमला करन पर बाध्य हाना पडा। चौथी अग्रिल-बुधारा कुहलताई के चुनाव के समय जनगण की चौकसी बहुत बढ गई। प्रतिनिधियो का बडा बहुमत देहकानो और कारीगरा मे मे चुना गया। कुहलताई म सभी जातिया के लाग चुन गये थे। राष्ट्रवादिया के गिलाफ सघप म बुधारा के कम्युनिस्टा को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति की सक्रिय सहायता मिली। नई कुहलताई की बनावट स ही बग शक्तियो का बदला हुआ सतुलन पूरी तरह जाहिर हो रहा था। अभिलेखागार म नई कुहलताई के ४२५ प्रतिनिधिया मे से कोई ३६० के बारे म जा सामग्री सुरक्षित है उससे स्पष्ट है कि २२७ देहकान थे, २७ मजदूर, ६३ पदाधिकारी, १७ कारीगर, १७ बुद्धिजीवी और नौ अय लोग थे। प्रतिनिधिया मे १३१ पार्टी-सदस्य थ। प्रतिनिधिया की जातीय बनावट से नई कुहलताई के बहुजातीय स्वरूप का पता चलता था। उसम २३७ उजबेक, ८१ ताजिक, १६ किगिज, २२ तुक्मान और ११ यद्दी थे।**

*म० बहावोव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७६-३८०।

**वही, पृष्ठ ३८१।

१९२२ में बुधारा और खीवा में पार्टी की सफाई का अच्छा अंश पड़ा। इस सफाई के बाद १६,००० सदस्यों में से केवल एक हजार पाग में रह गये थे। इससे सदस्यता की गुणावस्था बेहतर हो गई और उनकी वा चेतना का स्तर ऊँचा हुआ। १९२३ में बुधारा में पार्टी के १,५६० सम्म थे। इनमें ३५ प्रतिशत देहकान थे, १३ प्रतिशत मजदूर और ८५ प्रतिशत कारीगर थे। खीवा की पार्टी में सफाई के बाद केवल ५४७ सम्म रह गये थे, जिनमें ४१५ देहकान, ८० मजदूर, १५ पदाधिकारी, १६ कारीगर और ४१ अन्य लोग थे।*

बुधारा और प्यारजम लोग सोवियत जनतंत्रों के जीवन में इन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से कानूना में भी परिवर्तन हुआ जिसने उन्हें समाजवादी जनतंत्र में रूपांतरण की दिशा में आग बंधा दिया। १९२२ के अंत में अनवर पाशा के नेतृत्व में बासमची के मुख्य दल की शक्ति के बाद बुधारा में बासमचीवाद में कोई दम नहीं रह गया था। लगभग उन्ही दिना जुनैद खान और अन्य तुकिमान बचावली सरगारा के बासमची दल का भी सफाया कर दिया गया था। १९२३ में इन जनतंत्रों में शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ। जनगण का दृढ़ यनियना, किसान सभाओं, नौजवान सघ आदि जैसे विभिन्न संगठनों में संगठित करने के काम में काफी सफलता प्राप्त हुई। बुधारा में १९२३ तक ट्रेड-यनियना की सदस्य-संख्या १६५ हजार तक पहुँच गई थी। किसान सभाओं का संगठन भी सफलतापूर्वक किया गया था। प्यारजम में १९२३ में उनके सम्मों की संख्या १० हजार थी।** जनसाधारण अधिनायक समाजवादी विकास की आग आपतित हो रहे थे। पड़ोसी तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र में समाजवादी पुनर्निर्माण के लाभदायक अनुभव न खीवा और बुधारा के लोगों का विश्वास दिला दिया कि उनका जनतंत्र के लिए भी वही मार्ग अपनाया ज़रूरी है।

म० यहाँमान, उपरान्त पुस्तक, पृष्ठ २८०।

*“उदात्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र का इतिहास”, पृष्ठ २, पृष्ठ २१७-२१८।

१९२३ के बाद बुखारा और खोवा की जनता में अपने जनतन्त्रा को समाजवादी जनतन्त्रा में पुनर्गठित करने की इच्छा प्रबल रूप में प्रकट हो रही थी। इस के लिए ज़रूरी शत यह थी कि सत्ता के निवाया का पूरा जनवादीकरण तथा सोवियत संस्याम्रा से शोषक वर्गों के प्रतिनिधियों को निकालकर उनका मुदहीकरण किया जाये। जसा कि हम ने देखा, यह काम इन जनतन्त्रों में सफनतापूर्वक कर लिया गया था।

बुखारा और ख्वारज़्म के जनतन्त्रा ने आर्थिक बहाली के काम में भी काफी सफलता प्राप्त की थी। नई आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो कदम उठाये गये, उनका परिणाम बहुत लाभदायक हुआ था। कपास और खाद्यान्न की फसला के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई। १९२४ में बुखारा में कुल वाश्त की जमीन का क्षेत्रफल लगभग युद्धपूर्व के स्तर पर पहुच गया था। यह ५४,८६,००० तनाब था (१९१३ में इसका आकड़ा ५६,०३,००० तनाब था)। कपास की वाश्त की जमीन में प्रतिवष वृद्धि हो रही थी। १९२० में कपास १,००,००० तनाब जमीन पर उगायी गयी थी, १९२३ में १,३६,००० तनाब जमीन पर और १९२४ में १६०,००० तनाब जमीन पर।* कपास की वाश्त की इस वृद्धि के कारण यह ज़रूरी हो गया कि गहयुद्ध के दौरान जो कपास शोधन कारखाने बंदा हो गये थे, उन्हें तेज़ी से बहाल किया जाये। १९२३ में छह कपास शोधन कारखाने चाल किये गये। सरकार ने पशुपालन, खास कर करानुल भेडा के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये। करानुल भेडें खरोदने के लिए विशेष सहकारी समितियां संगठित की गईं। इन समितियों को २० लाख स्वर्ण रूबल की सहायता दी गई।

ख्वारज़्म में भी अत्यन्त का बहाल कच्चे उसका युद्धपूर्व स्तर तक पहुचान में बहुत प्रगति हुई। कपास की वाश्त का क्षेत्रफल १९२२ में ८ हजार देसियातीन से बढ़कर १९२४ में ३० हजार देसियातीन हो गया।

* द० इशानोव, "बुखारा लोक सावियत जनतन्त्र की स्थापना", ताशकन्द, १९५५, पृष्ठ १६०-१६१। (रूसी संस्करण)

१९२४ के प्रारम्भ तक छह कपास शोधन कारखानों का पुनरुद्धार और विस्तार किया जा चुका था।*

बुधारा और ट्वारज्म में सावियतीकरण और समाजवादी परिवर्तन का जटिल प्रक्रिया और उनका आर्थिक विकास और साथ ही बुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र का आगे विकास मध्य एशिया में सावियत जनता के आर्थिक एकीकरण से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध था। इस सवाल को हल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी (बा०) की केन्द्रीय समिति ने पहले पहल फरवरी १९२९ में उठाया। केन्द्रीय समिति ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार के एकीकरण से ट्वारज्म और बुधारा के अर्थतन्त्र की बहाली और विकास में बड़ी सुविधा होगी। पजीवादी राष्ट्रवादी इसका विरोधी थे। परन्तु उनका विरोध सफल नहीं हो सका। मध्य एशियाई जनतन्त्रों के ताशकन्द आर्थिक सम्मेलन ने तीनों जनतन्त्रों के आर्थिक कार्यक्रमों को एक संयुक्त आर्थिक नीति और समान आर्थिक योजना के आधार पर समन्वित करने का निश्चय किया। सभी आर्थिक मामलों का आम निदेशन मध्य एशियाई आर्थिक परिषद के सिपुद कर दिया गया जिसने आर्थिक सम्मेलन द्वारा तैयार और अनुमोदित आदेशों के अनुसार काम किया। सम्मेलन में भूमि सुधार आदेशों और वैदेशिक व्यापार वित्त, परिवहन, महंगाई, टाक-तार तथा सिंचाई के संबंध में विचारविमर्श किया गया। यह तय किया गया कि बुधारा और ट्वारज्म में एक ही मद्रा चाल का साथ, बड़ी जा पूरे इसी स्वा० सो० स० जनतन्त्र में चालू है। टाक-तार, नवी परिवहन और रेलों का संयुक्त प्रबंध पूरे मध्य एशियाई स्तर पर किया गया। मध्य एशियाई जनतन्त्रों का आर्थिक एकीकरण बुधारा और ट्वारज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे समाजवाद में संक्रमण के काम में उड़ बड़ी सुविधा हुई।

बुधारा और ट्वारज्म में करने उनका अपना अर्थतन्त्र सामाजिक राजनैतिक आधार समाजवादी परिवर्तन के लिए काफी रहा था। मास्को

संघ के समाजवादी उद्योग तथा मजदूर वर्ग के आवश्यक बाहरी आधार मुहैया किया। बुखारा और स्वारज्य लोक सविनय जनतंत्र का स्थापन साविनय संघ के साथ गहरे आर्थिक, मासृतिक और राजनीतिक सहयोग के बिना, साविनय संघ के प्रतिवारी मजदूर वर्ग और किसानों के साथ इन जनतंत्र के लागू की एकता के बिना नहीं सम्भव हो सकता था।

बुखारा लोक सविनय जनतंत्र की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का असाधारण अधिवेशन, जो १४ अगस्त, १९२३ को आयोजित किया गया, उस जनतंत्र के समाजवादी स्थापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सविधान की कई धाराओं में संशोधन करने का निश्चय किया। इन संशोधनों के अनुसार अमीर के सभी भूतत्त्व पदाधिकारियाँ, बड़े साहूकारों और व्यापारियों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार शोषक वर्गों का राजनीतिक सत्ता का भागीदार नहीं बनने दिया गया। मजदूरों और लाल सेना के जवानों के मतदाधिकार का बढ़ा दिया गया। संगठित मजदूरों का १०० मजदूरों पर एक प्रतिनिधि और लाल सेना के जवानों को २५० पर एक व्यक्ति चुनने का अधिकार दिया गया। सभी मंत्रालयों में समितियाँ नियुक्त की गईं जिससे मंत्रियों के लिए मतदान करना असम्भव हो गया।

अक्टूबर १९२३ में चौथी अखिल-स्वारज्य कुरुलताई का अधिवेशन हुआ। उसने नया सविधान स्वीकार किया और स्वारज्य लोक सविनय जनतंत्र के सविनय समाजवादी जनतंत्र में सश्रमण की घोषणा की। सविधान ने एलान किया कि सरकार का मुख्य काम ऐसी स्थितियाँ पदा करना है जिनमें मानव द्वारा मानव का शोषण असम्भव हो जाये। सारी भूमि जनगण की सम्पत्ति घोषित कर दी गई और श्रमजीवी किसानों को मुफ्त ट्रेडमाल के लिए दे दी गई। सविधान ने सभी शोषक वर्गों को मतदाधिकार से वंचित कर दिया। सितम्बर १९२४ में पाचवी अखिल-बुखारा कुरुलताई ने बुखारा में सविनय समाजवादी जनतंत्र की स्थापना घोषित की। उसने सविनय संघ के साथ अटूट और विरादराना एकता बनाये रखने की आवश्यकता की घोषणा की, क्योंकि एकमात्र इसी से समाजवाद का और सश्रमण में सहायता मिल सकती थी। इस प्रकार

बुद्धारा और ख्वारज्म लोक सोवियत जनतन्त्रा का सक्रमण सोवियत राब्त से सोवियत समाजवादी राजत्व मे सम्पन्न हुआ।

समाजवादी अवस्था मे सक्रमण के बारे मे अकसर गलतफहमी पाए जाती है। कुछ लेखका ने कृषि और औद्योगिक सबधों के ढांचे मे पटन से बुनियादी परिवर्तनों के बिना समाजवादी राजत्व मे प्रवेश को गन्त बनाया है। मसलन, अ० ज० पाक ने बुद्धारा और ख्वारज्म का समाजवादी अवस्था मे लान के अभियान का "शब्द" "राजनीतिक स्तर" का अभिप्राय बताया है।* उनके विचार मे यह काम जल्दी मे केवल "राजनीतिक शक्तियों के परस्पर सबध" को ऊपर ही ऊपर बदल कर, यानी 'धारे धीरे धीरे गैर कम्युनिस्ट नेताओं को अलग करके", पहले से काइ चाहे समाजवादी उद्घाटीकरण या कृषि सबधों मे शामिल परिवर्तन किए बिना किया गया।

परन्तु पाक भूल जाते हैं कि समाजवादी राजत्व का काम ही इन परिवर्तनों का लाना है। समाजवादी राज्य ही समाजवादी समाज का निर्माण करता है। इसके अलावा बुद्धारा और ख्वारज्म मे सोवियत दौर मे जो सामाजिक आर्थिक तन्त्रीलियां हुई, उन्हें पाक नजरअन्दा कर रहा है और समाजवादी राजत्व मे सक्रमण की तैयारी मे उनकी भूमिका का महत्व नहीं समझते। किसी राज्य का सामाजिक स्वरूप ठीक इस बात से निर्धारित होता है कि राजनीतिक सत्ता का मालिक कौन है। किसानों के व्यापक बायकलाप और राजनीतिक चेतना मे वृद्धि तथा व्यापारियों और साहूकारों जैसे शापक तत्वों के विरुद्ध उनके निरन्तर संघर्ष की बलवत् इन तत्वों का पार्टी और राज्य निवासा मे निवलना पड़ा। युगपान और उसमान खोजायेव जैसे व्यापारियों के प्रजाय राजनीतिक सत्ता भय देहकाना और धर्मजीवी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों के हाथ मे आ गई, जो अपने जनतन्त्रा का समाजवादी क रास्ते पर चिन्तित करना चाहते थे। इसलिए ख्वारज्म और बुद्धारा के जनतन्त्रा का समाजवादी जनता

* A G Park *Bolshevism in Turkestan 1917-27* New York 1957 pp 107-108

मे सत्रमण ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नम था। उनकी विशेष भौगोलिक स्थिति और इस म अस्तुत्तर प्राति के ऐतिहासिक प्रसंग म उनके लिए सामाजिक विकास की पूजावादी व्यवस्था स गुजरन की जरूरत नहीं रही। इसी मजदूर वग स उनके विमाना की एवता न अपन देशी मजदूर वग की कमी पूरी कर दी।

सोवियत जातीय जनतन्त्रों का निर्माण

१९२४ का जातीय राज्य सीमा निर्धारण — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण १९२४ में किया गया, जिसके फलस्वरूप जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों का निर्माण हुआ। इनमें से दो—उज़बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और तुर्कमान सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण सोवियत संघ के भीतर संघीय जनतन्त्रों के रूप में हुआ। दूसरे जैसे मिसाल के लिए ताजिक, का निर्माण उज़बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के भीतर स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के रूप में हुआ। मध्य एशिया के कज़ाख़ रस्तानों को रूसी सो० म० सं० जनतन्त्र के भीतर उस समय के किर्गिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में एकताबद्ध किया गया। क़रग़न्दाकिया स्वायत्त ओस्तास्त की हैगियत से किर्गिज़ स्वायत्त सो० सं० जनतन्त्र में शामिल हुआ। किर्गिज़ ने स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना की और रूसी सो० म० सं० जनतन्त्र के भीतर क़राकिर्गिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के नाम से शामिल हुए। इन जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों और स्वायत्त ओस्तास्तों में मध्य एशिया का मौलिक जातीयों का उनका जानाया गया का रूप में इतिहास में पहला बार एकताबद्ध किया गया।

तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण, जो रूसी सो० म० सं० जनतन्त्र में शामिल हुआ, मध्य एशिया



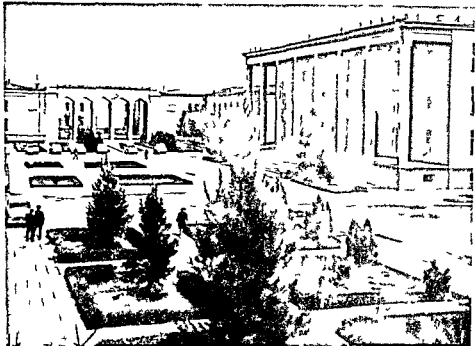
तुक्मान सो० स० जनतन्त्र की
विज्ञान अकादमी अशकाबाद

बज़ाख सो० स० जनतन्त्र की
विज्ञान अकादमी अशकाबाद

१९२४ का जातीय राज्य सीमा-निर्धारण — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

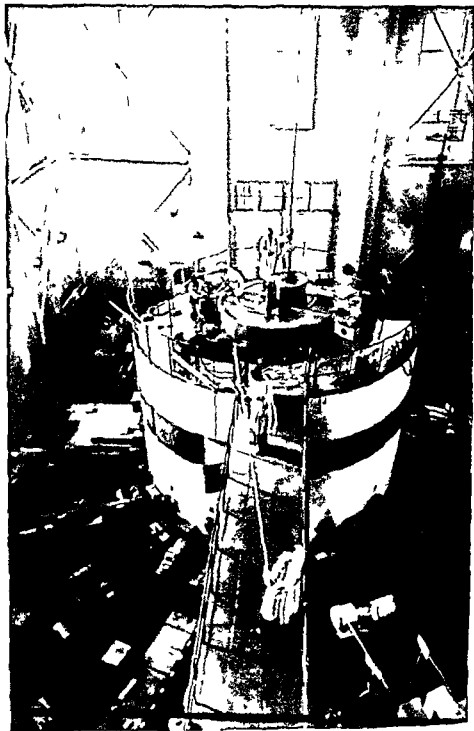
मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण १९२४ में किया गया, जिसके फलस्वरूप जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्रों का निर्माण हुआ। इनमें से दो—उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और तुर्कमान सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण सोवियत संघ के भीतर मध्य जन्तवों के रूप में हुआ। दूसरा जैसे मिसाल के लिए ताजिक, का निर्माण उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के भीतर स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के रूप में हुआ। मध्य एशिया के कजाख स्लावों को रूसी मा० स० स० जनतन्त्र के भीतर उस समय के किगिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र में एकीकृत किया गया। कर्गज़लाकिया स्वायत्त ओब्लास्त की हैमियत में किगिज़ स्वायत्त सा० म० जनतन्त्र में शामिल हुआ। किगिज़ों ने स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना की और रूसी मा० स० स० जनतन्त्र के भीतर कर्गज़किगिज़ स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के नाम से शामिल हुए। इस जातीय सोवियत समाजवादी जनतन्त्र और स्वायत्त ओब्लास्तों में मध्य एशिया की मोर्चा जातियाँ का उनका जातीय राज्यों के रूप में इतिहास में पहला बार एकताबद्ध किया गया।

तुर्किष्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी जनतन्त्र का निर्माण ज़ाक़ाव्ख़ान् रूसी सा० म० स० जनतन्त्र में शामिल हुआ, मध्य एशिया

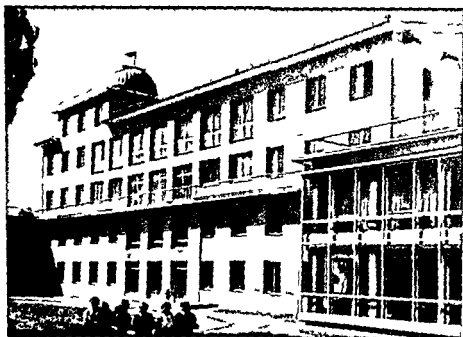
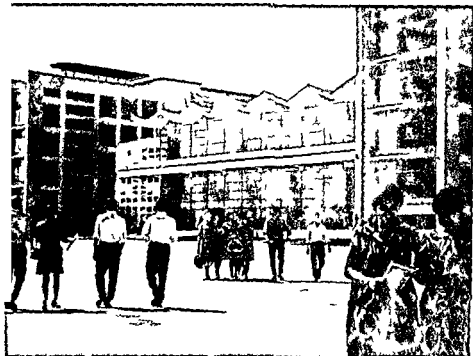


सुकमान सो० म० जनतन्त्र की
विज्ञान अकादमी अशवावाद

कजाख सो० स० जनतन्त्र की
विज्ञान अकादमी, अन्मा-अता

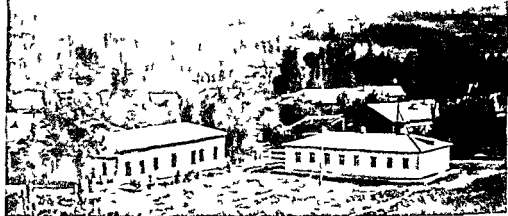


उत्तर मा० म० जनतंत्र की
विज्ञान प्रयोगशाला की नाभिकीय
भौतिकी समीक्षा में परमाणु रिएक्टर

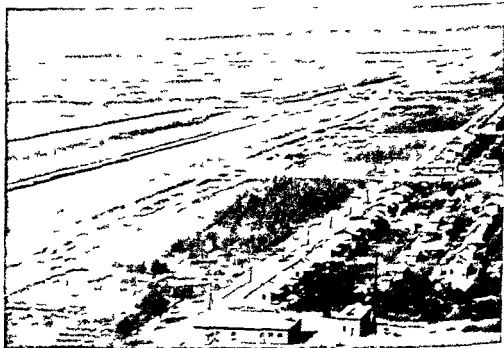


ताशवन्द म लेनिन राजकीय
विश्वविद्यालय

अल्मा अता म युवा पायानियर
तथा छात्र भवन



हिस्सार जिले में ज़दानाब सामूहिक
फार्म ताजिक सा० स० जनतंत्र





बराकूम नहर के तट पर स्थित
बराकूम राजकीय फार्म, तुकमान
सा० म० जनतल



अन्दीवान प्रन्त म गुनवध
 राजकीय काम म बपाम की
 बडा उरवेर गा० म० जनात्र

११
 १२
 १३
 १४



यादगार नसरिहीनोवा, १९५९-१९६० की अवधि में उद्भवेक सो० स० जनतंत्र की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमण्डल की अध्यक्ष

भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खा की मलाकात, ताशकन्द, १९६६।



अलीशेर नवाई उरदुल गजनाय
अलिरा भोर वन पिपटर

त० जनाय दाम तिमि
उरदुल अलिरा तानि भोर
जहग म मारियत मय वा मार
अभारी रनिमा नगराया

के लोगों के सोवियत जातीय राजत्व के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। बहुजातीय स्वायत्त तुकिस्तान जिसका अस्तित्व १९२४ तक रहा, याना जातीय सीमा निर्धारण के समय तक, उस भूतपूर्व जारशाही उपनिवेश में राजकीय ढाँचे का एकमात्र सही और उचित रूप था, जो उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुकूल था। अतः तब जाति के तुरत बाद मध्य एशिया के लोगों के जातीय निर्माण की धीमी प्रक्रिया के कारण विभिन्न जातियों के परस्पर सम्बन्धों की कठिनाइयों के कारण, जो अतीत से चली आ रही थी, और अन्य कारणों से भी जातीय सीमा-निर्धारण असम्भव था।

पहले यह जरूरी था कि अतः तब जाति की उपलब्धियों की रक्षा की जाये और उन्हें सुदृढ़ किया जाये, अदरुनी प्रतिजाति और वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप को निवृत्त देकर सोवियत सत्ता को मजबूत बनाया जाये। इसके अलावा बुखारा और खीवा में जाति १९२० तक नहीं हुई थी और मध्य एशिया में जातीय सीमा के निर्धारण का सवाल बुखारा और खीवा के बिना उठ ही नहीं सकता था। सफलतापूर्वक जातीय सीमा निर्धारण के लिए यह भी जरूरी था कि श्रमजीवी जनता राजकीय बाधकताओं में व्यापक पमान पर भाग ले। जातीय सीमा निर्धारण की एक और शक्ति यह थी कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में तथा समाजवादी जातियों के निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी हो।

जातीय-क्षेत्रीय सीमा निर्धारण योजना, जिसके अनुसार मध्य एशिया में उस समय के बहुजातीय तुकिस्तान, बुखारा और खारखम के बजाय उस इलाके की प्रत्येक मुख्य जाति के लिए अलग जातीय जनतन्त्र का निर्माण किया गया सावियत और गर-सावियत विद्वानों में बहुत बाद-विचार का विषय रही है। कुछ सोवियत-विराधी लेखकों को इस योजना के पीछे सावियत अधिकारियों का 'छत्रकपट और बुरा विचार' दिखाई दिया जिसका उद्देश्य उन लोगों के विशाल बहुमत का, जो "जाति और भाषा की दृष्टि से समरूप" और 'तुर्की' जाति के थे, कृत्रिम रूप से फूट डालकर अलग अलग करना था। उदाहरण के लिए, मुस्तफा चौबायब, जो एक समय कोकान 'स्वायत्त' सरकार के अध्यक्ष थे, इस

योजना को "तुकिस्तान को कन्नायली राज्यो मे विभाजित करन" की योजना बताते है जिसे बोल्शेविका ने इसलिए ईजाद किया था कि "मुसलमान कम्युनिस्टा" द्वारा तमाम तुर्की कबीलो का सोवियत तुकिस्तान के गिद एकताबद्ध करने के प्रयासा का विफल बनाया जाये।* एक हसी उत्प्रवासी विद्वान प्रिस लोवानाव-रोस्तोव्स्की का कहना है कि सीमा निर्धारण की योजना को "नस्ली जातीय गोरख घघे को हल करने की चिन्ता उतनी नही थी, जितनी इस समस्या से उत्पन्न राजनीतिक पहलू की" थी और कि वह केवल बासमची विद्रोह को बोल्शेविका का जवाब था।** अन्य लागा की तजर मे जातीय सीमा निर्धारण की योजना "लडाग्ना और राज करा के पुरान साम्राज्यवादी उसूल" का इजहार थी।*** ह युग सीटन-वाट्सन का जातीय सीमा निर्धारण म यह "स्पष्ट उद्देश्य" निखाई दिया कि "अनक भिन्न भिन जातिया" बनायी जाये जिह एक दूसरे स अनग रखा जा सके, एक दूसरे से लडाया जा सके और अलग अलग रसी जाति से जाडा जा सके"। उनकी राय म, यह इसलिए किया गया कि "मध्य एशिया के मुसलमाना का समुक्त मोरचा" बनन का खतरा दूर हो जाय।****

परन्तु ये दावे सनया पूर्वाग्रह का नतीजा ह और इनम जरा भी सच्चाई नही है। मध्य एशिया के जातीय सीमा निर्धारण का मूल मिद्दात स्वयं वाशिंग्टन जातीय नीति का प्रत्यक्ष नतीजा था। उपयुक्त आरोप लगान का मतनव खूब साची विचारी हुई सोवियत जातीय नीति की मौजूदगी

* Mustapha Chokayev *Turkestan and the Soviet Regime*, —*Journal of Royal Central Asian Society* London XVIII, 1931, p 414

• Lobanov Rostovsky *The Muslim Republics in Central Asia*,—*Journal of the Royal Institute of International Affairs* London 7 (1928) pp 249 50

****The Central Asian Review* London 8 (1960) pp 342-43

• Hugh Seton Watson, *The New Imperialism*, London 1964, Third Impression p 58

और मध्य एशिया की जातीय समस्या की जटिलता से इनकार करना है। जातीय सीमा निर्धारण के विचार का १९२४ में आविष्कार नहीं हुआ। वह बहुत पहले से मौजूद था, मगर केवल १९२४ में उसको कार्यावित किया गया, जब इसके लिए ऐतिहासिक परिस्थितियाँ परिपक्व हो गई। १९१३ में ही लेनिन ने अपनी वृत्ति “राष्ट्रीय प्रश्न के संवध में आलोचनात्मक अभ्युक्तियाँ” में ज़ारशाही रूस के पुराने मध्ययुगीन विभाजनों को बदलने और जहाँ तक हो सके आबादी की जातीय बनावट के अनुसार नये विभाजन कायम करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया था।* १९१३ में रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय समिति ने ‘स्वयं स्थानीय आबादी द्वारा उनके आर्थिक और नस्ली भेद तथा जातीय बनावट, आदि के अनुसार क्षेत्रीय स्वायत्त और स्वशासित इकाइयों की सीमाओं के निर्धारण’ की आवाज़ बुलंद की थी।** अप्रैल १९१७ में पार्टी के सातवें सम्मेलन ने इस पूरी बात की पुनर्पुष्टि की थी।*** जातीय सीमा निर्धारण के सिद्धांत पर उज़्बेकी, बेलो-रूसी, ज़ाज़ियाई, आरमीनियाई, आज़रबैजानी, तातार, बाश्कीर, चुवाश, काश्मिक और याकूती जातीय जनतन्त्रों की स्थापना करके पहले ही अमल किया जा चुका था। परंतु तुर्किस्तान में इस पर अमल नहीं किया जा सका था, क्योंकि वहाँ की स्थिति अधिक पचीदा थी। भिन्न मध्य एशियाई जातियाँ तुर्किस्तान, बुखारा और खोवा के तीन भिन्न राज्यों में घुली मिली हुई थी।

मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण का सवाल सबसे पहले लेनिन ने जुलाई १९२० में तुर्किस्तान जनतन्त्र के संवध में तुर्किस्तान आयोग द्वारा प्रस्तुत मसविदा पर अपनी टिप्पणियाँ में उठाया था। लेनिन ने तथाकथित तुर्की जनतन्त्र की स्थापना के बारे में रिस्क्लाव के राष्ट्रवादी मसविदे को अस्वीकार कर दिया था। निम्न भविष्य में जातीय सीमा

* V I Lenin, *Collected Works*, vol 20 p 48

** “सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव”, १९५४, भाग १ पृष्ठ ३१५। (रूसी संस्करण)

*** वही, पृष्ठ ३४६।

निर्धारण की सम्भावना की परिकल्पना करते हुए उन्होंने तुर्किस्तान का एक नस्ली नक्शा तैयार करने का आग्रह किया जिसमें उज्बेक, किर्गिज और तुर्कमान विभाजन दिखाया गया हो और इन तीनों भागों के वितरण या अलगाव की सहायक परिस्थितियों का आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक किया गया हो।* यद्यपि लेनिन अनेक जातीय जनतंत्रों में तुर्किस्तान के विभाजन के जरिये उसकी जातियों के सावियत जातीय राजत्व के आगे के विकास की प्रवृत्ति के महत्त्व को पूर्णतः समझ रहे थे मगर उन्होंने इस सवाल में जल्दबाजी करने से मना किया। प्रस्तावित सीमा निर्धारण करने से पहले सारी जरूरी तयारियाँ कर लनी थीं।

तुर्किस्तान आयाग न उस क्षेत्र की नस्ली और आर्थिक स्थिति का अनुसार तुर्किस्तान का प्रशासकीय पुनर्विभाजन करने के पक्ष में निश्चय किया था। परन्तु उसने तुर्किस्तान जनतंत्र के इलाके का तुरत कई जातीय जनतंत्रों में बांटने के सुझाव का विरोध किया। ५ जून, १९२० का उसने तार के जरिये अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मंडल और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति को सूचना दी कि इस प्रकार के विभाजन से तुर्किस्तान में अव्यवस्था फैल जायगी और राष्ट्रप्राप्ति तत्वा का अवश्य इसमें मदद मिलेगी। राजनीतिक परिस्थिति के कारण कुछ दिनों तक संयुक्त तुर्किस्तान जनतंत्र का गायब रहना था।** वेक्टर ने जातीय सीमा निर्धारण का स्थगित करने में सहमति प्रकट करते हुए तुर्किस्तान आयाग का आग्रह किया कि इस सवाल में सवध में तयारी का काम जारी रखें। जमा कि ऊपर कहा गया, ये आदेश लेनिन ने जुलाई १९२० में जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार मध्य एशिया में जातीय राज्य सीमा निर्धारण की मातृप्राप्तिपूर्ण तयारियाँ शुरू हुई और उम्मा कार्यवाही करता अथ वेबल समय का सवाल था।

*लेनिन सग्रह, खण्ड ३४ पृष्ठ ३२२-३२६। (रूसी संस्करण)

ख० त० तुगुनाय द्वारा उद्धृत "मध्य एशिया के जातीय राज्य सीमा निर्धारण के बारे में", तात्कालिक, १९५७ पृष्ठ ६। (रूसी संस्करण)

१९२१ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की दसवीं कांग्रेस ने पार्टी का आह्वान किया कि वह अतीत में आरशाही द्वारा उन्पीड़ित गैर-रूसी जातियों की श्रमजीवी जनता की सहायता करे ताकि वह हर तरीके से, जो उसकी जातीय तथा अन्य जीवन स्थितियों के अनुकूल हो, अपने सोवियत राजत्व को विवसित और सुदृढ़ कर सके।* १९२३ में बारहवीं पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर जातीय जनतंत्रों को सुदृढ़ बनाने और आगे निकमित करने की परम आवश्यकता पर जोर दिया।**

तुर्किस्तान बुखारा और ख़वारज़्म की सोवियत सरकारों की नीति ने जातीय विभागा के निर्माण, जातीय स्वायत्त ओब्लास्तों की स्थापना, देशी जातियों की भाषाओं साहित्य तथा अख़बारों के विकास के जरिये जातीय सीमा निर्धारण के लिए ज़मीन तैयार की है। तीनों मध्य एशियाई जनतंत्रों की सरकारों ने इस दिशा में जो कदम उठाये, उनसे विभिन्न जातियों में अपने अपने अलहदा जातीय राजत्व की इच्छा ने जोर पकड़ा। जातीय मामला की जन कमिसारियत ने, जिसकी स्थापना १९१८ में हा गई थी, अपने अतगत उज्बेक, ताजिक, तुर्कमान, किर्गिज़, तातार, आरमीनियाई, उज़्बेक तथा देशी यदूनिया के अलग-अलग विभाग कायम कर लिए थे। ३१ मार्च, १९२१ को तुर्किस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अतगत कज़ाख़ ख़लाको की सुखसमृद्धि का ध्यान रखने के लिए एक अलहदा कज़ाख़ विभाग खोला गया। तुर्किस्तान में जातीय मामला की कमिसारियत को भंग करने के बाद इसके अतगत जातीय विभागों का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के हवाले कर दिया गया और उनकी वही हैसियत थी, जो कज़ाख़ जातीय विभाग की थी। उन जातीय विभागों ने उन लोगों की, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे जीवन स्थिति ससृष्टि और भाषा को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने तुर्किस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का अपनी जातियों की आवश्यकताओं से अवगत

* "सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव", भाग १ पृष्ठ २५६।

** वही, पृष्ठ ७१५।

कराया। तुकिस्तान की जातियाँ के आत्मनिर्णय की तैयारी के लिए अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने अगस्त १९२० में तुकिस्तान केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को यह सुझाव दिया कि वह जातीय बनावट के अनुसार तुकिस्तान के प्रशासकीय जिला के पुनर्विभाजन की योजना बनाये। अगस्त १९२१ में ट्रांसकास्पियन ओब्लास्त का नाम बदलकर तुक्मान ओब्लास्त रख दिया गया, क्योंकि वहाँ तुक्मान जाति के लोग बहुमत थे।* अप्रैल १९२२ में जेतिसुव, सिर-दरिया और फरगाना ओब्लास्तों के किगिज़ बहुमतवाले क्षेत्रों का मिलाकर किगिज़ ओब्लास्त का संगठन किया गया। बुखारा और ख्वास्म की केंद्रीय कार्यकारिणी समितियाँ में तुक्मान और किगिज़ जातीय विभाग कार्य में लिये गये। बुखारा जनतंत्र में चारज़ू को केंद्र मानकर तुक्मान ओब्लास्त बनाया गया। १९२२ में पूर्वी बुखारा, जहाँ ताजिकों का बहुमत था, के प्रशासन के लिए एक विशेष आयोग स्थापित किया गया। अक्टूबर १९२३ में ख्वास्म जनतंत्र में एक तुक्मान और एक करानल्पाक ओब्लास्त संगठित किये गये। उज़्बेक बहुमत के इलाकों को अलग करके नोवा-उरगेंच ओब्लास्त और खोवा रायोन बनाया गया।**

१९२० में किगिज़ (बज़ाख) स्वायत्त सावियत समाजवादी जनतंत्र का निर्माण के साथ जातीय सीमा निर्धारण का सवाल सामने आ गया। अक्टूबर १९२० में तुकिस्तान स्वायत्त सावियत समाजवादी जनतंत्र के ट्रांसकास्पियन ओब्लास्त के उत्तरी भाग का बज़ाख लोग की इच्छा के अनुसार किगिज़ स्वायत्त सावियत समाजवादी जनतंत्र में मिला दिया गया। किगिज़ जनतंत्र की स्वायत्तता के सन्ध में रु० सा० स० स० जनतंत्र का केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा १ गिअम्बर, १९२० का जारी की गई आह्वान की धारा २ में यह प्रवृत्ति थी कि तुकिस्तान स्वायत्त सावियत

* श० ६० मुत्समाचारान "१९२४ में मध्य एशिया का जातीय राज्य सीमा निर्धारण" इतिहास की यात्रा, - 'गोस्सुखान वाश्कास्तान्स्किन १९५४ गण १ पृष्ठ ४४। (अंगी संग्रह)

** यही, पृष्ठ ४६।

समाजवादी जनतन्त्र के विगिज (कजाय) क्षेत्र को इन श्रोम्लास्तो के जनगण को इच्छा के अनुसार विगिज स्वा० सो० स० जनतन्त्र में मिला दिया जाय।* जनवरी १९२१ में तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र में कजाय शरीफो को प्रथम क्षेत्रीय कांग्रेस ने तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतन्त्र में गिर-दरिया और जेतोगुव श्रोम्लास्ता के कजाय इलाका को विगिज स्वा० सो० स० जनतन्त्र में मिला के माग की। मार्च १९२२ में सो० स० म० जनतन्त्र की जातीय भाषला की कमिसारियत में इस सवाल पर विचारविमर्श तथा अप्रैल १९२२ में तुकिस्तान और विगिज स्वा० सो० स० जनतन्त्र में ग्यारहवीं पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह साफ हो गया कि तुकिस्तान स्वा० सो० म० जनतन्त्र के कजाय क्षेत्रों को विगिज स्वा० सो० म० जनतन्त्र में मिलान का सवाल अभिन्न रूप से मध्य एशिया के जातीय सीमा निर्धारण के सामे सवाल से सम्बद्ध है। इस तरह हम देखते हैं कि जातीय सीमा निर्धारण की माग मध्य एशिया की जातियों ने स्वयं बनाने की। सबसे पहले स्थानीय पार्टियाँ तथा अन्य सामाजिक संगठन ने ही इसकी माग की और केन्द्र ने १९२४ में जातीय सीमा निर्धारण करने केवल इस माग की पूर्ति की।

फरवरी १९२४ में जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर बुधारा के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन इस नतीजे पर पहुँचा कि सवाल ज़िम्बुन सुमायियन है। इसके बाद बुधारा कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने २५ फरवरी, १९२४ को अपने पूर्णाधिवेशन में इस प्रश्न पर विचार किया। पूर्णाधिवेशन ने भी इसकी अनुमति दी। मार्च १९२४ में छवारस्म के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भी जातीय सीमा निर्धारण करने के विचार का समर्थन किया। १० मार्च १९२४ को तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति, तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और ताशकन्द के पार्टी तथा सोवियत कार्यकर्ताओं के संयुक्त सम्मेलन ने जातीय सीमा

*इ० खादाराव, "मध्य एशिया का जातीय सीमा निर्धारण"—'नोवी वोस्तोक', १९२५, अंक ८-९ पृष्ठ ६६।

निर्धारण के विचार का पूणत समथन किया। २३-२४ मार्च, १९२४ का तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पूणाधिवेशन ने जातीय सीमा निर्धारण का माग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी।

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल का तय करने में स्टारज्म जनतंत्र में कुछ कठिनाइयां हुई। स्टारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य समिति की कार्यकारिणी समिति ने जिना काई उचित कारण बताए हुए इसका विरोध किया। परन्तु बड़ी हद तक पार्टी के आम सदस्या व समथन के दबाव से स्टारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति का अपना गलत मत बदलना पड़ा। उसने भी स्टारज्म जनतंत्र के जातीय सीमा निर्धारण की आवश्यकता का स्वीकार किया।

१ अप्रैल १९२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रा समिति के पालिटब्यूरो ने मध्य एशिया के जनतंत्रों का जातीय सीमा निर्धारण करने के संघ में मध्य एशिया के पार्टी-संगठनों व मुतावा को मिद्धातत स्वीकार कर लिया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) व मध्य एशिया व्यूरो का आवश्यक तयारिया करने का आन्श दिया। २८ अप्रैल १९२४ का मध्य एशिया व्यूरो ने उज्बेका, तुर्मेना, कजाखा किगिजा और ताजिका के लिए क्षेत्रीय आयाग तथा उप आयाग नियमन दिये। उन्हें यह कार्यभार दिया गया कि जिन जनतंत्रों और ओझास्तों का निर्माण करना है उनमें इनके तय करने सीमा निर्धारण का ध्येयार भी ध्यावित करे।

मई १९२४ में तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस १ भाग सवान पर विचार लिया। इस कांग्रेस में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) की केन्द्रीय समिति व स्टज्म का स्थायी कम्युनिस्ट व विभाग का जातारा शामिल करने व लिए भेजा था। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी व गणित व जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर विस्तारपूर्ण प्रकाश पड़ा। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में गाविया जातीय नीति की तामाज में "यह एक प्रगतिशील काम" है। उक्त में प्रतिनिधियां व रूस जा पर

जोर दिया कि जातीय सीमा निर्धारण स मध्य एशिया की जातियों के अधिक और सांस्कृतिक विकास की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जायेंगी। एक ताजिक प्रतिनिधि सगिजवायेव ने बताया कि अगर यह प्रस्तावित सुधार नहीं किया गया, तो जातीय मतभेदों का कारण समाजवादी निर्माण के काम में बाधा पड़ती रहेगी।* हज़ुताव ने "मन की लहर" के आंदोलन के छतरे से छबरदार किया और पार्टी कायबर्तमा का आवाहन किया कि ऐसे आंदोलन को "स्वस्थ कम्युनिस्ट मार्ग" से विचलित नहीं होने दें।**

जातीय राज्य सीमा निर्धारण व्यवहार में

१० मई, १९२८ का जातीय सीमा निर्धारण आयोग ने जातीय आयोगों की सिफारिशों पर विचार किया। उसने पूर्ण रूप में उज़बेक और तुर्कमान जातीय जनतन्त्रों की तथा ताजिक और किर्गिज सोव्हास्तों की स्थापना का समर्थन किया। उसने तुर्किस्तान के कज़ाख़ इलाक़ों का कज़ाख़ स्वा० सा० सं० जनतन्त्र में मिलान और एक मध्य एशियाई मध्य स्थापित करने के लिए कज़ाख़ जातीय आयोग की सिफारिशों का अस्वीकार कर दिया। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति ने मध्य एशियाई व्यूरो ने जातीय सीमा निर्धारण आयोग की सिफारिशों का रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पास भेज दिया।

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पोलिटब्यूरो ने २ और १२ जून, १९२४ का इन सिफारिशों पर विचार किया। १२ जून को उसने मध्य एशिया के जनतन्त्रों के जातीय सीमा निर्धारण के संबंध में एक प्रस्ताव पास कर निम्नलिखित आता का मुद्दा दिया

१ स्वतन्त्र उज़बेक और तुर्कमान जनतन्त्रों का निर्माण किया जाय और टारख़म जनतन्त्र का, उससे तुर्कमान इलाक़ों को अलग करने के बाद वर्तमान रूप में कायम रखा जाये।

* वही।

** वही, अंक १८१ (४५८), १८ अगस्त, १९२४।

निर्धारण के विचार का पूणत समथन किया। २३ २४ मार्च, १९२४ का तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णाधिवेशन ने जातीय सीमा निर्धारण का भाग के लिए अपनी स्पष्ट अनुमति दी।

परन्तु जातीय सीमा निर्धारण के सवाल को तय करने में स्वारज्म जनतंत्र में कुछ कठिनाइयां हुई। स्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्राय समिति की कार्यकारिणी समिति ने बिना कोई उचित कारण बताय हुए इसका विरोध किया। परन्तु बड़ी हद तक पार्टी के आम सदस्या क समथन के दबाव से स्वारज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति को अपना गलत मत बदलना पडा। उसने भी स्वारज्म जनतंत्र के जातीय सीमा निर्धारण की आवश्यकता को स्वीकार किया।

५ अप्रैल, १९२४ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्राय समिति के पालिटब्यूरो ने मध्य एशिया के जनतंत्रों का जातीय सीमा निर्धारण करने के सवध में मध्य एशिया के पार्टी संगठना के मुचावा को मिद्धातत स्वीकार कर लिया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वा०) के मध्य एशिया व्यूरा को आवश्यक तयारिया करने का आदेश दिया। २८ अप्रैल, १९२४ का मध्य एशिया व्यूरो ने उज्बेको, तुकमाना, बजाया किगिजो और ताजिको के लिए क्षेत्रीय आयोग तथा उप आयाग नियुक्त किये। उह यह कायभार दिया गया कि जिन जनतंत्रा और ओब्लास्तो का निर्माण करना है उनके इलाके तय करके सीमा निर्धारण को व्यवहार में कार्यावित कर।

मई १९२४ में तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की आठवी कांग्रेस ने भा इस सवाल पर विचार किया। इस कांग्रेस में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति ने रुदजुताव को स्थायी कम्युनिस्टा के विचारा का जानकारी हासिल करने के लिए भेजा था। तुकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ने जातीय सीमा निर्धारण के सवाल पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में सावियत जातीय नीति की तामील में "यह एक प्रगतिशील कदम" है।* बहुत से प्रतिनिधिया ने इस बात पर

* 'तुकिस्तानस्काया प्राब्दा अक १०० (३७७) ८ मई, १९२४।

जोर दिया कि जातीय सीमा निर्धारण से मध्य एशिया की जानियों के आर्थिक और मासुविक विकास की सम्माननाएँ बहुत बढ़ जायेंगी। एक ताजिक प्रतिनिधि सगिजरायव ने बताया कि अगर यह प्रस्तावित सुधार नहीं किया गया, तो जातीय मतभेदा के कारण समाजवादी निर्माण के काम में बाधा पड़ती रहेगी। * मद्जुताव ने "मन की लहरा" के आन्दोलन के छतरे से घबरदार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि ऐसे आन्दोलन को 'स्वस्थ कम्युनिस्ट भाग' से विचलित नहीं होने दें। **

जातीय राज्य सीमा निर्धारण व्यवहार में

१० मई, १९२४ को जातीय सीमा निर्धारण आयोग ने जातीय आयोगों की सिफारिशों पर विचार किया। उसने पूर्ण रूप में उद्देश्य और तुक्मान जातीय जनतन्त्रा की तथा ताजिक और किर्गिज ओस्तास्तो की स्थापना का समर्थन किया। उसने तुकिस्तान के कजाख इलाका को कजाख स्वा० सो० स० जनतन्त्र में मितान और एक मध्य एशियाई मध्य स्थापित करने के लिए कजाख जातीय आयोग की सिफारिश का अस्वीकार कर दिया। इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के मध्य एशियाई व्यूरो ने जातीय सीमा निर्धारण आयोग की सिफारिशों को इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पास भेज दिया।

इसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) की केन्द्रीय समिति के पोलिटब्युरो ने २ और १२ जून १९२४ को इन सिफारिशों पर विचार किया। १२ जून को उसने मध्य एशिया के जनतन्त्रा के जातीय सीमा निर्धारण के संबंध में एक प्रस्ताव पास कर निम्नलिखित बातों का मुझाव दिया

१ स्वतन्त्र उज्बेक और तुक्मान जनतन्त्रा का निर्माण किया जाये और खारखम जनतन्त्र को उससे तुक्मान इलाका को अलग करने के बाद, वर्तमान रूप में कायम रखा जाये।

* वही।

** वही अंक १८१ (४५८) १८ अगस्त १९२४।

२ तुकिस्तान के किगिज़ (यानी कज़ाख) इलाकों का किगिज़ (कज़ाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र में मिला दिया जाये।

३ एक स्वायत्त कराकिगिज़ (यानी किगिज़) ओब्लास्त की स्थापना करके उसे रूसी सो० स० म० जनतंत्र में मिला दिया जाये।

४ उज़्बेक जनतंत्र के भीतर ताजिकों का एक अलहदा स्वायत्त ओब्लास्त कायम किया जाये।

५ सोवियत संघ की सोवियता की आगामी कांग्रेस में सोवियत संघ तथा स्वतंत्र तुक्मान और उज़्बेक जनतंत्रों के बीच इन जनतंत्रों के संघ में शामिल होने के बारे में संधि की जाये।*

आगे चलकर एवारज़म भी जातीय सीमा निर्धारण के दायरे में आ गया। एवारज़म की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के कार्यकारिणी ब्यूरो ने २६ जुलाई, १९२४ की अपनी बैठक में एवारज़म के जातीय सीमा निर्धारण के प्रति अपना विरोध का मत बदल दिया।

क्षेत्रीय आयोग ने अपना काम सितम्बर १९२४ में पूरा किया। उस में ममस्त जातियों का समान प्रतिनिधित्व था। १६ सितम्बर, १९२४ को तुकिस्तान की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के असाधारण अधिवेशन ने सीमा निर्धारण के प्रस्ताव पर अपनी कानूनी महर लगा दी और उज़्बेकों, तुक्माना, कज़ाखा, ताजिकों और किगिज़ों को इस जनतंत्र से अलग होने और स्वयं अपना जातीय राजत्व स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। २० और २९ सितम्बर, १९२४ का क्रमशः पाचवीं अखिल-बुखारा और अखिल एवारज़म कुहलताइयो के अधिवेशन ने भी इन जनतंत्रों में रहनेवाली विभिन्न जातियों का यही अधिकार दिया। १७ अक्टूबर १९२४ का अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने तुकिस्तान केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के १६ सितम्बर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और तुकिस्तान स्वा० मो० म० जनतंत्र को रूसी सो० स० स० जनतंत्र से अलग कर

* व० नपोमनिन द्वारा उद्धृत 'उज़्बेकिस्तान में समाजवाद के निर्माण का ऐतिहासिक अनुभव', पृष्ठ १६८-१६९।

दिया।* अखिल रूसी वैद्रीय कायकारिणी समिति ने ताजिक स्वायत्त ओग्लास्त को उज्बेक जनतंत्र के भीतर एक स्वायत्त जनतंत्र का दर्जा देने का निश्चय किया। २७ अक्टूबर १९२४ को सोवियत सघ की वैद्रीय कायकारिणी समिति ने एक परिविधि स्वीकार करके मध्य एशिया के सोवियत जनतंत्रों के जातीय सीमा निर्धारण तथा उज्बेक सो० स० जनतंत्र और तुक्मान सो० स० जनतंत्र के सघ में प्रवेश को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार मध्य एशिया का जातीय सीमा निर्धारण सम्पन्न हुआ। मध्य एशिया की जातियाँ को इतिहास में पहली बार अपने जातीय राज्य के गठन का मौका मिला। यह काम सोवियत सत्ता ने कुल मिलाकर सहज ढंग से कर लिया, यद्यपि अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। पूँजीवादी राष्ट्रवादियों ने स्थिति से फायदा उठाना चाहा। उन्होंने जातीय अघ राष्ट्रवादवाद की भावना को उत्तेजित करने की कोशिश की। उज्बेक पूँजीवादी राष्ट्रवादी ह्वारज़म जनतंत्र को जातीय सीमा निर्धारण से बचाये रखना चाहते थे। इसी प्रकार कज़ाख पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्त्वों ने ताशकंद शहर को उज्बेक जनतंत्र में देने के फैसले को बदलवाने के लिए अभियान करने की कोशिश की। उनकी माँग थी कि पूरे ताशकंद और मिर्जाचुल ज़ेरेदों को कज़ाख स्वा० सो० स० जनतंत्र में मिला दिया जाये। उज्बेक राष्ट्रवादियों की उलट इच्छा यह थी कि सिर-दरिया ओग्लास्त के उन शहरों को जहाँ उज्बेकों की बड़ी आबादी थी स्वायत्त शहरों के रूप में संगठित किया जाये। याद रहे कि चिमकंद और तुकिस्तान शहरों में उज्बेकों का बहुमत था परंतु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कज़ाख बहुमत में थे।

१९२४ में मध्य एशिया की परिस्थितियों में इस प्रकार के जातीयवाद विवाह का उत्पन्न होना विल्कुल स्वाभाविक था। प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी तत्त्वों का यद्यपि राजनीतिक दमन और किसी हद तक आधिक्य तौर पर उन्हें कमजोर कर दिया गया था परन्तु वे उस समय तक पूरी तरह लुप्त नहीं हुए थे। भूतपूर्व शोषक वर्गों को उचित मौकों का इंतज़ार था।

* व० नेपोमनिन द्वारा उद्धृत, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६८-१६९।

भूमि सुधार अभी पूरा नहीं हुआ था और कृषि का मामहिकीकरण और ममाजवादी उद्योगीकरण अभी शुरू नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पूँजीवादी राष्ट्रवादी तत्व कभी कभी पार्टी में घुस आने में सफल हो जाते थे। परन्तु पार्टी और सोवियत सरकार के लिए यह बात श्रेयस्कर है कि राष्ट्रबान्धु तत्वों को कभी यह मौका नहीं दिया गया कि विभिन्न जातीय समूहों में घणा की आग भड़काए और हिमा और मारकाट का बाजार गम करे। तुकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता में फट डालने की पूँजीवादी राष्ट्रवादियों की कोशिशों को विफल करने के लिए जातीय सीमा निर्धारण की योजना के उसूलों के बारे में जनगण को शिक्षित करने के लिए जन अभियान चलाया। जातीय सीमा निर्धारण पर अपने थीसिस में पार्टी ने कहा

“मध्य एशिया की श्रमजीवी जनता को सीखना चाहिए कि अलहदा स्वतन्त्र सोवियत जनतन्त्रों का निर्माण हमारे सामने अंतिम राष्ट्रीय कार्यभार और ध्येय नहीं पेश करता किसी जाति की श्रमजीवी जनता के जातीय अलगाव और अलहदगी तो और दूर की बात है। जातीय दुश्मनी नहीं, बल्कि सहकारा अंतराष्ट्रीयवाद नये जनतन्त्रों के भावी काम का आधार है। जो कोई उलटी बात सोचता है, वह जान या अनजान मजदूरों और किसानों की सत्ता का दुश्मन है।”*

जातीय सीमाओं का निर्धारण कोई आसान काम नहीं था। जातीय सीमा निर्धारण आयोग को अनक विवादोत्पन्न इलाकों की जातीय बनावट का अध्ययन करने और वहाँ के जनगण की रूढ़ि मालूम करने के लिए उन जगहों पर जाना पड़ा। सोवियत जातीय जनतन्त्रों और स्वायत्त ओब्लास्तों के क्षेत्रों और सीमाओं का निर्धारण करने में जातीय तत्व निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण था। जातीय राज्य संरचना में उन इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया गया जहाँ एक जातीय समूह के लोग गठित रूप में रहते थे। परन्तु जातीय तत्व के अलावा जातीय जनतन्त्रों में गठित

*ख० त० तुसूनोव द्वारा उद्धृत, “मध्य एशिया के जातीय राज्य सीमा निर्धारण के बारे में” पृष्ठ १८।

इलाके या स्वायत्त ओग्लास्त की जीवन-मद्दिनि तथा आधिक्य अपडना का भी ध्यान रखा गया। लेनिन न अपनी वृत्ति "राष्ट्रीय प्रश्न पर आलाचनात्मक भ्रम्भुनितया" म जहा तब सम्भव हो आवादी की जातीय वनावट के अनुसार क्षेत्र व विभाजन की आवश्यकता पर जोर देने हुए, यह भी कहा है कि अगरचे आगामी की जातीय वनावट अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है, मगर यह एवमात्र तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है, उसके अतिरिक्त और भी कारण है।

मध्य एशिया म जातीय सीमा निर्धारण करते समय लेनिन के इस कथन का पालन किया गया। बड़ा जातीय जनतन्त्रा और स्वायत्त ओग्लास्तों का निर्माण गठित जातीय इनाका के आधार पर किया गया, परन्तु ऐसे अलग अलग इलाके जहा एक जातीय समूह का बहुमत था मगर जो आधिक्य या भौगोलिक दृष्टि म दूसरे जातीय समूह के क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे (जैसे सिर-दरिया ओग्लास्त के बजार्ख इलाके में उर्दूक शहर) उन्हें आम तौर पर इन्हीं म मिला लिया गया। कई ताजिक इलाका का घनिष्ठ आधिक्य और मास्त्वितिक सन्ध्या के कारण उर्दूक जनतन्त्र म मिला दिया गया।

जातीय सीमा निर्धारण के कारण मध्य एशिया म भूतपूर्व तीन बहुजातीय राज्या के स्थान पर अनेक एकजातीय राज्य कायम हो गये। इससे जटिल जातीय गुत्थी को सुलझाने में काफी आसानी हुई, जो समाजवादी विकास के रास्ते म बाधा बनी हुई थी। पुरानी राजनीतिक और प्रशासकीय सीमाएँ बँकल जागरणाही विजय के समय के सैनिक, सामरिक तथा राजनीतिक उद्देश्या का नतीजा थी। और इस कारण उनसे जातीय समस्या और विगडती जाती थी। पुरानी सीमाएँ मध्य एशिया के जनगण के जातीय विभाजन का काटती चलती थी और तुकिस्तान, बुखारा और छोवा के पुराने शासन उनका इस्तेमाल करके अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक जातीय समूह का दूसरे से लडाया करते थे। जातीय सीमा निर्धारण से यह स्थिति बदल गई और जातीय शत्रुता का वह आधार ही खिसक गया, जिसपर पूँजीवादी राष्ट्रवादी हमशा पनपते थे।

अगर १९२४ के सीमा निर्धारण से पहले उज्बेको का बड़ा भाग, यानी ६६५ प्रतिशत तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र में रहते थे, मगर उस जनतंत्र की कुल जनसंख्या में उनका अनुपात केवल ४१४ प्रतिशत था, तो सीमा निर्धारण के बाद मध्य एशिया के कुल उज्बेको का ८२६ प्रतिशत उज्बेक सा० स० जनतंत्र में आ गया जहाँ उनका बहुमत बना—७६१ प्रतिशत। जानीय सीमा निर्धारण से पहले तुक्माना का मध्य एशिया के तीनो जनतंत्रों में से किसी में भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, मगर अब कुल तुक्मानो में ९४२ प्रतिशत तुक्मान सो० स० जनतंत्र में आये और जनतंत्र की कुल जनसंख्या में वे ७१९ प्रतिशत थे। इसी प्रकार ताजिक, जो तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की आबादी का ७७ प्रतिशत और बुखारा जनतंत्र की आबादी का ३१ प्रतिशत थे, उज्बेक सो० स० जनतंत्र के भीतर ताजिक स्वा० सो० स० जनतंत्र में आबादी का ७१२ प्रतिशत थे। मध्य एशिया के समस्त ताजिकों में ७५२ प्रतिशत ताजिक स्वा० सो० स० जनतंत्र में आ गये थे जिसे १९२९ में सघीय जनतंत्र का दर्जा दे दिया गया। किर्गिज, जो तुकिस्तान स्वा० सो० स० जनतंत्र की आबादी में केवल १०८ प्रतिशत थे, रूसी सो० स० स० जनतंत्र के भीतर नव संगठित कराकिर्गिज स्वायत्त ओब्लास्त की आबादी का ६६ प्रतिशत थे। मध्य एशिया के सभी किर्गिजों का ८६७ प्रतिशत अब इस स्वायत्त जातीय ओब्लास्त में था जिसे १९२६ में किर्गिज स्वा० सा० स० जनतंत्र बना दिया गया। १९३६ में उस एक सघीय जनतंत्र का दर्जा दे दिया गया। कराकल्पाका में ७९३ प्रतिशत अब किर्गिज (कजाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र के भीतर कराकल्पाक स्वायत्त ओब्लास्त में शामिल थे, जहाँ कुल जनसंख्या में उनका एक खासा बड़ा हिस्सा था—३८१ प्रतिशत। १९३२ में कराकल्पाक स्वायत्त ओब्लास्त का रु० मा० स० स० जनतंत्र के भीतर कराकल्पाक स्वा० सो० स० जनतंत्र बना दिया गया। १९३६ में वह एक स्वायत्त जनतंत्र के रूप में उज्बेक सा० स० जनतंत्र में शामिल हो गया। रु० सो० स० स० जनतंत्र के भीतर किर्गिज (कजाख) स्वा० सो० स० जनतंत्र में सभी कजाखा का ९३४ प्रतिशत शामिल थे, जो इस

जनतन्त्र की जनसंख्या में ५७४ प्रतिशत थे। १९३६ में वज़ाख स्वा० सो० स० जनतन्त्र को भी सघीय जनतन्त्र बना दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जातीय सीमा निर्धारण के बाद मध्य एशिया का जातीय नक्शा ज्यादा 'यायोचित' हो गया। पुरानी जातीय अमगितिया को दूर करके मध्य एशिया की जातीय समस्या का बेहतर हल ढूँढ़ निवाला गया। इससे जनगण को प्रशासन के अधिक नज़दीक लाकर मध्य एशिया की जातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जल्दी दूर करने का स्थायी आधार तैयार हुआ। इससे प्रशासन का अधिक जनवादीकरण और अधिक विकास तथा सांस्कृतिक प्रगति की रफ्तार बहुत तेज हो गई। इसने पज़ीवादी राष्ट्रवाद और महाशक्तिवादी अधराष्ट्रवाद की जड़ों पर घातक चोट पहुँचाई। विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति को सुनिश्चित करके इसने सोवियत संघ की जातियों के बीच मैत्री और भ्रातृत्व का प्रोत्साहित किया। जातीय संघर्षों का आधार खत्म करके उसने मध्य एशिया की जातियों को समाजवाद के निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में शामिल होने के योग्य बना दिया। संक्षेप में, जहाँ तक मध्य एशिया की जातियों की प्रगति और सुख-समृद्धि का संबंध है, जातीय सीमा-निर्धारण के परिणाम पूणतः सकारात्मक और लाभदायक थे।

मध्य एशिया में १९२४ में जातीय राज्य सीमा निर्धारण हुआ, उसका विश्वव्यापी महत्त्व था, खासकर पूर्व के उन देशों के लिए, जिनके सामने औपनिवेशिक जूए से मुक्ति पाने के बाद अपने प्रशासकीय विभाजनों के पुनर्गठन का सवाल खड़ा हुआ था। भारत भी ऐसा ही एक देश था, जहाँ प्रशासकीय पुनर्गठन का सवाल ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक हो गया था। ब्रिटिश शासन-काल का देश का पुराना प्रशासकीय विभाजन औपनिवेशिक कब्जे और उसके दमनकारी पदावली का और जनसाधारण की इच्छा के विपरीत था।

मध्य एशिया का ऐतिहासिक अनुभव इस बात का सबूत है कि भारत में भी अपने आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो कदम उठाये गये, वे सही थे।

आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन

समाजवादी उद्योगीकरण

सावियत सरकार ने सोवियत संघ की जातियाँ में वास्तविक समानता स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। यह एक बहुत कठिन और जटिल कार्य था। वास्तविक समानता कैसे हो सकती थी, जब मध्य एशिया के सावियत जनतंत्रों के पास अभी अपना कोई उद्योग नहीं था, जब उनकी वृत्ति बहुत पिछड़ी हुई थी और लोग अनपढ़ थे?

पार्टी की दसवीं कांग्रेस (१९२१) ने विभिन्न जातियों के बीच वास्तविक असमानता के उन्मूलन का उद्देश्य अपने सामने रखा। पार्टी को गैर-रूसी जातियों की श्रमजीवी जनता की सहायता करनी थी ताकि वे सफलतापूर्वक मध्य रूस के स्तर तक पहुँच जायें। बारहवीं कांग्रेस (१९२३) ने भी पिछड़ी हुई जातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर को उँचा करके जातियों के बीच असमानता को दूर करने का आह्वान किया। इस भारी आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को मिटाने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने की और बड़ी सच्चा में अत्यंत निपुण विशेषज्ञों की जरूरत थी। इतना बड़ा काम इतिहास की एक छोटी सी अवधि में केवल अधिन उन्नत रूसी जनगण की निरादराना सहायता से होना ही सकता था। मध्य एशियाई जनतंत्रों की सहायता नाना प्रकार से—राजनीतिक, वित्तीय, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में—समाजवादी निमाण की प्रक्रिया में की गई। इस सहायता का मतलब यह था कि रूसी जनगण का बुढ़ानियाँ दनी और कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि दश उस समय तक गरीब था और

उन्नत पूजीवादी देशों की तुलना में आर्थिक दृष्टि में काफी कमजोर था। परंतु अपना अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करने के लिए हमी मजदूर वगैरह इस कुर्बानी के लिए तैयार था।

मध्य एशियाई जनतन्त्रा की सावियत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता उनके आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे भी साल हुए हैं, जब कुछ जनतन्त्रा को उनके खर्च का ८०-९० प्रतिशत सघ से आर्थिक सहायता के रूप में मिला। मध्य एशिया की औद्योगिक उद्यमा और कृषि के लिए तकनीकी सामान और मशीनें भी दी गईं। अनेक अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता और अग्र विरोधन भी रूस से मध्य एशिया भेजे गये। यह उदार सहायता "गरीब रिश्तेदारों" को अपमानजनक दान नहीं थी। मध्य एशिया के जनगण ने जितनी ही आर्थिक प्रगति की उतना ही अधिक उन्होंने सोवियत सघ के समाजवादी निर्माण में योगदान किया। मध्य एशिया में कपास की पैदावार में वृद्धि हुई, तो सोवियत सघ को बाहर से उसके आयात की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। तुकमान सा० स० जनतन्त्र में तेल तथा तेल की वस्तुआ का उत्पादन तेजी से बढ़ा जा द्रुतगति से विकास करनेवाले सोवियत उद्योग के लिए आवश्यक था। सोवियत जनतन्त्रा में सबसेतुमुखी परस्पर-सहायता और सहयोग से उनकी अममानता को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने और उनकी मैत्री को सबल बनाने में सहायता मिली। सोवियत सघ की जातिया की इस मैत्री और भ्रातृत्व की ताजी मिसाल ताशकन्द को दी गई वह उदार सहायता है, जो अप्रैल १९६६ के भयकर भूचाल के बाद देश के कोने-कोने से उमड़ पड़ी। विभिन्न सावियत जनतन्त्रों से हजारों स्वयंसेवकों ने उज्बेकिस्तान की राजधानी में नये घरों का निर्माण किया। विरादराना जनतन्त्रा ने ताशकन्द में दस लाख वर्ग मीटर गृह निर्माण किया है।

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की तरह समाजवाद के लिए भी एक निश्चित स्तर की उत्पादन शक्तिया की एक निश्चित भौतिक तथा तकनीकी आधार की जरूरत थी। समाजवाद के लिए यह आधार बड़े पैमाने का भारी उद्योग है, जो कृषि को मशीनें तथा खाद मुहैया कर सके। बड़े पैमाने के उद्योग के बिना समाजवाद का निर्माण असम्भव है। अतः समाजवादी

अथर्व्यवस्था का निर्माण करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश को सबसे पहले उद्योगीकरण करना होता है।

जैसा कि कहा जा चुका है, आति से पहले मध्य एशिया का उद्योग बहुत अविकसित था। और फिर गहयुद्ध में उसका बड़ा नुकसान पहुँचा। १९२८ में ही उद्योग को उसके आतिपूर्व स्तर पर पुन बहाल किया जा सका।* कृषि की बहाली में भी बड़ी सफलताएँ प्राप्त हुई। कपास की खेती को उसके युद्धपूर्व स्तर पर पूणत पुन स्थापित करने का लक्ष्य १९२७ में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कपास की खेती का कुल क्षेत्र १९१३ में ४२३ ५ हजार हेक्टर था। १९२८ में वह युद्धपूर्व के स्तर से बढ़कर ५८८ ५ हजार हेक्टर तक पहुँच गया था।**

मध्य एशिया के श्रमजीवी जनगण ने १९२६-१९२७ में अपने जनतंत्र का उद्योगीकरण शुरू किया। मार्च १९२७ में उज्बेक सो० सं० जनतंत्र में सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने सूती कपड़ा उद्योग का निर्माण, कृषि कच्चा सामान को तैयार करने के उद्योग की नई शाखाओं का संगठन, बिजलीकरण की योजना की पूर्ति और कृषि मशीना और औजारों का उत्पादन का संगठन करना जरूरी समझा। १९२७ में उज्बेकिस्तान के उद्योगीकरण की दिशा में प्राथमिक कदम उठाये गये। उस साल कई

* कपास ओटाई उद्योग, जो मध्य एशिया का मुख्य उद्योग था, बहाली की अवधि के अंत में अपने युद्धपूर्व स्तर से कुछ पीछे था (१४७ ९ हजार टन जबकि १९१३ में १७७ ८ हजार टन था)। परन्तु तेल और बिजली के उत्पादन में वृद्धि सतोपजनक थी। १९१३ में तुर्किस्तान में तेल का उत्पादन १३२ हजार टन था। १९२७ १९२८ में वह बढ़कर ४७७ हजार टन हो गया, यानी युद्धपूर्व स्तर से ३५ गुना अधिक। बिजली का उत्पादन १९२३ में ३३ लाख किलोवाट घंटे था, वह बढ़कर १९२७ १९२८ में ३४३ लाख किलोवाट घंटे हो गया। ("उज्बेकिस्तान १५ वर्षों के दौरान", ताशकंद, १९३८, पृष्ठ ३७ ३९, रूसी संस्करण) ह्योलर का यह कथन कि "मध्य एशिया के उद्योग का उत्पादन (१९२८ में) सब मिलाकर १९१३ के स्तर का लगभग आधा था" स्पष्टतः गतत है और स्थिति को कम करके आकता है (उपरोक्त पुस्तक, पृ० १५९)।

** "उज्बेकिस्तान १५ वर्षों के दौरान", पृष्ठ ५३।

आधिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन २७५

विजलीघरो का निर्माण हुआ। मंगिलान और पुराने बुधारा में रेशमी कपड़े की फैक्टरिया लगाई गई। फरगाना में एक बताई-बुनाई फैक्टरी और ताशकंद में जूते और तम्बाकू फैक्टरिया खोली गई। तेल निस्सारण में भी कुछ प्रगति हुई। भारी उद्योग के विकास के लिए अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा थी।

१९२७-१९२९ के बीच किर्गिजस्तान के उद्योगीकरण के लिए भी कुछ कदम उठाये गये। इस अवधि में निजिल किया और सुलूक्तह कोयला खदानों का विस्तार किया गया, करासुब में एक कपास शोधन कारखाना, ओश में एक रेशम फैक्टरी तथा फ्रूजे में दो चमड़े की फैक्टरिया कायम की गई। दो आरा मिले भी खोली गई। इन कारखानों के निर्माण के बावजून किर्गिजस्तान में १९२९ में औद्योगिक पैदावार का कुल मूल्य केवल २ करोड़ ६० लाख रबल था जबकि १९१३ में २ करोड़ ८० लाख था।* किर्गिजस्तान के वास्तविक उद्योगीकरण के लिए भी अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना का इंतजार था।

तुर्कमानिस्तान में रेशम-वटाई बुनाई और कताई फैक्टरियों का अशकाबाद में निर्माण किया गया। लगभग उसी समय तुर्कमान सो० स० जनतंत्र के साधना का भगर्भीय सर्वेक्षण शुरू किया गया। तुर्कमान मजदूरों के आधुनिक औद्योगिक उत्पादन में प्रशिक्षण का कार्य तात्कालिक महत्त्व का था, क्योंकि जनतंत्र में उसके अपने देशी औद्योगिक कर्मियों का बड़ा अभाव था। १९१६ में केवल २४२ तुर्कमान मजदूर थे जिनमें ७ दक्ष मजदूर थे।** इस कमी को पूरा करने के लिए तुर्कमान सूती मिलों और तेल कारखाना के मजदूरों को क्रमशः मास्को और बाकू में प्रशिक्षित किया गया।

ताजिकिस्तान में उद्योगीकरण प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ। उससे पहले १९२४-१९२५ में कुछ तेल मिला और विजलीघरा का निर्माण किया गया था।

* 'सोवियत संघ में समाजवादी जाति का निर्माण', मास्को १९६२, पृष्ठ ४९६। (रूसी संस्करण)
** वही, पृष्ठ ५९७।

मध्य एशिया में उद्योगीकरण का प्रथम महत्वपूर्ण चरण प्रथम पंचवर्षीय योजना ही से शुरू हुआ। पार्टी की चौदहवीं कांग्रेस ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए अपने निदेश में इस बात पर जोर दिया था कि योजना में पिछड़े हुए इलाकों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का सवाल पर खास ध्यान देना चाहिए।* प्रथम योजना मध्य एशिया में वास्तविक औद्योगिक गति की शुरुआत साबित हुई।

नवम्बर १९२७ में उज़बेकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। उसने उज़बेकिस्तान के विकास की योजना पर सम्पूर्ण सोवियत संघ की योजना के एक आवश्यक अंग के रूप में विचार किया। प्रथम योजना का एक मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के वस्त्रोद्योग के लिए कपास में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना ने उज़बेकिस्तान में कोयला और तेल उद्योगों के विकास की ओर बहुत ध्यान दिया। उसने मध्य एशिया में एक धातुकर्म-उद्योग के निर्माण पर भी जोर दिया। कृषि की पैदावार के उपयोगीकरण से संबंधित अन्य उद्योगों की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। उज़बेकिस्तान के लिए योजना का पहला प्रारूप जून १९२८ में तैयार हुआ। दूसरा संशोधित प्रारूप मई १९२९ में उज़बेकिस्तान की सोवियत की तीसरी कांग्रेस में बहस के लिए पेश किया गया। तीसरा और अंतिम प्रारूप जुलाई १९२९ में केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन द्वारा स्वीकृत हुआ।

उज़बेक सो० सं० जनतंत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारी रकम लगाई गई। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास के लिए २,८८४ लाख रूबल की रकम दी गई, जो जनतंत्र की योजना के अन्तर्गत कुल पूँजी विनियोग का २६ प्रतिशत थी। इससे पहले के चार वर्षों (१९२४-१९२८) की तुलना में वह छह गुना ज्यादा था।**

* "सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव", भाग २, पृष्ठ ३४३।

** श० न० उरमस्वायेव, 'सोवियत उज़बेकिस्तान का औद्योगिक विकास', ताशकन्द, १९५८, पृष्ठ १०८। (रूसी संस्करण)

उज्बेकिस्तान में उस योजना के अंतर्गत जा पूजी लगाई गई, उसका बड़ा हिस्सा केन्द्र ने दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उज्बेकिस्तान के औद्योगिक विकास का तात्क्षणिक पहलू बिजली-उत्पादन, मशीन निर्माण तथा धातुकर्म-उद्योग का विकास था। ताशकन्द में एक कृषि मशीनरी कारखाना बनाया गया, जो जनतंत्र में कृषि, खासकर कपास की खेती की जरूरत की मशीनें तथा अन्य सामान मुहैया करता था। कृषि मशीनों की मरम्मत के लिए भी एक कारखाना खोला गया। आल्मालीक ताम्र प्रोसेसिंग प्लांट तथा चिरचिक रासायनिक कारखाने का निर्माण भी प्रथम योजना के ही दौरान हुआ। दूसरी योजना में उनका आगे विकास हुआ और वे अखिल-संघीय महत्त्व के विशाल औद्योगिक उद्यम बन गये। प्रथम योजना के दौरान दो सीमेंट फैक्टरिया भी कायम की गईं। १९३२ में ताशकन्द में एक बड़ा सूती कपड़ा कारखाने का निर्माण शुरू हुआ। बुखारा, फरगाना और मगिलान में रेशम बाटने और कातने की कई फैक्टरिया कायम की गईं। इनके अलावा फल और साग सब्जी की डिब्बाबंदी के भी कई कारखाने खोले गये। १९२८-१९३० की अवधि में खाद्य-पदार्थ उद्योग की कुल पैदावार के मूल्य में २३ गुना, सूती कपड़ा उद्योग में ५६ गुना और रेशम उद्योग में ५४ गुना वृद्धि हुई।*

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उज्बेक सो० सं० जनतंत्र ने समाजवादी उद्योगीकरण में बड़ी सफलता प्राप्त की। जबकि केन्द्रीय इलाका में तो दो गुना वृद्धि हुई उज्बेकिस्तान में औद्योगिक पैदावार २६ गुना बढ़ी।

ताजिकिस्तान में प्रथम योजना के दौरान मुख्यतः ऐसे उद्योगों का निर्माण हुआ, जिनका संबंध कृषि की पैदावार के विधायन के पहले चरण से था यानी कपास की सफाई, फल और सब्जी की डिब्बाबंदी और रेशम बाटने की फैक्टरिया कायम की गईं। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास में केवल ०० प्रतिशत पूजी लगाई गई और कृषि में ५० प्रतिशत।**

* श० न० उत्तमस्वायेव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १२३।

** "सावियत संघ की समाजवादी जाति का निर्माण", पृष्ठ ५३२।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किर्गिजस्तान में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई। प्रथम योजना के अंतर्गत किर्गिजस्तान के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ७७ ७५१ हजार रूबल की रकम लगाई गई। इसमें से आधी से ज्यादा यानी ४०,८७८२ हजार रूबल भारी उद्योगों में लगाये गये।* ४१ बड़े औद्योगिक उद्यमों का निर्माण किया गया। १९३२ में औद्योगिक उत्पादन का अनुपात कुल उत्पादन का २३.५ प्रतिशत हो गया था।** किर्गिजस्तान में औद्योगिक पैदावार १९२९ की तुलना में चार गुना और १९१३ की तुलना में ६१ गुना बढ़ गयी।***

तुर्कमानिस्तान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सूती कपड़ा, रासायनिक तथा खाद्य उद्योगों का निर्माण हुआ। योजना में जनतंत्र की अथर्वव्यवस्था में २७,०८ लाख रूबल पंजी लगाने का प्रबंध था।**** यह रकम १९२५-१९२८ की अवधि के पूँजी विनियोग की चौगुना से अधिक थी। कपास की सफाई, सूती कपड़ा, तेल और रेशम की फ़ैक्टरियाँ तथा कृषि की पैदावारों के प्रथम विधायन से संबंधित अन्य उद्योगों का व्यापक पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। योजना ने तेल रासायनिक तथा निर्माण वस्तुओं के उद्यमों जैसे भारी उद्योगों की आधारशिला रखी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कालीन बुननेवाली स्त्रियों का औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में संगठित किया गया और हर सम्भव तरीके से उनकी तकनीकी और वित्तीय सहायता की गई।

* "किर्गिजस्तान का इतिहास", खण्ड २, फ़ूजे १९५६, पृष्ठ १७१। (रूसी संस्करण)

** "किर्गिजस्तान सावियन सत्ता के ३० वर्षों की अवधि में" फ़ूजे, १९४८, पृष्ठ ३७। (रूसी संस्करण)

*** म० लि तुनोम्बाया, "किर्गिज सा० स० जनतंत्र का बजट और आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास", फ़ूजे, १९५८, पृष्ठ ११। (रूसी संस्करण)

**** "तुर्कमान सा० स० जनतंत्र का इतिहास" अशाकावाद, १९५७, खण्ड २, पृष्ठ ३१५। (रूसी संस्करण)

मध्य एशियाई जनतंत्रों में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सफलतापूर्वक पूरा किया गया। योजना के दौरान रुम के वैदेशीय ऋणों की तुलना में यहाँ के औद्योगिक विकास की रफ्तार ज्यादा तेज थी। अगर प्रथम योजना के दौरान पुर्गने औद्योगिक इलाकों में औद्योगिक पैदावार का गुना बढ़ी, तो जातीय जनतंत्रों में वृद्धि की दर ३५ गुना थी।* योजना के दौरान सोवियत जनगण न समाजवादी प्रतियोगिता में बड़ी सफलता में आम मजदूरों की शिरकात के जरिये श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जनगण के तकनीकी और साम्प्रतिक स्तर का सुधारने की हर कोशिश की गई। पार्टी और ट्रेड-यूनियनों के बड़े प्रयत्न के फलस्वरूप आविष्कारकों के आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। केंद्र ने मध्य एशियाई जनतंत्रों के उद्योगीकरण में बड़ी सहायता प्रदान की। उन्हें अत्यंत दक्ष विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करायी गईं और इसका अलावा ताश्कंद टेक्स्टाइल मिल, चिरचिक विजली रासायनिक कारखाने जैसे विशाल औद्योगिक उद्यमों तथा कई बड़े विजलीघरों के निर्माण के लिए धन सघीय बजट से दिया गया था। जाहिर है कि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पित पूँजी विनियोग के कारण मध्य एशिया के जातीय जनतंत्रों के बजटों में भयंकर घाटे की पूर्ति करना उनके बूते और साधनों में बाह्य की बात थी। १९२६-१९२७ में यानी प्रथम योजना की पूर्ववर्ती के वर्ष में उर्बेक सो० सं० जनतंत्र के बजट में तीन करांड रूबल का घाटा था। १९२४-१९२८ के दौरान उर्बेक सो० सं० जनतंत्र को १० करोड रूबल तुल्यमान सो० सं० जनतंत्र को सात करांड रूबल और किर्गिजस्तान का तीन करांड रूबल से अधिक खर्च इन जनतंत्रों के घाटे की पूर्ति के लिए सोवियत संघ के सोवियतखोज के बजट से दी गई।** ताजिकिस्तान में प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ४३५ करोड रूबल पूँजी मधीय बजट से लगायी गई।***

* "सोवियत संघ के अर्थतंत्र के विकास की प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम" मास्को १९३३, पृष्ठ २३६। (रूसी संस्करण)

** "अ० अ० गादियेंको, "मध्य एशिया में सोवियत जातीय राज्यों की स्थापना", पृष्ठ २२३।

*** वहीं, पृष्ठ २२६।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२ अरब रुबल (प्रथम योजना की २२ गुनी) रकम उज्बेक सो० स० जनतंत्र की अथर्व्यवस्था में लगायी गई।* योजना के अंतर्गत कुल पूँजी विनियोजन का ४६ प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिए अलग कर दिया गया था (प्रथम योजना में यह २६ प्रतिशत था)। उज्बेक सो० स० जनतंत्र में दूसरी योजना के अंतर्गत उद्योगों में जो रकम लगाई गई, वह १११६ करोड़ रुबल थी।**

दूसरी योजना का उद्देश्य सभी शोषक वर्गों को मिटाना और समाजवाद की स्थापना करना था। उद्योग के क्षेत्र में यह उद्देश्य चार वर्षों में ही पूरा हुआ और कृषि में लक्ष्य की अधिपूरति हुई। सोवियत संघ में औद्योगिक पैदावार १९१३ की तुलना में ८ गुना और १९२६ की तुलना में ४३ गुना बढ़ गई जबकि पूँजीवादी देश १९२६ की तुलना में मुश्किल से १०२५ प्रतिशत तक पहुँचे होंगे और १९३७ के उत्तरार्द्ध में वहाँ औद्योगिक पैदावार घटन लगी। १९३८ में पूँजीवादी देशों में औद्योगिक पैदावार १९२६ की तुलना में ६० प्रतिशत रह गई थी। परंतु सोवियत संघ में १९३७ की तुलना में ११३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीवादी देशों में उसी साल में १३५ प्रतिशत की कमी हुई।***

दूसरी योजना में भारी उद्योगों की ओर बहुत ध्यान दिया गया। इसमें उज्बेक सोवियत समाजवादी जनतंत्र में चिरचिक नदी का बाधन और बिजली शक्ति पैदा करने का लक्ष्य सामने रखा गया था। प्रथम बिजलीघर का निर्माण उसी समय शुरू हुआ, जब पहली योजना पूरी हुई और दूसरी में तुरंत हाथ लगा दिया गया था। इस बिजली शक्ति को इस्तेमाल करके चिरचिक में एक रासायनिक कारखाने का निर्माण पूरा किया गया। आल्मालीक में, जहाँ तांबा निकाला जाता था, ताम्र प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया। कृषि मशीनें बनाने के ताशकन्द कारखाने का विस्तार किया गया और

* श० न० उत्तमस्वायेव उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १४१।

** "उज्बेकिस्तान का उद्योग, विकास का संक्षिप्त विवरण, १९१३-१९३८", ताशकन्द, १९४१, पृष्ठ १४। (रूसी संस्करण)

*** "सोवियत संघ के अर्थतंत्र के विकास की दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", मास्को, १९३६, पृष्ठ १२। (रूसी संस्करण)

एक सूती बपट्टा बाग़दाने का निर्माण दमरी योजना के दौरान पूरा किया गया। उर्खेक सो० स० जनतंत्र में औद्योगिक पैदावार का मूल्य १९३२ के ६८४ करोड़ रूपय से बढ़कर १९३७ में १९६८ करोड़ रूपय हो गया (२४ गुना वृद्धि)।* सूती बपट्टा उद्योग में दमरी योजना के दौरान पैदावार ४८ गुना बढ़ी, तेल और गन्ध उद्योग में ७८ गुना बिजली-शक्ति उत्पादन में ३ गुना और धातुबस्त-उद्योग में ५ गुना।**

श्रम की उत्पादनशीलता की वृद्धि के लिए दशव्यापी मावजनिश आन्दोलन दूसरी योजना की अवधि में शुरू हुआ। आन्दोलन १९३५ के अगस्त में दोनबास में शुरू हुआ और वहाँ के एक कोयला मजदूर के नाम पर, जिसने मानव से १४ गुना अधिक कायला निकालने का रिकार्ड कायम किया था, उस आन्दोलन की ध्याति स्तूपानाव आन्दोलन के नाम से हुई। दूसरी योजना में समाजवादी प्रतियोगिता नई उत्पादन-तकनीक के आधार पर की गई। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर फैल गये। १९३७ तक उर्खेक सो० स० जनतंत्र में उद्योग में काम करनेवाले ४४ प्रतिशत मजदूर किसी न किसी प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। अगर १९२८ में १४०० इंजीनियर और तकनीकी मजदूर उर्खेकिस्तान में उद्योग में काम कर रहे थे, तो १९३७ में उनकी संख्या ६,००० तक पहुँच चुकी थी। तकनीकी विद्यालया तथा अन्य संस्थानों में छात्रों की संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक २६,००० हो गई थी।*** उर्खेक सो० स० जनतंत्र में उद्योगों में श्रम-उत्पादनशीलता १९१३ की तुलना में चार गुना बढ़ गई थी।****

अब हम दूसरी योजना के दौरान उर्खेक सो० स० जनतंत्र की उपलब्धियाँ का खुलासा यहाँ कर सकते हैं। बिजली शक्ति का उत्पादन जो १९३२ में ६३६ किलोवाट घंटे था, १९३७ में बढ़कर २७६२ करोड़ किलोवाट घंटे हो गया। १९१३ यह केवल ३३ लाख किलोवाट-

* वही, पृष्ठ ५४।

** वही, पृष्ठ ५५।

*** श० न० उरुमस्वायेव, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १३८।

**** 'उर्खेकिस्तान १५ वर्षों के दौरान', पृष्ठ ३६।

घटे था। अतः १९१३ की तुलना में ७३ गुना वृद्धि हुई।* तेल का उत्पादन, जो १९३२ में ४६८ हजार टन था, १९३८ में बढ़कर १९६४ हजार टन हो गया, यानी १९२४-१९२५ की तुलना में ३५८ गुना वृद्धि हुई।** सूती कपड़े की पैदावार १९३२ में ८५ लाख मीटर थी, वह बढ़कर १९३६ में ६१३ करोड़ मीटर हो गई।*** उज्बेकिस्तान में भारी उद्योग का उत्पादन १९२४-१९२५ की तुलना में १५ गुना बढ़ गया। इसका पैदावार का मूल्य १९३२ में ६३ करोड़ रूबल था और १९३७ में बढ़कर १५१२ करोड़ रूबल हो गया।**** इस प्रकार उज्बेकिस्तान के औद्योगिकरण में बड़ी सफलता प्राप्त हुई और वह एक दशक के भीतर एक शक्तिशाली औद्योगिक जनतंत्र बन गया।

मध्य एशिया के अन्य जनतंत्रों के औद्योगिकरण में भी बड़ी प्रगति हुई। तुर्कमान सो. सं. जनतंत्र में औद्योगिक पैदावार का मूल्य दूसरी योजना के दौरान १२९ करोड़ रूबल से बढ़कर २९३ करोड़ रूबल हो गया, यानी २३ गुना बढ़ गया।***** औद्योगिक पैदावार १९२५ में जनतंत्र की कुल पैदावार का २७.९ प्रतिशत थी, वह उससे बढ़कर १९३७ में ६८.९ प्रतिशत हो गई। मगर कृषि की पैदावार उत्पादन की आम वृद्धि के बावजूद ७२.१ प्रतिशत से घटकर ३१.१ प्रतिशत पर पहुंच गई।*) दूसरी योजना के दौरान तुर्कमान सो. सं. जनतंत्र के आर्थिक विकास की एक विशेषता तेल और रासायनिक उद्योग का द्रुत विकास थी। कृषि बोगाज गोल खाड़ी के खनिज साधनों के उपयोग के साथ रासायनिक उद्योग में बड़ी प्रगति हुई। तेल की पैदावार १९३२ में ३४ हजार टन थी, वह बढ़कर १९३७ में ४५२ हजार टन हो गई (१३ गुना वृद्धि हुई)।**)

* वही, पृष्ठ ३७।

** वही, पृष्ठ ३८।

*** वही, पृष्ठ ३९।

**** वही, पृष्ठ ३३।

***** "दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", मास्को १९३९, पृष्ठ ५३-५४।

*) "तुर्कमान सो. सं. जनतंत्र के १५ वर्ष", अशकाबाद, १९३९, पृष्ठ ९। (रूसी संस्करण)

**) "दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम", पृष्ठ ५३-५४।

आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उन्मूलन २८३

ब्रिगिज सो० स० जनतंत्र म १९३२-१९३७ मे ६१ बड़े औद्योगिक उद्योगों का निर्माण किया गया। स्थानीय कृषि की उपज से सवधित हलके उद्योगों के साथ-साथ कई भारी उद्योगों का भी निर्माण हुआ। १९३५ म ताशा-कुमिर कोयला खान पर काम शुरू किया गया। करा वाल्ती चीनी कारखाना और फ्रूजे चमड़ा कारखाना भी उसी अवधि म खोल गये। कैशिंग्जस्तान मध्य एशियाई जनतंत्रों का कोयला क्षेत्र बन गया। कोयले की पैदावार ७२० हजार टन से बढ़कर ८९६ हजार टन हो गई।*

इसी प्रकार ताजिकिस्तान म भी उद्योगीकरण ने बड़ी प्रगति की। अक्टूबर क्रांति से पहले इस इलाके म आधुनिक उद्योगों का नाम निशान तक नहीं था। प्रथम योजना क अंत तक इस जनतंत्र म १०० के करीब औद्योगिक उद्यम स्थापित हो चुके थे। दूसरी योजना के दौरान यह संख्या और बढ़कर १२५ हो गई। औद्योगिक पैदावार का मूल्य १९३२ क ५१ करोड़ रूबल से बढ़कर १९३७ म १८७ करोड़ रूबल तक, यानी ३७ गुना बढ़ गया।** तेल का उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ा। शुरुआत कोयला खदानों की तयारी के काम म प्रगति हुई। दुशावे और इसफारा म सिलिकॉन और चूने के कारखानों का निर्माण हुआ। वर्जाव म एक बड़ा विजलीघर बनाया गया। दुशावे की विशाल टेक्सटाइल मिल पर भी काम दूसरी पंच वर्षीय योजना क दौरान शुरू किया गया।

इन जनतंत्रों के आर्थिक ढांचे मे बड़े परिवर्तन हुए और उनका सामाजिक आर्थिक रूप इतना बदल गया कि पहचाना नहीं जाता था। समाजवादी उद्योगीकरण के साथ मध्य रूस के इलाकों के और मध्य एशिया के विकास स्तर का फाव बढ़ी हद तक दूर हो गया और इस समाजवादी योजना की अवधि म पूरे सोवियत संघ म औद्योगिक पैदावार ने मूल्य म २२०६ प्रतिशत वृद्धि हुई, मगर रू० सो० म० र० जातक म गई, मूल्य २२०४ प्रतिशत, जबकि सो० स० जनतंत्र म २४३० प्रतिशत और

* वही, पृष्ठ ५७।

** वही, पृष्ठ ५५।

ताजिकिस्तान में ३५५७ प्रतिशत थी।* आम तौर से पूँजी विनियोग की दर भी मध्य एशिया के जनतंत्रों में सोवियत संघ से अधिक थी। दूसरा योजना के दौरान जहाँ इसमें सोवियत संघ में २८ गुना वृद्धि हुई, वहाँ उर्ज़ेक सो० सं० जनतंत्र में ३८ गुना हुई।** मध्य एशियाई जनतंत्रों के बड़े उद्योगों में मजदूरों की संख्या में १९३२-१९३७ में ५६५ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों में यह वृद्धि २२२ प्रतिशत थी।

समुचित क्षेत्रीय विकास

ज० ह्वीलर ने इस बात की चर्चा करते हुए कि मध्य एशिया का ६० प्रतिशत कपास सूत के रूप में सोवियत संघ के अन्य भागों में भेजा जाता है, मध्य एशियाई अर्थव्यवस्था के “अपनिवेशिक” स्वरूप का उल्लेख किया है।*** परन्तु इससे सोवियत मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था का एकांगी “अपनिवेशिक” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, जसा कि मालूम है, कपड़ा उद्योग में ही नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि इसका प्रयोग मोटर-कार और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है और इनके विकास की अधिक अनुकूल परिस्थिति सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों में है। कपास के सूत का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के अन्य भागों में सूती कपड़ा कारखानों में भेज दिया जाता है, क्योंकि मध्य रूस के इलाकों

* “दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम”, पृष्ठ ११५।

** “उर्ज़ेक़िस्तान के अर्थतंत्र का इतिहास”, खण्ड १, ताशकंद, १९६२, पृष्ठ २७३। (रूसी संस्करण)

*** ज० ह्वीलर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्वीलर इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहते कि उर्ज़ेक़िस्तान, जिसकी जन संख्या सोवियत संघ की कुल जन-संख्या का ४६ प्रतिशत है, संघ का १५ प्रतिशत गन्स, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ५० प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग का सामान, ७२ प्रतिशत कपास-मफ़ाई सामान तथा १०० प्रतिशत कपास चुनने की मशीनें पैदा करता है।

का प्राप्ति के पहले ही सूती कपड़ा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। मध्य एशिया अपनी कपास केवल रूस ही में नहीं, बल्कि समाजवादी देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के अंतर्गत पोलैंड और चेकोस्लावाकिया में भी भेजता है। इनके अलावा अगर मध्य एशिया की कपास की सारी पदावार की खपत स्थानीय कारखानों में ही कर ली जाये, तो इसमें इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जायेगा और यह उद्योग की अर्थ १०० शाखाओं को, जो आज वहाँ हैं, विवसित करने की सम्भावना से वंचित हो जायेगा। आखिर समुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यंत विवसित पंजाबवादी देश में भी कपास उत्पादक राज्यों का औद्योगिक विकास सूती कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है और उनकी कपास का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों का भेजा जाता है।

मध्य एशिया से कपास की बड़ी मात्रा के निर्यात का यह मतलब नहीं कि वहाँ सूती कपड़ा उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। उर्वेक सो० सं० जनतंत्र न १९५८ में देश के कुल सूती कपड़े के ४ प्रतिशत का उत्पादन किया।* कपड़े का प्रतिव्यक्ति सालाना उत्पादन सोवियत संघ में २५ मीटर और उर्वेकिस्तान में २७ मीटर था।**

इसी तरह हंगेरि का यह कहना भी सही नहीं है कि १९५७ में पशुओं की संख्या प्रातिपूर्व की तुलना में केवल १७ प्रतिशत अधिक थी,

* "१९६१ में सोवियत संघ का अर्थतंत्र", मास्का, १९६२, पृष्ठ २५२। (रूसी संस्करण)

** यह सही है कि उर्वेक सो० सं० जनतंत्र में सूती कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन हाल के वर्षों में कुछ गिर गया है। १९६६ में वह २१ ३ मीटर था। इसका कारण यह है कि एक ओर सूती कपड़ों की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई है और दूसरी ओर शुद्ध और कृत्रिम रेशम की मांग तथा सिनथेटिक कपड़ों की मांग बढ़ी है। रेशमी कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन १९४० में १४ मीटर से बढ़कर १९६० में २८ मीटर और १९६६ में ४ मीटर हो गया। ("५० वर्षों की अवधि में उर्वेक सो० सं० जनतंत्र का अर्थतंत्र", तशकंद, १९६७, पृष्ठ ५३, रूसी संस्करण)।

ताजिकिस्तान में ३५५७ प्रतिशत थी।* ग्राम तौर से पूँजी विनियोग की दर भी मध्य एशिया के जनतंत्रों में सोवियत संघ से अधिक थी। दूसरी योजना के दौरान जहाँ इसमें सोवियत संघ में २८ गुना वृद्धि हुई, वहाँ उज़्बेक सो० सं० जनतंत्र में ३८ गुना हुई।** मध्य एशियाई जनतंत्रों के बड़े उद्योगों में मज़दूरी की संख्या में १९३२-१९३७ में ५६५ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि मध्य रूस के इलाकों में यह वृद्धि २२२ प्रतिशत थी।

संतुलित क्षेत्रीय विकास

ज० ह्वीलर ने इस बात की चर्चा करते हुए कि मध्य एशिया का ६० प्रतिशत कपास सूत के रूप में सोवियत संघ के अन्य भागों में भेजा जाता है, मध्य एशियाई अर्थव्यवस्था के “औपनिवेशिक” स्वरूप का उल्लेख किया है।*** परन्तु इससे सोवियत मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था का एकांगी “औपनिवेशिक” स्वरूप लक्षित नहीं होता। कपास, जसा कि मालूम है, कपड़ा उद्योग में ही नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि इसका प्रयोग मोटर कार और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है और इनके विकास की अधिक अनकूल परिस्थिति सोवियत संघ के अन्य क्षेत्रों में है। कपास के सूत का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के अन्य भागों में सूती कपड़ा कारखानों में भेज दिया जाता है, क्योंकि मध्य रूस के इलाकों

* “दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम”, पृष्ठ ११५।

** “उज़्बेकिस्तान के अर्थतंत्र का इतिहास” खण्ड १, ताशकंद, १९६२, पृष्ठ २७३। (रूसी संस्करण)

*** ज० ह्वीलर, उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ १६१। परन्तु ज० ह्वीलर इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहते कि उज़्बेकिस्तान, जिसकी जन संख्या सोवियत संघ की कुल जनसंख्या का ४६ प्रतिशत है, संघ का १५ प्रतिशत गन्स, ७ प्रतिशत खनिज-खाद, ५० प्रतिशत सूती कपड़ा उद्योग का सामान, ७२ प्रतिशत कपास-मफाई सामान तथा १०० प्रतिशत कपास चुनन की मशीनें पैदा करता है।

का क्रांति के पहले ही सूती कपड़ा उद्योग में विशेषीकरण हो चुका था। मध्य एशिया अपनी कपास केवल रुम ही में नहीं, बल्कि समाजवादी देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के अंतर्गत पोलैंड और चेकोस्लावाकिया में भी भेजता है। इससे अलावा अगर मध्य एशिया की कपास की सारी पैगवार की खपत स्थानीय बाजारों में ही कर ली जाये, तो इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जायेगा और वह उद्योग की श्रम १०० शाखाओं को, जो आज वहाँ है, विकसित करने की सम्भावना से वंचित हो जायेगा। आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यंत विकसित पूँजीवादी देश में भी कपास उत्पादक राज्यों का औद्योगिक विकास सूती कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है और उनकी कपास का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को भेजा जाता है।

मध्य एशिया से कपास की बड़ी मात्रा के निर्यात का यह मतलब नहीं कि वहाँ सूती कपड़ा उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। उज्बेक सो० सं० जनतंत्र ने १९५८ में देश के कुल सूती कपड़े के ४ प्रतिशत का उत्पादन किया।* कपड़े का प्रतिव्यक्ति सामाना उत्पादन सोवियत संघ में २५ मीटर और उज्बेकिस्तान में २७ मीटर था।**

इसी तरह हंगेरि का यह कहना भी ग़लत नहीं है कि १९५७ में पशुओं की संख्या नातिपूव की तुलना में केवल १७ प्रतिशत अधिक थी,

* "१९६१ में सोवियत संघ का अर्थतंत्र", मास्को, १९६२ पृष्ठ २५२। (रूसी संस्करण)

** यह सही है कि उज्बेक सो० सं० जनतंत्र में सूती कपड़ों का प्रतिव्यक्ति उत्पादन हान के वर्षों में कुछ गिर गया है। १९६६ में वह २१ ३ मीटर था। इसका कारण यह है कि एक ओर सूती कपड़ों की मांग अपेक्षाकृत कम हो गई है और दूसरी ओर शुद्ध और कृत्रिम रेशम की मांग तथा सिन्थेटिक कपड़ों की मांग बढ़ी है। रेशमी कपड़ा का प्रतिव्यक्ति उत्पादन १९५० में १४ मीटर से बढ़कर १९६० में २८ मीटर और १९६६ में ४ मीटर हो गया। ('५० वर्षों की अवधि में उज्बेक सो० सं० जनतंत्र का अर्थतंत्र', तशकंद १९६७ पृष्ठ ५३, रूसी संस्करण)।

जबकि जनसंख्या में ७५ प्रतिशत वृद्धि हो गई थी।* उनका दावा है कि जाति से पहले के मुकाबले में पशुओं की प्रतिव्यक्ति संख्या कम हो गई थी। पशुओं की संख्या १९१६ के २९ लाख से बढ़कर १९५९ में ३७ लाख हो गयी थी, यानी २७ प्रतिशत, और भेड़-बकरी में ७७ प्रतिशत वृद्धि हुई थी।**

पशुओं की संख्या में वृद्धि की तुलना जन-संख्या में ग्राम वृद्धि से नहीं, बल्कि कृषि आवादी में वृद्धि से करनी चाहिए, जिसमें मध्य एशिया में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई, यद्यपि इसका अनुपात १९१३ में ८१ प्रतिशत से घटकर १९५९ में ५५ प्रतिशत हो गया।*** यह बात भी याद रहे कि व्यापक पशुपालन खानाबदोश अव्यवस्था से (खासकर किमिजस्तान और तुर्कमानिस्तान में) आवासित कृषि में सन्मरण का प्रभाव मध्य एशिया के किसानों की अव्यवस्था में पशुओं के महत्त्व पर और उनकी वृद्धि की दर पर पड़ा। इसके अलावा पशुओं की संख्या में वृद्धि या कमी से अपने आप कोई बात सिद्ध अस्िद्ध नहीं होती, जबतक पशुओं की उत्पादित तथा कृषि में उनके सानुपातिक भाग पर विचार नहीं किया जाये। मध्य एशिया में पशुओं की उत्पादित में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भेड़ों से उन निकालने में औसतन मध्य एशिया का स्थान सप्सार के सबसे अगुआ देशों में है। जैसा कि ज्ञात है पशुओं की कुल संख्या में सप्सार में प्रथम स्थान भारत का है (१७५६ करोड़), परन्तु उत्पादित के मामले में उसका स्थान सबसे पीछे है। फिर, मध्य एशिया में कृषि शक्ति में पशुओं का सानुपातिक हिस्सा ६०७० प्रतिशत से लगभग शून्य पर पहुँच गया है। १९६३ में कृषि में १३५ करोड़ अश्व शक्ति ऊँचा का प्रयोग हुआ, जिसमें केवल २ लाख अश्व शक्ति पशुओं द्वारा प्राप्त हुई।**** १९६३ में मध्य एशिया के खेतों में १३० हजार ट्रैक्टर काम कर रहे थे।

* ज० ह्वीलर, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६१।

** '१९६१ में सावित्त सच का अद्यतन', पृष्ठ ३८४।

*** "१९६३ में मध्य एशिया का अद्यतन", ताशकन्त १९६४ पृष्ठ ८।
(रूसी संस्करण)

**** वही, पृष्ठ १८१।

पूरे सोवियत संघ तथा मध्य एशियाई जनतंत्रों के औद्योगिक उत्पादन में बड़ा अंतर नहीं है। उज्बेकिस्तान में कुल उत्पादन में उद्योग का हिस्सा ७३ प्रतिशत और कृषि का २७ प्रतिशत है, जबकि पूरे संघ के लिए ये आंकड़े क्रमशः ८० प्रतिशत और २० प्रतिशत हैं।* परन्तु मध्य एशिया में प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन पूरे सोवियत संघ के प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा है (पूरे सोवियत संघ की तुलना में प्रतिव्यक्ति उत्पादन उज्बेकिस्तान में ५२.५ प्रतिशत, तुर्कमेनिस्तान में ५०.२ प्रतिशत, किर्गिजस्तान में ४२.९ प्रतिशत और ताजिकिस्तान में ४६ प्रतिशत है।)** इस "पीछे रहने" के दो कारण हैं। इसका पहला कारण है उस भयंकर आर्थिक असमानता के अवशेष, जो जारशाही औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप चौथे दशक के आरम्भ तक मौजूद थे। सोवियत पंचवर्षीय योजनाओं ने शुरू ही से मध्य एशिया में औद्योगिक विकास-स्तर को ऊंचा करने की चेष्टा की। युद्धोत्तर वर्षों में इस दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। १९५० और १९६३ के बीच सोवियत संघ की कुल औद्योगिक पैदावार ३९४ प्रतिशत बढ़ी, जबकि मध्य एशिया में ५३० प्रतिशत बढ़ी।*** आठवीं पंचवर्षीय योजना (१९६६-१९७०) में मध्य एशिया के लिए नियोजित वृद्धि दर पूरे सोवियत संघ में अधिक थी। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में उज्बेकिस्तान में ६० प्रतिशत, किर्गिजस्तान में ७० प्रतिशत वृद्धि हुई (सोवियत संघ में ४६.४९ प्रतिशत)।

नवीं पंचवर्षीय योजना (१९७१-१९७५) ने मध्य एशिया के जनतंत्रों के लिए औद्योगिक विकास की तेज गति को कायम रखा है। समस्त सोवियत संघ में ४२-४६ प्रतिशत के औसत की तुलना में उज्बेकिस्तान

* "४० वर्षों की अवधि में सोवियत उज्बेकिस्तान का विकास", ताशकंद, १९६४, पृष्ठ २८ और '१९६९ में सोवियत संघ का अर्थतंत्र', मास्को, १९६२, पृष्ठ ७६। (रूसी संस्करण)

** "युद्धोत्तर अवधि में सोवियत संघ के समाजवादी अर्थतंत्र का विकास", मास्को, १९६५, पृष्ठ ५१९। (रूसी संस्करण)

*** वही, पृष्ठ ५१८, "१९६३ में मध्य एशिया का अर्थतंत्र", पृष्ठ २३।

गयी और ५ गुना अधिक मिजली शक्ति का प्रयोग हो गया। इन सब कारवाइयों के फलस्वरूप कृषि की लाभकारिता लगभग उतनी ही हुई जितनी उद्योग की है और सभी सोवियत जनतन्त्रों की राष्ट्रीय आय का स्तर कमोवेश समान हो गया।

परन्तु अखिल-संघीय स्तर की तुलना में इस सीमित "पीछे रहने" के बावजूद सोवियत मध्य एशिया न गत ४० वर्षों में बड़ी प्रगति की—औद्योगिक उत्पादन के उस स्तर से, जो तुर्की से पीछे था और लगभग भारत के स्तर के समान था, वह एक विकसित औद्योगिक देश के स्तर पर पहुँच गया है। १९६१ में सोवियत मध्य एशिया न, जिसकी जन-संख्या १५ करोड़ है, पूरे संसार के औद्योगिक उत्पादन का ०.७ प्रतिशत पैदा किया। परन्तु भारत ने, जिसकी जन-संख्या संसार की १९ प्रतिशत है, केवल १२ प्रतिशत किया। उसी अवधि में उज़्बेकिस्तान न जिसकी आबादी संसार की ०.३० प्रतिशत है संसार के औद्योगिक उत्पादन का ०.४५ प्रतिशत पैदा किया।

१९५७ में यूरोप के लिए आर्थिक आयोग द्वारा प्रकाशित 'सोवियत संघ में क्षेत्रीय आर्थिक नीति' की रिपोर्ट में मध्य एशियाई जनतन्त्रों तथा मध्य एस के उन्नत क्षेत्रों के विकास स्तर का खाई को दूर करने की दिशा में दो पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियाँ का घड़न करने की चेष्टा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य एशिया का उद्योग १९२६ में बहुत छोटा था और जितने वर्षों में जितनी प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया गया है (१९२६ से १९४० तक बारह गुना से अधिक), वह एक ऐसे देश के लिए, जो पुनर्निर्माण के दौर से गुज़र रहा हो, या औद्योगिक विकास की प्राथमिक अवस्था में हो, कोई अनोखा कारनामा नहीं है। एक और मिमाल ली जाय, पाकिस्तान में १९५० से १९५६ तक* छह वर्षों

* ज० ह्वीलर द्वारा उद्धृत उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५६ २६८
प्रतिशत (Statistical Year Book, United Nations New York, 1958)
और ३६१ प्रतिशत (Economic Survey and Statistics for 1958—1959
Karachi)

यूरोप की दो पूँजीवादी शक्तियाँ व बीच मडियों के लिए, उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए, ससार का घटवारा करने के लिए सघष की स्थिति में मध्य एशिया के कमज़ार सामंती खान प्रशासित राज्यों के लिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना असम्भव था। ज़ारशाही रूस ने मध्य एशिया का समामेलन करके वहाँ के लोगों को साम्राज्यवादी ब्रिटेन के चंगुल में फँसने से बचा लिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ज़ारशाही साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद से किसी तरह बेहतर था। सच तो यह है कि दो प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यों में किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। दोनों का एक ही उद्देश्य था—मध्य एशिया के लोगों का शोषण करना और उनको गुलाम बनाना। परंतु भेद का कारण निहित था रूसी साम्राज्य की परिस्थिति के विशेष स्वरूप में साम्राज्यवादी देश तथा उपनिवेश की आम जनता के विशेष राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों में, रूसी जनगण और रूसी साम्राज्य के सीमावर्ती जनगण की भौगोलिक निकटता में। इसके विपरीत भारत के जनगण अंग्रेज़ मजदूरों या किसानों से कभी मिल नहीं सकते थे। वे केवल औपनिवेशिक अधिकारियों—गोरे साहबों—को ही जानते थे।

ज़ारशाही के साम्राज्यवादी औपनिवेशिक उद्देश्यों के बावजूद रूस से मध्य एशिया का समामेलन “इतिहास की दृष्टि से” निस्संदेह वस्तुतः प्रगतिशील था। पूँजीवाद के सारे नकारात्मक तथा स्याह पहलुओं के बावजूद मध्य एशिया के समामेलन के बाद पूँजीवादी संबंधों की उत्पत्ति प्रगतिशील थी। इसके कारण उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ और मजदूर वर्ग ने जन्म लिया। अगर ब्रिटेन का कब्जा हो गया होता तो मध्य एशिया के लोगों को रूसी जनगण के करीब आन का मौका नहीं मिलता, जो उनके भावी ऐतिहासिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। औपनिवेशिक इलाकों के श्रमजीवी जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का रूस के मजदूरों के आतिकारी आन्दोलन के साथ एक धारा में मिल जाना वास्तव में मध्य एशिया पर ज़ारशाही के कब्जे का एक महान प्रगतिशील परिणाम था।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सिक्याम को मध्य एशिया के खिलाफ आक्रमण का अड्डा बनाने की चेष्टा की। वे चाहते थे कि परगना घाटी में अपना असर फैलाने के लिए याकूब बेग के राज्य का इस्तेमाल करें। काशगर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुर्की के सुल्तान के धार्मिक प्रभाव से भी फायदा उठाया। अपनी कठपुतली याकूब बेग के पतन तथा उसके राज्य पर चीनियों का कब्जा हो जाने के बाद अंग्रेजों ने चीनियों को रियायतें देने की नीति अपनायी, क्योंकि वंजारशाही रूस के खिलाफ अपनी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे।

अकतूरर शांति ने मध्य एशिया की जातियों के जीवन में एक नए युग का प्रारम्भ किया। उसने अतीत में वंजारशाही द्वारा उत्पीड़ित जातियों को वास्तव में स्वतंत्र और समान बनाया, उन्हें राजनीतिक समानता और राजत्व ही प्रदान नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का दूर करने का अवसर भी दिया। सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पीड़न और असमानता का उन्मूलन किया और बड़ी तथा छोटी जातियों के बीच मैत्री और विरादराना सह्या की बुनियाद डाली। इस स्थिति में राष्ट्रीय समस्या का अत्यंत उल्हासपूर्ण समाधान हुआ।

सोवियत मध्य एशिया में जीवन-मंतर, सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, संचार और उत्पादना का स्तर अधिनाश अपनी की और एशियाई दशा से बहुत ऊंचा है।

सोवियत शासन द्वारा मध्य एशिया के जनगण व जीवन में अर्द्ध शताब्दी के ऐतिहासिक दृष्टि से कम समय में खबरदस्त सामाजिक-मार्कसवाद तब्दीली हा गया है। सामाजिक रूपांतरण की सोवियत विधिया और तरीका, उनके परिणामा तथा उनके प्रति जनगण की प्रतिनियामा और अनुचारा का अध्ययन सभी नवम्वाधीन अफ्रीकी और एशियाई दशा के लिए बहुत ही दिलचस्प और लाभदायक होगा, क्योंकि ये दशा भी अपने राष्ट्रीय विकास के माग पर सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। मध्य एशिया में पुराने से नए में परिवर्तन आगाम है।

या। कभी-कभी गलतिया और कुछ ज्यादातिया भी हुईं। परन्तु इसको स्वीकार करने का मतलब इससे इनकार करना नहीं है कि जो तब्दीलिया हुई, व बड़ी हद तक जनगण की अपनी डच्छा और मर्जी से की गयी थी।

मध्य एशिया के जनगण की इन महान सफलताओं का श्रेय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था, नियोजित आर्थिक विकास तथा सोवियत जातिया की मैत्री और परस्पर सहायता को है। मध्य एशिया की जातिया का ऐतिहासिक अनुभव विश्वव्यापी महत्व का है। इतिहास में वे पहली जानिया थी, जिन्होंने पूँजीवादी विनास की पीड़ाओं में गुजर बिना समाजवाद का रास्ता अपनाया। आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों के लिए पूँजीवादी विकास का रास्ता दुःख और पीड़ा का रास्ता है। इससे पिछड़ापन और दरिद्रता कायम रहती है। सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के ऐतिहासिक अनुभव न साबित कर दिया है कि एकमात्र समाजवादी विकास का रास्ता ही इन देशों के लिए तेजी से प्रगति करने का रास्ता है। सोवियत मध्य एशिया के जनतंत्र पूर्व में समाजवाद के प्रकाश-स्तम्भ हैं, जो करोड़ों जनगण के लिए शांति और समाजवाद के मध्य का मार्ग उज्ज्वल कर रहे हैं।

कुछ पश्चिमी लेखकों ने सोवियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के शासन-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में समाजवादी व्यवस्था के महान योगदान का नज़रअंदाज़ करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए, अमरीकी विद्वान रिचर्ड अ० पियस न टिप्पणी की है

“ये उपलब्धिया अवश्य ही वास्तविक हैं, परन्तु सिक्के की दूसरी तरफ भी है। पहली बात यह कि यह विकास बड़ी हद तक शायद सोवियत व्यवस्था के बिना ही हो जाता क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती जाती है और प्रगति किसी एक व्यवस्था का इजारा नहीं है।”*

लेकिन सोवियत मध्य एशिया के जनतंत्रों की प्रगति के स्तर का मुकाबला पड़ोस के मुस्लिम राज्यों से किया जाये, तो इसमें कोई सन्देह

नही रहेगा कि व्यवस्था का महत्त्व बहुत है। पिछले जमाने में तुर्की मध्य पूरु का सबसे शक्तिशाली राज्य था। १९१७ से पहले वह कई लिहाज से मध्य एशिया से आगे था। मध्य एशियाई राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के नेता उसे एक आदर्श राज्य तथा अनुकरणीय उदाहरण मानते थे। परन्तु तुर्की आज तक एक कृषिप्रधान देश है। उसकी राष्ट्रीय आय में उद्योग का हिस्सा दसव भाग से कुछ ही अधिक है। तुर्की लगभग केवल कृषि की उपज का निर्यात करता है, आयात मुख्यतः मशीना और अन्य औद्योगिक सामान का होता है। परन्तु समाजवाद की विजय ने सोवियत मध्य एशिया के जनतन्त्रा को उनका औद्योगिक कृषिक क्षेत्र बना लिया है। अन्य सभी जनतन्त्रा तथा विदेशों को उनका निर्यात कृषिक उपज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मशीनें और औद्योगिक सामान भी शामिल हैं। उज्बेकिस्तान में १९६२ में बिजली का प्रति-यक्ति उत्पादन तुर्की का लगभग सात गुना था। अन्य देश—ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान—अभी मध्य एशिया के मुकाबल में तुर्की से भी अधिक पीछे हैं।

सोवियत एशिया की पिछड़ी हुई जातियाँ की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का कारण एडवर्ड शैवशा* और सीटन वाट्सन जैसे लोग इस तथाकथित “सन्न्यापी नियम” में दूढ़ने का प्रयास करते हैं कि साम्राज्यवाद सदा भौतिक प्रगति का बाधक होता है। कहा गया है कि साम्राज्यवादी राम ने यराप का फायदा पहुँचाया और ब्रिटेन ने अफ्रीका का। (अवश्य ही भूतान, राय बलस्वी, फेरबुड और स्मिथ जैसे लोग अफ्रीकी जातियों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अनमान भट्ट हैं।) सीटन वाट्सन सोवियत सत्ता और ब्रिटिश साम्राज्य की भौतिक उपलब्धियों के अंतर के दो कारण बताता है। एक यह कि हमें साम्राज्य की गरिमा जातियों सम्मिता के अपने आम स्तर की दृष्टि से अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों और भारत तक की भी जातियों में अधिक उन्नत थी। (याता

* Foreword to *Communism and Colonialism* by Walter Kolarz London New York 1964 p XIV

बदोश किंगिज, कजाख और तुक्मान, जिनकी अपनी भाषाओं की क्रांति से पहले कोई लिपि भी नहीं थी, भारत के बंगालियों और तामिला से, जिनके साहित्य की परम्परा सैंकड़ा वर्ष पुरानी है, अधिक उन्नत थे।) दूसरा कारण था शामक देश के लोगो तथा औपनिवेशिक जातिया के अनुपात में फर्क। सीटन वॉटसन के अनुसार रूसिया और मध्य एशियाई मुसलमानों का अनुपात १५ का था, जबकि अंग्रेजों और उनकी एशियाई और अफ्रीकी रियाया का अनुपात १५० का था।* परंतु भौतिक प्रगति के प्रश्न का सारतत्व गोरे और वाले लोगो की संख्या का अनुपात नहीं, बल्कि यह है कि लोग किस सामाजिक व्यवस्था में जीवन व्यतीत करते और काम करते हैं।

सोवियत युग में मध्य एशिया के जनगण ने, जो पहले ज़ारशाही रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में शतरंज के मोहरा की तरह थे, अब स्वयं अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया है। एशिया के पड़ोसी देशों से उनका बिलगाव अब अतीत की बात हो गई है और अब वे उनसे तथा ससार के अन्य देशों से सफलतापूर्वक गहरे दोस्ताना संबंध विकसित कर रहे हैं। मध्य एशिया के मुख्य शहरों के अनेक कारखाने और प्लांट ऐसा सामान और मशीनें पैदा कर रहे हैं जिनसे भारत, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान, बर्मा और नेपाल जैसे देशों के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। अनेक अफ्रो एशियाई और लैटिन अमरीकी देशों के नौजवान विशेषज्ञ ताश्कंद में प्रशिक्षित हो रहे हैं। ताश्कंद सारी दुनिया के लेखकों, प्राच्यवेत्ताओं, फिल्मनिर्माताओं, सांख्यिकीय स्वास्थ्यकर्मियों, पीछे उपजानेवालों तथा सहकारिता विशेषज्ञों का मिलन स्थान बन गया है। अफ्रो एशियाई लेखकों का पहला सम्मेलन अक्टूबर १९५८ में ताश्कंद में ही हुआ था। और फिर यही अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन सेमिनार, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिक्षा पर गांधी, उष्णदेशीय रागा के संबंध में सम्मेलन, शुष्क इलाकों के अध्ययन के लिए यूनेस्को सलाहकार समिति का अधिवेशन तथा महिलाओं की शिक्षा के सवाल पर एशियाई

* H Selon Watson *New Imperialism*, p 124

और अफ्रीकी देशों की महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था।

ताशकन्द घोषणापत्र जिसके जरिये दो एशियाई दशा—भारत और पाकिस्तान—में शान्ति स्थापित हुई, इस बात का शानदार सबूत है कि मध्य एशिया के लोग अपने दो महान एशियाई पड़ोसियों के बीच सामान्य सवध पुनः स्थापित करने में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उज्ज्वल जनगण ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के सम्मेलन की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण कायम करने का पूरा प्रयत्न किया। अनेक मध्य एशियाई राजनीतिज्ञ और जन नेता जैसे शरफ रशीदोन, मिर्जा तुसुन जादा और बाबाजान गफूराव अफ़ा एशियाई एकजुटता, राष्ट्रीय मुक्ति तथा विश्वशक्ति के आन्दोलनों में प्रमुख भाग ले रहे हैं। स्वतंत्र और समान साक्ष्यित जातियों की विरादरी में मध्य एशिया की जातियाँ धीरे-धीरे उस स्थान पर पहुँच रही हैं, जहाँ वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभा सकें। इस प्रक्रिया का सभी शांतिप्रेमी एशियाई दशा, खासकर भारत द्वारा सक्रिय समर्थन और हार्दिक स्वागत किया जाता है। भारत के लोगों के मन में मध्य एशिया की जातियों के प्रति सदा ही मैत्रीपूर्ण सदभावना रही है।

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और डिज़ाइन सम्बन्धी आपसे विचारों के लिए आपका अनुगृहीत होगा। आपका अवगुणाव प्राप्त कर भी हम बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारा पता है

प्रगति प्रकाशन, २९, जूनाम्बी बुलवार,
माम्बा, साक्षियन सघ।

उन्हीं विशेष ध्यान उन वर्ष २१
 तत्कालीन-सामंती अवस्था में पूजा के
 छाड़त हुए समाजवादी समाज में उन मण
 की विशेष प्रशिक्षण-की आरंभ की जा
 इन जनतंत्रों में पिछले पचास वर्षों में हुई हैं।
 लेकिन न बताया है कि इसी प्रक्रिया में
 सावियत संघ की अन्य विरासत जातिवा
 की सहायता से इन इलाकों का जो पहले
 जारशाही रूप के पिछड़े हुए, औपनिवेशिक
 सीमावर्ती इलाके थे, वैसे रूपांतरण हुआ और
 वे वैसे बहुत कम समय में स्वतंत्र, और
 उनमें समाजवादी जनतंत्र बन गये जहाँ
 विविध उद्योग, मशीनीकृत कृषि है और
 विज्ञान और संस्कृति में बड़ी प्रगति की है।

द्वेन्द्र कौशिक ने तथ्यों के आधार पर
 सावियत मध्य एशिया के इतिहास के बारे में
 जेफ्री हॉलर रिचर्ड पाइप्स और मीटन
 वाटसन जैसे पूजावादी इतिहासविदों के विवृत
 विचारों का खंडन किया है।

सावियत मध्य एशियाई जनतंत्रों के
 इतिहास और वर्तमान जीवन की जानकारी
 प्राप्त करने में अपने पाठकों की सहायता
 करके लेखक ने सोवियत संघ और भारत के
 लोगों में एक दूसरे की समझ सांस्कृतिक
 समीपता और मैत्री स्थापित करने में बहुमूल्य
 योगदान किया है।